राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

सट्टेबाजी से लिंक में शाकिब पर दो साल की पाबंदी

>>14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 141

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 30 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

मप्र में सैकड़ों महिलाओं की प्रेरणा बनी यह किसान बिटिया

धार : मध्य प्रदेश के धार जिले की 24 वर्षीय रंजना वास्केल ने दो साल के परिश्रम और

सूझबूझ से न केवल पिता की 4 बीघा जमीन को मुनाफे का सौदा बना दिया, बल्कि 7 गांवों की सैकड़ों महिलाओं को खेती में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार कर दिया है। (पेज-11)

जागरण विशेष

आग से बचाएगा 'द फायर वॉरियर' नामक रोबोट

मंडी : बहुमंजिला भवनों में अब आग बुझाना आसान होगा। आइआइटी मंडी,

के प्रशिक्षुओं ने द फायर वॉरियर नाम से फायर फाइटिंग रोबोट तैयार किया है, जो आग बुझाने व भवन में फंसे लोगों को तलाश करने में मदद करेगा। (पेज-10)

कुलगाम में पांच गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या

नरसंहार ▶ यूरोपीय सांसदों के कश्मीर दौरे के पहले दिन आतंकियों ने दिया हत्याकांड को अंजाम, जान गंवाने वाले श्रमिक बंगाल के

ईयू प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों और नेताओं से ली हालात की जानकारी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर के हालात का जायजा लेने पहुंचे यूरोपीय संघ के 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के पहले दिन मंगलवार को अपने झूठ की पोल खुलने से हताश पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने कुलगाम में बड़ा नरसंहार कर दिया। आतंकियों ने पांच गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी, जबकि एक मजदूर की हालत गंभीर है। मारे गए सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। यही नहीं, पाक परस्त अलगाववादियों व आतंकियों ने यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान कश्मीर में जबरन बंद करवाकर पथराव किया, जिसमें चार लोग घायल हो गए। इस बीच, ट्रक चालकों की हत्या को देखते हुए प्रशासन ने ट्रकों को जम्मू व ऊधमपुर में ही रोक दिया है।

कश्मीर में ईयू के दौरे के दौरान कई स्थानों पर अलगाववादी तत्वों ने पत्थरबाजी की। **जागरण**

कुलगाम से मिली सूचना के अनुसार, मंगलवार शाम को स्वचालित हथियारों से लैस पांच से छह आतंकी कतरस्सु गांव में दाखिल हुए। उन्होंने गांव के बाहरी छोर पर रह रहे गैर कश्मीरी मजदूरों के डेरे पर दस्तक दी और सात लोगों को अपने साथ चलने को कहा। वहां से कुछ ही दूर चलने पर आतंकियों ने मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगते ही सभी श्रमिक जमीन पर गिर पड़े। उन्हें मरा समझकर आतंकी वहां से चले गए। आतंकियों के जाने के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित करते हुए खून से लथपथ पड़े सभी श्रमिकों को निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने पांच श्रमिकों को मृत घोषित कर दिया। जबकि गंभीर रूप से घायल जहीरूदीन नामक मजदूर को इलाज के लिए श्रीनगर लाया गया है। मृतकों की पहचान समरूद्दीन, शेख मोहम्मद रफीक, नसीमुद्दीन, रफीक उल शेख और शेख मुर्सलीन के रूप में हुई है।

नरसंहार के बाद घाटी में तनाव : मजदूरों की हत्या के बाद पूरी घाटी में तनाव है। अभी किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सुरक्षाबलों ने हत्यारे आतंकियों को मार गिराने का अभियान छेड़ दिया है। देर शाम तक कुलगाम सहित पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया।

तेरह साल बाद इतना बड़ा हत्याकांड : करीब 13 साल बाद यह पहला मौका है जब आतंकियों ने एक साथ दो या उससे ज्यादा संख्या में गैर कश्मीरी लोगों की हत्या की हो। इससे पूर्व 26 जून 2006 को आतंकियों ने कुलगाम के ही बुदरू इलाके में नौ श्रमिकों की गोली मारकर हत्या की थी। जबकि, अगस्त 2000 में आतंकियों ने अनंतनाग जिले के मीर बाजार में 19 और मीर नौगाम में सात श्रमिकों को मार डाला था।

दौरे से एक दिन पहले भी किए दो हमले : आतंकवादियों ने सोमवार को भी कश्मीर में दो हमले किए थे। उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में किए गए ग्रेनेड हमले में 20 लोग घायल हो गए थे। वहीं, बिजबिहाड़ा में दहशतगर्दों ने एक ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

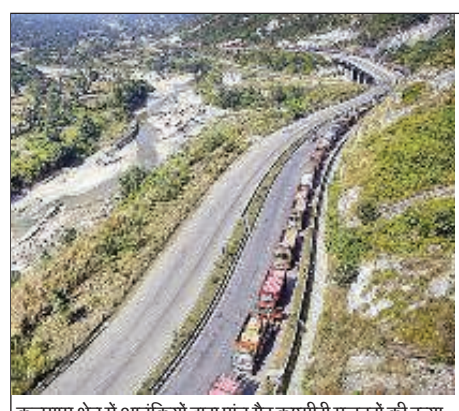

कुलगाम क्षेत्र में आतंकियों द्वारा पांच गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या किए जाने की घटना के बाद प्रशासन ने श्रीनगर जाने वाले सभी ट्रकों को जम्मू और उधमपुर में हाईवे पर ही रोक दिया है। **जागरण**

जम्मू व ऊधमपुर में रोके गए ट्रक

कश्मीर घाटी जाने वाले ट्रकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही सरकार ने जम्मू व उधमपुर में ही ट्रकों को रोक दिया है। ट्रकों को एक नवंबर तक रोके रखने का आदेश जारी किया गया है। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हजारों ट्रक खड़े हो गए। इनमें से अधिकतर ट्रक चालक दक्षिण कश्मीर में फलों की सप्लाई लेने जाने वाले हैं।

पाकिस्तान की खोली पोल

इससे पहले, 23 सदस्यीय यूरोपीय सांसदों के दल के सामने सेना, प्रशासन के अफसरों, नेताओ व नागरिक संगठनों से जुड़े लोगों ने घाटी में अशांति फैलाने के लिए पाक की नापाक हरकतों का ब्योरा रखा। पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद पहली बार विदेशी प्रतिनिधिमंडल दौरे पर आया है। बादामी बाग स्थित सेना की चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो व अन्य अफसरों ने बताया कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद व इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने में लगा है। वह निरंतर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है।

कूटनीतिक महत्व है दौरे का

कश्मीर के मुद्दे पर दुनियाभर में पाकिस्तान को अलग-थलग करने के बाद मोदी सरकार यूरोपीय सांसदों का कश्मीर दौरा कराने में सफल रही है। इसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो सांसद आए हैं वे अपने-अपने देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। (पेज 6 भी देखें)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

रक्षा तकनीकी सहयोग होगा 'टू प्लस टू' वार्ता के केंद्र में

नई दिल्ली : भारत-अमेरिका के बीच दिसंबर में होने वाली 'टू प्लस टू' वार्ता में रक्षा तकनीकी सहयोग केंद्र में होगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव की गत सप्ताह हुई बैठक में फैसला किया गया कि अब संयुक्त तौर पर विकसित होने वाले उपकरणों को लेकर समयबद्ध व स्पष्ट लक्ष्यों के साथ काम किया जाएगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

बंगाल में भाजपा के 'मिशन एनआरसी' को मिला बल

कोलकाता : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई है कि बंगाल में विदेशी अपराधियों की संख्या बढ़ी है। इसमें भी सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अपराधी हैं। यही वजह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यहां भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू कर विदेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की योजना बना रही है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

सचिवों की समिति टेलीकॉम उद्योग की चिंता का हल खोजेगी

नई दिल्ली : स्पेक्ट्रम लाइसेंस फीस और यूसेज चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हलकान टेलीकॉम उद्योग की चिंताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। सचिवों की यह समिति उद्योग की मांगों के साथ वित्तीय पैकेज की संभावनाओं पर विचार करेगी।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

अस्पताल में भर्ती नवाज शरीफ की हालत बेहद नाजुक

लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (69) की हालत बेहद नाजुक है। नवाज शरीफ के निजी चिकित्सक डॉ अदनान खान ने कई ट्वीट कर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की हालत बेहद नाजुक है। उन्होंने कहा कि कम प्लेटलेट्स काउंट और दिल का दौरा पड़ने के कारण नवाज शरीफ की किडनी भी ठीक से काम नहीं कर रही। उनका वजन भी सात किलो घट गया है।

भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करें सऊदी कंपनियां : मोदी

रियाद, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सऊदी अरब की कंपनियों को भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अगले पांच साल में इस क्षेत्र में 100 अरब डॉलर (करीब सात लाख करोड़ रुपये) के निवेश का लक्ष्य तय किया है।

'दावोस इन द डेजर्ट' सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर निवेश का प्रस्ताव देता है। मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है। लिहाजा सरकार की योजना बुनियादी ढांचा क्षेत्र में ही अगले पांच साल में 105 लाख करोड़ रुपये के निवेश की है।

कारोबारी माहौल सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, लॉजिस्टिक परफॉरमेंस इंडेक्स और इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। जबकि भारत के कर ढांचे और बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यवस्था को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सऊदी कारोबारियों से भारत के स्टार्टअप मूवमेंट का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए मोदी ने कहा कि स्टार्टअप के लिए माहौल के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और निवेशकों को सबसे ज्यादा रिटर्न का प्रस्ताव करता है।

पीएम ने कहा, भारत अगले तीन-चार साल में 40 करोड़ लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देगा। उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों को सिर्फ वस्तुओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उनमें श्रम संसाधन और प्रतिभा आवाजाही को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम ने सरकार को 20 अरब डॉलर (1.5 लाख करोड़ रुपये) बचाने में मदद की है।

संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर दिया जोर : प्रधानमंत्री मोदी ने इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र में 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुसार सुधारों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने संयुक्त राष्ट्र को विवाद सुलझाने की संस्था के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि कुछ कानून का पालन नहीं करते, कुछ कानून के बोझ तले दबे हैं। दुनिया को कानून का पालन करना होगा।'प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का विवाद सुलझाने की संस्था के रूप में उस तरह विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र की संचरना में सुधार के बारे में सोचना चाहिए। सम्मेलन में मुख्य संबोधन देने वाले मोदी ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र केवल एक संस्था नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मक बदलाव के लिए एक साधन भी होना चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि जब संघर्षों के समाधान की बात आती है तो क्या संयुक्त राष्ट्र ने अपनी भूमिका सही परिप्रेक्ष्य में अदा की है। मैंने संयुक्त राष्ट्र के 70 साल पूरे होने पर यह मुद्दा उठाया था, लेकिन इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी। उम्मीद है कि इस पर संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर ज्यादा चर्चा होगी।'

'दावोस इन द डेजर्ट' में किंग की भेंट पेज>>3

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में फ्यूचर इंवेस्टमेंट इनीशिएटिव-2019 के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। एनएनआइ

ग्लोबल इकोनॉमी काफी हद तक भारत जैसे देशों पर निर्भर

रियाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के 'असंतुलन' को आर्थिक अनिश्चितता की वजह बताया है। उन्होंने कहा, ग्लोबल इकोनॉमी काफी हद तक भारत और सऊदी अरब जैसे विकासशील देशों द्वारा तैयार किए गए 'मार्ग' पर निर्भर है। हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि अमेरिका-चीन व्यापार विवाद और अन्य वैश्विक विवादों की वजह से इस साल वैश्विक वृद्धि दर तीन फीसद रहेगी जो 2018 में 3.6 फीसद थी। दो दिवसीय यात्रा पर सोमवार रात सऊदी अरब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एक साक्षात्कार मंगलवार को 'अरब न्यूज' में प्रकाशित हुआ है। (पेज-3)

महाराष्ट्र में भाजपा-सेना के बीच तेज हुआ सत्ता संघर्ष

फड़नवीस बोले, 50-50 का कोई वादा नहीं, उद्धव ने रद की अमित शाह के साथ बैठक

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के यह कहने के बाद कि शिवसेना के साथ 50-50 फॉर्मूले (ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री) पर कभी कोई बात नहीं हुई, शिवसेना ने भाजपा के साथ मंगलवार देर शाम होने वाली बैठक टाल दी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री अपने शब्दों से पीछे हट रहे हैं तो बैठक करके क्या फायदा? सीएम के बयान के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनने का रास्ता जल्द साफ होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को मुंबई आने का कार्यक्रम रद कर दिया है, लिहाजा उद्धव से उनकी मुलाकात नहीं होगी। इस बीच, बुधवार को भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी, इसके लिए शाह ने नरेंद्र सिंह तोमर व अविनाश राय खन्ना को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का उक्त बयान मंगलवार दोपहर पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक वार्ता के दौरान आया। इसमें उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ स्वयं उनकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बैठक के दौरान 50-50 फॉर्मूले की कोई बात नहीं उठी थी। यह पूछे जाने पर कि क्या शाह ने उद्धव को ऐसा कोई आश्वासन दिया है, फड़नवीस ने कहा कि उन्होंने भी उद्धव को ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को इस पर संदेह नहीं होना चाहिए कि अगले पांच वर्ष फिर से भाजपानीत सरकार नहीं बनने जा रही। मुख्यमंत्री ने शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में छप रही खबरों एवं संपादकीय पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते। 'सामना' की भूमिका संबंधों को पटरी से उतारने वाली रहती है। शिवसेना के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह की बातचीत जारी है।

मुंबई में मंगलवार को दो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन पत्र सीएम देवेंद्र फड़नवीस को सौंपा। एएनआइ

यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा उपमुख्यमंत्री का पद शिवसेना को देगी? फड़नवीस ने कहा, उचित समय पर आपको पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा? इसके जवाब में फड़नवीस ने कहा कि अब भी कोई शक है आपको? पीएम खुद इसकी घोषणा कर चुके हैं। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है।

फड़नवीस के बयान पर शिवसेना की तीखी प्रतिक्रिया कुछ ही देर में देखने को मिल गई। मुख्यमंत्री का यह बयान सार्वजनिक होने के बाद शिवसेना के राज्यसभा सदस्य और 'सामना' के कार्यकारी संपादक संजय राउत तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया देने से बचते रहे लेकिन कुछ देर बाद ही बाकायदा संवाददाता सम्मेलन बुलाकर उन्होंने उद्धव के हवाले से जानकारी दी कि मंगलवार शाम सरकार गठन को लेकर भाजपा के साथ होने वाली बैठक शिवसेना ने रद कर दी है। उनके अनुसार जब सीएम अपनी कही बात से पीछे हट रहे हैं तो बैठक का क्या लाभ? राउत ने सवाल उठाया कि जब लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी कोई बात हुई ही नहीं तो उस समय गठबंधन हुआ कैसे? इसका उत्तर सीएम दें।

मुख्यमंत्री की वीडियो क्लिप वायरल पेज>>4

574 करोड़ के चिटफंड घोटाले में पैलान ग्रुप का मालिक गिरफ्तार

कोलकाता : चिटफंड घोटालों की जांच कर रही सीबीआइ ने मंगलवार को पैलान ग्रुप के मालिक अपूर्व साहा को गिरफ्तार कर लिया। ग्रुप पर चिटफंड के जरिये गैर कानूनी रूप से आम लोगों से 574 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मंगलवार को तीन घंटे पूछताछ के बाद सीबीआइ ने साहा को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हो, सारधा, रोजवैली घोटाले की जांच के दौरान सीबीआइ को पैलान समेत कई अन्य कंपनियों के नाम की जानकारी मिली थी। (पेज-5)

अमेरिका का दावा : बगदादी का उत्तराधिकारी भी ढेर

वाशिंगटन : आतंकी संगठन इस्लामिक इस्टेट (आइएस) के सरगना अबू बकर अल बगदादी को ढेर करने के बाद अब उसके पहले नंबर के उत्तराधिकारी को भी ढेर कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। माना जा रहा था कि बगदादी के बाद आतंकी संगठन की कमान अब्दुल्लाह कार्दश को सौंप दी गई थी। ट्रंप ने मारे गए आतंकी का नाम नहीं बताया है। (पेज-13)

आतंकवादियों के निशाने पर राष्ट्रपति, पीएम, अमित शाह और विराट कोहली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नए आतंकी संगठन ऑल इंडिया लश्कर-ए-तैयबा के नाम से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को भेजी चिट्ठी
- राज्यपाल सत्यपाल मलिक, केंद्रीय मंत्री राजनाथ, सीतारमण, नड्डा, आडवाणी और संघ प्रमुख भागवत पर भी खतरा
- भारत पर आतंकी हमलों की जिम्मेदारी से बचने के लिए दुनिया की आंख में धूल झोंकने की तैयारी

आतंकी फंडिंग के आरोपों में घिरे पाकिस्तान ने दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए नया पैंतरा चला है। इसके लिए खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने नए आतंकी संगठन 'ऑल इंडिया लश्कर-ए-तैयबा' का नाम आगे किया है। साजिश ये है कि आने वाले समय में भारत में होने वाले आतंकी हमलों की जिम्मेदारी नए संगठन पर डाल दी जाए। ताकि लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को बचाया जा सके। नए आतंकी संगठन ने अपनी हिट लिस्ट भी जारी की है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ-साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का भी नाम शामिल है। आतंकी हिट लिस्ट में पहली बार किसी क्रिकेटर का नाम आया है।

ध्यान देने की बात है कि आतंकी फंडिंग को लेकर पाकिस्तान पर एफएटीएफ की काली सूची में डाले जाने की तलवार लटक रही है और फिलहाल उसे तीन महीने का समय दिया गया है। पाकिस्तान पर लश्कर और जैश-ए-मुहम्मद जैसे आतंकी संगठनों व उनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ उसकी फंडिंग बंद करने का दबाव है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि एफएटीएफ की काली सूची से बचने के लिए पाकिस्तान ने नई चाल चली है।

ऑल इंडिया लश्कर-ए-तैयबा को पहचान देने के लिए इसकी ओर से बाकायदा एनआइए को धमकी भरा पत्र भी भेजा गया है। इसके भेजने वाले के नाम की जगह ऑल इंडिया लश्कर-ए-तैयबा हाई पावर कमेटी, कोझीकोड, केरल लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों मारे गए साथियों का बदला लेने के लिए एक दर्जन विशिष्ट लोग उसकी हिट लिस्ट में हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, क्रिकेट कप्तान विराट कोहली के साथ-साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम शामिल है। एनआइए ने खत मिलने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है।

प्रतिभा को सम्मान

हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की सूची में शांतनु नारायण, अजय बंगा व सत्य नडेला छाए, एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग को मिला है पहला स्थान

दुनिया के 10 बेहतरीन सीईओ में तीन भारतीय मूल के

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : ग्लोबल कंपनियों में भारतीय प्रतिभाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की वजह कुछ और नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, लगन और उनसे हासिल नतीजे हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू (एचबीआर) की इस वर्ष की सूची से यह बात एक बार फिर साबित होती है। एचबीआर द्वारा जारी दुनिया के बेहतरीन सीईओ की इस वर्ष सूची में शीर्ष 10 में भारतीय मूल के तीन दिग्गजों को जगह दी गई है। इनमें एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बंगा और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला शामिल हैं। एचबीआर द्वारा बनाई गई 'द बेस्ट-परफॉर्मिंग सीईओ इन दि वर्ल्ड, 2019' नाम की इस सूची में 100 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को उनके प्रदर्शन के क्रम में रखा गया है।

इस सूची में पहला स्थान अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग को दिया गया है। शांतनु नरायण को छठा, अजय बंगा को सातवां और नडेला को सूची में नौवां स्थान मिला है। इसमें एक और भारतीय मूल के अधिकारी पीयूष गुप्ता को 89वां स्थान मिला है। वह डीबीएस बैंक के सीईओ हैं।

एपल के सीईओ टिम कुक को इस सूची में 62वें स्थान पर रखा गया है। वहीं नाइकी के सीईओ मार्क पार्कर को 20वां स्थान मिला है। जेपी मोर्गन चेज के मुखिया जेमी डिमॉन 23वां स्थान पाने में सफल रहे हैं। वहीं लॉकहिड मॉर्टिन की सीईओ मर्लिन हिवसन को 37वां स्थान मिला है।

एचबीआर ने कहा है कि 2015 के बाद से इस सूची को बनाते समय वित्तीय प्रदर्शन के साथ पर्यावरण, समाजिक और प्रशासनिक (ईसीजी) क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा जाता है। इसकी सत्यता इस बात से साबित होती है कि वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस 2014 तक लगातार इस सूची में पहले स्थान पर रहते थे। लेकिन इस बार ईसीजी में कम अंक पाने के चलते वह सूची में स्थान बनाने में नाकाम रहे।

उद्योग जगत के इन दिग्गजों ने यूं हासिल किया मुकाम

शांतनु नारायण

दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एपल इंक से कैरियर की शुरुआत करने वाले और पिक्ट्रा नाम की डिजिटल फोटो शेयरिंग कंपनी के सह-संस्थापक नारायण वर्ष 1998 से टेक्नोलॉजी कंपनी एडोब में हैं। उन्हें वर्ष 2007 में कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया था। वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के मैनेजमेंट एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं।

अजय बंगा

वर्ष 1981 में एफएमसीजी कंपनी नेस्ले से कैरियर की शुरुआत करने वाले अजयपाल सिंह बंगा पेप्सिको होते हुए मास्टरकार्ड में आए। वहां अप्रैल, 2010 में सीईओ घोषित होने से पहले उन्होंने काफी समय तक प्रेसिडेंट व सीओओ के रूप में सेवा दी। वे यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन भी हैं।

सत्य नडेला

पिछले 27 वर्षों से माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े सत्य नारायण नडेला सबसे प्रतिष्ठित और मशहूर भारतीय अमेरिकी सीईओ में शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर रिसर्च व डेवलपमेंट तक में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नडेला को फरवरी, 2014 में कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया था।

दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, गाजियाबाद की स्थिति सबसे खराब

मंगलवार को दिन के 1:30 बजे धुंध की चपेट में कनाट प्लेस का पूरा इलाका। संजय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को दिनभर स्मॉग की चादर छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण मॉनीटरिंग स्टेशन में एयर इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में दर्ज हुआ, जो सोमवार को बहुत खराब श्रेणी में था। इसमें गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सोमवार को प्रदूषण का स्तर दिल्ली में 368 दर्ज किया गया था। मंगलवार को यह 400 तक पहुंच गया, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली-एनसीआर में गाजियाबाद में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया, जहां एयर इंडेक्स 446 दर्ज हुआ। नोएडा में यह 439 रहा। (पेज-2 भी देखें)

15 और प्रखर वैन शामिल हुईं दिल्ली पुलिस के बेड़े में। इन वैन को पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनके शामिल होने के बाद अब प्रत्येक जिले में दो-दो प्रखर वैन हो गई हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 30 अक्टूबर 2019

दिल्ली-एनसीआर में छाई स्मॉग की चादर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को दिनभर स्मॉग की चादर छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन में एयर इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में दर्ज हुआ, जो कि सोमवार को बहुत खराब श्रेणी में था। इसमें गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हालत सबसे ज्यादा खराब है।

सोमवार को प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में 368 दर्ज किया गया था। मंगलवार को यह 32 प्वाइंट की वृद्धि के साथ 400 तक पहुंच गया, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक प्रदूषण गाजियाबाद में दर्ज किया गया, जहां एयर इंडेक्स 446 दर्ज हुआ, जबकि नोएडा में यह 439 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में पराली जलाने के कारण वहां से दिल्ली की तरफ प्रदूषण का धुआं हवा के साथ पहुंच रहा है। वहीं रविवार को दिवाली पर पटाखे जलाने से भी प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में मंगलवार को पटाखों के धुएं के साथ पराली का धुआं मिलने से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। उन्होंने बताया कि दिन में कुछ जगहों पर सिर्फ 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। हवा की गति कम होने के चलते प्रदूषक कण वातावरण में एक ही जगह पर ठहर गए। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में दिनभर स्मॉग की चादर छाई रही।

मंगलवार को दिन के 11:30 बजे अक्षरधाम फ्लाईओवर से स्मॉग के बीच निकलते वाहन चालक। संजय

दिल्ली-एनसीआर एयर इंडेक्स		
स्थान	सोमवार	मंगलवार
दिल्ली	368	400
फरीदाबाद	358	387
गाजियाबाद	396	446
गुरुग्राम	372	368
नोएडा	397	439
ग्रेटर नोएडा	375	428

31 से प्रदूषण में सुधार की उम्मीद : मौसम विज्ञानी कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 31 अक्टूबर की शाम से हवा की गति बढ़ेगी, इससे प्रदूषण में हल्का सा सुधार होने की संभावना है। इसके बाद नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर में पहुंचेगा। इसके कारण दिल्ली की हवा में 15 किलोमीटर से तेज गति से हवा चल सकती है। इसके कारण दिल्ली के वातावरण में मौजूद प्रदूषक कण एक जगह से आगे बढ़ जाएंगे। इससे दो से तीन नवंबर तक बढ़ते हुए प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने पर ही प्रदूषक कण वातावरण से हटेंगे, जिसके बाद ही दिल्ली में स्मॉग की चादर पूरी तरह से साफ होगी।

प्रदूषण में बहुत ज्यादा सुधार की उम्मीद कम : स्काइमेट के मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदूषण में बहुत ज्यादा सुधार की उम्मीद कम ही है। सर्दी की वजह से हवा की गति तेज होने के बाद भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी से नीचे आकर बहुत खराब व खराब श्रेणी के बीच रहेगा। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ ही इसमें वृद्धि भी होती रहेगी।

पंजाब-हरियाणा में 24 घंटे में तेजी से बढ़ीं पराली जलाने की घटनाएं

जासं, नई दिल्ली : राजधानी में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने के साथ ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण बढ़ने का ठीकरा पड़ोसी राज्यों पर फोड़ा है। साथ ही सेटेलाइट से जारी तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि 24 घंटे में हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इसकी वजह से ही दिल्ली गैस के चैंबर के रूप में बदल गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि पंजाब एवं हरियाणा राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। सोमवार को जहां 1654 जगहों पर पराली जलाई गई थी। वहीं मंगलवार को यह संख्या 2577 पहुंच गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रोजेक्ट सफर द्वारा बताया गया है कि पराली जलाने के कारण दिल्ली में पहुंचे प्रदूषक कणों की वजह से इस वर्ष दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर दर्ज हो सकता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मंगलवार को ट्वीट करते हुए पंजाब एवं हरियाणा सरकार से अपील की है कि वह इसे रोकने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाएं, ताकि दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिल सके।

चार रात एलिवेटेड रोड रहेगा बंद, दिल्ली जाना होगा मुश्किल

जागरण संवाददाता गाजियाबाद

मेरठ और शहर के लोगों का बुधवार यानी (आज) से चार रातों तक दिल्ली जाना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का खोड़ा के पास हिंडन नहर के पुल पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते 30 अक्टूबर से लेकर दो नवंबर तक एलिवेटेड रोड पर राजनगर एक्सटेंशन रोटरी से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन रात नौ से लेकर सुबह छह बजे तक नहीं जा सकेंगे। इससे शहर के करीब दो से तीन लाख लोगों को असुविधा होगी।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का काम जिले में तेजी से चल रहा है। एनएचएआइ इन दिनों एक्सप्रेस-वे के दूसरे फेस पर तेजी का काम कर रही है, जोकि यूपी गेट से लेकर डासना तक बनना है। इन दिनों खोड़ा के पास हिंडन नहर पर पुल बनाने का काम किया जा रहा है। इसके चलते एनएचएआइ के अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस से रात के एलिवेटेड रोड बंद करने की मांग की थी, जिससे कि निर्माण कार्य तेजी से किया जा सके। उधर, शहर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर परमहंस तिवारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने राजनगर एक्सटेंशन रोटरी से दिल्ली की ओर जाने वाली एलिवेटेड रोड को 30 अक्टूबर से दो नवंबर तक रात के नौ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इस बीच दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले वाहनों चालकों को इस बीच को दिक्कत नहीं रहेगी। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला एलिवेटिड रोड खुला रहेगा। उधर, राजनगर एक्सटेंशन, इंदिरापुरम, वसुंधरा, साहिबाबाद, संजयनगर, राजनगर, कविनगर, शास्त्रीनगर, गोविंदपुरम, नेहरू नगर, मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ व उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को दिल्ली जाने में दिक्कत होगी।

अब इन रास्तों का करें प्रयोग

- मोहननगर से यूपी गेट होते हुए दिल्ली जाएं
- अप्सरा रोड से आनंद विहार होते हुए दिल्ली जाएं
- डाबर चौक के पास से आनंद विहार होते हुए दिल्ली जाएं
- एनएच-9 से वाया खोड़ा होते हुए यूपी गेट तक जाएं
- इंदिरापुरम से यूपी गेट के नीचे वाले रास्ते से दिल्ली जाएं

महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा : केजरीवाल

बड़ा कदम ▶ मुख्यमंत्री ने भैया दूज की शुभकामनाएं देते हुए कहा, दिल्ली की बहनों, उनके भाई का तोहफा है बसों में मुफ्त सफर

कहा-विपक्ष के कुछ लोग महिलाओं के मुफ्त सफर की योजना का कर रहे हैं विरोध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भैया दूज के अवसर पर मंगलवार से दिल्ली सरकार ने महिलाओं को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू कर दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि आज सुबह से दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त हो गई है। महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने की ओर ये एक ऐतिहासिक कदम है। एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंक टिकट दिल्ली परिवार की सभी बहनों भाई दूज का तोहफा है। आप सुरक्षित रहें, खूब तरक्की करें। महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तभी देश आगे बढ़ेगा।

राजधानी में भैया दूज से महिलाओं के लिए दिल्ली परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा सेवा शुरू होने के बाद कुछ इस तरह खुश दिखी महिलाएं व युवतियां। संजय

देश में महिलाओं को बराबरी के अवसर नहीं मिलते : केजरीवाल ने कहा कि देश में महिलाओं को बराबरी के अवसर नहीं मिलते हैं। जब भी उन्हें बराबर का अवसर मिला, तो उन्होंने कमाल कर दिखाया फिर चाहे खेल की दुनिया हो, पढ़ाई की दुनिया हो, अंतरिक्ष की बात हो या कारोबार की दुनिया हो।

पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं को कम दिया जाता है वेतन : मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कामकाजी लोगों में सिर्फ 11 फीसद ही महिलाएं हैं, 89 फीसद पुरुष हैं। इसका मतलब उन्हें बराबरी के अवसर नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में रोजना सफर करने वाली सिर्फ 30 फीसद महिलाएं हैं। इसके अलावा बस में रोजाना सफर करने वालों में भी महिलाएं महज 30 फीसद हैं। इससे साफ है महिलाओं को बराबरी के अवसर नहीं मिलते। अगर कहीं पर एक फैक्ट्री हो या कोई जगह हो, वहां नौकरी पर रखा जाए तो महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं, पुरुषों को अधिक पैसे दिए जाते हैं।

बहनों, बेटियों को मिलेगा मौका, नहीं छूटेगी पढ़ाई : मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे समाज में कुछ लोग कोख में बच्चा पता करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि लड़की है तो गर्भपात करा लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कई लोगों को जानता हूं जिनकी बेटी का कॉलेज या स्कूल दूर है वह आने-जाने का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं जाहिर है इस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। आज यह कदम हम उठा रहे हैं, जिससे ऐसी सभी बहनों, बेटियों को मौका मिलेगा। उनकी पढ़ाई अब नहीं छूटेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी बहन को दूर नौकरी करने जाना है तो उसे यह नहीं सोचना पड़ेगा कि कितना किराया लगेगा। दिल्ली की सरकार ने आपका किराया मुफ्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वह कहते हैं कि केजरीवाल सब कुछ मुफ्त कर रहे हैं।

दोपहर तक दो लाख महिलाओं ने किया मुफ्त सफर

दिल्ली परिवहन निकम (डीटीसी) की बसों में मुफ्त सफर योजना के पहले दिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। डीटीसी के अधिकारियों ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि बसों में मुफ्त यात्रा के दौरान दोपहर 2 बजे तक पहली शिफ्ट में 2 लाख 20 हजार 691 महिलाओं ने बसों में सफर किया। इसके साथ ही महिला यात्रियों के सफर का कुल फीसद 32 .65 रहा। इस दिन टिकट लेकर बसों में यात्रा करने वाले कुल यात्री 6 लाख 76 हजार 28 लोग रहे। पहले दिन महिलाओं की यात्रा करने का अनुपात दो फीसद बढ़ गया।

महिलाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक : आतिशी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई डीटीसी व क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार की बसों में मुफ्त सफर योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यह टिकट केवल यात्रा पास नहीं है बल्कि महिला सशक्तीकरण के नए युग की उत्पत्ति का चिह्न है। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में 131 देशों में से 120 वें पायदान पर है।

योजना को भाजपा ने बताया चुनावी घोषणा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा ने महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना को चुनावी घोषणा करार दिया है। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी का कहना है कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों की कमी दूर किए बिना इस तरह की योजना का कोई लाभ महिलाओं को नहीं मिलेगा। उन्होंने इस योजना में बुजुर्गों व छात्रों को भी शामिल करने की मांग की है। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा का भाजपा स्वागत करती है, लेकिन इस योजना के पीछे दिल्ली सरकार की नीयत सही नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इससे सिर्फ चुनावी लाभ उठाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में दिल्ली में 15 फीसद रिहायशी इलाका बढ़ गया है। यहां की जनसंख्या भी लगभग 20 लाख बढ़ी है, लेकिन डीटीसी बसों की संख्या बढ़ने की बजाय घट गई है। 2015 में डीटीसी के 574 रूट थे, इनमें 132 रूट बंद करने के साथ ही बसों के 12 सौ फेरे कम कर दिए गए हैं। राष्ट्रमंडल खेल के समय दिल्ली की सड़कों पर सात हजार बसें चलती थीं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों से दस हजार नई बसें खरीदने का वादा किया था, लेकिन एक भी बस नहीं खरीदी गई। इस समय डीटीसी की 3781 बसें रह गई हैं।

हर मामले में राजनीति करना ठीक नहीं : सीएम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार जनता को सुविधाएं मुहैया करा रही है, लेकिन विपक्ष के लोग सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहे हैं। हर मामले में राजनीति करना ठीक नहीं है, जनता के हित की जहां बात हो, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कही है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं पर विपक्षी दलों द्वारा सवाल किए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें राजनीति से परे होती हैं। दिल्ली सरकार की योजनाओं का विरोध कर रहे दलों को यह समझने की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था लोगों के कल्याण पर खर्च किए जाने वाले 100 रुपये में से 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और जनता तक केवल 15 रुपये ही पहुंचते हैं। उनकी सरकार यह 85 रुपये बचाकर यदि जनता को सुविधाएं दे रही है, तो इसमें गलत क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा की तर्ज पर बुजुर्गों और छात्रों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया में कुछ अड़चनें हैं, जिन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा।

भाजपा के वार रूम से होगा विरोधी दलों पर हमला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव की तैयारी को धार देने के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में अस्थायी चुनाव कार्यालय (वार रूम) बनेगा। बुधवार को भूमि पूजन के साथ वार रूम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पार्टी में एकजुटता दिखाने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए सभी सांसदों, विधायकों व पार्षदों के साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भी भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया है।

प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मुख्यालय प्रभारी राजेश भाटिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए अस्थायी कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। चुनावी रैली, रोड शो सहित अन्य चुनावी कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं के लिए भी अलग से कमरे बनेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया एवं मीडिया कक्ष के साथ ही चुनावी व्यवस्थाओं के लिए अलग-अलग कार्यालय व बैठक कक्ष होगा। इस अस्थायी कार्यालय से दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रवादी सोच है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को धोखा देने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री व दिल्ली के चुनाव सह-प्रभारी हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, दिल्ली के सभी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।

ट्रॉली बैग के पहिये में छिपाया था सोना, तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए एक भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपित ने ट्रॉली के पहिये में सोना छिपाकर लाया था। उसके पास से सोने के 12 टुकड़े बरामद हुए जिनका वजन करीब 420 ग्राम है। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वह इससे पहले भी सोने की तस्करी कर चुका है। पहले भी वह ट्रॉली के पहिये में सोना छिपाकर लाया था।

आइजीआइ एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारी ने बताया कि घटना 25 अक्टूबर की है। बैंकॉक से स्पाइस जेट की उड़ान आइजीआइ एयरपोर्ट पर आई थी। इससे उतरा एक संदिग्ध शख्स एयरपोर्ट से बाहर निकलने की जुगत में लगा था। कस्टम अधिकारी उसपर नजर रख रहे थे। इसी दौरान उसने ग्रीन चैनल पार किया उसके सामान की जांच की गई। उसके पास तीन ट्रॉली बैग थे। जांच में पता चला कि ट्रॉली बैग के पहिये में सोना छिपाया गया है। बाद में पहिये के अंदर से सोने के 12 टुकड़े मिले। सोना बरामद होते ही तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। यह जांच की जा रही है कि तस्कर कहां से सोना लेकर आया था और उसे कहां खपाया जाना है।

तीन लाख बच्चियों को छात्रवृत्ति देगा मौलाना आजाद फाउंडेशन

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की जनरल बॉडी की 70वीं बैठक की अध्यक्षता करते केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री व फाउंडेशन के अध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष तीन लाख बच्चियों को छात्रवृत्ति देगा। वह फाउंडेशन की जनरल बॉडी की 70वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न रोजगारपरक कौशल विकास एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा की गई।

नकवी ने बताया कि यह छात्रवृत्ति बेगम हजरत महल योजना के अंतर्गत छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों- जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, सिख व मुस्लिमों की आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों को दी जाएगी। गत वर्ष दो लाख बच्चियों को छात्रवृत्ति दी गई थी। 31 अक्टूबर के बाद आवेदनों को सूचीबद्ध करके इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। इस मौके पर फाउंडेशन के सचिव रिजवान उर रहमान, उपाध्यक्ष अशफाक सैफी आदि उपस्थित रहे।

दिवाली के बाद अब ट्रेनों में उमड़ी छठ की भीड़

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिवाली के बाद अब रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा में घर जाने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। जनरल कोच में लोग शौचालय में खड़े होकर सफर कर रहे हैं। वहीं स्लीपर कोच में भी चढ़ने के लिए यात्रियों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। बुधवार को भीड़ और बढ़ने की संभावना है। इसे ध्यान में रखकर नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर भीड़ संभालने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इन स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) व रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) के जवानों की अतिरिक्त तैनाती के साथ ही सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

स्टेशनों पर भीड़ न बढ़े इसके लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की ओर विशेष पंडाल में अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया गया है। इसमें टिकट काउंटर, पूछताछ काउंटर, सहायता बूथ, पेयजल, मोबाइल शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। खान-पान के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर न जाना पड़े। इसी तरह की व्यवस्था आनंद विहार टर्मिनल पर भी की गई है।

अस्थायी प्रतीक्षालय में उद्घोषणा प्रणाली भी लगाई गई है। इसके साथ ही पूरे परिसर में अतिरिक्त लाउड स्पीकर लगाए गए हैं जिसके माध्यम से यात्रियों को नियमित व विशेष ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि 86 के करीब विशेष ट्रेनें चल रही हैं जिसमें अनारक्षित ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके साथ ही खाली रैक तैयार किए गए हैं। भीड़ बढ़ते ही मौके पर विशेष ट्रेन भी चलाई जाएगी। जनरल टिकट लेने में यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए बिहार के कई शहरों के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। पूर्व दिशा की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 व आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर एक से रवाना हो रही हैं। ताकि यात्रियों को फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करना पड़े।

प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को कतार में खड़ा करने के लिए भी आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। इन तमाम प्रबंधों के बावजूद यात्रियों की भीड़ के आगे रेल प्रशासन बेबस नजर आ रहा है।

छठ को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने अपने घर जाने वाले यात्रियों की उमड़ी भीड़। जागरण

छठ पर चलाई जाएं निशुल्क विशेष ट्रेनें : कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छठ पूजा को लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन कीर्ति आजाद ने कहा कि यमुना किनारे छठ घाट पर जरूरी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। वहीं काफी संख्या में लोग दिल्ली से अपने घर जाकर यह त्योहार मनाते हैं। कहने को तो इनके लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं लेकिन उसका किराया नियमित ट्रेनों से कई गुना ज्यादा है। उन्होंने निशुल्क विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की है। आजाद ने कहा कि दिल्ली से दरभंगा का साधारण किराया 535 रुपये है, जबकि विशेष ट्रेन के नाम पर यात्रियों से 1865 रुपये किराया वसूला जा रहा है। गरीब लोग घर जाकर अपने परिवार के साथ छठ पर्व मना सकें इसके लिए रेलवे को उचित कदम उठाना चाहिए। दोनों नेताओं ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए निशुल्क विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की है।

उपलब्धि

उत्तर भारत के किसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला यह सबसे बड़ा कार्गो विमान है, इससे पहले इस तरह के विशाल मालवाहक विमान मुंबई से उड़ान भरा करते थे

आइजीआइ एयरपोर्ट से बोइंग 747-8एफ ने भरी उड़ान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट से मंगलवार को मालवाहक विमान बोइंग 747-8एफ की शुरुआत की गई। उत्तर भारत के किसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला यह सबसे बड़ा कार्गो विमान है। इससे पहले इस तरह के विशाल मालवाहक विमान मुंबई से उड़ान भरा करते थे। अब यह विमान दिल्ली से हफ्ते में छह दिन उड़ान भरेगा। इससे विदेशी माल की ढुलाई में तेजी आएगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने इसका स्वागत किया है।

आइजीआइ एयरपोर्ट से शुरू किए गए मालवाहक विमान के साथ कंपनी के अधिकारी।

डायल प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी कंपनी यूपीएस ने बोइंग 747-8एफ विमान के साथ दिल्ली से छह साप्ताहिक उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। यह उड़ान दिल्ली से कोलोन और दिल्ली-दुबई-कोलोन मार्ग पर उपलब्ध होगी। इसकी पहली उड़ान मंगलवार को दिल्ली से कोलोन के लिए रवाना की गई। इससे पहले कंपनी बोइंग बी 747-400, बी 747-8 और बी 767 जैसे अपेक्षाकृत छोटे कार्गो विमानों का संचालन कर रही थी। अब कम समय में ज्यादा स्थानों से अधिक माल लाया जा सकेगा, इससे उत्तर भारत में कारोबार तेजी से बढ़ेगा। इस मौके पर डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरिया ने कहा कि आइजीआइ एयरपोर्ट देश में कार्गो सेवा के लिए हब बन चुका है। नए मालवाहक विमान के संचालन से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि होगी। हाल ही में देश के पहले ट्रांसशिपमेंट एक्सीलेंस सेंटर (टीईसी) की शुरुआत कर एयरपोर्ट ने कार्गो के क्षेत्र में खासी बढ़त हासिल की है। यूपीएस के भारत के प्रबंध निदेशक रचीद फर्गीति ने कहा कि दिल्ली से इस नवीनतम मालवाहक विमान के संचालन से भारत से यूरोप और अमेरिका के बाजारों में सामान जल्दी से पहुंच सकेगा।

दरअसल आइजीआइ एयरपोर्ट देश का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है, जहां तीन रनवे हैं। यहां 150 एकड़ क्षेत्र में दो अत्याधुनिक एकीकृत कार्गो टर्मिनलों का भी निर्माण कराया गया है, जहां कार्गो विमानों को खड़ा करने के लिए नौ फ्राइटर पार्किंग वे भी बनाए गए हैं। यहां से बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स व दवा इत्यादि सामान की ढुलाई की जाती है।

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रबुद्ध जनमत जरूरी शर्त : वेंकैया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में (डीयू) में अरुण जेटली की स्मृति में आयोजित व्याख्यानमाला का प्रथम व्याख्यान उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने दिया। उन्होंने कहा कि एक प्रबुद्ध जनमत स्वस्थ लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है। जन शिक्षा के लिए मीडिया एवं राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन दोनों ही संस्थाओं ने अपनी भूमिका का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया है। राजनीतिक दलों को सतत जनसंपर्क के माध्यम से जनचेतना बढ़ानी चाहिए। इसी तरह मीडिया को भी सतत जनचेतना और जनशिक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति के साथ ही अरुण जेटली के परिवार के सदस्य - पत्नी संगीता जेटली, बेटे रोहन जेटली, बेटी सोनाली और उनके दामाद जयेश बख्शी मौजूद थे। साथ ही डीयू के कुलपति प्रो. योगेश त्यागी भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति डीयू के कुलाधिपति भी हैं। व्याख्यान से पहले अरुण जेटली के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।

दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस रीगल कंवेंशन हॉल में आयोजित प्रथम अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को स्मृति चिह्न भेंट करते कुलपति प्रो. योगेश कुमार त्यागी। ध्रुव कुमार

डीयू को गर्व है कि अरुण जेटली हमारे पूर्व छात्र थे : डीयू के कुलपति प्रो. योगेश त्यागी ने कहा कि हमें अपने पूर्व छात्र रहे अरुण जेटली पर गर्व है। बीते सालों में हमेशा यह प्रयास रहा कि वे डीयू में एक पूर्व छात्र के तौर पर आएं और व्याख्यान दें, लेकिन व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हो सका। इस बात का हमेशा खेद रहेगा कि यह अब कभी संभव नहीं होगा। उनके जाने से देश को, डीयू के बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। अरुण जेटली ने डीयू के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की थी।

2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के बीच 'टू प्लस टू' वार्ता का फैसला किया गया था। अभी तक इसकी एकमात्र बैठक हुई जो कि दिल्ली में अक्टूबर, 2018 में हुई थी।

ग्लोबल इकोनॉमी काफी हद तक भारत जैसे देशों पर निर्भर : मोदी

बोले ▶ आर्थिक अनिश्चितता की वजह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का असंतुलन

'अरब न्यूज' को दिए साक्षात्कार में बोले प्रधानमंत्री

रियाद, प्रेट्र : बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के 'असंतुलन' को आर्थिक अनिश्चितता की वजह बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (ग्लोबल इकोनॉमी) काफी हद तक भारत और सऊदी अरब जैसे विकासशील देशों द्वारा तैयार किए गए 'मार्ग' पर निर्भर है। हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने कहा था कि अमेरिका-चीन व्यापार विवाद और अन्य वैश्विक विवादों की वजह से इस साल वैश्विक वृद्धि दर तीन प्रतिशत रहेगी। 2018 में वैश्विक वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत रही थी।

सोमवार रात सऊदी अरब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एक साक्षात्कार मंगलवार को 'अरब न्यूज' में प्रकाशित हुआ। इसमें मोदी ने कहा, 'वैश्विक आर्थिक परिदृश्य काफी हद तक भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा तैयार मार्ग पर निर्भर है। मैंने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा था कि हमारा ईमानदारी से मानना है कि सभी की वृद्धि के लिए हमें समन्वित प्रयासों की जरूरत है। इसमें सभी का भरोसा भी होना चाहिए।' 'जी-20 में भारत और सऊदी अरब असमानता दूर करने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।' यह पूछे जाने पर कि भारत और सऊदी अरब सहित अन्य देशों को वैश्विक आर्थिक सुस्ती से कैसे निपटना चाहिए, मोदी ने कहा, भारत ने कारोबार के अनुकूल माहौल पैदा करने के लिए कई सुधार किए है। इसका नतीजा है कि विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में 2019 में भारत 63वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2014 में इस सूची में भारत 142वें स्थान पर था। सुधारों का मकसद यह भी है कि हम वैश्विक वृद्धि और स्थिरता के लिए प्रमुख भूमिका में रहें। उन्हें खुशी है कि सऊदी अरब ने भी अपने दृष्टिकोण 2030 के तहत सुधार कार्यक्रम शुरू किया है।

भारत-सऊदी अरब में बढ़ रहा सुरक्षा सहयोग : पीएम ने कहा, आतंकवाद से मुकाबला करने सहित सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर भारत और सऊदी अरब के बीच आपसी सहयोग बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। 'मेरा मानना है कि भारत और सऊदी अरब जैसी एशियाई शक्तियां अपने-अपने पड़ोस में समान रूप से सुरक्षा चिंताओं को साझा करती हैं। मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में रियाद का दौरा किया था जो बेहद सार्थक रहा।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारी, रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त समिति है जो नियमित बैठकें करती है। हमने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी हित और सहयोग के कई क्षेत्रों की पहचान की है। दोनों देश सुरक्षा सहयोग और रक्षा उद्योगों में सहयोग पर समझौते करने की प्रक्रिया में हैं और एक व्यापक सुरक्षा संवाद तंत्र बनाने पर भी दोनों देश सहमत हैं।'

क्रेता-विक्रेता संबंधों से आगे बढ़ रहे दोनों देश : प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सऊदी अरब क्रेता-विक्रेता संबंधों से करीबी रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें सऊदी अरब का भारत के तेल एवं गैस परियोजनाओं में निवेश शामिल है। मोदी ने कहा, 'सऊदी अरैमको भारत के पश्चिमी तट पर बड़ी रिफाइनरी और पेट्रो कैमिकल परियोजनाओं में हिस्सेदारी कर रही है। हमें अरैमको की भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में हिस्सेदारी की भी उम्मीद है।' सऊदी अरैमको दुनिया की सर्वाधिक लाभकारी कंपनी है। इसका दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार पर नियंत्रण है। वहीं, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने के मामले में इराक के बाद सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है। भारत अपने कच्चे तेल के आयात की 18 फीसद जरूरत सऊदी अरब से पूरी करता है।

भारतीय समुदाय का परिश्रम संबंधों को मजबूत बनाने में मददगार : प्रधानमंत्री ने कहा कि सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के कड़े परिश्रम और प्रतिबद्धता ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में काफी मदद की है। उन्होंने कहा, 'करीब 26 लाख भारतीयों ने सऊदी अरब को अपना दूसरा घर बना लिया है। वे उसकी वृद्धि और विकास में योगदान दे रहे हैं। कई भारतीय हर साल हज, उमराह और कारोबारी वजहों से सऊदी अरब की यात्रा करते हैं।' भारतीय समुदाय को अपना संदेश देते हुए मोदी ने कहा, 'सऊदी अरब में आपने अपने लिए जो स्थान बनाया है, भारत को उस पर गर्व है।

भारत के खुदरा तेल कारोबार में निवेश करेगा सऊदी अरब

नई दिल्ली, रायटर : पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सऊदी अरब की कंपनियां भारत के ऑयल और गैस रिटेलिंग सेक्टर में निवेश की तैयारी कर रही हैं। इसमें दोनों देशों के हित शामिल होंगे। समझौते के बाद सऊदी अरब को भारत में एक स्थायी खुदरा बाजार मिल सकेगा। ज्ञात हो, सऊदी अरब की कंपनी अरैमको और यूएई की कंपनी एडनॉक ने भारत की सरकारी कंपनियों के साथ प्राथमिक समझौता किया है। इसके तहत ये कंपनियां भारत के पश्चिमी तट पर 12 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाली रिफाइनरी लगाएंगी। इस रिफाइनरी में इन कंपनियों की 50 परसेंट हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा सरकार भारत पेट्रोलियम में अपनी 53 .29 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है।

'दावोस इन द डेजर्ट' में सऊदी किंग से की मुलाकात

रियाद, प्रेट्र : 'दावोस इन द डेजर्ट' सम्मेलन में भाग लेने दो दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और घटनाओं की निंदा करते हुए द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। सऊदी किंग ने प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर के भोज का आयोजन भी किया। 'दावोस इन द डेजर्ट' सम्मेलन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक सम्मेलन की तर्ज पर हो रहा है। इसमें इससे जुड़े देशों में निवेश की भावी संभावनाओं पर विचार होगा।

प्रधानमंत्री मोदी और किंग सलमान के बीच बैठक और भोज के बाद प्रधानमंत्री के आर्थिक संबंधों के सचिव टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद की सभी रूपों और घटनाओं की निंदा करते हुए द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच कृषि, तेल एवं गैस, समुद्री सुरक्षा, नवीन प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों में सहयोग, सुरक्षा सहयोग, हवाई सेवा समझौते, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा उत्पादों के नियमन और नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम जैसे क्षेत्रों में विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। त्रिमूर्ति ने बताया कि राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्राउन प्रिंस सलमान के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार को राजधानी रियाद में सऊदी अरब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज एल साउद से मुलाकात हुई। एएनआइ

कई सऊदी मंत्रियों ने की मोदी से मुलाकात : विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान, श्रम व सामाजिक विकास मंत्री अहमद बिन सुलेमान अलराजी और पर्यावरण, जल व कृषि मंत्री अब्दुल रहमान बिन अब्दुलमोहसेन अल फेडली ने मुलाकात की। सऊदी अरब के मंत्रियों से चर्चा सार्थक रही। खासतौर से दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई।

रायगढ़ की महत्वाकांक्षी परियोजना पर अहम चर्चा : सऊदी ऊर्जा मंत्री अजीज के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खासतौर पर अहम है क्योंकि दोनों देशों ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पश्चिमी तट पर बड़ी रिफाइनरी परियोजना लगाने का फैसला किया है। इसमें सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी अरैमको और भारत की सरकारी तेल कंपनियां बड़ा निवेश करने वाली हैं।

पीएम मोदी की दूसरी सऊदी अरब यात्रा : प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले वह 2016 में यहां आए थे। इसी साल फरवरी में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिल सलमान भारत आए थे। बीते कुछ साल में दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। वर्ष 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार 27.48 अरब डॉलर का रहा। इस तरह सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा व्यापार साझेदार बन गया। सऊदी अरब ने पिछले माह घोषणा की कि वह भारत के ऊर्जा, पेट्रो कैमिकल, रिफाइनिंग, बुनियादी ढांचे, कृषि व खनन क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

जॉर्डन के किंग से भी मिले मोदी : रियाद में ही प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, खासकर व्यापार और निवेश में परस्पर रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। जॉर्डन में 10 हजार भारतीय रहते हैं।

▶ दोनों नेताओं ने की आतंकवाद की निंदा, द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति

भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल खपतकर्ता देश

- अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल खपतकर्ता देश है।
- भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 83 फीसद आयात करता है।
- वर्ष 2018-19 में सऊदी अरब ने 4 .33 करोड़ टन कच्चा तेल भारत को बेचा, जबकि भारत ने कुल 20 .73 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया।
- भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत सऊदी अरब से हर माह दो लाख टन एलपीजी खरीदता है।

जस्टिस बोबडे होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मंगलवार को राष्ट्रपति ने जस्टिस एसए बोबडे को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 17 नवंबर को रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद 18 नवंबर को जस्टिस बोबडे पद की शपथ लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बोबडे ने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जिसमें अयोध्या राम जन्मभूमि मामला भी शामिल है। मंगलवार को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस एसए बोबडे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 18 नवंबर से प्रभावी होगी।

जस्टिस बोबडे का जन्म 24 अप्रैल 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी करने के बाद 1978 में वह महाराष्ट्र बार काउंसिल में अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत हुए और उन्होंने बांबे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के समक्ष वकालत शुरू की। उन्होंने नागपुर पीठ के अलावा बांबे हाई कोर्ट की मुख्य पीठ और सुप्रीम कोर्ट में भी 21 वर्ष से ज्यादा समय तक वकालत की। 1998 में वह वरिष्ठ वकील नामित हुए। संवैधानिक, प्रशासनिक, कंपनी, पर्यावरण और चुनाव कानून में उनकी विशेषज्ञता है।

जस्टिस बोबडे 29 मार्च 2000 को बांबे हाई कोर्ट मे एडिशनल न्यायाधीश नियुक्त हुए और 28 मार्च 2002 को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त हुए। 16 अक्टूबर 2012 को वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 12 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत होंगे। उनका मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल एक वर्ष पांच महीने का होगा।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस बोबडे ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए जिसमें निजता का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित करने का फैसला, आधार न होने के कारण किसी भी नागरिक सरकारी सेवाओं के लाभ और मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता तथा प्रदूषण के चलते 2016 में दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला शामिल है।

▶ राष्ट्रपति ने जस्टिस एसए बोबडे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया
▶ रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस बोबडे 18 नवंबर को पद की शपथ लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने मंगलवार को नई दिल्ली में जस्टिस एसए बोबडे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। एएनआइ

एजेंट से बुक कराए गए रेल टिकट के लिए ओटीपी रिफंड प्रणाली

नई दिल्ली, प्रेट्र: अधिकृत रेलवे एजेंटों के जरिये टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत आइआरसीटीसी ओटीपी आधारित प्रणाली लेकर आया है, जो यात्रियों को टिकट कैंसल कराने और आइआरसीटीसी द्वारा दिए गए पासवर्ड का इस्तेमाल कर रिफंड पाने की सुविधा देगा।

आइआरसीटीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह प्रणाली केवल उसके अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक कराए गए ई-टिकटों पर लागू होगी। नई प्रणाली के तहत, जब भी कोई यात्री अधिकृत आइआरसीटीसी एजेंट के जरिये बुक कराए गए टिकट या पूर्ण वेटलिस्ट टिकट कैंसल कराता है तो रिफंड राशि और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का एक एसएमएस यात्री के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यात्री को रिफंड पाने के लिए एजेंट के साथ यह ओटीपी साझा करना होगा। आइआरसीटीसी के एक अधिकारी ने प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया कि अब जब रिफंड ओटीपी आधारित होगा।

रक्षा तकनीकी सहयोग होगा अमेरिका के साथ अगली 'टू प्लस टू' वार्ता के केंद्र में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वर्ष 2015 में भारत-अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में संयुक्त तौर पर अत्याधुनिक तकनीक वाले रक्षा उपकरणों को विकसित करने का एक समझौता हुआ था। विगत चार वर्षों में इस समझौते के तहत कोई जमीनी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, लेकिन अब इस समझौते की सूरत बदलने वाली है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच गठित फोरम डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव (डीटीआइआइ) की पिछले हफ्ते नई दिल्ली में हुई बैठक में कुछ अहम फैसले किए गए हैं। इसमें एक फैसला यह है कि अब संयुक्त तौर पर विकसित होने वाले रक्षा उपकरणों को लेकर समयबद्ध और साफ लक्ष्यों के साथ काम किया जाएगा और दोनों देशों की तरफ से गठित विशेष समिति इसकी लगातार निगरानी करेगी। इस बारे में दिसंबर, 2019 में अमेरिका में दोनों देशों की 'टू प्लस टू' वार्ता के दौरान हस्ताक्षर किए जाने के संकेत दिए गए हैं।

'टू प्लस टू' वार्ता का फैसला जून, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई पहली आधिकारिक बैठक में किया गया था। इसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री सदस्य होते हैं। अभी तक इसकी एकमात्र बैठक नई दिल्ली में अक्टूबर, 2018 में हुई थी। अमेरिकी सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि आगामी 'टू प्लस टू' बैठक में संयुक्त तौर पर विकसित होने वाले या निर्माण किए जाने वाले रक्षा उपकरणों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) पर भी अंतिम फैसला हो जाएगा। डीटीआइआइ की पिछले हफ्ते संपन्न बैठक में एसओपी के विभिन्न पहलुओं पर सहमति बन गई है। इसे अमेरिकी पक्षकारों ने एक बड़ी उपलब्धि के दौर पर चिह्नित किया है क्योंकि अब दोनों पक्षों को मालूम होगा कि एक दूसरे की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं। साथ ही दोनों पक्षों को साथ-साथ काम करने की चुनौतियों और अवसरों के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम होगा। अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक, डीटीआइआइ की बैठक में मुख्य तौर पर दोनों देशों की निजी रक्षा कंपनियों के बीच बेहद अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने को लेकर बात हुई है। दोनों तरफ के उद्योग किन-किन क्षेत्रों में काम करेंगे इसको परिभाषित करने वाले एक विशेष मसौदे पर आगामी 'टू प्लस टू' वार्ता में हस्ताक्षर होंगे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल दो सबसे अहम परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसमें एक है संयुक्त तौर पर अत्याधुनिक युद्धक विमान के लिए इंजन तैयार करना और दूसरा भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक विमानवाहक पोत का निर्माण। इन दोनों पर सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगुआई में हुई द्विपक्षीय बैठक में बनी थी। इसे बाद में मोदी और ट्रंप ने भी आगे बढ़ाया। माना जा रहा है कि आगामी 'टू प्लस टू' वार्ता के बाद उक्त दोनों परियोजनाएं रफ्तार पकड़ सकती हैं।

कम या गलत सजा से जुड़े ज्यादा मामले होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि निचली अदालतों द्वारा कम या गलत सजा दिए जाने के चलते उसके सामने अधिक मामले आ रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है जबकि निचली अदालतों से सजा निर्धारित करते समय सभी पहलुओं पर ध्यान देने को लेकर बार-बार कहा गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सजा तय करने की प्रक्रिया को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका समाज पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी की। प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। हाई कोर्ट ने चार लोगों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन-तीन साल की सजा को कम करते हुए उनके द्वारा जेल में बिताए गए दिनों के बराबर कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा, 'उसके पास ज्यादातर मामले ऐसे आ रहे हैं जिनमें निचली अदालतों द्वारा कम या गलत सजा सुनाई गई होती है।

राष्ट्रपति कोविंद का सुझाव, अनाथों और दिव्यांगों पर अधिक खर्च करें कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कंपनियों को सुझाव दिया है कि वे कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत अनाथ और दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए अधिक राशि खर्च करें। राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि सीएसआर गतिविधियों के जरिये विकास की चुनौतियों के लिए नवोन्मेषी समाधान ढूंढे जा सकते हैं।

कोविंद ने पहले राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा, धन का दान करने पर सम्मान मिलता है, उसे जमा करने पर नहीं। कंपनी कानून, 2013 के तहत सीएसआर प्रावधान एक अप्रैल, 2014 से लागू हुए हैं। इसके तहत निश्चित श्रेणी की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का दो फीसद एक वित्त वर्ष में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि 2014-15 से कंपिनयां हर साल सीएसआर पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करती हैं। उन्होंने कहा, समाज कल्याण गतिविधियों पर खर्च करने के लिए संसाधन, इच्छाशक्ति और रूपरेखा अहम होते हैं। उन्होंने सवाल किया कि हमें किसकी अधिक मदद करनी चाहिए....? साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि अनाथों और दिव्यांगों पर अधिक खर्च किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि 2030 तक प्रत्येक अनाथ की देखरेख की जा सकेगी। अब से राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार हर साल दो अक्टूबर को दिए जाएंगे।

समारोह के बाद महिला पुलिसकर्मी को देखने पहुंचे राष्ट्रपति: समारोह समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति उस महिला पुलिसकर्मी के पास पहुंचे जो गिर गई थी। दिल्ली की महिला पुलिसकर्मी विज्ञान भवन में मंच के सामने खड़ी थी। जिस समय राष्ट्र गान बजाया जा रहा था उसी दौरान वह गिर गई और बैठ गई। राष्ट्र गान समाप्त होने के बाद कोविंद को निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर के साथ बातचीत करते देखा गया। इसके बाद राष्ट्रपति सुरक्षाकर्मियों के साथ मंच से उतरकर महिला पुलिसकर्मी तक पहुंचे। आम तौर पर राष्ट्र गान समाप्त होने के तुरंत बाद ही राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल से विदा हो जाते हैं।

▶ राष्ट्रपति ने पहले राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार समारोह को संबोधित किया

राष्ट्रपति ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पहले राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व अवार्ड प्रदान किए। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपस्थित रहीं। प्रेट्र

'साझा स्टाफ' वाले तकनीकी संस्थानों पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंजीनियरिंग कालेज और अन्य तकनीकी संस्थानों के शिक्षक अब एक साथ दो कालेजों में नहीं पढ़ा सकेंगे। 'साझा स्टाफ' वाले तकनीकी संस्थानों पर कार्रवाई होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी शिक्षा में नियामक संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने ऐसी अव्यवस्था के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है।

एआइसीटीई ने इन तकनीकी संस्थानों को चेताते हुए कहा कि अगर उनके शिक्षकों को उसी संस्थान के किसी अन्य कालेज या किसी अन्य संस्थान में भी पढ़ाते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन संस्थानों को मिली मान्यता को भी रद किया जा सकता है। एआइसीटीई ने सभी मान्यताप्राप्त संस्थानों को भेजे पत्र में कहा है कि ऐसे गलत आचरण से ना सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि यह संस्थानों को मिली मंजूरी की शर्तों का भी उल्लंघन है।

पत्र में कहा गया है कि परिषद को यह जानकारी मिली है कि कुछ संस्थान अपने यहां पढ़ाए जा रहे कुछ पाठ्यक्रमों या तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में परिषद से मिली विस्तार की मंजूरी का उल्लंघन करते हुए विभागीय सदस्यों से एक ही संस्थान के दो कालेजों का काम करा रहे हैं या फिर शिक्षक एक नौकरी के साथ ही दूसरे कालेज में भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। एक साथ दो संस्थानों या दो स्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं है। इससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसे आचरण में लिप्त कालेजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

नगा वार्ता में दूसरे दिन भी गतिरोध बरकरार

नई दिल्ली, प्रेट्र : नगालैंड में सात दशक पुरानी उग्रवाद की समस्या का अंतिम समाधान निकालने के लिए मंगलवार को लगातार दूसरे दिन वार्ता में गतिरोध बरकरार रहा। केंद्र के वार्ताकार और राज्यपाल आरएन रवि ने एनएससीएन-आइएम और सात संगठनों के शीर्ष गठबंधन के साथ अलग-अलग वार्ता की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के साथ वार्ता निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ रही है, जबकि पूर्वोत्तर में बड़ा उग्रवादी समूह एनएससीएन-आइएम नगाओं के लिए अलग झंडे और संविधान की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। घटनाक्रम से परिचित एक अधिकारी ने कहा, 'वार्ताकार ने सुबह एनएनपीजी और दोपहर में एनएससीएन-आइएम के साथ चर्चा की। जल्द ही फिर वार्ता होने की संभावना है।' मतभेद दूर करने, खासकर एनएससीएल-आइएम की मांग के संबंध में अड़चन दूर करने के लिए दिल्ली में वार्ता का आयोजन किया गया था। हालांकि, केंद्र अलग झंडे और अलग संविधान जैसी मांगों को पहले ही खारिज कर चुका है।

बड़े मामले

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, विभिन्न छुट्टियों के कारण गोगोई के पास कामकाज के लिए सिर्फ चंद दिन ही बचे हैं

आठ कार्यदिवस में सीजेआइ को देने हैं कई फैसले

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले महज अगले आठ कार्यदिवस में वह रामजन्मभूमि, राफेल पर फैसले की समीक्षा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गलतबयानी समेत कई अहम मामलों पर अपना फैसला सुनाएंगे।

मौजूदा समय में सर्वोच्च अदालत में दीपावली का अवकाश है और सुप्रीम कोर्ट दोबारा आगामी चार नवंबर को खुलेगा। इसके बाद भी सर्वोच्च अदालत में आगामी 11 और 12 नवंबर को भी अवकाश रहेगा। इस लिहाज से मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के 17 नवंबर को रिटायर होने से पहले अदालत के पास कामकाज के लिए केवल आठ दिन ही बचे हैं।

सीजेआइ रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच जजों की एक और संविधानपीठ को राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील रामजन्मभूमि विवाद पर अपना फैसला सुनाना है। इस फैसले तक पहुंचने के लिए 70 साल पुराने अदालती मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिनों तक मैराथन सुनवाई की थी। अयोध्या में रामजन्मभूमि विवाद में सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला विगत 16 अक्टूबर को सुरक्षित कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्ष 2010 के फैसले के खिलाफ 14 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। इसमें से चार दीवानी मामले थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन को तीन पक्षों राम लला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बांटा जाए।

▶ अयोध्या जन्मभूमि मामले पर 17 नवंबर से पहले आना है निर्णय
▶ सबरीमाला समेत कई मामलों पर चीफ जस्टिस गोगोई को देना है आदेश

रंजन गोगोई फाइल फोटो

राहुल गांधी और राफेल विमान सौदे पर आना है फैसला

गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ केरल में सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर फैसला सुनाएगी। इसके अलावा, गोगोई के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' की गलतबयानी पर अपना फैसला सुनाएगी। वहीं, राफेल सौदे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा करेगा। तब सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में फ्रेंच कंपनी दासौ से खरीदे 36 लड़ाकू विमानों के सरकारी सौदे को क्लीनचिट दे दी थी।

सूचना के अधिकार के मामले पर भी आएगा फैसला

विगत चार अप्रैल को पांच जजों की संविधान पीठ ने चीफ जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता में दिल्ली हाईकोर्ट के एक विवादास्पद फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सूचना के अधिकार के दायरे में सीजेआइ का दफ्तर भी आता है।

छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू के रडार पर एक और आइएएस

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) एक और आइएएस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। 2004 बैच के इस आइएएस पर स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में एमडी रहने के दौरान भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है।

ईओडब्ल्यू के अफसरों के अनुसार मामला करीब 10 वर्ष पुराना 2009-10 का है। राज्य प्रशासनिक सेवा से आइएएस बने उक्त अफसर उस वक्त कॉर्पोरेशन में एमडी थे। इस दौरान कार्पोरेशन में प्रबंध लेखा व उप प्रबंधक तकनीकी के तीन पदों पर भर्ती निकाली गई, लेकिन इसके लिए सरकार से अनुमति नहीं ली गई। इस मामले में कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी टी राधाकृष्णन ने 2016 से ही इन तीनों अधिकारियों को पद से हटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ईओडब्ल्यू ने शिकायत के बाद इसकी नए सिरे से जांच करने की तैयारी में है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

176 नवनिर्वाचित विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं महाराष्ट्र में। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें से 113 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 30 अक्टूबर 2019

दुष्यंत का पलटवार, कहा- जजपा धोखा देकर या डरा-धमकाकर आगे नहीं बढ़ी

दिया जवाब ▶ शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने ट्वीट कर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री पर की थी टिप्पणी

संजय राउत ने लिखा था कि महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत नहीं है, जिसके पिता जेल में हों

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के बयान पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी (जजपा) किसी को धोखा देकर और डरा-धमकाकर आगे नहीं बढ़ी है। गौरतलब है कि राउत ने मंगलवार को ट्वीट किया था कि भाजपा यह समझ ले कि महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत चौटाला नहीं है, जिसके पिता जेल में हों।

राउत के ट्वीट से खफा दुष्यंत ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का गठन 11 माह पहले हुआ है। 11 माह में उनकी पार्टी कभी किसी को धोखा देकर, लड़ाई झगड़ा करके या डरा-धमकाकर आगे नहीं बढ़ी है। इस दौरान दुष्यंत ने यह भी साफ कर दिया कि उनके पिता सजा पूरी होने के बाद ही जेल से बाहर आएंगे।दुष्यंत ने नई दिल्ली स्थित अपने निवास 18 जनपथ पर पत्रकारों से बातचीत में

दुष्यंत चौटाला। फाइल

साफ कहा कि हरियाणा की सरकार भाजपा-जजपा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर चलेगी। इस सरकार को चलाने में पार्टियों के हित से ज्यादा प्रदेश की जनता का हित जुड़ा है। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही दुष्यंत ने साफ कर दिया था कि कृषि, किसान और युवाओं से लेकर उनके लिए रोजगार सबसे अहम मुद्दे रहेंगे। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही बता दिया था कि अब राज्य के युवाओं को सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दूर नहीं जाना होगा।

दुष्यंत को हरियाणा का उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने को हाई कोर्ट में चुनौती

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि, इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चौधरी देवीलाल जब देश के उपप्रधानमंत्री बने थे, तब उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने नियुक्ति रद न करते हुए साफ कहा था कि उपप्रधानमंत्री या उपमुख्यमंत्री को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आधार पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अभी तक कोई राजनीतिक खतरा नहीं है।

मंगलवार को हाई कोर्ट में दायर याचिका कानूनन मजबूत नजर नहीं आ रही है। आंध्रप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन न्यायपालिका ने किसी भी राज्य में अभी तक किसी भी उपमुख्यमंत्री को कोर्ट द्वारा नहीं हटाया गया है। हाई कोर्ट के वकील जगमोहन भट्टी द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का उपमुख्यमंत्री नियुक्त करना नियमों के खिलाफ है। राज्यपाल द्वारा दुष्यंत चौटाला को उपमुख्यमंत्री की शपथ दिलाना आर्टिकल 164 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि संविधान में कही भी उपमुख्यमंत्री का प्रावधान नही है तो राज्यपाल ने कैसे उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। जब तक यह याचिका विचाराधीन रहती है तब तक दुष्यंत चौटाला को उपमुख्यमंत्री के नाते मिलने वाली सभी सुविधाओं पर रोक लगाई जाए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी राज्य में उपमुख्यमंत्री को अतिरिक्त सुविधाएं देने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके आधार पर दुष्यंत चौटाला सुरक्षित हैं। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सचिव हरियाणा, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री को प्रतिवादी बनाया गया है।

विधानसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी कांग्रेस : भूपेंद्र सिंह हुड्डा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पूर्व सीएम ने कहा दस साल के कार्यकाल में कभी बदले की भावना से नहीं किया काम
- भाजपा-जजपा गठबंधन पर खड़े किए सवाल, कहा- पहले 2014 के वादे पूरे करे भाजपा
- जजपा ने जनादेश का निरादर करते हुए भाजपा से गठबंधन किया

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जागरण

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा-जजपा गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताते हुए कहा कि कांग्रेस विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हुड्डा ने जजपा नेताओं के उस बयान को सिरे से खारिज किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वजह से ओमप्रकाश चौटाला व अजय सिंह चौटाला जेल में बंद हैं।

चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि अपने दस साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध से काम नहीं किया। जिस केस में ओमप्रकाश चौटाला जेल में बंद हैं, उस समय वह खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही जांच की सिफारिश की थी। तब केंद्र में भाजपा की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद चौटाला पर कार्रवाई हुई थी।

हुड्डा ने कहा कि 2014 के भाजपा के कार्यकाल में इनेलो ने भाजपा के सहयोगी दल की भूमिका निभाई। 2019 में जजपा के जितने भी उम्मीदवार जीते, उन्हें भाजपा के खिलाफ दिए गए वोट मिले थे, लेकिन जनादेश का निरादर करते हुए अब जजपा नेता भाजपा के साथ खुले तौर पर सरकार में शामिल हो गए हैं। जजपा को भाजपा के विरुद्ध आया जनादेश स्वीकार करना चाहिए था।

पूर्व सीएम ने गठबंधन की मियाद से जुड़े सवाल पर कहा कि भाजपा व जजपा नेताओं को मेरी शुभकामनाएं हैं। उन्हें पहले 2014 के वादे पूरे करने चाहिए। फिर 2019 में किए गए वादों को पूरा करने की तरफ बढ़ना चाहिए। हुड्डा ने धान की खरीद में आ रही दिक्कतें खत्म करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने तथा अपराधों पर अंकुश के लिए भाजपा-जजपा से एक्शन प्लान मांगा है।

एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि जजपा नेता कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन नहीं मांगा था। अगर ऐसा नहीं है तो क्या जजपा नेताओं ने भाजपा के लिए जन समर्थन मांगा। उन्हें स्थिति साफ करनी चाहिए।

कांग्रेस में समय रहते बदलाव होता तो अधिक लाभ मिलता

पूर्व सीएम ने माना कि यदि हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व में समय रहते बदलाव हो जाता तो नतीजे और भी बढ़िया होते। हुड्डा के अनुसार उन्होंने पिछले दिनों पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। उन्हें पूरे राज्य की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि लोगों में भाजपा के विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर थी और वे कांग्रेस को दोबारा सत्ता में देखना चाहते थे। उन्होंने कुछ सीटों पर कम अंतर से हार का मंथन करने की बात कही है। हुड्डा ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी।

हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ मिशन-एमडी

नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के कमेटी कक्ष में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, साथ में हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर। जागरण

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा की मनोहर-टू सरकार में अब अपराधियों की खैर नहीं होगी। संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा को अपराध और अपराधियों से मुक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए मिशन एमडी (मनोहर-दुष्यंत) चलाया जाएगा। जल्द ही गृह और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है, ताकि प्रदेश में एक अभियान के तहत अपराधियों का सफाया किया जा सके।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से सटा होने की वजह से हरियाणा अपराधियों की शरण स्थली बना हुआ है। प्रदेश सरकार भले ही अपराध कम होने का दावा करे, लेकिन हकीकत यही है कि अपराधियों के लिए हरियाणा से सुरक्षित ठिकाना कोई दूसरा नहीं है। प्रदेश में फिलहाल चार दर्जन से अधिक बड़े गैंगस्टर सक्रिय हैं। कई संगठित गिरोह काम कर रहे हैं, जिनकी गतिविधियां एनसीआर में सबसे ज्यादा हैं। बदमाशों के सफाए के लिए राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) पहले से कार्यरत है, लेकिन अब उसे अधिक सक्रिय और पावरफुल करने की योजना है।

विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी सैलजा ने हरियाणा में अपराधियों के सक्रिय होने तथा अपराध बढ़ने का मुद्दा जोरशोर से उठाया था। हुड्डा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में हरियाणा को अपराध मुक्त करने का बड़ा वादा किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत ने अपनी-अपनी पार्टियों के प्लेटफार्म पर अपराध मुक्त हरियाणा पर फोकस रखा, जिसे अब अमल में लाने की रणनीति तैयार की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत सिंह चौटाला में मिशन-एमडी (मनोहर-दुष्यंत) चलाने पर सहमति बन चुकी है। इसका प्रारूप क्या होगा, इस पर अधिकारियों के साथ फाइनल मंत्रणा होगी। गृह सचिव नवराज संधू, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव और सीआइडी चीफ अनिल कुमार राव को एक्शन प्लान तैयार करने के संकेत दे दिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार पहले ही पांच लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा अपने चुनाव घोषणा पत्र में कर चुकी है।

हरियाणा सरकार सबसे पहले महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर नकेल से अपने मिशन की शुरुआत करेगी।

विधानसभा चुनाव के दौरान निशाने पर रहे 25 मोस्टवांटेड और 113 गुर्गे : विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा पुलिस ने 25 मोस्टवांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया। लूट, चोरी, हत्या, जबरन वसूली, एटीएम लूट, डकैती और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल 36 सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इनके 113 गुर्गों को भी दबोचा गया। चार मोस्ट वांटेड अपराधियों को सिरसा, जबकि भिवानी, रोहतक और दादरी से दो-दो तथा पानीपत, करनाल, नारनौल, रेवाड़ी, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, अंबाला, सोनीपत और कुरुक्षेत्र से एक-एक अपराधी को पकड़ा गया है।

लोकसभा चुनाव में भाजपा के निकट आने को तैयार थे दुष्यंत चौटाला

महेश कुमार वैद्य, रेवाड़ी

जननायक जनता पार्टी (जजपा) नेता और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भाजपा के साथ कदमताल करने का फैसला उन लोगों के लिए जरा भी हैरत भरा नहीं है, जो प्रदेश के राजनीतिक मिजाज को समझते हैं। दुष्यंत चाहते तो चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की गई साथ आने की अपील स्वीकार कर सकते थे, लेकिन विरासत के कारण कम उम्र में ही राजनीति दाव-पेच सीख चुके जूनियर चौटाला ने यह प्रस्ताव ठुकराने में देर नहीं की। उनके मुख्यमंत्री मनोहरलाल के साथ जाने की अपनी वजह भी है। विधानसभा चुनावों में परिस्थितियों ने भले ही चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र को भाजपा के साथ कदमताल का अवसर दिया है, मगर हकीकत में दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा के निकट आने को तैयार थे।

दुष्यंत को समझना है तो थोड़ा अतीत में झांक लीजिए। अगर लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उनको साथ चलने का सम्मानजनक ऑफर देते तो दुष्यंत इन्कार न करते। वह 23 अक्टूबर 2018 का दिन था। तब इनेलो दुष्यंत को निष्कासित करने के लिए कारण बताओ नोटिस दे चुका था, लेकिन इससे बेपरवाह दुष्यंत हरियाणा नापने के लिए निकल चुके थे। उस दिन दुष्यंत ने अपने कुछ खास मित्रों को मन की बात बताई थी। जब दुष्यंत की कार अहीरवाल के गढ़ रेवाड़ी जिले की सड़कों पर हिचकोले खा रही थी तब दुष्यंत के चेहरे पर भाव आ-जा रहे थे। दैनिक जागरण के कुरेदने पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसी दिन दुष्यंत ने अपने खास मित्रों से कहा था कि मोदी अगर देश की चिंता कर रहे हैं तो उन्हें भी उनका साथ देने में परहेज नहीं होगा। दुष्यंत की निगाह तब केंद्र में पावरफुल मंत्रालय पर थी, परंतु मोदी लहर में भाजपा ने ऐसी कोई जरूरत ही नहीं समझी, न उसे पड़ी।

किसान हित में चाहते थे बड़ा फैसला : दुष्यंत केंद्र में मंत्री बनकर एक कलम से किसान हित में बड़ा फैसला लेना चाहते थे। उन्होंने तब अपनी पूरी कार्ययोजना तो स्पष्ट नहीं की थी, परंतु इतना अवश्य कहा था कि मौका मिला तो किसान जीवनभर उनको याद रखेंगे। उस बातचीत के गवाह जजपा के पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव भी हैं। हालांकि, लोस चुनाव में भाजपा ने जजपा को साथ लेने का प्रयास नहीं किया और अकेले दम पर मैदान जीत लिया, लेकिन अमित शाह संपर्क करते तो यह युवा नेता उनकी टीम का हिस्सा हो सकता था। जजपा नेता की तमन्ना देश का बड़ा किसान नेता बनने की थी। सूत्रों के अनुसार अब भी उनका मिशन यही रहेगा।

एक वर्ष पहले दुष्यंत ने क्या कहा था

हमने रख दिया कलेजा जालिमों के तीर पर,
फैसला कर लिया आसमान छूने का बादलों को चीरकर।

न तो मैं मौन हूं, न मेरे कदम रुके हैं, मैं तो चल पड़ा हूं।

वो तो आजमा रहे हैं, हमें कलेजा आजमाने दो,
वो डर दिखा रहे हैं, हमें हौसला दिखाने दो।

दादा के उसूलों से हमने सीखा है-चाहे कांटे लगे या छाले पड़ें, चलना है तो चलना है।

दूसरी बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे नीतीश कुमार

राज्य ब्यूरो, पटना

- दिल्ली स्थित मावलंकर हॉल में होगी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक
- दिल्ली विधानसभा चुनाव में जदयू की सहभागिता पर भी चर्चा होगी।

नीतीश कुमार। फाइल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार बुधवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। दिल्ली स्थित मावलंकर हॉल में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। बैठक में देशभर से आए जदयू के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सात दिनों के भीतर यह दूसरा मौका है जब दिल्ली में जदयू के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हाल ही में दिल्ली प्रदेश जदयू के प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे।

राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक 20 अक्टूबर को राजगीर में तय थी। उप चुनाव को ध्यान में रखकर दिल्ली में बैठक करने का फैसला किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री का विशेष संबोधन होगा। राजनीतिक मसले के साथ ही सामाजिक क्षेत्र और खास तौर पर पर्यावरण के क्षेत्र में पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। बिहार में चल रहे जल-जीवन-हरियाली अभियान के बारे में भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय परिषद में यह भी स्पष्ट तौर पर सामने आएगा कि बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू और भाजपा के गठबंधन को लेकर किसी तरह के संशय की स्थिति नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जदयू की सहभागिता पर भी चर्चा होगी। जदयू से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय परिषद में पूरब के राज्यों के अतिरिक्त दक्षिण और उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

दुष्यंत चौटाला का उप मुख्यमंत्री बनना खुशी की बात : उमा भारती

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : गंगोत्री से गंगासागर तक पैदल यात्रा पर निकलीं भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने हरियाणा में नवनिर्वाचित सरकार को बधाई देते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला का उप मुख्यमंत्री बनना खुशी की बात है। गोपाल कांडा को लेकर किए गए ट्वीट पर उन्होंने कहा कि जो ठीक लगा, कह दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उमा भारती ने ट्वीट कर हरियाणा में गोपाल कांडा के भाजपा को समर्थन पर आपत्ति की थी।

14 अक्टूबर से उमा भारती 'गंगा पैदल-डोली एवं संवाद यात्रा' के तहत गंगोत्री से पैदल यात्रा कर रही हैं। इस दौरान वह गंगा तट के गांवों में लोगों से संवाद कर गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर उन्हें जागरूक कर रही हैं। उमा भारती ने कहा कि यात्रा के दौरान वे ग्रामीणों को गंगा तट पर जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं ताकि गंगाजल प्रदूषित न हो।

यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि 'मैं गंगोत्री से गंगा के साथ चल रही हूं और संवाद कर रही हूं। यदि मां गंगा ने शक्ति दी तो गंगासागर तक जाऊंगी।' कहा कि इसी यात्रा की तैयारियों के कारण उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। इस दौरान उन्होंने भैया दूज की बधाई भी दी।

सत्ता संघर्ष के बीच शिष्टाचार भेंट

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रसाद लाड ने मंगलवार को मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। भाजपा और शिवसेना के बीच वर्तमान में सरकार बनाने को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। शिवसेना जहां एक ओर राज्य में 50-50 के फार्मूले पर अड़ी हुई है। वहीं भाजपा ने इस फार्मूले को नकार दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने खुद के पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का दावा किया है। वर्तमान में महाराष्ट्र में जल्द सरकार बनने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उद्धव ठाकरे की होने वाली बैठक को भी रद कर दिया गया है। एएनआइ

सपा में विलय नहीं, जरूरत पड़ी तो करेंगे गठबंधन : शिवपाल

जागरण संवाददाता, बरेली : प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी काफी वक्त है, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अभी से अपनी भूमिका बना रहे हैं।

मंगलवार को एक निजी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए रामपुर जाते समय उन्होंने परसाखेड़ा के एक मैरिज हॉल में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत की। समाजवादी पार्टी में फिर जाने के सवाल पर कहा कि सपा में विलय संभव नहीं है। हां, 2022 में प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जरूरत पड़ी तो सपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं।

प्रसपा मुखिया ने कहा कि सूबे में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। शासन व प्रशासन में बैठे आला अधिकारी मंत्री और नेताओं व जनप्रतिनिधियों की बात सुनने को भी तैयार नहीं हैं। देश मंदी के दौर से जूझ रहा। वहीं, रोजगार की स्थिति भी चरमराई हुई है। अब होमागार्डों को भी बेरोजगार करने की तैयारी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा करते हुए बोले कि पीड़ितों को न्याय मिलना दूर, उनकी थानों में पिटाई हो रही। जनता आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी।

झारखंड चुनाव

पार्टी मान रही महागठबंधन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आवश्यक तो झारखंड विकास मोर्चा की भी जरूरत, पिछले चुनाव की तरह गठबंधन से झाविमो को बाहर करने की रणनीतिक चूक नहीं चाहती कांग्रेस

झामुमो-झाविमो के चक्कर में सीटें गंवाएगी कांग्रेस

आशीष झा, रांची

कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर चलना चाहती है और इसके एवज में पार्टी को निश्चित तौर पर सीटें गंवानी पड़ेंगी। दावा जितनी सीटों पर है उतनी सीटें मिलनी मुश्किल हैं और कुछ सीटों को झाविमो के लिए तो कुछ सीटों को झामुमो के लिए छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने पर महागठबंधन में बहुत बाधाएं हैं। कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव की तरह विपक्षी महागठबंधन को कमजोर नहीं होने देना चाहती। झाविमो के अलग से चुनाव लड़ने के कारण पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्ष की सीटें कम हुई थीं और भाजपा-आजसू को अपने बूते पूर्ण बहुमत मिल सका।

अभी हाल में ही संपन्न लोकसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन को भले ही सीटें अधिक नहीं मिलीं लेकिन वोट प्रतिशत को लेकर विपक्षी दलों में उत्साह है। कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस व झामुमो ने ढंग का प्रदर्शन किया और बढ़त ली। झामुमो ने समझौता के लिए अपनी सीटें छोड़ी थीं और यही आधार बनेगा कि झामुमो अब अपने हिस्से की सीटें नहीं छोड़ेगा। इसके विपरीत पार्टी कांग्रेस पर दबाव बनाकर सीटें छोड़ने की जिद करेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान झामुमो को विधानसभा में नेतृत्व देने का वादा भी किया था और इसका सीधा मतलब सीटों में भी बढ़त देने का है। ऐसे में कांग्रेस झामुमो के लिए भी कई सीटों पर अपना दावा छोड़ सकती है। इसी प्रकार झाविमो को एडजस्ट करने के लिए भी कई सीटें छोड़नी होंगी।

कांग्रेस त्याग को तैयार है लेकिन इसके लिए अन्य विपक्षी पार्टियों को भी तैयार होना होगा। छोटी-छोटी बातों को भूलकर सभी विपक्षी दलों को एक छत के नीचे आना होगा।

राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष, कांग्रेस।

विधानसभा चुनाव 2014 का प्रदर्शन

पार्टी	वोट प्रतिशत	सीटें
भाजपा	31.3	37
झामुमो	20.4	19
कांग्रेस	10.5	7
झाविमो	10.0	8

(शुरू में ही 6 भाजपा में गए और अभी एक और)

2009 चुनाव का प्रदर्शन

पार्टी	वोट प्रतिशत	सीटें
भाजपा	20.18	18
झामुमो	15.20	18
कांग्रेस	16.16	14
झाविमो	8.99	11

झाविमो के आठ में से सात विधायक दो चरणों में भाजपा में चले गए हैं लेकिन दावा उनका उन सभी सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में वे जीते थे। जिन सीटों पर झाविमो दूसरे नंबर पर रहा था वहां भी उनका दावा कमजोर नहीं है। ऐसे में इस बात का आकलन किया जा रहा है कि झाविमो का कितनी सीटों पर दावा बनता है और इसी हिसाब से उनके लिए सीटें छोड़ी जाएंगी।

2009 चुनाव की तुलना में झामुमो और झाविमो ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अधिक वोट प्रतिशत हासिल किया था और झामुमो के हिस्से में एक अधिक सीट भी आई लेकिन झाविमो और कांग्रेस की सीटें कम हुईं और इसका व्यापक असर भाजपा की सीटों की संख्या में हुआ।

इन सभी बातों का आकलन कर विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं मान रही हैं कि महागठबंधन का स्वरूप तैयार नहीं हुआ तो भाजपा को रोकना मुश्किल होगा। इसके लिए निश्चित तौर पर सबसे पहले दावेदारी कम करने के लिए कांग्रेस ही तैयार होगी। फिलहाल कांग्रेस 25 सीटों पर दावेदारी कर रही है और देखना होगा कि महागठबंधन में इन्हें मिलता कितना है।

मुख्यमंत्री की 50-50 फार्मूले वाली वीडियो क्लिप वायरल

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने स्वयं संवाददाता सम्मेलन में 50-50 फॉर्मूले की जानकारी दी थी। सुबह से उनकी यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे सही समय पर इस मुद्दे पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री पद हमारा हक है। हम उसी की मांग कर रहे हैं। वह भाजपा को देना पड़ेगा।

शिवसेना बोली, खुले हैं दूसरे विकल्प : यह विधानसभा चुनाव भाजपा-शिवसेना गठबंधन करके लड़ी हैं। भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही शिवसेना भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए 50-50 फॉर्मूले की बात उठाने लगी है। उसकी ओर से धमकी भी दी गई है कि यदि भाजपा ने उसकी यह शर्त नहीं मानी तो उसके पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं।

एक-दूसरे के विधायकों के संपर्क में होने का दावा : सरकार बनाने के लिए दोनों दलों में अन्य विधायकों की खींचतान भी बढ़ गई है। चुनाव परिणाम आने के दिन ही मुख्यमंत्री फड़नवीस ने दावा किया था कि निर्दलीय चुनकर आए 15 विधायक उनके संपर्क में हैं।

पिछले तीन दिनों में शिवसेना भी चार विधायकों के समर्थन का दावा कर चुकी है। इसके अलावा मंगलवार को भाजपा के एक राज्यसभा सदस्य संजय काकड़े ने कहा है कि शिवसेना के 45 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। इस संबंध में संजय राउत से पूछे जाने पर उन्होंने भड़कते हुए प्रतिप्रश्न किया कि संजय काकड़े हैं कौन? क्या उन्हें भाजपा ने यह बयान देने के लिए अधिकृत किया है? यदि मैं कहूं कि भाजपा के 75 विधायक हमारे संपर्क में हैं तो क्या कोई मानेगा?

पंजाब सरकार अदा करे 20 डॉलर की फीस : सुखबीर

बोले बादल ▶ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत पंजाब सरकार करवाती रही है गुरुद्वारों के दर्शन

अकाल तख्त सिखों की सुप्रीम संस्था और जत्थेदार का हुक्म सभी के लिए मान्य

जागरण संवाददाता, अमृतसर

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रधान एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पूर्व अकाली-भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी। दो-ढाई सौ करोड़ से सरकार अपने खर्च पर संगत को गुरुघरों के दर्शन करवाती रही है। इसी तर्ज पर पंजाब की कांग्रेस सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं का खर्च अदा करना चाहिए और पाक द्वारा लगाई गई 20 डॉलर की फीस सरकार को देनी चाहिए। सुखबीर बादल अपनी धर्मपत्नी एवं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के साथ माथा टेकने श्री दरबार साहिब आए हुए थे।

550वें वार्षिक प्रकाश पर्व को लेकर आयोजित होने वाले समारोह में एसजीपीसी और पंजाब सरकार के बीच चल रहे विवाद पर सुखबीर ने टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि श्री अकाल तख्त से जो फैसला आया है या आएगा, वही सबको मान्य होगा। श्री अकाल तख्त सिखों की सुप्रीम संस्था है और जत्थेदार साहिब द्वारा जो भी हुकुम दिया गया है, वह हम सभी के लिए मान्य है।

सुखबीर ने शिअद टकसाली के नेताओं द्वारा उन पर की गई टिप्पणी पर कहा कि वह मेरे सीनियर लीडर हैं, मैं उन्हें सम्मान देता हूं और उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। करतारपुर साहिब कॉरिडोर से क्या वह पाक जा रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि पाक जाने वाले पहले जत्थे में शामिल होने के लिए उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। उधर, हरसिमरत कौर बादल ने भी श्रद्धालुओं की फीस पंजाब सरकार द्वारा अदा करने की मांग रखी।

सरकार नाम की पंजाब में कोई चीज नहीं : सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब में चार विधानसभा हलकों में हुए उपचुनाव में सरकार ने पूरी सरकारी मिशनरी का उपयोग किया। दाखा हलके में वर्करों की मेहनत से जीत हुई है और बाकी हलकों में भी वर्करों ने सरकारी तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कैप्टन सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं। पंजाब में सरकार नाम की चीज नहीं है।

अमृतसर में मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रधान एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल अपनी धर्मपत्नी केंद्री य मंत्री हरसिमरत कौर के साथ श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे। इस दौरान श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने जाते पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। जागरण

एसजीपीसी का अरबों का बजट, 20 डॉलर के भुगतान की पहल खुद करे : मान

संवाद सूत्र, सुनाम ऊधम सिंह वाला (संगरूर)

पाकिस्तान की तरफ से श्री करतारपुर साहिब के लिए दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से 20 डॉलर की फीस वसूलने के मामले पर सियासत गरमा गई है। आप सांसद भगवंत मान ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) पर सवाल उठाया है। हलका विधायक अमन अरोड़ा के निवास पर पत्रकारों से बातचीत में मान ने कहा कि एसजीपीसी का साल का अरबों का बजट है, इसलिए उसे श्री करतारपुर साहिब की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के 20 डॉलर का भुगतान खुद करना चाहिए। राज्य सरकार को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही यह फीस सरकार की तरफ से अदा करने की बात कही है। अब एसजीपीसी को दूसरों को सलाह देने की बजाय फीस अदा करने के लिए खुद पहल करनी चाहिए।

प्रकाश पर्व पर एसजीपीसी व सरकार के संयुक्त साझा समारोह को लेकर चल रही खींचतान पर मान ने कहा कि यह बहुत ही शर्म की बात है। एसजीपीसी व सरकार दोनों को प्रकाश पर्व पर सियासत से ऊपर उठ कर कार्य करना चाहिए।

खैहरा ने अपने दरवाजे खुद बंद किए : विधायक सुखपाल खैहरा पर बात करते हुए मान ने कहा कि पार्टी के रास्ते दरवाजे उन्होंने खुद ही बंद किए हैं। जब पार्टी को उनकी जरूरत थी, तब वह छोड़ कर गए, जबकि तब उन्हें पार्टी का साथ देना चाहिए था। अब अपना इस्तीफा वापस लेकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वह आज की राजनीति के योग्य नहीं हैं।

गुरु नानक देव पर होगा विशेष विधानसभा सत्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को लेकर 6 नवंबर को होने वाले एक दिन के विशेष सत्र में पंजाब विधान सभा का नजारा बदला-बदला नजर आएगा। जहां पर स्पीकर बैठते हैं, वहां, पर उनके साथ कई और हस्तियां भी बैठेंगी। इसमें उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आदि शामिल होंगे। एक दिन के विशेष सत्र को लेकर पंजाब सरकार ने उप राष्ट्रपति व पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह समेत देश और विदेश की कई बड़ी हस्तियों को न्योता दिया है। उपराष्ट्रपति ने सत्र में हिस्सा लेने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। इस बात की पुष्टि खुद विधान सभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने भी की है। वहीं, माना जा रहा है कि पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह भी अपनी स्वीकृति दे देंगे।

पाक ने ननकाना साहिब जाने वाले शिष्टमंडल को नहीं दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर श्री ननकाना साहिब जाने वाले पंजाब सरकार के 31 सदस्यीय शिष्टमंडल को पाकिस्तान उच्चायोग ने मंजूरी नहीं दी है। यह शिष्टमंडल मंगलवार को रवाना होना था। पाकिस्तान उच्चायोग ने भारत सरकार की ओर से भेजे गए पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लिहाजा शिष्टमंडल का श्री ननकाना साहिब जाने का कार्यक्रम अब लगभग रद हो गया है। इसमें पंजाब सरकार के मंत्री, अधिकारी और पत्रकार शामिल थे। पर्यटन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास प्रताप ने कहा कि अभी तक पाकिस्तान सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिष्टमंडल को तीन नवंबर को वापस आना था, इसलिए अब इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पाक के इस फैसले से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार की संभावना को झटका लगा है। हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के बीच करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के फैसले से दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद जगी थी। अब शिष्टमंडल को इजाजत न देने मिलने से संबंधों में फिर से खटास पैदा हो सकती है।

भारत ने पाक को सौंपी कॉरिडोर से पहले जत्थे में जाने वाले 575 लोगों की सूची

भारत सरकार ने कॉरिडोर से पहले जत्थे के रूप में करतारपुर साहिब जाने वाले 575 लोगों की सूची पाकिस्तान को सौंप दी है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पंजाब के सांसद व विधायक भी इस जत्थे का हिस्सा होंगे।

सरकार के पंडाल में दिखेगी ननकाना साहिब की झलक

हरनेक सिंह जैनपुरी, कपूरथला : श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पंजाब सरकार की ओर से सुल्तानपुर लोधी में बनाए गए विशाल पंडाल में संगत को ननकाना साहिब की झलक दिखेगी। बाबा नानक की पवित्र बेई के पास तैयार इस पंडाल में करीब 50 हजार श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। पंडाल किसी खूबसूरत पैलेस की तरह लगता है। रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु इस पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पंडाल के बाहर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में भी शेयर कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से किसी भी श्रद्धालु को अभी तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पंडाल को अंदर से देखने की जिद में कई बार तो श्रद्धालुओं की सुरक्षाकर्मियों से बहस भी हो रही है। पंडाल के साथ ही संगत के लिए गठड़ी घर, लंगर और लाउंज का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा इसमें एक साथ 10 हजार लोग लंगर छक सकते हैं। लोगों को परेशानी न हो इसलिए पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया गया है।

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुटों में संघर्ष, राहगीर की मौत

जागरण संवाददाता, वीरभूम

- वीरभूम के सांईथिया में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आमने-सामने आए दोनों गुट
- फायरिंग व बमबारी में कई लोग जख्मी, तनाव के मद्देनजर गांव में पुलिस तैनात

बंगाल में वीरभूम जिले के सांईथिया में वर्चस्व को लेकर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में हुए संघर्ष में जमकर बमबारी व फायरिंग हुई। इस दौरान गोली लगने से एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। गांव में तनाव के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार सांईथिया के कल्याणपुर गांव में वर्चस्व कायम करने को लेकर लंबे समय से तृणमूल के क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला तृणमूल के एक नेता के बीच विवाद चला आ रहा है। सोमवार रात दोनों गुटों के समर्थक गांव में वर्चस्व कायम करने को लेकर आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ते ही दोनों ओर से बमबारी और फायरिंग होने लगी। मंगलवार सुबह भी दोनों गुटों में संघर्ष हुआ। इसी बीच शेख इंसान (26) नामक युवक के तीन गोली लग गईं। गंभीर रूप से जख्मी हालत में उसको लोगों ने स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संघर्ष में दोनों गुटों के कई लोग भी जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। तनाव के मद्देनजर गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शेख के परिवार का दावा है कि उसका किसी भी सियासी पार्टी से संबंध नहीं था। आरोप लगाया कि डालिम, तहिरुल समेत अन्य लोगों ने जानबूझ कर उसको गोली मार दी। उन्होंने आरोपितों को कठोर सजा दिए जाने की मांग की है।

उधर, भाजपा ने मामले के पीछे तृणमूल की गुटबाजी बताया है। जिला तृणमूल उपाध्यक्ष अभिजीत सिंह ने आरोप को निराधार बताया। कहा कि असमाजिक तत्वों के बीच संघर्ष में ही युवक की जान चली गई।

मकसूदां विस्फोट का आरोपित लुधियाना में गिरफ्तार

जासं लुधियाना

चार साल पहले जालंधर के मकसूदां इलाके में हुए कार बम विस्फोट में वांछित रतन धंजल उर्फ चूहा को लुधियाना पुलिस की क्राइम इनवेस्टिगेशन एजेंसी (सीआइए-2) की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। धंजल पर वारदात में इस्तेमाल आरडीएक्स की डिलीवरी देने का आरोप है। हालांकि, धंजल की गिरफ्तारी लुधियाना के साहनेवाल इलाके में साल 2015 में हुए एक हत्या के मामले में हुई है, लेकिन जल्द ही सीबीआइ उसे मकसूदां ब्लास्ट मामले में प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में ले सकती है।

वह सिरसा (हरियाणा) के गांव जीवन नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ सीबीआइ ने मकसूदां ब्लास्ट केस में हत्या व एक्सप्लोसिव सबस्टांस एक्ट-1908 के तहत मामला दर्ज किया था। मोहाली स्थित सीबीआइ के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जितेंद्र पाल सिंह की अदालत धंजल और महंगा सिंह संत (सिरसा, हरियाणा) को भगोड़ा करार दे चुकी है। इस मामले में आरोपित के साथियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि महंगा सिंह अभी तक फरार है। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल का कहना है कि आरोपित से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। गौरतलब है कि जालंधर के मकसूदां इलाके में दिसंबर 2015 में हुए कार बम विस्फोट के दौरान जालंधर के मोती नगर निवासी अजय कुमार शर्मा की मौत हो गई थी, जबकि जगमोहन सिंह नाम का व्यक्ति घायल हो गया था।

दिवाली पर मां से मिलने घर आया था : एसीपी क्राइम-2 सुरिंदर मोहन ने बताया कि 2015 में साहनेवाल के गांव बिलगा के पास सौरव (25) नाम के युवक का शव मिला था। इस कत्ल केस की गुत्थी को पुलिस अब तक सुलझा नहीं सकी थी। कुछ दिन पहले पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सौरव की हत्या रतन धंजल ने की थी। पुलिस ने इस मामले में धंजल को नामजद कर उसकी तलाश शुरू की थी। दो दिन पहले पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित दीवाली पर अपनी मां से मिलने अपने घर जा रहा है। सोमवार को उसे काबू कर लिया गया।

जालंधर के मकसूदां में हुए कार बम धमाके के आरोपित रतन की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते एसीपी क्राइम सुरिंदर मोहन व इंचार्ज परवीन रणदेव। जागरण

सभी शिक्षा बोर्ड पर नियंत्रण के लिए एक संस्था का प्रस्ताव

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में सभी शिक्षा बोर्ड के लिए एक केंद्रीय नियामक संस्था गठित करने का प्रस्ताव किया है। इस संस्था के प्रमुख केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री होंगे। इसका मतलब यह होगा कि सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन आ जाएंगे।

अभी तक केंद्र की निगरानी में सिर्फ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही आता है। राज्यों के शिक्षा बोर्ड से केंद्र का कुछ लेना-देना नहीं होता। राज्य शिक्षा बोर्ड स्वायत्त हैं और राज्य सरकार का उन पर नियंत्रण होता है।

एनईपी के अंतिम मसौदे के मुताबिक भारत के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयी बोर्ड के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तहत राष्ट्रीय स्तर पर नियामक संस्था का गठन किया जाएगा। यह संस्था सभी बोर्ड के आकलन और शर्तों व मानकों के मूल्यांकन प्रक्रिया पर नजर रखेगी। संस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न बोर्ड के आकलन के तरीके 21वीं शताब्दी की जरूरतों और राज्यों के लक्ष्यों के अनुकूल हों।

एनईपी के मसौदे पर एचआरडी मंत्रालय ने अपनी मुहर लगा दी है। अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाना है। हालांकि, मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि आखिरी क्षण में इसमें कुछ मामूली बदलाव भी हो सकता है।

- नई शिक्षा नीति के मसौदे में राष्ट्रीय नियामक संस्था के गठन का प्रावधान
- इस तरह सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का होगा नियंत्रण

बोर्ड परीक्षाओं को भी आसान बनाया गया

नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं को भी आसान बनाया गया है। इसके मुताबिक बोर्ड परीक्षा से बच्चों की क्षमता का आकलन किया जाएगा। नियमित रूप से स्कूल जाने और कक्षा में उपस्थित रहने वाले छात्र थोड़े मेहनत से ही आसानी से बोर्ड परीक्षा पास कर लेंगे। परीक्षा के दौरान उन्हें तैयारी को लेकर तनाव से नहीं गुजरना होगा। इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंप भी दी है।

गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ और पांच मामलों की जांच करेगी सीबीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ और पांच मामलों की जांच सीबीआइ करेगी। जांच एजेंसी जिन नए मामलों की जांच करने जा रही है उनमें से दो गैंगस्टर के शुरुआती दिनों के हैं। 36 साल से ज्यादा समय पहले वह अपने मेंटर राजन नायर के लिए शराब के अवैध कारोबार संलिप्त था। यह जानकारी मंगलवार को अधिकारियों ने दी।

1980 के एक मामले में उसके गॉडफादर नायर उर्फ बड़ा राजन को भी आरोपित बनाया गया है। दूसरा मामला 1983 का है जिसमें पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार से उसका पीछा किया था और उसने पकड़ने की कोशिश करने पर दो पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था। अन्य तीन मामले अपहरण और फिरौती से जुड़े हैं। उसके गिरोह के सदस्यों ने 90 के आखिर और 2000 के शुरू में ऐसे मामलों को अंजाम दिया था।

छोटा राजन। फाइल

21 नवंबर 1980 को छोटा राजन, उसके मेंटर नायर और सहयोगी अब्दुल एवं रमेश शर्मा ने कथित रूप से एंथोनी फर्नांडिस को चाकू मारकर घायल कर दिया था। उस समय फर्नांडिस राम नारकर रोड पर रिक्शा की प्रतीक्षा कर रहा था। फर्नांडिस के बयान पर मुंबई पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी। 1982 में नायर मारा गया जिसके बाद राजन सदाशिव निकलजे उर्फ छोटा राजन गिरोह का सरगना बन बैठा।

सीबीआइ ने 1983 के उस मामले को भी अपने हाथों में ले लिया है जिसमें मुंबई पुलिस ने छोटा राजन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एक टैक्सी को रोकने का प्रयास किया था। उसी टैक्सी में छोटा राजन और उसके सहयोगी शराब तस्करी कर ले जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर वे सभी भाग निकले। इसी क्रम में जिन दो पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया था उसे उसने चाकू मारकर घायल कर दिया था। इस अभियान में पुलिस राजन को गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी। 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया में छोटा राजन के गिरफ्तार होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उसके खिलाफ 71 मामले सीबीआइ को सौंप दिए थे।

छठी बार भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन

जासं, फिरोजपुर: भारत-पाकिस्तान स्थित बीएफएफ की बीओपी राजा मौहतम चौकी के पास भारतीय क्षेत्र में सोमवार रात को एक बार फिर से ड्रोन देखे गए हैं। पुलिस इसे हथियारों या हेरोइन की तस्करी की दृष्टि से देख रही है। हालांकि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आशंका है कि पाकिस्तान की तरफ से तस्करी करने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही अभी तक इस माह ममदोट इलाके में यह छठी बार ड्रोन देखने का मामला सामने आया है।

मौहतम चौकी के पार सोमवार रात को ये ड्रोन दो बार 7:05 बजे और 7:15 बजे देखे गए। इस संदर्भ में बीएसएफ व सुरक्षा एजेंसियों ने रात को सर्च अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त मंगलवार को दिन में भी बीएसएफ जवान मुस्तैद रहे। पुलिस इंस्पेक्टर गुरतेज सिंह बराड़ ने बताया कि जानकारी देने के बाद पुलिस ने रात के समय ही सर्च अभियान चलाया गया। लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है।

अब लखनऊ पुलिस करेगी हत्यारोपितों के मदद करने वालों की तलाश

जागरण संवाददाता, बरेली

कमलेश तिवारी हत्याकांड

6 आरोपित, मुख्य साजिशकर्ता व मददगार जेल जा चुके हैं। कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं, उन पर अब लखनऊ पुलिस काम करेगी।

-डीके ठाकुर, एडीजी, एटीएस।

कमलेश तिवारी हत्याकांड में आरोपितों की मदद करने वालों को अब लखनऊ पुलिस तलाश करेगी। बरेली में ऐसे चार लोगों पर निगाह है, जिनका सुराग लगाया जा रहा। अभी तक इस पूरे प्रकरण को एटीएस व एसटीएफ देख रही थी। पूरे मामले से जुड़े सभी प्रमुख आरोपितों को जेल भेजने के बाद प्रकरण पुलिस को सौंप दिया गया है।

18 अक्टूबर को लखनऊ में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के बाद दोनों आरोपित अशफाक व मोइनुद्दीन बरेली आ गए थे। यहां नावेद व कैफी ने दोनों के रुकने, इलाज आदि का इंतजाम किया था। जानकारी होने के बाद एटीएस व एसटीएफ ने यहां दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पता चला कि इन दोनों के अलावा चार अन्य लोग भी हैं जिन्होंने हत्यारोपितों की मदद की थी। इनमें एक व्यक्ति ट्रैवल्स एजेंसी संचालक है, दूसरा एक होटल मालिक और बाकी दो युवकों ने आर्थिक मदद की थी। उन्होंने ही रुपये का इंतजाम किया, जिसके बाद आरोपित नेपाल भागे थे। हालांकि वहां से वे वापस लौटे और गुजरात में गिरफ्तार कर लिए गए थे।

आर्थिक मदद करने वालों के पास कहां से आ रही रकम : दूसरी ओर खुफिया टीमों को सक्रिय किया गया है। पता किया जा रहा कि आर्थिक मदद करने वाले युवकों की आय का जरिया क्या है। वे कहां से और किन संसाधनों से रुपये कमा रहे हैं और हत्याकांड के आरोपितों को रकम देने के पीछे मंशा क्या थी। माना जा रहा है कि कुछ और लोग भी इस पूरे प्रकरण से जुड़े हो सकते हैं।

मौलानाओं पर कार्रवाई के लिए लखनऊ के इशारे का इंतजार: कमलेश तिवारी की हत्या में नामजद मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम पर कार्रवाई को लेकर 10 दिन से असमंजस बना हुआ है। एसआइटी एक बार पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल दोनों बिजनौर पुलिस के पास हैं।

विरोध

मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति में भी नहीं है रोजगार में आरक्षण देने का प्रावधान

विवादों में प्रोत्साहन योजना, आरक्षण के खिलाफ उठने लगे सुर

नई दुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कमलनाथ सरकार ने जो नई प्रोत्साहन योजना बनाई है, उसके एक प्रावधान के कारण यह विवादों में घिर गई है। हाल ही में जारी आदेश में योजना में स्थानीय स्तर पर 70 फीसदी लोगों को रोजगार देने में आरक्षण नियमों का पालन करने की शर्त जोड़ी गई है। उद्योग जगत इसके पक्ष में नहीं है।

दरअसल, उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन की दरकार होती है और जरूरी नहीं है कि आरक्षित वर्ग में वह व्यक्ति मिल ही जाए। ऐसे में जिस तरह सरकारी नौकरियों में बैकलॉग बरसों से चला आ रहा है, वही स्थिति उद्योगों में भी निर्मित हो सकती है। इसका असर उत्पादन पर पड़ सकता है। वृहद उद्योगों के लिए लागू उद्योग संवर्धन नीति में भी इस तरह का प्रावधान नहीं है।

कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के मुहैया कराने के लिए 70 फीसदी काम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाने की शर्त रखी थी। उद्योग जगत ने इसका स्वागत किया और सभी इसका पालन करने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ योजना में स्थानीय व्यक्तियों को 70 प्रतिशत रोजगार के प्रावधान को आरक्षण से जोड़ने पर असहमति के सुर हैं। उद्योग संवर्धन नीति में भी इस तरह का प्रावधान नहीं है। सरकार के स्तर पर भी इस प्रावधान को लेकर तर्क रखे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रावधान को हटाने को लेकर जल्द ही निर्णय हो सकता है, क्योंकि निवेश के लिए मैग्निफिसेंट एमपी से बने माहौल के बीच सरकार ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं चाहती, जिससे नकारात्मक संदेश जाए।

कमलनाथ। फाइल

यह है प्रावधान: योजना के बिंदु क्रमांक 4.18 के तहत प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने वाली इकाईयों को कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। इस 70 प्रतिशत रोजगार में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्व भी दिया जाना अनिवार्य है। प्रदेश में अनुसूचित जाति को 20, अनुसूचित जनजाति को 16 और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण शासकीय नौकरियों में दिया है।

पॉलिसी अच्छी, शर्त गलत: शर्मा: पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा का कहना है कि एमएसएमई विकास नीति के तहत लाई गई प्रोत्साहन योजना अच्छी है। इसमें प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के जो प्रावधान किए हैं वे तारीफ के काबिल हैं पर आरक्षण की शर्त लगाना गलत है। निजी क्षेत्र में कानून द्वारा आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उधर, सक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आरिफ अकील ने कहा कि मैं बाहर हूं और पॉलिसी देखकर ही कुछ बता पाऊंगा।

संयुक्त मोर्चा ने किया स्वागत, सपाक्स करेगा विरोध

प्रोत्साहन योजना में 70 प्रतिशत रोजगार में अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की शर्त को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आरक्षण का प्रावधान करने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार जताया है। उधर, सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण समाज पार्टी (सपाक्स) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी बैठक में स्थानीय स्तर पर 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने की शर्त का स्वागत किया गया। साथ ही रोजगार में आरक्षण (रोस्टर) के प्रावधान का विरोध करने का निर्णय लिया गया।

574 करोड़ के चिटफंड घोटाले में पैलान ग्रुप का मालिक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- गैर कानूनी रूप से निवेशकों से रुपये जुट की धोखाधड़ी
- सीबीआइ ने मैराथन पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार

चिटफंड घोटालों की जांच कर रही सीबीआइ ने मंगलवार को पैलान ग्रुप के मालिक अपूर्व साहा को गिरफ्तार कर लिया। ग्रुप पर चिटफंड के जरिये गैर कानूनी रूप से आम लोगों से करीब 574 करोड़ रुपये एकत्र कर धोखाधड़ी करने का आरोप है। मंगलवार को लगभग तीन घंटे पूछताछ के बाद सीबीआइ ने साहा को गिरफ्तार कर लिया।

गौरतलब है कि सारधा, रोजवैली चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान सीबीआइ को कई अन्य चिटफंड कंपनियों के नाम की जानकारी मिली थी, जिसमें पैलान ग्रुप भी शामिल था। जांच में पता चला कि पैलान ग्रुप ने रुपये दोगुना करने का झांसा देकर गैर कानूनी रूप से आमलोगों से करीब 574 करोड़ रुपये कंपनी की विभिन्न योजनाओं में निवेश कराए थे। लेकिन, समयसीमा के बाद भी निवेशकों को उनके रुपये नहीं लौटाए गए। इस मामले में बीते अगस्त माह में सीबीआइ ने ग्रुप के निदेशक धनंजय कुमार सिंह को सियालदह स्टेशन से गिरफ्तार किया था। इसके बाद ही ग्रुप के मालिक अपूर्व साहा की गिरफ्तारी का ब्लू प्रिंट तैयार हो गया था। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को साल्टलेक के सीजीओ कांप्लेक्स स्थित सीबीआइ कार्यालय पहुंचे पैलान ग्रुप के मालिक अपूर्व साहा से जांच अधिकारियों ने करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। सीबीआइ ने करीब 574 करोड़ रुपये का सुराग पाने के लिए सवाल किए, लेकिन वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इसके बाद सीबीआइ ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब अन्य तथ्यों की जानकारी के लिए अपूर्व साहा से पूछताछ की जाएगी।

1872 में महाराजा रणबीर सिंह ने बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए दरबार को छह महीने श्रीनगर व छह महीने जम्मू में रखने की प्रथा शुरू की थी। महाराजा का काफिला अप्रैल में श्रीनगर के लिए रवाना हो जाता था व वापसी अक्टूबर में होती थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 30 अक्टूबर 2019

विदेशी सांसदों को श्रीनगर ले जाने पर संसद में सियासत गरमाएगा विपक्ष

तल्खी ▶ विरोधियों ने अपनों को रोकने और बाहरियों को घुमाने को बताया गलत

प्रियंका ने भी साधा भाजपा के राष्ट्रवाद पर निशाना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

यूरोप के कुछ देशों के सांसदों को जम्मू-कश्मीर ले जाने के सवाल पर विपक्ष ने सरकार की घेरेबंदी तेज कर दी है। विदेशी सांसदों के भ्रमण को जम्मू-कश्मीर के आतंरिक मामले में बाहरी दखल मान रहे विपक्ष ने साफ कर दिया है कि सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर सरकार को कड़े सवालों के जवाब देने होंगे। संसद के आगामी शीत सत्र में विपक्ष ने अपने सांसदों के जम्मू-कश्मीर जाने पर पाबंदी और विदेशी सांसदों की मेहमानवाजी को लेकर सियासी संग्राम के इरादों का संकेत भी दे दिया है।

विपक्षी दलों को सबसे ज्यादा एतराज इस बात को लेकर है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सरकार अपने देश के सांसदों और नेताओं को वहां जाने की इजाजत नहीं दे रही। वहीं, यूरोपीय देशों के जिस 23 सदस्यीय सांसदों के दल को सरकारी मेहमान बनाकर श्रीनगर भेजा गया है उनमें अधिकांश की पृष्ठभूमि विवादित है और उनके अपने देश में ही उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के अनुसार सरकार का यह पीआर एक्सरसाइज गलत सलाह पर आधारित है। इसमें शामिल कई विदेशी सांसदों की विश्वसनीयता संदेहास्पद रही है और वे अपने देश की मुख्यधारा की कूटनीति के प्रतिकूल विचार रखते हैं। शर्मा ने कहा कि यह पहल कूटनीतिक आपदा से कम नहीं और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

कश्मीर के हालात जानने के लिए मंगलवार को 23 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन का प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा। जागरण

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि 'कश्मीर में यूरोपीय सांसदों को सैर-सपाटा और हस्तक्षेप की इजाजत, लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को पहुंचते ही हवाई अड्डे से वापस भेजना। बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद है यह।' कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने तो यूरोपीय देशों के इन सांसदों की यात्रा का प्रबंधन करने वाले एनजीओ पर भी सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ दलों ने जंतर-मंतर पर एक विरोध सभा कर शीत सत्र में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के अपने इरादे साफ कर दिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाब नबी आजाद ने कहा कि विदेशी सांसदों या मेहमानों को जम्मू-कश्मीर ले जाने पर हमें एतराज नहीं। मगर आपत्ति इसको लेकर है कि पांच अगस्त को सूबे का कानून बदलने के बाद से अपने सांसदों और नेताओं को सरकार जम्मू-कश्मीर जाने नहीं दे रही। विपक्षी दल सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आजाद और दूसरे नेताओं को श्रीनगर या जम्मू एयरपोर्ट से वापस भेजने के वाकये का जिक्र करना नहीं भूले। राहुल गांधी की अगुआई में गए 10 से अधिक विपक्षी दलों के सांसदों को भी श्रीनगर एयरपोर्ट से बैरंग वापस लौटा देने का भी आजाद ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सूबे के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके कैबिनेट के सदस्य रहे नेताओं को सरकार ने जेल में रखा हुआ है। जबकि वे खुद भी पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए चौथे प्रयास में सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से सीमित दौरे की अनुमति हासिल कर सके।

महज संयोग नहीं थी कश्मीरी नेताओं की यूरोपीय दल से मुलाकात!

राज्य ब्यूरो, जम्मू

यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर आगमन से पहले नई दिल्ली में पीडीपी, कांग्रेस और पीपुल्स कांफ्रेंस के नेताओं से मुलाकात ने रियासत की सियासत तेज कर दी है। हालांकि इस मुलाकात से केंद्र साफ संकेत देने में सफल रहा है कि कश्मीर में सियासी गतिविधियों को बहाल करने की कवायद सफल हो रही है। पीडीपी ने मंगलवार सुबह ही इस मुलाकात से किनारा कर हालात को संभालने का प्रयास किया। वहीं, कांग्रेस और पीपुल्स कांफ्रेंस ने इस मुलाकात पर चुप्पी साध रखी है।

गौरतलब है कि 5 अगस्त के बाद कश्मीर के दौरे पर आने वाला यह पहला विदेशी दल है। इस दल के 23 सदस्य मंगलवार सुबह श्रीनगर पहुंचे। इससे पूर्व यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडु और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की थी। इसके साथ ही बैठक में पीडीपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल पूर्व सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग, पीपुल्स कांफ्रेंस के इमरान रजा अंसारी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्वमंत्री उस्मान मजीद, पूर्व शिक्षामंत्री अल्ताफ बुखारी और कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेता खालिद जहांगीर ने मुलाकात की थी।

कांग्रेस ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से जोड़ा : कांग्रेस ने इस दौरे को कश्मीर मामले में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के साथ जोड़ते हुए इसका विरोध किया है। वहीं, सभी दल एक ओर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के कश्मीर दौरे की निंदा कर रहे थे और दूसरी ओर इन्हीं दलों के कई नेता यूरोपीय प्रतिनिधियों से मिल रहे थे।

मैं निजी हैसियत से मिला : बेग : पीडीपी संरक्षक और पूर्व सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि मुझे यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने ही बुलाया था। हमने उनसे कहा कि कश्मीर मसले को शिमला समझौते के अनुरूप ही भारत-पाकिस्तान को मिलकर हल करना चाहिए।

हमने कश्मीरियों के रुख को रखा : पीडीपी के बागी और पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता इमरान रजा अंसारी ने कहा कि हमने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों को कश्मीरियों के रुख के बारे में बताया है। हमने बताया कि कश्मीर मसले को एक मानवीय मुद्दे के तौर पर हल किया जाना चाहिए।

महज संयोग नहीं यह मुलाकात : कश्मीर मामलों के जानकार युसुफ जमील ने कहा कि पीडीपी, पीपुल्स कांफ्रेंस और कांग्रेस के कुछ खास नेताओं की दिल्ली में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात को महज संयोग नहीं कहा जा सकता। आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने कश्मीर में मुख्यधारा की सियासी गतिविधियों को शुरू करने के लिए कई दलों के नेताओं के साथ संपर्क-संवाद का चैनल बहाल किया होगा।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जमीनी हकीकत देखने पहुंचे यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने मंगलवार को श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील में शिकारा में बैठकर घाटी की खूबसूरती को निहारा। प्रेट्र

ईयू प्रतिनिधिमंडल के ब्रिटिश सांसद का आरोप भारत ने कश्मीर दौरे का न्योता वापस लिया

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के एक वरिष्ठ सांसद ने मंगलवार को भारत सरकार पर आरोप लगाया कि अभी कश्मीर के दौरे पर गए यूरोपीय संघ (ईयू) के एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए उन्हें दिए गए न्योते को केंद्र सरकार वापस ले लिया। ब्रिटिश नेता का दावा है कि उन्होंने पुलिस सुरक्षा के बिना स्थानीय लोगों से बात करने की मांग की थी।

यूरोपीय संघ के 23 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दो दिनों के दौरे पर मंगलवार को श्रीनगर पहुंचा। अधिकारियों ने कहा कि इस दल में मुख्य रूप से 27 सांसद थे। इनमें से ज्यादातर धुर दक्षिणपंथी या दक्षिणपंथी दलों से हैं। लेकिन उनमें से चार कश्मीर के दौरे पर नहीं गए और अपने-अपने देश लौट गए। यूरोपीय संसद के डेमोक्रेट सदस्य क्रिस डेविस ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के फैसले से साफ है कि वह अपनी कार्रवाई की वास्तविकता छिपाने की कोशिश कर रही है और प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता को बाधित कर रही है। डेविस के 27 से 30 अक्टूबर के बीच के दौरे के न्योते को कथित तौर पर वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा, 'मैं मोदी सरकार के प्रचार हथकंडे का हिस्सा बनने और सब कुछ ठीक-ठाक है कहने के लिए तैयार नहीं हूं। यह बहुत स्पष्ट कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कश्मीर में तार-तार किया जा रहा है और विश्व को इसका संज्ञान लेना शुरू कर देना चाहिए।'

गौरतलब है कि विगत सोमवार को यूरोपीय संघ के सदस्यों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आशा जताई कि जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों की उनकी यात्रा सार्थक होगी। अनुच्छेद 370 हटाने के दो महीने बाद डेविस को भारतीय अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा करने का न्योता दिया था। हालांकि, डेविस का आरोप है कि बहुत संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ न्योता वापस ले लिया गया क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें स्थानीय लोगों से बात करने की छूट मिले। उन्होंने कहा, 'भारत सरकार के पास छिपाने के लिए ऐसा क्या है? वह पत्रकारों और आगंतुक नेताओं को स्थानीय लोगों से बात करने की आजादी क्यों नहीं दे रही? मैं इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिनके परिवार का कश्मीर से जुड़ाव है। वे चाहते हैं कि वे अपने रिश्तेदारों से मुक्त रूप से बात कर पाएं। वे चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए।'

घाटी के लोग मानवाधिकार से वंचित : संयुक्त राष्ट्र

जिनेवा, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि कश्मीर के लोग लगातार मानवाधिकारों से वंचित हैं और भारत को उनके अधिकार पूरी तरह बहाल करने चाहिए। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मामलों के उच्चायुक्त के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविले ने कहा, 'हम अत्यंत चिंतित हैं कि कश्मीर में लोग लगातार व्यापक मानवाधिकारों से वंचित हैं और हम भारतीय अधिकारियों से स्थिति को ठीक करने तथा लोगों के अधिकारों को पूरी तरह बहाल करने का आग्रह करते हैं।' कोलविले ने कश्मीर पर एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का लोगों का अधिकार प्रभावित हो रहा है। हमें ये खबरें भी मिली हैं कि कश्मीर में सशस्त्र समूह सक्रिय हैं और वे कारोबार शुरू करने या स्कूल जाने की कोशिश करने वालों को डरा-धमका रहे हैं।'

चुनाव आयोग की निगरानी में होगा परिसीमन

राज्य ब्यूरो, जम्मू : केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में बदलने जा रही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जम्मू संभाग के साथ बीते 70 साल से चला आ रहा राजनीतिक भेदभाव समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। 31 अक्टूबर के बाद भारतीय चुनाव आयोग राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। प्रस्तावित परिसीमन में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की सात सीटें बढ़ने की उम्मीद है। यह सीटें संभवतः जम्मू संभाग में ही बढ़ेंगी। स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित परिसीमन 2011 की जनगणना के मुताबिक होगा। इसके आधार पर जम्मू संभाग की आबादी 69,07,623 है, जबकि कश्मीर की आबादी 53,50,811 है।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत चुनाव आयोग केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में परिसीमन करने के लिए प्राधिकृत है। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर राज्य में जिसका लद्दाख भी एक हिस्सा है, की विधानसभा में गुलाम कश्मीर के लिए आरक्षित 24 सीटों समेत कुल 111 सीटें हैं। इनमें दो सीटें नामांकन कोटे हैं। शेष 87 सीटों में चार लद्दाख, 46 कश्मीर और 37 जम्मू संभाग में हैं। इन्हीं 87 सीटों के लिए चुनाव होता है। पहले लद्दाख को भी कश्मीर का हिस्सा माना जाता था। इस तरह से कश्मीर में 50 सीटें होती थीं।

जम्मू-कश्मीर कैडर के आइएएस व आइपीएस पुरानी भूमिका में बने रहेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर राज्य गुरुवार से औपचारिक रूप से दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बंट जाएगा। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर कैडर के आइएएस, आइपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अफसर अपनी सेवाएं इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में यथावत जारी रखेंगे। लेकिन इन सेवाओं में जो नई भर्तियां होंगी, वह 'एजीएमयूटी' (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरेटरीज) कैडर के तहत होंगी।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार प्रांतीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारी अपनी सेवाएं मौजूदा तरीके से तब तक जारी रखेंगे जब तक कि दो नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल नए आदेश जारी नहीं कर देते हैं।

अगस्त में संसद के दोनों सदनों में पारित नए अधिनियम के अनुसार भविष्य में जिन केंद्रीय अफसरों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त किया जाएगा, उन्हें केंद्र सरकार जरूरत के हिसाब से एजीएमयूटी कैडर के लिए भी नियुक्त कर सकती है। इसके तहत इन दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भी होगी जैसे पुडुचेरी में है। जबकि लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश होगा, जैसा चंडीगढ़ है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए क्रमशः गिरीश चंद्र मुर्मू और पूर्व रक्षा सचिव राधा कृष्ण माथुर को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

- **नए भर्ती हुए अफसरों को एजीएमयूटी कैडर में रखा जाएगा**
- **कल से दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलेंगे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख**

नए अधिनियम के अनुसार आइएएस, आइपीएस और भारतीय वन सेवा के कैडर के लिए जम्मू-कश्मीर कैडर बहाल रहेगा। 31 अक्टूबर से वह अपने मौजूदा कैडर के तहत काम जारी रख सकेंगे। अधिनियम के अनुसार दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन और अधिसूचित होने के बाद उपराज्यपाल अफसरों की संख्या और अधिकारियों की तैनाती पर फैसले लेंगे। नए अधिनियम के अनुसार राज्य कर्मचारियों के सामने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में से एक को चुनने का विकल्प होगा। उनके तबादलों पर भी उपराज्यपाल की मुहर लगेगी। अधिनियम के अनुसार इस खंड के तहत जारी आदेशों की समीक्षा का अधिकार उपराज्यपाल को होगा। इस अधिनियम में इन केंद्र शासित प्रदेशों में लोक सेवा आयोग की भी भूमिका की व्याख्या की गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी से लोक सेवा आयोग लद्दाख की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवारत होगा।

स्कूल के बाहर सुरक्षाकर्मियों पर आतंकी हमला, बाल-बाल बचे छात्र

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर के द्रबगाम पुलवामा में मंगलवार को स्कूली छात्र उस समय बाल-बाल बच गए, जब एक परीक्षा केंद्र के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवानों ने छात्रों और खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। इसके बाद आतंकी भाग गए। बता दें कि हालात सामान्य होने पर कश्मीर में मंगलवार से दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। आतंकियों ने शिक्षण संस्थान न खोलने और परीक्षार्थियों को निशाना बनाने की कथित तौर पर धमकी दे रखी है। इसके चलते प्रशासन ने पूरी वादी में सभी परीक्षा के केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है। धारा 144 भी लगाई गई है। इसी बीच, पुलवामा के द्रबगाम इलाके में एक सरकारी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने दूर से छह से सात राउंड गोलियां दागीं। उस समय कुछ बच्चे परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे थे। इस पर सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों को बचाते हुए आतंकियों पर पलटवार कर दिया। इससे आतंकी भाग गए। इलाके में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है।

पाक सेना ने पुंछ सेक्टर में की भारी गोलाबारी

जासं, पुंछ : पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को जम्मू के पुंछ सेक्टर में भारी गोलाबारी की। इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सीमा पर तनाव बढ़ गया है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। जानकारी के अनुसार, सुबह करीब दस बजे पाकिस्तानी सेना ने पुंछ सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी। पाक सेना ने सैन्य चौकियों को निशाना बनाने के साथ रिहायशी क्षेत्रों पर भी मोर्टार दागे। उसी समय भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू दी। इसके बाद पाक सेना ने गोलाबारी बंद कर दी।

सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों को आतंकी बना सकते हैं निशाना

नई दिल्ली, प्रेट्र : पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चलाने वाले आतंकी संगठन आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने के लिए आतंकी बंधक बनाने जैसी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी दी है।

अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के हवाले से कहा कि सूचना से यह भी संकेत मिला है कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कश्मीर के जोनाकर, रैनावाड़ी, सफाकदल और धर्मशाल जैसे क्षेत्रों में सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए लंबे समय तक बंधक बनाने जैसी स्थिति उत्पन्न करने के वास्ते श्रीनगर में सुरक्षाबलों के प्रतिष्ठानों तथा सरकारी कार्यालयों को निशाना बना सकते हैं।

रहस्यमय हालात में मारा गया ट्रक चालक की हत्या करने वाला आतंकी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर के कनलीवन, बिजबिहाड़ा में मंगलवार को एक आतंकी रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया। फिलहाल, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस प्रवक्ता ने कनलीवन में आतंकी की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि सोमवार रात इसी इलाके में आतंकियों ने एक ट्रक चालक की हत्या की थी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान गोलियों से छलनी एक शव मिला। जांच करने पर पता चला कि वह उन आतंकियों के साथ शामिल था, जिन्होंने ट्रक चालक की हत्या की। उसकी पहचान मौके पर मौजूद एक अन्य ट्रक चालक ने भी की है।

पांच गोलियां लगी थीं, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित : इस बीच, सुबह जब आतंकी का शव मिला तो पुलिस और सेना के अधिकारियों ने दावा किया कि तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में ट्रक चालक की मौत में लिप्त आतंकी मारा गया है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि मारे गए आतंकी का शव कनलीवन से करीब तीन किलोमीटर दूर मंगलवार सुबह लोगों ने पड़ा देखा था। उसके शरीर पर पांच गोलियां लगी थीं और उसके पास हथियार भी नहीं थे। ग्रामीण उसे निकटवर्ती अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है।

ट्रक चालक पर गोलियां बरसाने के समय चपेट में आने की आशंका

सूत्रों का कहना है कि जब ट्रक चालक पर गोलियां बरसाईं उस समय हो सकता है कि एक आतंकी भी उनकी चपेट में आ गया हो। उसके साथी उसे उपचार के लिए लेकर निकले हों, लेकिन रास्ते में वह मर गया हो। इसके बाद उसका हथियार अपने साथ ले गए। यह दावा भी किया जा रहा है कि ट्रक चालक की हत्या के बाद जब आतंकी अपने किसी ठिकाने की तरफ जा रहे थे तो उनमें विवाद पैदा हो गया और आपसी गुटबाजी में एक आतंकी मारा गया।

आतंकी के परिजनों ने दावे को नकारा :

सूत्रों ने बताया कि मारे गए आतंकी के बारे में पुलिस ने पहले दावा किया था कि वह मंडूरा त्राल का रहने वाला है। इस पर आतंकी के परिजनों को बुलाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचे लोगों ने पुलिस के दावे को नकारते हुए कहा कि मृतक मंडूरा त्राल का रहने वाला नहीं है।

पीडीपी नेताओं को नहीं मिली महबूबा से मिलने की अनुमति

राज्य ब्यूरो, जम्मू : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के जम्मू के नेताओं को पार्टी की प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने की इजाजत नहीं मिली। पीडीपी की जम्मू इकाई ने श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर को सोमवार को पत्र लिखकर इजाजत मांगी थी कि उन्हें पार्टी प्रधान से मिलने दिया जाए।

जिला प्रशासन ने फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता वेद महाजन ने मंगलवार को बताया कि उनके पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि उन्हें इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि इजाजत नहीं दी गई है। इससे पहले छह अक्टूबर को पीडीपी के नेताओं को महबूबा मुफ्ती से मिलने की अनुमति मिल गई थी। पार्टी नेताओं को 7 अक्टूबर को श्रीनगर में महबूबा से मिलना था लेकिन कार्यक्रम को पार्टी नेताओं की ओर की से ही रद कर दिया गया। बता दें कि पार्टी नेता 30 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती से मिलना चाहते थे।

सुधरे हालात

जम्मू के विंटर जोन में 99 .6 फीसद रही हाजिरी, कश्मीर संभाग में बारहवीं की परीक्षाएं आज से होंगी शुरू

कश्मीर संभाग में 99 फीसद विद्यार्थियों ने दी दसवीं की परीक्षा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

कश्मीर संभाग और जम्मू के विंटर जोन में मंगलवार से कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच दसवीं कक्षा की परीक्षा शुरू हुई। कश्मीर संभाग में 99.12 और जम्मू के विंटर जोन में 99.6 फीसद हाजिरी रही।

हालांकि कई दिनों से कश्मीर के स्कूलों में बहुत कम संख्या में विद्यार्थी पहुंच रहे थे। प्रशासन और राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा करवाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए, जिसका परिणाम यह रहा कि पहले पेपर में ही 99 फीसद हाजिरी रही। पहले दिन दसवीं कक्षा का सोशल साइंस का पेपर हुआ। कश्मीर में करीब 65 हजार और जम्मू के विंटर जोन में 24 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। कुल मिलाकर 89 हजार विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। कश्मीर में 615 और जम्मू विंटर जोन में 296 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। विद्यार्थी निर्धारित समय पर परीक्षा देने के लिए पहुंच चुके थे। कई विद्यार्थी अभिभावकों के साथ परीक्षा केंद्रों में पहुंचे। अभिभावक पेपर समाप्त होने तक परीक्षा केंद्रों के बाहर बैठे रहे।

राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की चेयरपर्सन प्रो. वीना पंडिता ने बताया कि कश्मीर संभाग और जम्मू के विंटर जोन में परीक्षाएं सुचारु रूप से शुरू हुई हैं। विद्यार्थियों ने काफी उत्साह दिखाया है। मैंने कुछ परीक्षा केंद्रों का दौरा कर प्रबंधों का जायजा लिया। बिलकुल सामान्य हालात में परीक्षाएं हुई हैं। हमारी कोशिश रही कि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो। बुधवार से कश्मीर संभाग में बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वहीं, विंटर जोन में बारहवीं कक्षा की परीक्षा एक नवंबर से शुरू होगी।

दूसरी तरफ श्रीनगर समेत अन्य जिलों में जिला प्रशासन ने परीक्षाओं के लिए प्रभावी कदम उठाए थे। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए यातायात के विशेष प्रबंध किए गए थे। संवेदनशील इलाकों के स्कूलों में प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए थे। स्कूलों के आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा बरती गई।

कश्मीर संभाग में मंगलवार को दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई। श्रीनगर के कोठीबाग इलाके में एक स्कूल के बाहर परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थी। जागरण

आजाद ने खाली किया श्रीनगर का सरकारी बंगला

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में प्राप्त सरकारी आवासीय सुविधा छोड़ दी है। उन्हें राज्य एस्टेट विभाग ने जम्मू-कश्मीर बैंक का एक अतिथिगृह पूर्व मुख्यमंत्री को आवासीय सुविधा के तहत उपलब्ध करा रखा था। आजाद के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी सरकारी आवास पहली नवंबर तक खाली करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला हालांकि अपने ही मकान में हैं। यह मकान राज्य एस्टेट विभाग ने कथित तौर पर किराए पर ले रखा है और फारूक को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित किया है।

फारूक, उमर और महबूबा को आवंटित मकान कड़ी सुरक्षा वाले पॉश इलाके गुपकार मार्ग पर हैं। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को भी गुपकार मार्ग से आगे जठियार स्थित जम्मू-कश्मीर बैंक का अतिथिगृह बतौर आवासीय सुविधा प्रदान किया गया था।

जम्मू-कश्मीर बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार गुलाम नबी आजाद ने हमारा गेस्ट हाउस खाली कर दिया है। इस बारे में एस्टेट विभाग ने सूचित किया है, लेकिन कब्जा और चाबी नहीं दी है। एस्टेट विभाग के मुताबिक, उमर और महबूबा को भी सरकारी निवास खाली करने होंगे।

साज-सज्जा पर खर्च किए 50 करोड़ : राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के सरकारी निवास में करीब 50 करोड़ रुपये विभिन्न सुविधाओं को जुटाने और साज-सज्जा पर खर्च किए गए हैं। उमर के सरकारी निवास में जिम भी है। यही नहीं, श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र नौगाम में स्थित महबूबा के पिता स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद के निजी मकान के सौंदर्यीकरण और आवश्यक मरम्मत पर भी राज्य सड़क एवं भवन निर्माण विभाग ने लाखों रुपये खर्च किए हैं।

3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है बीएसएफ के जवानों ने छत्तीसगढ़ में नारायणपुर-कांकेर जिले की सीमा पर जंगल में तलाशी के दौरान। उनके पास से दो बंदूकें भी बरामद की गई हैं। पकड़े गए नक्सलियों की पहचान नारायणपुर थाना क्षेत्र निवासी राजेंद्र उसेंडी, राकेश उसेंडी और राजूराम के रूप में की गई है।

बंगाल में भाजपा के 'मिशन एनआरसी' को मिला बल

सामने आया सच ▶ एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल में हैं सबसे अधिक बांग्लादेशी अपराधी

मोदी सरकार की एनआरसी लागू कर विदेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की है योजना

जागरण संवाददाता, कोलकाता

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की हालिया रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई है कि बंगाल में विदेशी अपराधियों की संख्या बढ़ी है। इसमें भी सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अपराधी हैं। यही वजह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यहां भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू कर विदेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की योजना बना रही है। भाजपा का भी मानना है कि देश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए घुसपैठियों को बाहर करना बहुत जरूरी है।

बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ व राज्य के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए यहां की कुल 42 संसदीय सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की थी। अब राज्य की ममता सरकार को घेरने के लिए प्रदेश भाजपा एनसीआरबी की रिपोर्ट का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। एनसीआरबी के वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार बंगाल में अन्य राज्यों की तुलना में विदेशी कैदियों की संख्या सबसे अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की जेलों में कुल 1,379 विदेशी कैदी हैं, जो अन्य राज्यों की

एनआरसी के जरिये चिन्हित किए जा रहे हैं विदेशी लोग। प्रतीकात्मक

तुलना में 61.9 फीसद है। वहीं, महाराष्ट्र में यह संख्या सात फीसद व उत्तर प्रदेश में 6.8 फीसद दर्ज हुई है। भारत में विदेशी अपराधियों की संख्या सबसे अधिक बांग्लादेश से है। भारतीय जेलों में बंद कुल 1,403 बांग्लादेशी अपराधियों में से अकेले 1284 बंगाल की जेलों में बंद हैं।

घुसपैठ से देश की अर्थव्यवस्था को भी खतरा : विजयवर्गीय : भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही देश की सुरक्षा को भी खतरा है। ऐसे में तत्काल एनआरसी लागू कर घुसपैठियों को बाहर फेंकने की जरूरत है।

मोदी सरकार पर तृणमूल का प्रहार : एक ओर भाजपा बंगाल में एनआरसी लागू कर यहां से विदेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की बात कर रही है, वहीं राज्य की ममता सरकार की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस महासचिव व राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राज्य सरकार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की चलती है। ऐसे में घुसपैठ के लिए राज्य नहीं, केंद्र सरकार जिम्मेदार है।

विस चुनाव में भाजपा उठाएगी एनआरसी का मुद्दा : भाजपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी एनआरसी के मुद्दे को उठाकर आम लोगों के बीच जाएगी। इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने का काम करेगी। इसकी तैयारियां जोर-शोर से जारी है। प्रदेश भाजपा सूत्रों की मानें तो एनसीआरबी रिपोर्ट के अलावा पार्टी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से हासिल डेटा का भी चुनाव में इस्तेमाल कर तृणमूल को घेरने का काम करेगी। बीएसएफ ने दावा किया है कि मौजूदा साल तक कुल 1,364 बांग्लादेशियों को घुसपैठ करते पकड़ा गया है।

पूर्व विदेशी कैदियों के लिए सुरक्षित गृहों का निर्माण करेगी सरकार : राज्य सरकार पूर्व विदेशी कैदियों के लिए सुरक्षित गृहों का निर्माण करेगी। ये परियोजना उन विदेशी कैदियों के लिए होगी, जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन विभिन्न कारणों से उनकी अब तक रिहाई नहीं हो पाई है। सुरक्षित गृहों का निर्माण न्यूटाउन और बनगांव में किया जाएगा।

बेंगलुरु में घुसपैठियों को पनाह देने वालों पर भी होगी कार्रवाई

▶ मकान मालिकों व नियोक्ताओं पर दर्ज होगा आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा

बेंगलुरु, प्रेट्र : पुलिस ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ-साथ उन्हें पनाह और रोजगार देने वालों पर भी शिकंजा कसने की चेतावनी दी है। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि बिना पुलिस जांच के घर किराये पर देने वाले मकान मालिकों व रोजगार देने वाले नियोक्ताओं पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बेंगलुरु पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने कहा, 'बांग्लादेशी घुसपैठिये बिना अनुमति के अवैध रूप से देश में रह रहे हैं। वे राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। इसके बावजूद लोग उन्हें आश्रय उपलब्ध करा देते हैं।' राव ने कहा, 'बांग्लादेशी घुसपैठियों को आश्रय देने वालों के खिलाफ हम आइपीसी की धारा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत कार्रवाई करेंगे।'

उन्होंने कहा कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के कुछ ठेकेदारों की भी निगरानी की जा रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से काम लेते हैं और उन्हें बहुत कम मजदूरी देते हैं। हम ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करेंगे और उनकी करतूतों की सूचना उच्चाधिकारियों को भी देंगे।

गत दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने बेंगलुरु शहर के अलग-अलग हिस्सों से आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपित वर्धवान धमाकों से जुड़े रहे थे। वे दक्षिण भारत में अपना तंत्र स्थापित करना चाहते थे, ताकि आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकें। एनआइए ने जांच में पाया कि आरोपित बम बनाने में माहिर हैं और पड़ोसी तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में प्रशिक्षण शिविर का संचालन कर चुके हैं। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज करने संबंधी बेंगलुरु पुलिस का फैसला इसी क्रम में आया है।

उप्र में नेताओं-अफसरों ने नहीं भरा 13 हजार करोड़ का बिल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- अब सरकारी बंगलों में लगेगा बिजली का स्मार्ट मीटर, एक लाख का दिया ऑर्डर
- प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा- सरकारी विभागों का भी रिकॉर्ड नहीं है ठीक
- सरकार ने किस्तों में बकाया भुगतान करने का दिया विकल्प

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का मानना है कि बिजली बिल के भुगतान के मामले में प्रदेश के नेताओं, अधिकारियों और सरकारी विभागों का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वे बिजली इस्तेमाल करने में जितने तेज हैं, बिल जमा करने में उतने ही सुस्त हैं। बिल का भुगतान न करने के कारण उन पर बिजली विभाग का लगभग 13 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इसलिए, ऊर्जा विभाग अब उनके सरकारी बंगलों पर प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाएगा, ताकि बिल की रकम एडवांस आ जाए और वसूली का कोई झंझट ही न रहे।

इसकी शुरुआत ऊर्जा मंत्री खुद अपने कालिदास मार्ग स्थित सरकारी बंगले में 15 नवंबर को प्रीपेड मीटर लगाकर करेंगे। इसके साथ ही सरकारी आवासों में यह मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। मंत्री ने बताया कि एक लाख प्रीपेड मीटरों के ऑर्डर दे दिए गए हैं। जैसे-जैसे मीटर आते जाएंगे, इन्हें लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली बकाये के भुगतान के लिए सरकारी विभागों तथा नेताओं व अफसरों को किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया गया है। दूसरी तरफ वसूली की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी कर ली गई है। मंत्री ने सभी लोगों से अपने कनेक्शन पर प्रीपेड मीटर लगाने की अपील की है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बीते सितंबर तक सिंचाई विभाग में राजकीय नलकूपों व नहरों पर 2656.31 करोड़, जल निगम की नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं पर 128.78 करोड़, स्थानीय निकायों के मार्ग प्रकाश व जलकल पर अगस्त तक 1810.18 करोड़, जल संस्थानों पर 1697.22 करोड़ और मध्यांचल निगम के सरकारी कनेक्शन पर 829.53 करोड़ रुपये बकाया था।

खोले जाएंगे विशेष थाने

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए प्रदेश में 75 विशेष थाने खोले जाने हैं, जिनमें से 68 थाने अब तक खुल चुके हैं। इन थानों के लिए सरकार ने 2,050 पद सृजित किए हैं। इन थानों में तैनात पुलिसकर्मियों के वेतन व अन्य खर्च पावर कारपोरेशन वहन करेगा। इन थानों में 75 निरीक्षक, 375 उपनिरीक्षक, 675 मुख्य आरक्षी, 150 मुख्य आरक्षी कंसोल ऑपरेटर और 675 सिपाहियों के पद मंजूर किए गए हैं। इन थानों का काम जिले के हर इलाके में बिजली चोरी रोकना है।

न्यूज गैलरी

परमहंस योगानंदजी की स्मृति में 125 रुपये का सिक्का जारी : 'योगी कथामृत' के रचयिता एवं येगदा सत्संग सोसाइटी के संस्थापक परमहंस योगानंदजी की 125 वी जयंती के उपलक्ष्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 125 रुपये का संस्मरणात्मक सिक्का जारी किया। उनकी कालजयी कृति ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का सभी भारतीय भाषाओं सहित विश्व की 52 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। (वि)

पिथौरागढ़ की जगह देहरादून उतरा विमान

साहिबाबाद : हिंडन से पिथौरागढ़ के लिए नौ यात्रियों को लेकर गए हेरिटेज एविएशन के विमान की मंगलवार को गंतव्य पर लैंडिंग नहीं हो सकी। विमान को देहरादून भेज कर वहां लैंडिंग कराई गई। उम्मीद थी कि कुछ देर में दोबारा पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन वहां भी दृश्यता कम होने के चलते उड़ान रद करनी पड़ी। अब बुधवार को विमान यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ रवाना होगा। पिथौरागढ़ से विमान को मंगलवार की दोपहर साढ़े बारह बजे हिंडन पहुंचना था, जो करीब डेढ़ घंटे देरी से हिंडन पहुंचा। यहां से एक बजे के स्थान पर करीब पौने तीन बजे पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी। एयरलाइंस के अधिकारियों के अनुसार पिथौरागढ़ के पास पहुंचने पर बेहद कम दृश्यता के चलते वहां लैंडिंग में समस्या आई। इसके बाद विमान को देहरादून एयरपोर्ट भेजकर वहां उतारा गया। यात्रियों को कहा गया कि कुछ देर में दृश्यता बेहतर होने पर दोबारा उन्हें पिथौरागढ़ भेजा जाएगा। लेकिन, शाम तक दृश्यता बेहतर न होने पर फ्लाइट को रद कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि दृश्यता बेहतर न होने के चलते इसे रद किया गया है। अब बुधवार सुबह यात्रियों को लेकर विमान पिथौरागढ़ रवाना होगा। उधर, कंपनी की ओर से होटल में यात्रियों के रहने की व्यवस्था की गई है। हालांकि, भैयादूज मनाने पिथौरागढ़ जा रहे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। (जासं)

हज कमेटी के 11,368 आजमीन ले जाएंगे टूर ऑपरेटर्स

जमीर सिद्दीकी, कानपुर

▶ प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए केंद्र सरकार ने निर्धारित किया कोटा

केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को कोटा आवंटित करने के साथ हज कमेटी द्वारा चयनित 11,368 आजमीन को ले जाने की व्यवस्था की गई है। इन्हें निजी तौर पर जाने वाले आजमीन की तरह सुविधाएं देनी होंगी लेकिन हज कमेटी से तय किराया ही लिया जाएगा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं केंद्रीय हज कमेटी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हज का कोटा आवंटित करती है। वह आजमीन को काफी महंगे पैकेज पर ले जाते हैं लेकिन अब हज कमेटी जिन आजमीन को चयनित कर प्राइवेट ऑपरेटर्स को देगी, उन्हें भी पूरी सुविधा देनी पड़ेगी। बता दें कि हज कमेटी में दो श्रेणी हैं। ग्रीन श्रेणी में सुविधाएं अधिक हैं। इसमें जाने वालों से दो लाख, 90 हजार 850 रूपये जमा कराए गए जबकि दूसरी श्रेणी अजीजिया की है, इसमें हर आजमीन से दो लाख 53 हजार 800 रुपये लिए गए हैं।

केंद्र सरकार ने टूर ऑपरेटर्स के लिए हज ग्रुप आर्गनाइजेशन बनाया है। इसमें उनका पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को तीन श्रेणी में बांटा गया है।

- स्टार श्रेणी में 117 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का ग्रुप है, प्रत्येक को 114 हज आजमीन को ले जाने का कोटा दिया गया है। इनमें हर ऑपरेटर्स को हज कमेटी के चयनित 36-36 आजमीन को ले जाना है ।
- फर्स्ट श्रेणी में 196 ग्रुप हैं, इनमें प्रत्येक ऑपरेटर्स को 79 का हज कोटा मिला है। इनमें हर ऑपरेटर्स को हज कमेटी से चयनित किए गए 26 आजमीन को ले जाना होगा।
- सेकंड श्रेणी में 412 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स शामिल हैं, इनमें प्रत्येक ऑपरेटर को 50 हज का कोटा है। हर ऑपरेटर को हज कमेटी के चयनित पांच आजमीन को ले जाना ही है।

तंजीम खुद्दाम हज कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हज कमेटी द्वारा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को 11,368 आजमीन को ले जाने का कोटा निश्चित है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो सुविधाएं अपने आजमीन को देते हैं, उन्हें हज कमेटी के आजमीन को भी वही सुविधाएं देनी होंगी।

कारोबारी ने पत्नी की हत्या कर की खुदकशी

जागरण टीम, मालेरकोटला (संगरूर)

- बेटे पर भी दागीं चार गोलियां चल रहा है इलाज, दिवाली की छुट्टी पर आया था घर
- लोगों के अनुसार, लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान थे विजय जैन

शहर के मशहूर मिठाई विक्रेता व जैन स्वीट्स के मालिक विजय जैन ने मंगलवार तड़के चार बजे अपने रिवॉल्वर से पत्नी व मासूम बेटे को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दो गोलियां लगने से पत्नी आशा जैन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विजय जैन ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं, चार गोलियां लगने के बाद गंभीर रूप से घायल 13 वर्षीय साहिल को डीएमसी लुधियाना में भर्ती किया गया है। यहां करीब पांच घंटे के ऑपरेशन के बाद उसकी गोलियां निकाल ली गई हैं। उसकी हालत खतरे से बाहर है। प्रारंभिक जांच में घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन आसपास के लोगों व दुकानदारों का कहना है कि विजय जैन लंबे समय से मानसिक तौर पर परेशान थे। इसके चलते ही उन्होंने यह कदम उठाया। एसपी ऑपरेशन संगरूर हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि विजय जैन ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से मालेरकोटला के छत्ता मोहल्ला की छत्ता वाली गली में स्थित अपने घर पर वारदात को अंजाम दिया। विजय ने सबसे पहले पत्नी को बाजू व पेट में गोली मारी। इसके बाद साहिल पर चार गोलियां चलाईं। उसे मरा समझ विजय जैन अपने कमरे से निकलकर घर की ऊपरी

साहिल जैन

संगरूर जिले के मालेरकोटला शहर के मिठाई विक्रेता मालिक विजय जैन व उनकी पत्नी आशा जैन। सभी फाइल फोटो

मंजिल के कमरे में गए। वहां खाली रिवॉल्वर में दोबारा गोलियां भरीं व खुद की छाती पर रिवॉल्वर रखकर गोली मार ली।

चार गोलियां लगने के बाद दादी को फोन किया, दरवाजा भी खोला : विजय जैन के घर के बिल्कुल सामने के घर में रहतीं विजय की माता दर्शना जैन ने पुलिस को बताया कि सुबह चार बजे उनके पोते साहिल ने फोन कर घटना के बारे में बताया। जब उसने घर का दरवाजा खटखटाया, तो गंभीर रूप से घायल साहिल ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि बेड पर बहू आशा जैन की लाश पड़ी थी। विजय भी छत पर घायल पड़ा था। उसने चिल्ला कर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। विजय व साहिल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन विजय ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। साहिल नाभा के पंजाब पब्लिक स्कूल में नौवी में पढ़ता है और हॉस्टल में रहता है। वह दीवाली के लिए छुट्टी पर वह घर आया था।

लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या, फैला सांप्रदायिक तनाव

जासं, बिजनौर : उप्र के बिजनौर स्थित धामपुर तहसील के गांव नौरंगाबाद में सोमवार को अल्पसंख्यक समुदाय के युवक की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। विरोध में परिजनों ने शव को हरिद्वार-मुरादाबाद हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। परिजनों ने पहले एक हिंदू संगठन के नेता पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन तहरीर में उसका नाम नहीं है। गांव में पुलिस तैनात की गई है।

नौरंगाबाद निवासी मो. अकरम मजदूरी करता था। उसके सात बच्चे हैं। सोमवार दोपहर शराब के नशे में वह गांव के बाहर मुरादाबाद रोड स्थित एक दुकान पर गया था। तभी दूसरे संप्रदाय के कुछ युवकों से उसका झगड़ा हो गया। आरोप है कि युवकों ने लाठी-डंडों से उसकी पिटाई की। लोगों ने बीच-बचाव कराया और अकरम को घर ले गए। देर शाम तबीयत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। सोमवार रात उसकी मौत हो गई। परिजनों ने चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। विरोध में मंगलवार शाम परिजनों ने शव को हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया।

चिदंबरम क्रोन्स बीमारी से ग्रस्त, तुरंत विशेष उपचार की जरूरत

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम क्रोन्स बीमारी से पीड़ित हैं और किसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उनका तत्काल विशेष उपचार कराए जाने की जरूरत है। चिदंबरम के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी। कांग्रेस नेता आइएनएक्स मनी लांड्रिंग मामले में फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं।

नाम उजागर न करने की शर्त पर सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि खराब सेहत को देखते हुए चिदंबरम को इलाज के लिए किसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तत्काल भेजा जाना बेहतर होगा। क्रोन्स बीमारी आंतों में सूजन की एक बीमारी है जो मुंह से लेकर गुदा तक पेट एवं आंत संबंधी तंत्र के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है। इस बीमारी के लक्षणों में पेट में दर्द, दस्त (सूजन गंभीर होने पर खून भी आ सकता है), बुखार और वजन घटना शामिल है। चिदंबरम को सोमवार को सुबह के समय राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल ले जाया गया था और बाद में उन्हें एम्स भेजा गया था। उन्हें रात में अस्पताल से छुट्टी दी गई थी।

अबूझमाड़ में 13 मोस्टवांटेड नक्सलियों ने ले रखी है पनाह

हिमांशु शर्मा, रायपुर

विभिन्न मामलों में वांछित 13 बड़े नक्सलवादी छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में पनाह लिए हुए हैं। इसका पर्दाफाश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में नक्सल हिंसा पर जारी एक रिपोर्ट से हुआ है। देशभर के दस नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सल हिंसा में नौ साल के भीतर 3769 लोगों के मारे जाने की बात रिपोर्ट में सामने आई है। इसमें सर्वाधिक 1370 लोगों ने छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में जान गंवाई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में विभिन्न वाम चरमपंथी संगठनों में सीपीआइ माओवादी सबसे ताकतवर है। इसी संगठन के कई बड़े लीडर अबूझमाड़ इलाके में डेरा जमाए हुए हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने इनके हुलिये के साथ संभावित ठिकानों की एक सूची जारी की थी, जिसमें मोस्टवांटेड लिस्ट के सर्वाधिक नक्सलियों के इसी जोन में शरण लेने की बात सामने आ रही है। उधर, राज्य सरकार दावा कर रही है कि राज्य में नक्सलियों के तमाम बड़े नेताओं को पुलिस ने मुठभेड़ों में मार गिराया है।

मोस्टवांटेड नक्सलियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम मुप्पला लक्ष्मण राव का है, जिसे गणपति और रमन्ना के नाम से भी जाना जाता है। 71 साल का यह शख्स हाल ही में नक्सलियों के सबसे बड़े ओहदे सेंट्रल कमेटी के महासचिव पद से रिटायर हुआ है। एनआइए को अंदेशा है कि यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में छिपा है। इसके साथ ही लिस्ट में नम्बल्ला केशव राव उर्फ बसव राजू का नाम भी शामिल है। यह नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का नया महासचिव है और इसके भी अबूझमाड़ क्षेत्र में छिपे होने की बातें सामने आ रही हैं। इनके अलावा टॉप मोस्ट सूची में प्रशांत बोस उर्फ किसनजी का नाम शामिल है, जिसके झारखंड के सारंदिया क्षेत्र में होने की बातें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश और ओडिशा बॉर्डर पर सायन्ना नाम के नक्सली नेता के होने का अंदेशा एनआइए को है। सूची में अगला नाम मल्लोइयुला वेनुगोपाल का है, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर सक्रिय है और यहां से नक्सली गतिविधियों को लीड कर रहा है। एनआइए को इन सब की तलाश है। वैसे एजेंसी का मानना है कि इनमें से ज्यादातर बड़े नक्सली किसी एक ठिकाने पर स्थायी तौर पर न रहकर लगातार मूवमेंट करते हैं।

मुंबई में पीएमसी के ग्राहकों ने किया आरबीआइ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन

मुंबई, प्रेट्र : पंजाब व महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के परेशान ग्राहकों ने मंगलवार को यहां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ग्राहकों ने फंसे हुए रुपये की अदायगी की मांग की। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स स्थित आरबीआइ के कार्यालय में एक मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।

पीएमसी बैंक में 4,355 करोड़ रुपये का घोटाला प्रकाश में आने के बाद रिजर्व बैंक ने उससे रुपये की निकासी के मामले में पाबंदी लगा दी है। पहले एक ग्राहक बैंक से सिर्फ एक हजार रुपये निकाल सकता था। बाद में इस सीमा को 40 हजार रुपये कर दिया गया। घोटाला प्रकाश में आने और निकासी के मामले में पाबंदी लगाए जाने के बाद से अब तक कम से कम पांच ग्राहकों की मौत हो चुकी है। एक ने आत्महत्या कर ली थी।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल जित्शु सेठ ने कहा कि आरबीआइ अधिकारी ने ग्राहकों की राशि सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है। आरबीआइ से आग्रह किया गया है कि चाहे तो वह पीएमसी बैंक में 4,000 करोड़ रुपये डाले या इसका किसी मुनाफे में चल रहे बैंक के साथ विलय कर दे।

मुंबई में आरबीआइ दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते पीएमसी बैंक के खाता धारक। एएनआइ

उल्लेखनीय है कि पीएमसी बैंक घोटाले में अब तक एचडीआइएल के प्रवर्तकों समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि हाउसिंग डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) के अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है।

परंपरा

अगले छह माह ऊखीमठ में बाबा केदार और खरसारी में होंगे यमुना के दर्शन, अब 17 नवंबर को बंद किए जाएंगे बदरीनाथ धाम के कपाट

केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बंद, पहुंचे 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु

जागरण टीम, गढ़वाल

उत्तराखंड में चार धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला जारी है। भैया दूज के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। अब आगामी छह माह बाबा केदार के दर्शन शीतकालीन गद्दीस्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर और यमुना के दर्शन उत्तरकाशी जिले के खरसाली में किए जा सकेंगे। इससे पहले सोमवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। मंगलवार को गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में विराजमान हो गई है। बता दें कि इस बार रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे थे। वहीं, बदरीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे।

समुद्रतल से करीब 11500 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में कपाट बंद करने की प्रक्रिया प्रातः तीन बजे शुरू हो गई थी। केदारनाथ के मुख्य पुजारी केदार लिंग के नेतृत्व में वेदपाठियों ने विशेष पूजा अर्चना के साथ ही बाबा केदार का महाभिषेक किया। ठीक साढ़े छह बजे उत्सव डोली को गर्भगृह से बाहर निकाला गया और गर्भगृह के कपाट बंद किए गए। लगभग दो घंटे तक उत्सव डोली को मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया। इसके बाद ठीक 8:30 बजे मंदिर के मुख्य कपाट बंद कर दिए गए। बाबा केदार के जयकारों के साथ सेना की बैंड की धुन पर उत्सव डोली अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर धाम में करीब 1500 श्रद्धालु उपस्थित थे। रामपुर में रात्रि विश्राम के बाद उत्सव डोली 30 अक्टूबर को गुप्तकाशी और 31 अक्टूबर को ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी।

दूसरी ओर उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर बाद 1:30 बजे बंद कर दिए गए। शनिदेव की अगुआई में यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली पहुंची। आगामी छह माह श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन खरसाली में होंगे।

केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। साभार-मंदिर समिति

▶ गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में हुई विराजमान

छह वर्ष में केदारनाथ पहुंचे यात्री

वर्ष	श्रद्धालु
2014	42000
2015	109000
2016	309000
2017	471000
2018	732000
2019	10,00021

मंदिर समिति ने कमाए 16 करोड़ : उत्तराखंड में इस बार चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब से श्री बदरी-केदार मंदिर समिति में भी उत्साह है। समिति को 16 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि वर्ष 2013 में आए सैलाब के बाद यहां व्यापारियों और आम जनता में मायूसी का आलम था, लेकिन 2014 में केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने के बाद हालात में खासा बदलाव आया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करीब-करीब हर साल केदारनाथ यात्रा पर आए और देश-विदेश में इसका अच्छा संदेश गया। इस बार हेली सेवाओं ने भी 84 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। यात्रा का उत्साह श्रद्धालुओं में इस कदर था कि 16 जून को एक ही दिन में 36 हजार लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए। यह भी एक रिकार्ड है। ऐसे में घोड़ा-खच्चर संचालकों के चेहरे खिले रहे और उन्होंने करीब 94 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

केदारनाथ के तीर्थपुरोहित श्रीनिवास पोस्ती कहते हैं कि आपदा के बाद जिस तरह इस वर्ष देश-विदेश के यात्रियों का हुजूम उमड़ा है वह आने वाले वक्त के लिए एक नई उम्मीद है।

हेरोइन सप्लाई करने तरनतारन पहुंची महिला एएसआइ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटियाला : पंजाब में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने मंगलवार को खाकी वर्दी की आड़ में नशे की तस्करी करने वाली पटियाला की महिला एएसआइ को तरनतारन के पट्टी में गिरफ्तार कर लिया। उससे 50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। नशा खरीदने वाले तस्कर को भी काबू कर लिया गया। एएसआइ रेनू बाला पटियाला के थाना अर्बन एस्टेट में 19 जून से बतौर एएसआइ तैनात थी। उसका पति और अन्य तीन परिजन भी पुलिस विभाग में ही कार्यरत हैं।

रेनू बाला पिछले कुछ दिन से छुट्टी पर चल रही थी। मंगलवार को वह पटियाला से पट्टी में निशान सिंह नामक युवक को हेरोइन सप्लाई करने गई थी। पुलिस को सूचना लग चुकी थी कि रेनू बाला हेरोइन लेकर बस से पट्टी जा रही है। एंटी नारकोटिक्स सेल पट्टी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुखराज सिंह की टीम पूरी तैयारी के साथ बस अड्डा पट्टी में मौजूद थी। बस से उतरते ही रेनू बाला को गिरफ्तार कर लिया गया।

Download UPSC IAS Material: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 30 अक्टूबर 2019

दैनिक जागरण
विनम्रता सभी गुणों की जननी है

सरकार का इंतजार

महाराष्ट्र में सरकार गठन में हो रही देरी भाजपा और शिवसेना के बीच बढ़ती खींचतान को ही बयान कर रही है। ऐसा लगता है कि यह खींचतान लंबी खिंचेगी, क्योंकि जहां शिवसेना इस पर अड़ी है कि ढाई-ढाई साल के फार्मूले के तहत दोनों दल के नेता बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनें वहीं भाजपा ऐसी किसी व्यवस्था को स्वीकार करने से इन्कार कर रही है। गठबंधन सरकार के गठन के दौरान सहयोगी दलों के बीच कुछ न कुछ खींचतान होती ही है, लेकिन महाराष्ट्र में वह कुछ ज्यादा ही विद्रूप होती जा रही है। समस्या केवल यह नहीं कि सरकार गठन को लेकर कोई सहमति नहीं बन रही है, बल्कि यह भी है कि दोनों दलों के बीच मतभेद कटुता का रूप ले रहे हैं। यह कटुता दोनों दलों के संबंधों में खटास ही पैदा करेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत में दोनों दल एक-दूसरे से छिटक चुके हैं। पिछला विधानसभा चुनाव दोनों दल अलग-अलग लड़े थे। राजनीतिक मजबूरी के चलते दोनों फिर से करीब आए। अब उनमें फिर से दुराव पैदा हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण शिवसेना की ओर से यह प्रदर्शित किया जाना है कि वह भाजपा पर जितने ज्यादा तीखे हमले करेगी, उसका दावा उतना ही मजबूत होगा।

यह गठबंधन धर्म के खिलाफ है कि शिवसेना भाजपा पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकाने का काम करे। शिवसेना की ओर से यह संकेत दिया जाना एक तरह की धमकी ही है कि अगर उसकी शर्तें न मानी गईं तो वह कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पाले में जा सकती है। फिलहाल यह नहीं लगता कि वह अपनी इस धमकी को लेकर गंभीर है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सत्ता की ललक में राजनीतिक दल किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। पता नहीं शिवसेना क्या करेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बारी-बारी से मुख्यमंत्री पद संभालने की व्यवस्था एक नाकाम फार्मूला है। यह कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक-दूसरे के प्रति अविश्वास पर टिका होता है। ऐसा कोई फार्मूला शासन व्यवस्था के लिए एक बोझ ही साबित होगा। इसका कोई मतलब नहीं कि कोई सरकार ढाई साल तक एक तरह से चले और शेष ढाई साल दूसरी तरह से। अगर ऐसा नहीं होना है तो फिर इसका औचित्य ही क्या है कि बारी-बारी से दो मुख्यमंत्री ढाई-ढाई साल सरकार चलाएं? यह समय उन तौर-तरीकों पर विचार करने का है जिनसे महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षाओं को सही तरह से पूरा किया जा सके। यह देखना दयनीय है कि इसके बजाय सत्ता की ज्यादा मलाई हासिल करने को लेकर खींचतान हो रही है।

निर्मल गंगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार निर्मल गंगा अभियान उत्तराखंड में परवान चढ़ने लगा है। हालांकि गोमुख और बदरीनाथ से ऋषिकेश के बीच गंगा का पानी काफी हद तक स्वच्छ है, लेकिन ऋषिकेश और हरिद्वार में हालात इतने सुकूनदायक नहीं हैं। नमामि गंगे के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान जनवरी बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा दोनों शहरों में गंगा में गिर रहे ज्यादातर नाले टैप कर दिए गए हैं और शेष भी जल्दी टैप हो जाएंगे। निःसंदेह इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर नजर दौड़ाएं तो गोमुख से लेकर ऋषिकेश तक गंगा के पानी की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की है। बावजूद इसके हरिद्वार में गंगा के पानी के कतिपय नमूनों में कुछेक स्थानों पर फीकल कॉलीफार्म (मल-मूत्र) भी पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ समय से स्थिति में सुधार आया है। दरअसल देखा जाए तो यह समस्या का सिर्फ एक पहलू है। गंगा को यदि निर्मल रखना है तो इस नदी के साथ ही सहायक नदियों की स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। आम तौर पर देखने में आया है कि उत्तरकाशी हो या देवप्रयाग अथवा रुद्रप्रयाग और बदरीनाथ। गंगा तट पर बसे ज्यादातर कस्बों और शहरों में अक्सर किनारे कूड़े के ढेर लगे हैं। हालांकि नदियों के किनारे कूड़े डालने पर प्रतिबंध है, लेकिन इस पर अभी पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा है। पॉलीथिन के ढेर इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। यह समस्या बरसात में और भी गंभीर हो जाती है। तब यह कूड़ा नदियों में पहुंच जाता है। इसके लिए जिलों में प्रशासन ने जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया, लेकिन एक दो दिन के कार्यक्रम से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए लगातार सक्रिय रहने की जरूरत है। इसके अलावा नगर निकायों को भी गंगा स्वच्छता में अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। अक्सर देखने में आया है कि निकायों ने नियम-कानून तो बना दिए हैं, लेकिन उनके पास इन नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। उत्तराखंड गठन के बाद से निकाय क्षेत्रों को विस्तार तो हुआ, बावजूद इसके स्टॉफ में कोई वृद्धि नहीं की गई। इसके साथ ही राजस्व को लेकर भी निकायों की स्थिति दयनीय है। जाहिर है निकायों को मजबूत किए बिना गंगा स्वच्छता किसी चुनौती से कम नहीं है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को भी जागरूक करने की जरूरत है। ट्रैकिंग पर जाने वाले पर्यटक भी हिमालय में बड़ी मात्रा में कूड़ा छोड़ आते हैं। इसको लेकर भी गंभीर होने की जरूरत है।

कूटनीति को नई धार देता भारत

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि दोस्ताना रिश्ते निभाने में वह एक कदम आगे चलने को तैयार है, पर अपने आंतरिक मामलों में किसी का दखल उसे बर्दाश्त नहीं होगा

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय सऊदी अरब दौरे पर हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस दौरे के साथ ही उन्हें अंकारा भी जाना था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के कश्मीर पर बिगड़े बोल से कुपित पीएम मोदी ने अपना तुर्की दौरा रद कर दिया। एर्दोगन ने न केवल कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध किया, बल्कि चीन और मलेशिया के साथ मिलकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को काली सूची में जाने से भी बचाया। मानों इतना ही काफी नहीं था, एर्दोगन ने यह भी कहा कि वह आगे भी वैश्विक मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते रहेंगे। मोदी के तुर्की दौरे का मकसद था दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम देना, लेकिन एर्दोगन की बदजुबानी ने इस मुहिम को परवान चढ़ने से पहले ही फुस्स कर दिया। इससे पहले तक भारत-तुर्की संबंधों में सब कुछ सही दिख रहा था। बीते पांच वर्षों में मोदी और एर्दोगन तीन बार मुलाकात कर चुके हैं।

भारत सरकार मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से भी खफा है। उन्होंने भी कश्मीर में भारत के कदम की आलोचना करते हुए उसे पाक के साथ मिलकर मसला सुलझाने की वकालत की। इससे नाराज सरकार मलेशिया से पाम ऑयल आयात बंद करके इंडोनेशिया, अर्जेंटीना या यूक्रेन जैसे किसी अन्य देश से मंगाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने कूटनीतिक, राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक ताकत का इतना बखूबी इस्तेमाल किया है जिसकी स्वतंत्र भारत के इतिहास में मिसाल मिलनी मुश्किल है। शासन कला में व्यापार एवं वाणिज्य बेहद अहम पहलू होते हैं। तुर्की और मलेशिया के मसले को मोदी ने सही तरीके से संभाला। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। दोनों जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है और पड़ोसियों के साथ तनातनी के चलते सुरक्षा के मोर्चे पर भी हालात सही नहीं हैं। ऐसे परिदृश्य में भारत के साथ रिश्तों को तल्ख बनाना इन देशों के लिए कूटनीतिक रूप से समझदारी नहीं कही जा सकती।

तुर्की का क्षेत्रफल, 7,83,562 वर्ग किलोमीटर है। इस लिहाज से वह भारत के तकरीबन पांचवें हिस्से के बराबर है, मगर वह चार प्रमुख चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों- बाल्कन, कॉकेशस, पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी के बीच स्थित है। एनाटोलियन प्रायद्वीप पर तुर्की काला सागर, भूमध्य सागर और एजियन सागर से घिरा है। एनाटोलिया ऐसा केंद्रीय बिंदु है जिसकी धुरी पर एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप मिलते हैं। वैश्वीकरण के अलावा इन क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों और संघर्षरत देशों के साथ तुर्की की नजदीकी उसकी अहमियत और बढ़ा देती हैं। वहीं 3,28,550 वर्ग किलोमीटर में फैला मलेशिया भारत के लगभग दसवें हिस्से के बराबर है। यह दक्षिणपूर्व एशिया में मुख्यभूमि से लेकर द्वीप समूहों तक एक प्रमुख भू-रणनीतिक पट्टी के रूप में स्थित है। दक्षिणपूर्व एशिया के मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी बिंदु पर मलेशिया प्रायद्वीप है जबकि पूर्वी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर है जहां से दक्षिण चीन सागर 600 किलोमीटर दूर है। इसके साथ लगे मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से पूर्व और पश्चिम के बीच अधिकांश व्यापार होता है जिसके किनारे मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच विभाजित हैं। इन सभी के एक दूसरे से तल्ख रिश्ते हैं। एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत इन दोनों क्षेत्रों में एक अहम अंशभागी है। ऐसे में वह अपने आंतरिक मामलों पर तीखी टिप्पणियां नहीं पचा सकता।

तुर्की के राष्ट्र निर्माता मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने अपने देश को आधुनिक बनाने के मकसद से 29 अक्टूबर 1923 को खलीफा शासन की समाप्ति का एलान कर तुर्की को गणतंत्र घोषित किया। इसके साथ ही वहां धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता और आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। तुर्की ने शरीया कानूनों को आधिकारिक दायरे से बाहर रखकर मुस्लिम बहुल देशों में अपने लिए एक अलग पहचान गढ़ी, लेकिन एर्दोगन अब उसी पहचान को मिटाने पर तुले हैं। हालांकि वहां अभी तक धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचा कायम है, लेकिन उनके राज में तुर्की के हालिया घटनाक्रम खतरनाक बदलावों की ओर संकेत करते हैं। तुर्की ने बीते 9 अक्टूबर को सीरिया में अपनी सैन्य तैनाती को 'जिहाद' करार दिया जिससे इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सवालिया निशान लगते हैं। सरकारी धार्मिक मामलों के निदेशालय ने तुर्की की सभी 90,000 मस्जिदों को लाउडस्पीकरों से उस संदेश के प्रसारित करने का आदेश दिया जो इस्लाम की निंदा पर हिंसक होने के लिए उकसाने वाली कवायद है। तुर्की के समाज पर शरीया को थोपने के लिहाज से यह अहम पड़ाव है। एर्दोगन सरकार ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया है। इस्लाम की निंदा या उसके उचित अनुपालन न होने पर कड़ाई की जा रही है। तुर्की राष्ट्रीय पुलिस नवंबर 2017 से धार्मिक टिप्पणियों की ऑनलाइन निगरानी कर रही है और उसे जहां भी इस्लाम पर कोई टिप्पणी खटकती है तो वह तुरंत कार्रवाई करती है। सार्वजनिक रूप से इस्लाम की आलोचना अपराध बन गई है। सोशल मीडिया में इस्लाम पर नकारात्मक टिप्पणियों या हास-परिहास को लेकर लोगों पर मुकदमें चलाए जा रहे हैं।

तुर्की ने इसी महीने की शुरुआत में सीरिया से लगी सीमा पर कुर्दों के खिलाफ हमला बोल दिया। तुर्किश वायु सेना ने सीमावर्ती इलाकों पर बम बरसाए। इसके चलते 1,30,000 लोग विस्थापन के लिए मजबूर हुए। वहीं सीरिया में करीब 70 नागरिकों की जान चली गई तो तुर्की में भी 20 लोग मारे गए। एर्दोगन की विदेश नीति को नियो-ऑटोमन नीति कहा जा रहा है। वहां सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान तुर्की-सीरिया सीमा पर सीरियन-कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स को ताकत हासिल करने से रोकने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत को भी मानवाधिकारों के ऐसे उल्लंघन के मुद्दे को मुखरता से उठाने से नहीं हिचकना चाहिए।

मोदी सरकार मलेशिया को भी अपनी नाखुशी को लेकर सख्त संदेश देना चाहती है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय भावनाओं को समझते हुए भारतीय व्यापारियों ने मलेशियाई पाम ऑयल के अघोषित बहिष्कार का फैसला किया। बीते शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशियाई विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला को अपने सख्त रुख से अवगत कराया। भारत विश्व में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। ऐसे में अगर वह दूसरे देशों से आयात की संभावनाएं टटोलेगा तो मलेशिया को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

भारतीय कूटनीतिक तंत्र ने पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि दोस्ताना रिश्तों को निभाने में वह एक कदम आगे चलने को तैयार है, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में किसी का दखल उसे बर्दाश्त नहीं होगा।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

उदारवादियों का विचार-विमर्श

राजीव सचान

क्या यह संभव है कि बगदादी को मजहबी विद्वान बताने वाले यह न जानते हों कि वह कितना खूंखार था?

दुनिया के सबसे वहशी आतंकी अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने पर दुनिया ने इसके बावजूद राहत की सांस ली कि न तो इस्लामिक स्टेट का खात्मा होने जा रहा है और न ही अन्य अनेक जिहादी संगठनों का। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इस्लामिक स्टेट का सरगना अल बगदादी आधुनिक काल का सबसे घिनौना और बर्बर आतंकी था। उसने मध्ययुगीन बर्बरता को भी मात दे रखी थी। उसने लोगों के बेरहमी से सिर तो कलम किए ही, उन्हें जलाकर, लोहे के पिंजरे में कैद करने के बाद पानी में डुबोकर, ऊंची इमारतों से फेंककर और बूचड़खानों में काट-काट कर भी मारा। इसी तरह उसने महिलाओं को यौन दासियों में तो तब्दील किया ही, उनकी नीलामी भी की और उनसे खुलेआम दुष्कर्म भी। उसकी बर्बरता के किस्से रोंगटे खड़े करने वाले थे, फिर भी दुनिया भर के तमाम देशों के युवक उसके संगठन में शामिल होने के लिए इराक-सीरिया चले आए। इनमें अच्छी-खासी संख्या उनकी थी जो पढ़े-लिखे और यूरोप-अमेरिका में सुविधा संपन्न जीवन जीने वाले थे। माना जाता है कि इसकी एक वजह उन्हें यौन दासियां उपलब्ध कराना और साथ ही खिलाफत को फिर से कायम करने का सपना दिखाना था। आश्चर्यजनक रूप से इस्लामिक स्टेट में शामिल होने वालों में युवतियां भी थीं। बगदादी की बर्बर विचारधारा से आकर्षित जो युवा इराक-सीरिया नहीं जा सके वे अपने-अपने देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। इसके चलते यूरोप, अमेरिका के साथ-साथ अन्य अनेक देशों में आतंकी हमले कर खौफ पैदा किया गया। बगदादी के उन्मादी आतंकियों की नृशंसता का शिकार इराक गए 39 भारतीय भी बने।

बगदादी सरीखे महापातकी आतंकी के मारे जाने की खबर दुनिया भर में प्रमुखता पानी ही थी। उसने पाई भी, लेकिन एक खबर कुछ इस तरह से थी-कट्टर मजहबी विद्वान अल बगदादी की 48 साल की उम्र में मौत। यह खबर अमेरिका के बड़े अखबार 'वाशिंगटन पोस्ट' की वेबसाइट पर आई तो सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। अमेरिकी प्रशासन से जुड़े लोगों और पत्रकारों के अलावा अन्य अनेक लोगों ने इस खबर की जमकर खिंचाई की। इसी के साथ वाशिंगटन पोस्ट का मजाक उड़ाने वाले ट्वीट किए जाने लगे, लेकिन क्या यह महज हास-परिहास का विषय था? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बगदादी को मजहबी विद्वान के तौर पर पेश करने का काम किसी गफलत के चलते नहीं हुआ। यह सोच-समझ कर ही किया गया होगा, क्योंकि पहले इस समाचार का शीर्षक कुछ इस तरह था-इस्लामिक स्टेट के सरगना अल बगदादी की मौत। फिर कुछ सोचकर, पता नहीं क्या सोचकर, उसे मजहबी विद्वान बता दिया गया। जब इसे लेकर वाशिंगटन पोस्ट की फजीहत होने लगी तब फिर से शीर्षक बदल कर अल बगदादी को इस्लामिक स्टेट का सरगना कहा गया। इसके साथ ही यह सफाई भी पेश की गई कि उसे मजहबी विद्वान बताने वाली खबर का वह मतलब नहीं था जो समझा गया। पता नहीं इस स्पष्टीकरण के जरिये क्या स्पष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन बगदादी के मारे जाने पर उसे खूंखार आतंकी बताने में वाशिंगटन पोस्ट के अलावा अन्य अनेक पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने भी परहेज किया। यह परहेज उन मीडिया संस्थानों की ओर से किया गया जो लिबरल या लेफ्ट लिबरल के तौर पर जाने जाते हैं। लिबरल यानी उदारवादी, लेकिन आम जनता के लिए यह समझना कठिन है कि आखिर किसी बर्बर आतंकी को मजहबी विद्वान बताने वाले खुद को लिबरल या उदारवादी कैसे कह सकते हैं? वास्तव में इन्हें कुदारवादी या ऐसे ही किसी अन्य शब्द से परिभाषित किया जाना बेहतर होगा।

निःसंदेह ऐसा नहीं हो सकता कि बगदादी को मजहबी विद्वान बताने वाले यह न जानते हों कि वह कितना घृणास्पद था। यह जानते हुए भी उन्होंने उसके प्रति नरमी दिखाई तो शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नापसंद करने के कारण ही। संभवतः वे यह नहीं चाहते होंगे कि ट्रंप को बगदादी के मारे जाने का किसी तरह का राजनीतिक लाभ मिले। यह तब और स्पष्ट हुआ जब वाशिंगटन पोस्ट में ही इस आशय का एक लेख आया कि ट्रंप का यह दावा सही सही नहीं कि बगदादी की मौत एक कायर की तरह हुई, क्योंकि उसने तो अमेरिकी सैनिकों की गिरफ्त में जाने के बजाय खुद को विस्फोट के जरिये उड़ाने का फैसला किया। इसके जरिये यही कहने की कोशिश की गई कि बगदादी ने बहादुरी दिखाई। एक अमेरिकी थिंक टैंक से जुड़े नीति विश्लेषक और स्तंभकार मैक्स बूट के इस लेख की भी तीखी आलोचना हुई। जब आलोचना ज्यादा तीखी हुई तब इस लेख की उस पंक्ति में हेरफेर किया गया और यह हास्यास्पद सफाई दी गई कि उससे यह प्रतीति हो रही थी कि बगदादी साहसी था। इन दिनों अमेरिकी मीडिया में ऐसे विचारों की भरमार है जिनके जरिये यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप को बगदादी के मरने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यह आकलन एक बड़ी हद तक सही जान पड़ता है। बगदादी मरा है, लेकिन उसकी विचारधारा नहीं। बावजूद इसके इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि ट्रंप के प्रति अपनी नापसंदगी प्रकट करने के लिए एक खूंखार आतंकी के प्रति नरमी बरती गई। उदारवादियों और वस्तुतः कुदारवादियों का यह व्यवहार अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। क्या कोई 'एंड दे हैंग्ड याकूब' शीर्षक को भूल सकता है जो मुंबई बम धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद एक अंग्रेजी दैनिक की पहली खबर बना था। यह महज अपवाद नहीं, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद एक अन्य अंग्रेजी दैनिक की खबर इस शीर्षक से थी-'कार बांबर किल्स 37 ट्रूपर्स।' यह तो याद ही होगा कि आतंकी बुरहान वानी को किस तरह स्कूल हेडमास्टर का बेटा बताया गया था।

निःसंदेह उदारवादियों उर्फ कुदारवादियों को निवार्चित शासकों को नापसंद करने और उनकी निंदा-भर्त्सना करने का अधिकार है, लेकिन इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि वे अपने इस अधिकार का इस्तेमाल आतंकियों के प्रति हमदर्दी प्रकट करने या फिर उनकी कुत्सित हरकतों की अनदेखी करने में करें।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय का मूल्य

जीवन की परिभाषा समय है, क्योंकि जीवन समय से बनता है। समय का सदुपयोग जीवन का उपयोग है, समय का दुरुपयोग जीवन को नष्ट करना है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह निरंतर अज्ञात दिशा में जाकर विलीन होता रहता है। हमारा कर्तव्य है समय का पूरा-पूरा सदुपयोग करें। समय परमात्मा से भी महान है। भक्ति-साधना द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कई बार किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय पुनः नहीं मिलता। संत कबीर ने चेतावनी देते कहा है-'कल पर अपने काम को न टालें। आज करना है, उन्हें आज पूरा कर लें।

प्रत्येक काम का अवसर होता है। अवसर वही है, जब वह काम सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व समाप्त हो जाता है तथा बोझ बढ़ता जाता है। जवानी के समय को विश्राम के नाम पर नष्ट करना घोर मूर्खता है, क्योंकि यही वह समय है, जिसमें मनुष्य जीवन का, भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा ठंडा पड़ जाने पर घन पटकने से कोई लाभ नहीं, उसी तरह अवसर निकल जाने पर मनुष्य का प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। विश्राम अवश्य करें। अधिक कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए विश्राम आवश्यक है, लेकिन उसका समय निश्चित करें। समय बड़ा मूल्यवान है। उसे किफायत से व्यय करें। जितना समय-धन को बचाकर उसे आवश्यक उपयोगी कार्यों में लगाएंगे, उतनी व्यक्तित्व की महत्ता एवं हैसियत बढ़ेगी। नियमित समय पर काम करने का अभ्यास डालें।

आदत पड़ जाने पर स्वयं ही बड़ा आनंद आएगा। अपने काम और समय का इस तरह मेल रखें कि उसमें एक मिनट का अंतर न आए। तभी अपने समय का पूरा-पूरा सदुपयोग कर सकेंगे। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह कई रूपों में मनुष्य पर अधिकार जमाता है। कई बार कुछ काम किया कि विश्राम के बहाने हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। वैसे बीमारी, तकलीफ आदि में विश्राम करना बुरा नहीं है, लेकिन आंखें खुलीं तो तुरंत अपने काम में लगें।

मुकेश ऋषि

भुखमरी दूर करने का मौलिक तरीका

अनीश कुमार

जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पूरा बल नहीं दिया जाएगा तब तक देश से भुखमरी की समस्या को दूर करना कठिन बना रहेगा

विश्व बैंक ने कहा है कि 1990 के बाद अब तक भारत अपनी गरीबी दर को आधे स्तर पर ले जाने में सफल रहा। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भुखमरी और कुपोषण के मामले में भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं नेपाल से भी पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर है। अगर देश में गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठ रहे हैं तो भुखमरी के कारण देश फिसड्डी क्यों हो रहा है। अर्थशास्त्र का यह दोहरा अर्थ समझ पाना बहुत मुश्किल है। मानव विकास के मोर्चे पर भारत की विफलता का यह मामला तब सबके सामने है जब दुनिया भर में भूख और गरीबी मिटाने का मौलिक तरीका क्या हो उसे बताने वाले भारतीय अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबल दिया गया है।

रिपोर्ट में यह भी साफ है कि भारत में 6 से 23 महीने के सिर्फ 9.6 फीसद बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकृत भोजन हो पाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में यह आंकड़ा और भी कमजोर मात्र 6.4 बताया गया है। यूनिसेफ भी कह रहा है कि दुनिया में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि कद के अनुरूप वजन के मामले में भारतीय बच्चे सबसे फिसड्डी, सबसे पीछे और यमन जैसे युद्ध झेलकर जर्जर हुए देश के बच्चों से भी भारत पीछे हैं।

हालांकि भारत में मृत्यु दर, कम वजन और अल्प पोषण जैसे संकेतकों में सुधार दिखता है। ऐसे में सवाल है कि जब विश्व बैंक भारत को गरीबी के मामले में तुलनात्मक उठा हुआ मानता है तो फिर भुखमरी क्यों है? गौरतलब है कि 1989 की लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट में गरीबी 36.1 फीसद बताई गई थी तब विश्व बैंक भारत में यही आंकड़ा 48 फीसद मानता था और इसमें यह भी देखा गया कि 2400 कैलोरी ऊर्जा ग्रामीण और 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने वाले शहरी लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं। मौजूदा समय में आर्थिक दृष्टि से देखें तो 1.90 डॉलर प्रतिदिन कमाने वाले गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं। अब समझने वाली बात यह है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जैसी जरूरी आवश्यकताएं क्या इतने में पूरी हो सकती हैं? जाहिर है गरीबी से ऊपर उठने का जो स्तर तय किया गया है वह निहायत न्यून प्रतीत होता है।

जीवन को बाजार के भाव पर आंका जाय तो यह दर बहुत कम है। शायद यही कारण है कि भारत गरीबी रेखा से ऊपर के मामले में बेहतर आंकड़े की ओर है। जबकि हंगर इंडेक्स के आंकड़े उसे फिसड्डी साबित कर रहे हैं। जब तक वैकल्पिक रास्ता नहीं अपनाया जाएगा मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पूरा बल नहीं दिखाया जाएगा तब तक भुखमरी के आंकड़े समेत गरीबी को दूर करने की संतोषजनक स्थिति प्राप्त करना कठिन बना रहेगा। सरकार को बेरोजगारी की कतार को कम करना चाहिए। अवसर की प्रतीक्षा में भी जो हैं उनके साथ सामाजिक न्याय हो ताकि जब गरीबी घटे तो भुखमरी भी घटे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

न दृष्टि, न इतिहास

भारतीय दृष्टि वाला इतिहास शीर्षक आलेख में हृदयनारायण दीक्षित ने ठीक ही लिखा है कि अब अंग्रेजी सत्ता, संस्कृति, सभ्यता व वामपंथ को समर्थन देने वाले इतिहास कर्म का पोस्टमार्टम जरूरी हो गया है। पश्चिमी या इस्लामी दृष्टि से लिखे गए भारत के इतिहास को पीएन ओक ने 'धृष्टतापूर्ण मनोरंजन' बताया है। नेपोलियन का कहना था कि चूंकि इतिहास विजेताओं द्वारा ही लिखवाया जाता है, इसलिए वह एक सत्यता-रहित दंतकथा जैसा प्रतीत होता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में गुरुदेव टैगोर ने लिखा है-सौभाग्यशाली हैं वे देश जो चिरंतन स्वदेश को अपने इतिहास में ही ढूंढ लेते हैं। बचपन में इतिहास ही उनका परिचय अपने देश से करा देता है। अंग्रेजों के बच्चे जानते हैं कि उनके बाप-दादों ने व्यापार किया, देश जीते और दुनिया पर शासन किया। वे स्वयं भी उनकी तरह धन-गौरव, रण-गौरव और विजय-गौरव के अधिकारी बनना चाहते हैं, पर भारत के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उनके पुरखों ने न तो व्यापार किया, न देश जीते, न कोई साम्राज्य खड़ा किया। यही जानने के लिए है भारत का इतिहास। किंतु उनके पुरखों ने क्या किया, ये वो नहीं जानते। इस विकृत इतिहास को पढ़ने से कोई प्रेरणा हमें-हमारे बच्चों को प्राप्त नहीं होती। जब इस विकृति को दूर कर सही तथ्यों से युक्त नया इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने विद्यार्थियों को दिया तो वामपंथियों ने भगवाकरण का हौवा खड़ा कर दिया। इसकी पोल न्यायपालिका में खुल गई, वैसे ही जैसे भगवा आतंकवाद की हवा निकली। विकृत इतिहास में आर्यों को प्रथम आक्रमणकारी बताया जा रहा था, गुरु तेगबहादुर, शिवाजी, महाराणा प्रताप को हत्यारे और डकैत बताया गया था। जहां तक आर्य-आक्रमण की बात है तो उसके संबंध में तो बाबा साहब आंबेडकर ने ही लिखा

मेलबाक्स

कि यह सिद्धांत इतना वाहियात है कि काफी पहले इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए था। तो अब देशवासियों को प्रेरणा देने वाले भारतीय दृष्टि से लिखे गए इतिहास का वक्त आ पहुंचा है। हमारी इतिहास पुस्तकें इतिहास बताने वाली हों, इति न हास अर्थात ऐसा नहीं हुआ समझाने वाली नहीं।

अजय मित्तल, मेरठ

आदर्श स्थापित करे दिल्ली

देश के विभिन्न राज्यों से लोग दिल्ली इसलिए पलायन करते हैं ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। काम के साथ-साथ तमाम सुख-सुविधाएं उन्हें मिल सके। लेकिन साल दर साल दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में हो रहे इजाफे को देखकर अब लोग सोचने पर विवश हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन लोगों ने कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए दिवाली पर खूब पटाखे जलाए। परिणाम स्वरूप दिल्ली की आबोहवा प्रदूषण के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। यह स्थिति तब है जब सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया था कि रात आठ से दस के बीच ही पटाखे जलाए जाएंगे, वह भी ग्रीन पटाखे। सोचने वाली बात यह है कि हमारा वास्तविक समाज किस अंधविश्वास का पालन कर रहा है। जो एक स्वस्थ जीवन को चुनौती दे रहा है। जिस दिल्ली को देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श स्थापित करनी चाहिए थी, वह दिल्ली प्रदूषण का संदेश दे रही है। अब तो ऐसा लगता है जैसे जहरीली हवा में घुट-घुट कर जीवन जीना ही दिल्लीवासियों की नियति बन गई है।

मिथिलेश कुमार

सादगी भरी हो त्योहार की खुशी

प्रत्येक वर्ष दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो जाता है, जो एक स्वस्थ्य मनुष्य के जीवनकाल को प्रभावित करता है। इस खतरनाक प्रदूषण के कारण लोगों में सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत रहती है। लेकिन इससे कुछ सीखने के बजाय हम हर बार एक ही गलती को दोहराते जाते हैं। प्रशासन के लाख सतर्कता और पटाखा जलाने के लिए समय निर्धारित करने के बाद भी कुछ लोगों पर कोई असर देखने को नहीं मिला। उन्होंने पटाखे जलाकर दिवाली का जश्न मनाया। इस वर्ष बेशक प्रदूषण का स्तर विगत 5 वर्षों में सबसे कम रहा हो, लेकिन इस समय भी प्रदूषण का जो स्तर है वह काफी खतरनाक है। यह मानवीय स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला है। इससे जाहिर है कि लोगों द्वारा ही ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों ही जिंदगी इस प्रदूषण की बलि चढ़ जाए। आखिर लोग इस बात को क्यों नहीं मानते कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरनाक है?

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1980 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा 145 सीटों पर चुनाव लड़कर 9.38 फीसद वोट और 14 सीटें जीतने में सफल रही थी। जबकि उस समय तक शिवसेना ने विधानसभा चुनाव लड़ना शुरू नहीं किया था।

आजकल

साफ हवा का दम घोंट रही हमारी लापरवाही

आंकड़ों में दीपावली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भले ही पिछले वर्षों के मुकाबले कुछ कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन शहर का धुंधलाया आसमान यह गवाही दे रहा है कि पटाखों पर प्रतिबंध की बात हो या इस इलाके में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान प्रदूषण रोकने के मामले में ये महज दिखावटी उपाय ही साबित हुए हैं। एयर क्वॉलिटी इंडेक्स से जुड़े आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि दिल्ली में सांस लेने लायक साफ हवा अभी भी एक सपना ही है। अभी भी समय है। यदि हम नहीं चेते तो हमारी उदासीनता हमारा अस्तित्व समाप्त कर देगी

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

दावों को देखें तो लगता है कि बीते चार वर्षों के मुकाबले दिवाली पर इस बार प्रदूषण तुलनात्मक रूप से कम रहा, लेकिन क्षितिज में फैली जहरीली धुंध पर और सांसों में जाती प्रदूषित हवा को देखें तो महसूस होता है कि राहत की बातें सिर्फ एक धोखा हैं। यूं इस बार देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने जागरूकता अभियान चलाने और लेजर शो के आयोजन से लेकर कई ऐसे प्रबंध किए थे, ताकि लोग दिवाली पर पटाखे चलाने से बाज आएं, लेकिन इस प्रकाश पर्व के अगले दिन एयर क्वॉलिटी इंडेक्स से जुड़े आंकड़े साफ कर रहे थे कि सांस लेने लायक साफ हवा अभी भी एक सपना ही है। आंकड़ों में प्रदूषण का स्तर भले ही पिछले वर्षों के मुकाबले कुछ कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद-नोएडा आदि शहरों का धुंधलाया आसमान यह गवाही दे रहा है कि पटाखों पर प्रतिबंध की बात हो या इस इलाके में लागू ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान, ये सभी महज दिखावटी उपाय साबित हुए हैं।

सिर्फ पटाखे ही नहीं हैं प्रदूषण की वजह : पिछले साल दीपावली के नजदीक सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि या तो हरित पटाखे छोड़े जाएं या फिर त्योहारों के मौके पर शाम 8 से 10 तक ही पटाखे चलाए जाएं। इसके बाद मार्च, 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट देश भर में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दलील दी गई थी कि इनकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है तो अदालत ने कहा था कि लोग पटाखों के पीछे क्यों पड़े हैं जबकि इनसे ज्यादा प्रदूषण तो वाहनों और तमाम उद्योगों से होता है। जैसे कि शहरों की बात करें तो वहां होने वाले वायु प्रदूषण के लिए कारें ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अदालत ने पटाखों और ऑटोमोबाइल से होने वाले प्रदूषण के बीच तुलनात्मक अध्ययन की बात कह कर एक ऐसी विसंगति पर अंगुली रखी थी जो देश में एक ओर रोजगार तो दूसरी तरफ प्रदूषण के मारक असर की चिंता से जुड़ी है। पटाखों पर बैन के कारण इस उद्योग से जुड़े रोजगार के खात्मे की आशंका के तहत अदालत की चिंता यह थी कि कहीं इस उपाय से देश में बेरोजगारी न बढ़ जाए। इसलिए प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखों को जिम्मेदार मानकर उसके असली कारकों की अनदेखी घातक सिद्ध हो सकती है। सवाल है कि अगर पटाखे शहरों में वायु प्रदूषण की मुख्य वजह नहीं हैं तो क्या कार आदि वाहनों और उद्योग-धंधों से निकलने वाला जहरीला धुआं ही प्रदूषण का असली कारण है?

वाहन एवं उद्योग भी भर रहे हवा में जहर : ऐसे कई अध्ययन हुए हैं, जो साबित करते हैं कि दिखावे के पटाखे और खेतों में जलाई जाने वाली पराली (कृषि अवशेष) के अलावा कार के रूप में संपन्नता ने असल में हवा को जहर बनाने में ज्यादा योगदान दिया है। वर्ष 2019 की शुरुआत में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट में बताया था कि आबोहवा खराब करने की वजहों में 61 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों और इंडस्ट्री से होने वाले प्रदूषण की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में ही कार जैसे वाहनों की वजह से 39 प्रतिशत और इंडस्ट्री के कारण 22 प्रतिशत प्रदूषण हो रहा है। इनके अलावा धूल से 18 प्रतिशक प्रदूषण फैल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या फिलवक्त सवा करोड़ से ऊपर है। यह संख्या सालाना करीब 10 लाख की दर से बढ़ रही है। उल्लेखनीय यह है कि निजी वाहनों में सबसे बड़ी संख्या कारों की है जिसका उपभोक्ता शहरी मध्यवर्ग है। दिल्ली सरकार ने बताया था कि देश की राजधानी में वर्ष 2015 में साढ़े 6 हजार लोगों की मौत सांस संबंधी बीमारियों की वजह से हुई जिसके लिए यहां की प्रदूषित हवा सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वैसे तो सम-विषम फॉर्मूला अपना कर, कार-फ्री डे का आयोजन करके और 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सख्ती के साथ सड़कों से हटाने जैसे उपाय यहां की सरकार कर चुकी है। इस साल एक बार फिर 4 नवंबर से यही व्यवस्था दिल्ली में लागू होने जा रही है, लेकिन जिस तरह से लोग कारों के पीछे भाग रहे हैं, उसके कारण ट्रैफिक जाम और स्मॉग (जहरीली धुंध) की समस्याएं यहां की सतत नियति बन चुकी हैं।

आकाल मौत का कारण बन रहा प्रदूषण : कारों की बढ़ती संख्या दो अहम सवाल खड़े करती है? पहला यह कि आखिर क्यों लोग अपनी पूंजी ऐसी मद में खर्च करते हैं जो आगे चलकर उन्हीं की जिंदगी हलकान करती है? और दूसरा यह कि कारों पर लगाम लगाने में सरकारें नाकाम क्यों हो रही हैं? मसला अकेले दिल्ली-मुंबई का नहीं है। कानपुर, इंदौर, लुधियाना, अहमदाबाद समेत ज्यादातर उत्तर-मध्य भारतीय शहरों में ट्रैफिक जाम और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण ने लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया है। चूंकि वाहनों की संख्या बढ़ रही है इसलिए हवा में बढ़ता प्रदूषण लोगों में सांस की बीमारियां पैदा कर रहा है। इसके कारण आम लोगों की जिंदगी औसतन तीन साल तक कम हो रही है। कुछ ही समय पहले इस बारे में एक अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, हार्वर्ड और येल के अर्थशास्त्रियों ने किया। उनके अध्ययन से पता चला कि हमारे देश के करीब 66 करोड़ लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां की हवा में मौजूद सूक्ष्म कण पदार्थों (पार्टिकुलेट मैटर) का प्रदूषण सुरक्षित मानकों से ऊपर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) हाल के एक सर्वे में यह भी बता चुका है कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से पांच शहर भारत में हैं। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा था कि वायु प्रदूषण भारत में अकाल मौतों की प्रमुख वजहों में से एक है। इससे संबंधित बीमारियों की वजह से हर साल छह लाख बीस हजार लोगों की मौतें भारत में होती हैं।

सार्वजनिक परिवहन की सीमा : कार पर पूंजी लगाने वालों की मजबूरी यह है कि महंगी होती प्रॉपर्टी और आबादी के दबाव के मद्देनजर उन्होंने जिन उपनगरीय इलाकों में निवास को प्राथमिकता दी है, वहां से कार्यस्थल तक आना-जाना आसान नहीं है। दिल्ली से बाहर मेट्रो का इतना विस्तार नहीं हुआ है कि सभी लोग आसानी से दिल्ली पहुंच सकें। अन्य शहरों में तो अभी मेट्रो की शुरुआत ही हो रही है। मेट्रो की अपनी सीमाएं भी हैं, वह बस-कार की तरह शहर के हर कोने तक नहीं पहुंच सकता है। दिल्ली-एनसीआर में तो लोग मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी कारों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें इस वास्ते फीडर बसों का विकल्प नहीं मिल पाता है। मेट्रो के बरक्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में बसें लोगों को ऐसी सहूलियत मुहैया नहीं करा पा रही हैं कि वे कार खरीद को तिलांजलि दे सकें। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआरआरआइ) के प्रमुख साइंटिस्ट डॉ. एस वेलमुरगन के मुताबिक दिल्ली में 6,088 बसों के बेड़े में से औसतन 3,850 बसें ही रोजाना सड़कों पर निकल पाती हैं जो जरूरत के मुकाबले नाकाफी हैं। ऐसे में लोगों को खुद का वाहन एक सुविधाजनक विकल्प लगता है। हालांकि इसके पीछे सोशल स्टेटस भी एक बड़ी वजह है। कई बार लोग जरूरी नहीं होने पर भी कार खरीदते हैं और इसके लिए तरह-तरह की आपातकालीन जरूरतों का हवाला देते हैं।

समाधान के बजाय समस्या बनतीं कारें : हालांकि कारों को समस्या के रूप में देखने की नीति या समझ के विरोधियों का एक अलग मत भी है। वे कहते हैं कि समस्या कारें नहीं, बल्कि सड़कों एवं ट्रांसपोर्ट के दूसरे इंतजामों की है। हमारे देश में ज्यादातर सड़कें कारों के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई हैं। पार्किंग के समुचित प्रबंध नहीं किए हैं। कानून में नए घर-मकानों के लिए यह जरूरी नहीं किया गया है कि उनमें कारों की पार्किंग के लिए अनिवार्य रूप से जगह हो। देश की राजधानी दिल्ली में सैकड़ों अवैध कॉलोनियां ऐसी हैं जहां कारें बाहर गली में खड़ी की जाती हैं। ऐसी ही समस्याओं के चलते कारें किसी समस्या का समाधान बनने के बजाय खुद में एक समस्या बन गई हैं।

जिंदगी पर भारी पड़ती जहरीली हवा

प्रदूषित हवा हमारी सेहत पर कितनी भारी पड़ रही है, इसका एक खुलासा इस साल मार्च में अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (एचईआइ) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट-स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर-2019 में किया गया गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक घर से बाहर रहने या घर में वायु प्रदूषण की वजह से 2017 में स्ट्रोक, मधुमेह, दिल का दौरा, फेफड़े के कैंसर या फेफड़े की पुरानी बीमारियों से पूरी दुनिया में करीब 50 लाख लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि इनमें से 30 लाख मौतें सीधे तौर पर पीएम 2.5 से जुड़ी हैं। इनमें से करीब आधे लोगों की मौत भारत और चीन में हुई है। साल 2017 में इन दोनों देशों में 12-12 लाख लोगों की मौत इस वजह से हुई थी। उस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया को सबसे प्रदूषित क्षेत्र माना गया था जिसमें भारत, पाक, बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं। हालांकि चीन और भारत में प्रदूषण से होने वाली मौतों का आंकड़ा एक जैसा है, लेकिन संस्था का कहना था कि चीन ने प्रदूषण को कम करने में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है। गौरतलब है कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी खतरों से होने वाली मौतों का तीसरा सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण और इसके बाद धूम्रपान है। खराब आबोहवा की वजह से दक्षिण एशिया में मौजूदा हालात में जन्म लेने वाले बच्चों की जिंदगी ढाई से तीन साल कम हो रही है।

जमीन पर असर नहीं छोड़ रहे उपाय

पर्यावरण और साफ आबोहवा की जरूरत को समझते हुए सरकारों और अदालतों ने इस मुद्दे को काफी अहमियत दे रखी है, लेकिन विडंबना यह है कि इनसे संबंधित सारे उपाय हकीकत की जमीन पर कामयाब नहीं हो रहे हैं। चंद सक्रिय लोगों, संगठनों और अदालती फैसलों के दबाव में सरकारें भी आनन-फानन कुछ कदम उठा लेती हैं, लेकिन चंद रोज में फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर आ जाता है। इसकी एक सच्चाई यह है कि विकास के नाम पर सरकारों ने औद्योगिक इकाइयों को जहरीला धुआं फैलाने की खुली छूट दे रखी है। कहीं-कहीं तो अदालतों को भी ठेंगा दिखा दिया जाता है, जैसे हरियाणा के अरावली क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी करते हुए 119 साल पुराना कानून बदल डाला था। पीएलपीए (पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900) में संशोधन के जरिये उसने अरावली और शिवालिक पहाड़ियों की 29,682 हेक्टेयर संरक्षित भूमि को विकास कार्यों के लिए खोल दिया था। हालांकि बाद में अदालत ने इस संशोधन पर रोक लगा दी, लेकिन कई अन्य राज्यों ने पर्यावरण के नियमों को धता बताते हुए औद्योगिक इकाइयों, बिल्डरों और खनन माफिया को मदद पहुंचाई है। वायु प्रदूषण के कुछ और कारण भी जिम्मेदार हैं। जैसे आइआइटी कानपुर के एक अध्ययन के मुताबिक प्रदूषण के लिए औद्योगिक इकाइयों और पराली जलाने जैसी सामयिक वजहों के अलावा गाड़ियों की बढ़ती संख्या, छोटे उद्योगों का डीजल जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भर होना और निर्माण कार्यों एवं टूटी सड़कों की वजह से हवा में धूल का उड़ना भी जिम्मेदार है। आज भी ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में वायु प्रदूषणरोधी उपाय नहीं किए गए हैं। कुछ शहरों में पेट्रोल-डीजल की जगह गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन इसके अपेक्षित नतीजे अभी आने बाकी हैं।

खरी-खरी

कचौड़ी का ठेला

अंशुमाली रस्तोगी

पकौड़े बेचने का प्लान धरा का धरा रह गया। अब तय किया है कि कचौड़ी बेचूंगा! यों भी, हिंदुस्तान में पकौड़े-कचौड़ी वालों का भविष्य उज्ज्वल है। हिंदुस्तानी सबकुछ छोड़ सकता है पर खाना, वो भी बाहर का, कभी नहीं छोड़ सकता। नौकरी या लेखन में अब कुछ रखा नहीं। खर्च बढ़ता जा रहा है और आमदनी वही अठन्नी। नौकरी में क्या कम झंझट हैं। बॉस की सुनो। क्लाइंट की सुनो। टाइम पर आओ जरूर पर जाने का कोई टाइम नहीं। शाम को थके-हारे घर लौटो तो बीवी की शिकायतें और किस्म-किस्म की फरमाइशें। बात पिक्चर दिखाने, शॉपिंग कराने, ससुराल जाने देने संबंधी फरमाइशों की है।

लेखन में ही भला कौन-सा सुख है। नौकरी की तरह ही लेखन में भी दबाके कॉम्पिटिशन हो गया है। इतनी तरह के तो लेखक आ गए हैं। कोई भी लेखक हजार तरह का लेखन कर गुजरता है। यह नहीं कि अगला व्यंग्य लिखता है तो व्यंग्य ही लिखेगा। व्यंग्य के साथ वो कविता, कहानी और उपन्यास भी लिख लेता है। वो तो गनीमत है कि अब नहीं लिखते, वरना पहले तो वे वक्त-जरूरत पड़ने पर मकान की रजिस्ट्री, किरायानामा, नोटरी की ड्राफ्टिंग आदि भी लिख लेते थे। लेखक जो ठहरे। जहां तक लिखकर पेट भर सकने की बात है तो लिखने के बाद भी यह गारंटी नहीं कि फलां जगह छपेगा ही। और छप भी गया तो चेक या नकद मिलेगा ही! जुगाड़ अपन को आता नहीं, इसके बिना छप पाता नहीं।

कितने ही पुरस्कार जुगाड़ के चलते इस या उस को दिए और दिलवा दिए जाते हैं। यहां तो इतना समय हो गया लिखते हुए, मजाल है किसी ने पुरस्कार के नाम पर एक कलम भी दी हो। कुछ जगह तो मेहनताने के पैसे तक दबे पड़े हैं। मगर देखने वाले को लगता है कि अगला लेखक है तो दबाकर पीट रहा होगा। इसीलिए तो मैंने नौकरी और लेखन को त्याग कर कचौड़ी बेचने का निर्णय लिया है। कम से कम रोज की कमाई तो पक्की है इसमें। जब चाहो कचौड़ियां तलो, न मन हो तो मत तलो।

हालांकि मेरे इस निर्णय पर बीवी को घोर आपत्ति है। वो कहती है-इत्ती अच्छी जॉब छोड़कर कचौड़ी बेचोगे! तुम्हें शर्म नहीं आएगी? नाते-रिश्तेदारों में नाक कटवाओगे क्या? मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं-कचौड़ी से नाक का क्या ताल्लुक? इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि ठेला तो मैं कचौड़ी का ही लगाऊंगा। भले ही फिर मेरे खुद के पकौड़े क्यों न तल जाएं?

ट्वीट-ट्वीट

एक और ऐतिहासिक पड़ाव। भारत 22 नवंबर को कोलकाता में अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेलेगा। यह जिस वक्त आयोजित होगा, वह अवधि भी खासी दिलचस्प होगी, क्योंकि ओस का असर एक अहम पहलू होगा। मगर फिर भी शुरुआत तो हुई और यह सौरव गांगुली द्वारा बीसीसीआइ की कमान संभालने का पहला संकेत भी है।
हर्षा भोगले@bhogleharsha

जनसंख्या नियंत्रण पर बोलिए तो मुसलमानों को दिक्कत, पटाखे न छोड़ने की हिदायत दे दीजिए तो आप हिंदू विरोधी। बहुत गजब स्थिति है। खाने-पीने को संसाधन बचें न बचें, फेफड़े बचें या न बचें, लेकिन धर्म का झंडा बुलंद रहना चाहिए। धर्म में जो मानवता, दान, सहृदयता सिखाई गई वे सब जीरो और झंडा उठाने में हीरो।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

क्या धनतेरस पर गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े ऑटो क्षेत्र में सुधार के संकेत हैं? अगर ऐसा है तो यह शुभ समाचार है। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार यकीनन तेज होगी।
सुनील जैन@thesuniljain

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या आइएस सरगना बगदादी के मारे जाने से आतंकियों के हौसले पस्त होंगे?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या यूरोपीय संघ के सांसदों को कश्मीर दौरे की इजाजत देकर मोदी सरकार ने सही किया है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बंधु सियासत में नहीं होता कोई मित्र,
पल-पल इस उद्योग में दिखे बदलता चित्र।
दिखे बदलता चित्र जहां दिख जाए सत्ता,
घुस जाते हैं लोग वहीं ले कपड़ा-लत्ता।
महाराष्ट्र में आज दिख रही ये ही सांसत,
जय-वीरू की फिल्म रही ना बंधु सियासत।
– ओमप्रकाश तिवारी

गलतियों से सबक सीखने को तैयार नहीं शिवसेना

ओमप्रकाश तिवारी
ब्यूरो प्रमुख, मुंबई

महाराष्ट्र डायरी

मद अभिमान न कीजिए, कहैं कबीर समुझाय।
जा सिर अहं जु संचरै, पड़ै चौरासी जाय।

अर्थात, मद-अभिमान मत कीजिए। जिसकी खोपड़ी में अहंकार का संचार होता है, वह चौरासी लाख योनियों में भटकने जाता है।

पंद्रहवीं सदी के रहस्यवादी कवि संत कबीरदास के समय में न तो आज की राजनीति थी, न आज के लोग। लेकिन घटनाक्रम संभवतः हर युग में स्वयं को दोहराता रहता है, जिससे प्रेरणा पाकर लिखी गई कबीर जैसे संत की पंक्तियां हर युग में सच साबित होती दिखाई देती हैं। आज महाराष्ट्र की राजनीति में भी ऐसा ही कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में 56 सीटें जीती शिवसेना 105 सीटों वाली भाजपा की बाहें मरोड़ने को तैयार है। क्योंकि महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीति में 'बड़ा भाई' होने का भ्रम वह भूलने को तैयार नहीं है। इसी बड़प्पन के भ्रम में वह 50-50 का दावा कर रही है। ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांग रही है। ऐसा न होने की स्थिति में 'अन्य विकल्प खुले रहने' की बात कर रही है।

बात आगे कि जाए, उससे पहले शिवसेना के बड़प्पन के दावे की पड़ताल कर लेनी चाहिए। यह सच है कि गठबंधन की राजनीति में भाजपा-शिवसेना का गठबंधन अब तक एक अनूठा प्रयोग साबित हुआ है। यह गठबंधन थोड़े-बहुत मानमनौवल के साथ करीब 30 साल से चलता आ रहा है। उम्मीद है कि आगे भी चलता ही रहेगा। क्योंकि दोनों वैचारिक धरातल पर कहीं न कहीं समान हैं। यदि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सोच को दरकिनार कर दिया जाए तो दोनों का मतदाता वर्ग भी कम से कम हिंदुत्व के मुद्दे पर तो एक ही है। यही वह प्रमुख मुद्दा था, जिसके उभार के बाद 1985 में दोनों दलों को एक-दूसरे के करीब आने की जरूरत महसूस हुई। उन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व की बात भाजपा में लालकृष्ण आडवाणी और अटलबिहारी वाजपेयी कर रहे थे तो महाराष्ट्र में उसी हिंदुत्व की बात शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे भी कर रहे थे। ठाकरे अपनी विशेष शैली में आडवाणी-वाजपेयी की तुलना में यही बात ज्यादा प्रखर तरीके से कर रहे थे। लेकिन वह महाराष्ट्र से बाहर निकलने को राजी नहीं थे। यह और बात है कि उनकी प्रखरता को भुनाते हुए अन्य राज्यों में कुछ लोगों ने शिवसेना का संगठन खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और सोच दोनों का अभाव होने के कारण उनकी कोशिशें सफल नहीं हो सकीं।

दूसरी ओर भाजपा के पास जनसंघकालीन राष्ट्रव्यापी संगठन रहा है। उसे भी सहारा देने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा पितृ संगठन रहा है। जनसंघ ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश में स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव से ही भाग्य आजमाना भी शुरू कर दिया था। जबकि उस समय शिवसेना का जन्म भी नहीं हुआ था। बड़ा भाई होने का दावा करनेवाली शिवसेना को यह भी याद जरूर कर लेना चाहिए कि भारतीय जनसंघ ने 1967 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी 166 सीटों पर चुनाव लड़कर 8.17 फीसद वोट हासिल किए थे और चार सीटें जीती थीं। जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी में बदलने के तुरंत बाद हुए 1980 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा 145 सीटों पर चुनाव लड़कर 9.38 फीसद वोट और 14 सीटें जीतने में सफल रही थी। जबकि उस समय तक भी शिवसेना ने विधानसभा चुनाव लड़ना शुरू नहीं किया था। भाजपा से गठबंधन के बाद शिवसेना जब अपना पहला विधानसभा चुनाव 1990 में लड़ने उतरी तो उस समय तक उसके पास अपना अधीकृत चुनाव निशान भी नहीं था।

यह और बात है कि 1985 में श्रीरामजन्मभूमि मसले के उभार के बाद महाराष्ट्र के भाजपा नेता प्रमोद महाजन ने जब शिवसेना के साथ मिलकर राजनीति करने की सोची तो बाल ठाकरे की प्रखरता को महाराष्ट्र में भुनाकर सत्ता में आने का विचार उन्होंने जरूर किया होगा। इसी सोच के तहत उन्होंने राज्य की राजनीति में शिवसेना को ज्यादा सीटें लड़ने और राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा को अधिक सीटें लड़ाने का फैसला भी किया होगा। इस रणनीति का फायदा भी हुआ। कभी कांग्रेस का गढ़ समझे जानेवाले महाराष्ट्र में 10 साल बाद ही 1995 में शिवसेना-भाजपा की गठबंधन सरकार शपथ ले चुकी थी। लेकिन राजनीति में कोई परिस्थिति स्थाई नहीं होती। राष्ट्रीय राजनीति के लिए तय शर्तों का अतिक्रमण स्वयं शिवसेना की तरफ से होने लगा। शुरुआत में भाजपा द्वारा लड़ी गईं लोकसभा सीटों पर भी शिवसेना का दावा बढ़ने लगा। इसी तरह विधानसभा सीटों पर भाजपा अपना दावा बढ़ाने लगी। शिवसेना से काफी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद लड़ी गई सीटों पर जीत का प्रतिशत भाजपा का ही ज्यादा रहता था। इसलिए भाजपा लगातार शिवसेना से उन सीटों की मांग करती रही, जिनपर वर्षों से लड़ने के बावजूद शिवसेना कभी जीत नहीं सकी थी।

2014 में गठबंधन टूटने के पहले भी भाजपा ऐसी ही सीटों की मांग कर बराबरी पर लड़ने की बात कर रही थी। यहां तक कि 2019 में भी शिवसेना की तरफ से ऐसी ही अतिरिक्त सीटें भाजपा को दी गई हैं, जिन पर उसके उम्मीदवार कभी नहीं जीते थे। यदि शिवसेना 1999 में ही भाजपा की इस मांग पर गौर कर बराबरी की सीटों पर लड़ने की बात स्वीकार कर लेती तो लड़ी गई सीटों पर भाजपा के जीत प्रतिशत अधिक होने का लाभ पूरे गठबंधन को मिलता और उसे अगले 15 साल सत्ता से बाहर नहीं गुजारने पड़ते। अब इस चुनाव में भाजपा से लगभग आधी सीटें पाने के बावजूद यदि शिवसेना 'अन्य विकल्प खुले रहने' की बात कर रही है तो माना जाना चाहिए कि वह पिछली गलतियों से सबक सीखने को कतई तैयार नहीं है।

मुद्दा

दूध को सुरक्षित बनाने की पहल

दूध में मिलावट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। समझना होगा कि जब अर्थव्यवस्था की तिमाही जांच की जा सकती है तो खाद्य व्यवस्था की क्यों नहीं। जबकि यह हमारी जिंदगी से जुड़ा मसला है

रिजवान अंसारी
अध्येता, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 'राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा तथा गुणवत्ता सर्वेक्षण 2018' रिपोर्ट जारी की। सर्वेक्षण में दुग्ध को काफी हद तक सुरक्षित पाया गया है। रिपोर्ट की मानें तो परीक्षण किए गए दुग्ध के नमूनों में से लगभग 93 फीसद नमूनों को उपभोग के लिए सुरक्षित पाया गया और बाकी सात फीसद नमूनों में एफ्लाटॉक्सिन-एम1, एंटीबायोटिक्स जैसे दूषित पदार्थों की उपस्थिति पाई गई। दरअसल संस्थान ने पूरे देश से 6,432 सैंपल इकट्ठा किए थे। ये सैंपल देश के 1,103 ऐसे शहरों और कस्बों से लिए गए थे जिनकी आबादी कम से कम 50 हजार है। इन नमूनों में से 456 असुरक्षित पाए गए। 77 नमूने ऐसे थे जिनमें एंटीबायोटिक्स की मात्रा स्वीकृत स्तर से ज्यादा थी। इनमें 12 सैंपल ऐसे भी थे जिनमें यूरिया, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड, डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई थी। इन 12 नमूनों में से 9 तेलंगाना, दो मध्य प्रदेश और एक केरल से थे।

यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि सुरक्षित नमूनों में 41 फीसद ऐसे भी हैं जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों पर पूरे खरे नहीं उतरते। कहने का अर्थ है कि जिन चार पैरामीटर पर नमूनों की परख हुई है उनमें क्वॉलिटी पैरामीटरों में कुछ न कुछ कमी है। हालांकि प्राधिकरण ने साफ किया है कि बिना डरे इनका उपभोग किया जा सकता है। रिपोर्ट की मानें तो तमिलनाडु, केरल और दिल्ली ऐसे तीन राज्य हैं जहां के दूध सैंपलों में सबसे ज्यादा एफ्लाटॉक्सिन-एम1 नामक घातक कैंसरकारी तत्व पाया गया है जो दुधारू पशुओं को दिए जाने वाले चारे में मिला होता है। इनमें तमिलनाडु के 551 में से 88 सैंपल इस समस्या से ग्रसित पाए गए हैं। कच्चे दूध के बरक्स प्रसंस्कृत दूध में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा ज्यादा पाई गई है। ये कुछ खास किस्म के फफूंद से पैदा होना वाला जहरीला पदार्थ है जो मक्का, मूंगफली, कपास आदि फसलों में मिलता है। इसी तरह एंटीबायोटिक्स के मामले में तीन राज्य-मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हैं। इन तीनों राज्यों में कुल 39 सैंपलों में एंटीबायोटिक्स तय स्तर से ज्यादा पाए गए।

इन तमाम तथ्यों पर गौर करने पर हम पाते हैं कि सभी प्रमाण दुग्ध से जुड़ी दो धारणाओं के उलट हैं। खाद्य सुरक्षा नियंत्रक का हमेशा ही मानना रहा है कि दूध में मिलावट की सबसे अधिक समस्या उत्तर भारत के राज्यों में पाई जाती है। 2017 में हुए एक सर्वे में पाया गया था कि नकली दूध के मामले में उत्तर भारत के राज्य अव्वल हैं। लेकिन इस ताजा सर्वे में सबसे खराब सैंपल वाले पहले तीन राज्यों में दो-तमिलनाडु और केरल दक्षिण भारत के ही हैं। लिहाजा यह सर्वे इस मिथक को तोड़ने में कामयाब रहा है कि उत्तर भारत में मिलावट की सबसे अधिक समस्या है।

दूसरा मिथक यह रहा है कि भारत में सुरक्षित और उपभोग योग्य दुग्ध विरले ही पाए जाते हैं। एक ऐसी छवि बनी हुई है जिसमें दूध और डेयरी उत्पादों को संदेह की नजर से देखा जाता है। लेकिन इस ताजा सर्वे ने यह साफ कर दिया है कि महज देशभर में सात फीसद ही दूध और डेयरी उत्पाद ऐसे हैं जो उपभोग के योग्य नहीं हैं। हालांकि दिसंबर 2018 में भी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा राज ने यह साफ किया था कि मिलावटी दूध के मामलों में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने साफ किया कि खराब फार्म से आए नमूने ही प्रदूषित पाए गए हैं। जाहिर है इस नए सर्वे ने इन दो मिथकों को तोड़ने का काम किया है।

यकीनन इस सर्वे से डेयरी उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी और दूध के कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ भी पहुंचेगा। लेकिन फिर भी कई मोर्चों पर काम किए जाने की जरूरत है। यह कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दुग्ध से जुड़ा मसला हमारी सेहत से जुड़ा है। दुग्ध के नमूनों में मिलने वाले एफ्लाटॉक्सिन-एम1, माल्टोडेक्सट्रिन और चीनी जैसे दूषित पदार्थों की संभावित मात्रा से अधिक उपस्थिति चिंता का विषय होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि दूध या दूध से बनने वाले पदार्थों की जांच सालाना के बजाय तीन या छह महीनों के अंतराल पर कराई जाए। समझने की जरूरत है कि यह हमारी सेहत से जुड़ी बात है और इसमें ज्यादा अंतराल पर्यावरणीय समस्या और विभिन्न तरह की बीमारियों वाले माहौल में एक बड़े खतरे का कारण बन सकता है। एफ्लाटॉक्सिन-एम1, यूरिया, डिटर्जेंट जैसे कैंसर को जन्म देने पदार्थों की मिलावट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। समझना होगा कि जब अर्थव्यवस्था की तिमाही जांच की जा सकती है तो खाद्य व्यवस्था की क्यों नहीं। जबकि यह हमारी जिंदगी से जुड़ा मसला है।

इसके अलावा दूध उत्पादन के सबसे निचले चरण के लोग यानी साधारण किसान और पशुपालकों के लिए सही व्यवस्था करने की जरूरत है। सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि पशुओं के चारे, जरूरी उपकरण, आर्थिक मदद आदि को सुनिश्चित किया जाए। इस तरह की मदद से किसानों की आमदनी में इजाफ होगा और तभी दूध में मिलावट की संभावना पर लगाम लग सकेगी। इससे इतर देखें तो देश में संगठित डेयरी उद्योग के समांतर विशाल असंगठित सेक्टर एक चिंता का विषय है। गली-मोहल्लों में नगर निगमों और जिला प्रशासनों की नाक के नीचे ऐसी डेयरियां धड़ल्ले से चल रही हैं जहां प्राधिकरण के मानक तो बहुत दूर की बात हैं बुनियादी साफ सफाई की ओर भी कम ही ध्यान दिया जाता है। फिर ऐसी डेयरियों पर भी लगाम कसने की जरूरत है।

हालांकि सरकार ने परीक्षण और सैंपलिंग से जुड़ी एक योजना को भी अगले साल से शुरू किए जाने का प्रस्ताव रखा है। प्राधिकरण की मानें तो मिलावट की जांच के लिए एक विशेष परीक्षण किट भी विकसित किया गया है, लेकिन इस किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण अभी नहीं किया जा सका है। कुल मिलाकर दूध को अभी सौ फीसद सुरक्षित बनाने की दिशा में संजीदगी से पहल करने की जरूरत है।

6 बजे सुबह अब मंगला आरती की जाएगी बरसाना स्थित श्रीजी मंदिर में। श्रृंगार आरती सुबह साढ़े आठ बजे, राजभोग आरती दोपहर डेढ़ बजे होगी। उसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। शाम साढ़े चार बजे मंदिर के पट खुलेंगे। मौसम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 30 अक्टूबर 2019

डाटागीरी

पृथ्वी में मौजूद है कुल 1.85 अरब गीगाटन कार्बन

पृथ्वी पर मौजूद कुल कार्बन का मात्र 0 .2 प्रतिशत ही ऊपरी वायुमंडल और महासागरों में पाया जाता है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की ओर से किए गए अध्ययन में यह जानकारी दी गई है। अध्ययन के मुताबिक पूरी पृथ्वी में 1.85 अरब गीगाटन कार्बन मौजूद है। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्वालामुखियों के जरिए होता है उससे कहीं गुना अधिक उत्सर्जन मानवीय गतिविधियों से होता है।

28 से 36 करोड़ गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है प्रति वर्ष

40 से लेकर 100 गुना तक ज्वालामुखी के उत्सर्जन से ज्यादा होता है मानवीय कारणों से उत्सर्जन

डीप कॉर्बन ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट की एक शृंखला जारी की गई है। प्रतीकात्मक

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की ओर से किए गए एक दस साल के प्रोग्राम डीप कॉर्बन ऑब्जर्वेटरी (डीसीओ) की रिपोर्ट की एक शृंखला जारी की गई है। इसके माध्यम से पृथ्वी पर कुल कार्बन का अनुमान लगाया गया है। इसमें ज्वालामुखियों द्वारा उत्सर्जित कुल कार्बन डाइऑक्साइड का विश्लेषण भी शामिल है। बताया गया है कि पृथ्वी में कार्बन का जितना उत्सर्जन मानव गतिविधियों की वजह से होता है उसकी तुलना में ज्वालामुखियों से होने वाला उत्सर्जन बहुत कम है।

ज्वालामुखियों और अन्य प्राकृतिक और मानवीय कारणों से प्रत्येक वर्ष 28 से 36 करोड़ टन कॉर्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिसमें से केवल मानवीय गतिविधियों जैसे- जीवाश्म ईंधन जलाने, जंगल जलाने आदि से प्रतिवर्ष होने वाला कार्बन उत्सर्जन ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित कार्बन की तुलना में 40 से 100 गुना अधिक होता है। पृथ्वी के कुल कार्बन का मात्र 0.2 प्रतिशत (43,500 गीगाटन) महासागरें, सतह और वायुमंडल में है। बाकी का 1.845 गीगाटन पृथ्वी के अंदरूनी सतह पर है।

ऊपरी वायुमंडल में मात्र 0.2 फीसद है कार्बन

जमीन के नीचे	
निचली परत में	1.5 अरब गीगाटन
महाद्वीप और महासागरीय स्थलमंडल में	31.5 करोड़ गीगाटन
ऊपरी परत में	3 करोड़ गीगाटन
ऊपरी वातावरण में	
गहरे समुद्र में	37000 गीगाटन
समुद्र की तलछट में	3000 गीगाटन
स्थलीय जीवमंडल में	2000 गीगाटन
समुद्र की सतह पर	900 गीगाटन
वातावरण में	590 गीगाटन

प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देश

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक देश चीन (27 प्रतिशत) है। इसके बाद अमेरिका (15 प्रतिशत) दूसरे और यूरोपीय यूनियन (10 प्रतिशत) तीसरे स्थान पर है। चौथे नंबर पर भारत (सात प्रतिशत) है। दुनिया के कुल उत्सर्जन में इन चार जगहों की 58 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विश्व के बाकी देश समग्र रूप से 42 फीसद उत्सर्जन करते हैं।

जागरण विशेष ▶ आइआइटी मंडी ने तैयार किया रोबोट, आग से पार पाना होगा आसान

आग से बचाएगा 'द फायर वॉरियर'

देश में उपलब्ध नहीं हैं अग्निशमन और बचाव में कारगर ऐसे उपकरण

हंसराज सैनी, मंडी

बहुमंजिला भवनों में अब आग से पार पाना आसान होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी, हिमाचल प्रदेश के प्रशिक्षुओं ने द फायर वॉरियर नाम से फायरफाइटिंग रोबोट तैयार किया है, जो आग बुझाने व भवन में फंसे लोगों को तलाश करने में मदद करेगा। इससे समय रहते आग पर काबू पाना संभव होगा, साथ ही जान-माल की क्षति को भी रोका जा सकेगा।

अग्निशमन कर्मी ऐसी कारगर युक्ति की मांग लंबे समय से करते आए हैं। विदेश में ऐसी युक्तियां अमल में आ चुकी हैं, लेकिन भारत में अग्निशमन व बचाव कार्यों में अब भी पुराने तौर-तरीकों को ढोया जा रहा है। आग की घटनाओं से देशभर में हर साल जान-माल का भारी नुकसान होता है। आग बुझाते समय दमकल कर्मियों को भी जान से हाथ धोना पड़ता है। यह रोबोट इन सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है। अग्निशमन कर्मियों का कहना है कि इस तरह के तकनीकी उपायों को जल्द से जल्द व्यावहारिक अमल में लाने की आवश्यकता है।

आइआइटी के छात्रों ने बताया कि यह रोबोट मौके पर दमकल कर्मियों की जगह भी काम करने में दक्ष होगा। अग्निशमन कर्मी भी घटनास्थल के बाहर से इसे आसानी से संचालित कर सकेगा।

रोबोट उच्चक्षमता के कैमरे और जीपीएस से लैस होगा, जिससे आग प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को आसानी से खोजा और बचाया जा सकेगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष के छात्रों ने मिलकर यह रोबोट बनाया है।

इसके अलावा संस्थान के एमटेक के तीन छात्र-छात्राओं ने जीएसएम आधारित फायर सेफ्टी अलर्ट सिस्टम भी ईजाद किया है। यह सिस्टम बिजली, आग व गैस से भवनों को बचाएगा। इस तकनीक को टेक फेस्ट में प्रथम पुरस्कार मिला है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

यदि अमल में लाया गया यह रोबोट तो बहुमंजिला भवनों में आसान हो जाएगा बचाव कार्य

लाइव कैमरे की मदद से फंसे लोगों तक पहुंचा जा सकेगा

अंतिम रूप दिए जाने के बाद ऐसा दिखेगा 'द फायर वॉरियर' रोबोट। साभार : आइआइटी, मंडी

आग से जान-माल का नुकसान कम करने व संभावित खतरे का अलर्ट देने के लिए आइआइटी के छात्रों ने द फॉयर वॉरियर नामक रोबोट व अलर्ट सिस्टम ईजाद किया है। इससे आग की घटना से निपटने में आसानी होगी।

-प्रो. टिमोथी ए गोंजाल्विस, निदेशक, आइआइटी मंडी

आइआइटी के छात्रों ने बताया कि यह रोबोट मौके पर दमकल कर्मियों की जगह भी काम करने में दक्ष होगा।

देशभर में दमकल विभाग के पास अब तक इस तरह के उपकरण व रोबोट उपलब्ध नहीं हैं। दमकल कर्मियों को ही हर स्थिति में जूझना पड़ता है। मुंबई दमकल विभाग के पास जो रोबोट हैं, वे सिर्फ पानी की पाइप को आग वाले स्थल तक लेकर जाते हैं। सेंसर और कैमरायुक्त रोबोट दमकल विभाग के लिए सोने पर सुहागा होगा। इससे आग में फंसे लोगों का पता लगाने में आसानी होगी। जानमाल का नुकसान भी कम होगा।

-दिनेश सागर, फायर स्टेशन ऑफिसर, मंडी

ताजमहल में होगा वाटर चैनल का संरक्षण

ताजमहल में इसी वाटर चैनल के खराब हुए पत्थरों को बदला जाना है। जागरण

जागरण संवाददाता आगरा : दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताजमहल के वाटर चैनल का संरक्षण किया जाएगा। खराब हुए पत्थरों को बदला जाएगा। सेंट्रल टैंक में प्वॉइंटिंग का काम किया जाएगा। यहां खराब हुए कुछ पत्थर भी बदले जाएंगे। इस पर करीब 20 लाख रुपये खर्च होंगे।

ताज का उद्यान मुगलकालीन चारबाग पद्धति पर बना हुआ है। इसमें वाटर चैनल भी बने हुए हैं। वीडियो प्लेटफार्म से सेंट्रल टैंक होते हुए मुख्य मकबरे तक जाने वाले वाटर चैनल में फव्वारे चलते हैं। वीडियो प्लेटफार्म से मुख्य मकबरे तक जाने वाले वाटर चैनल का संरक्षण करने की योजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने बनाई है। इसमें वाटर चैनल के दोनों ओर के 80 फीसद तक खराब हो चुके रेड सैंड स्टोन को बदलकर नए पत्थर लगाए जाएंगे। सेंट्रल टैंक में लीकेज रोकने को प्वॉइंटिंग का काम होगा। अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि ताज में वाटर चैनल के संरक्षण का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा।

गीता जयंती पर गीताप्रेस देगा नायाब तोहफा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

गीता जयंती पर गीता प्रेस आम जनमानस को नायाब तोहफा देने जा रहा है। हिंदी-संस्कृत भाषा में पहली बार सचित्र ग्रंथाकार गीता प्रकाशित की जाएगी। गीता जयंती (आठ दिसंबर) तक इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसका मूल्य अभी तय नहीं हो सका है। पुस्तक में चित्रों की पर्याप्त संख्या रहेगी। मूल श्लोक के साथ उसका अर्थ भी दिया जाएगा।

गीताप्रेस 15 भाषाओं में धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करता है। हर भाषा में छोटी-बड़ी आकार की अब तक कुल 14.50 करोड़ से अधिक गीता की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। गीताप्रेस की शुरुआत ही गीता के प्रकाशन से 1923 में हुई थी। गीताप्रेस पहली बार ग्रंथाकार सचित्र गीता का प्रकाशन करने जा रहा है। इसमें समाहित सभी चित्र गीताप्रेस के कलाकारों द्वारा बनाए गए हैं।

गीता का प्रकाशन 15 भाषाओं में लगातार हो रहा है। इस बार गीता जयंती से पहले एक विशेष तरह की ग्रंथाकार गीता का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें चित्रों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और यह चार रंगों में प्रकाशित की जाएगी। तैयारियां चल रही हैं।

-लालमणि तिवारी, उत्पाद प्रबंधक, गीताप्रेस

प्रतीकात्मक

किस भाषा में कितने प्रकार की गीता

हिंदी-संस्कृत	33	असमिया	02
अंग्रेजी	06	उड़िया	14
बंगला	08	उर्दू	02
मराठी	12	तेलुगु	11
गुजराती	12	मलयालम	02
तमिल	08	पंजाबी	01
कन्नड़	07	नेपाली	03

गीता जयंती तक प्रकाशित हो जाएगी ग्रंथाकार गीता

हिंदी-संस्कृत में पहली बार प्रकाशित होगी सचित्र गीता

गीता की बिक्री

हिंदी-संस्कृत	10,26,76,750
अंग्रेजी	33,51,850
तेलुगु	79,72,500
बंगला	47,14,500
मराठी	26,36,000
असमिया	2,21,500
तमिल	17,80,400
नेपाली	61,000
गुजराती	1,05,87,000
मलयालम	3,37,000
कन्नड़	35,22,700
उड़िया	72,08,500
पंजाबी	3,000
उर्दू	26,000

उत्तराखंड में हादसे ले रहे बेजुबानों की जान

केदार दत्त, देहरादून

19 साल में दुर्घटनाओं में मारे गए 133 गुलदार, 64 हाथी व 15 बाघ

वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे उत्तराखंड में विकास और जंगल में सामंजस्य का अभाव बेजुबानों पर भारी पड़ रहा है। लगातार हो रहे हादसे वन्यजीवों की जान ले रहे हैं। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। इन पर गौर करें तो 2001 से लेकर मार्च 2019 तक के वक्फे में 212 हाथी, गुलदार व बाघों की जान दुर्घटनाओं में गई है। इस सबने महकमे को भी सोचने पर विवश कर दिया है। हादसे थामने के मद्देनजर शासन ने वन विभाग से कार्ययोजना मांगी है, ताकि बेजुबानों की जान बचाने को प्रभावी ढंग से कदम उठाए जा सकें। यह किसी से छिपा नहीं है कि तमाम दुश्वारियां झेलने के बावजूद राज्य ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। बाघों व हाथियों का लगातार बढ़ता कुनबा इसकी बानगी है। यह सुकून देने वाली बात है, मगर तस्वीर का दूसरा पहलू चौंकाने वाला है। जंगलों से गुजर रहे रेल व सड़क मार्गों के साथ ही बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप ने बेजुबानों की मुसीबत बढ़ाई है। नतीजा, बढ़ते हादसों के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें बेजुबान जान गंवा रहे हैं।

वसरकारी आंकड़ों को ही देखें तो 19 साल में दुर्घटनाओं में 133 गुलदारों की मौत हुई। इसी प्रकार इस अवधि में 64 हाथी और 15 बाघ भी हादसों में मारे गए। इन तीनों वन्यजीवों को ही लें तो हर साल औसतन 11 की जान जा रही है। इससे महकमे के साथ ही वन्यजीव विशेषज्ञ भी चिंतित है। उनका कहना है कि हादसे थामने को जरूरी है कि जंगल और विकास में बेहतर सामंजस्य जरूरी है। इसे लेकर शासन स्तर पर भी मंथन शुरू हो गया है, ताकि प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर इसे धरातल पर उतारा जा सके।

हादसे थामने के मद्देनजर शासन ने वन विभाग से मांगी कार्य योजना

प्रतीकात्मक

हादसों में मारे गए वन्यजीव

वर्ष	हाथी	गुलदार	बाघ
2001	02	00	00
2002	00	00	00
2003	01	00	00
2004	02	00	00
2005	04	04	00
2006	02	04	00
2007	04	03	02
2008	03	07	00
2009	02	01	00
2010	02	09	00
2011	06	14	03
2012	00	17	03
2013	03	09	00
2014	08	08	03
2015	05	09	00
2016	06	11	02
2017	09	25	02
2018	04	10	00
2019 (मार्च तक)	01	02	00

'दुर्घटनाओं के साथ ही अन्य मामलों में वन्यजीवों की मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही दुर्घटनाएं थामने को विभाग से कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि इस दिशा में कदम उठाए जा सकें।'

-आनंदवर्द्धन, प्रमुख सचिव वन

'दुर्घटनाओं को रोकना बड़ी चुनौती है। इस दिशा में विभाग गंभीर है। जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की गाइडलाइन के हिसाब से कार्ययोजना तैयार की जाएगी।'

-राजीव भरतरी, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक

नींबू और संतरे से बनाईं विशाल कलाकृतियां

फोटो न्यूज

2010 में शुरू किया गया था यह अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल

54 प्रतिशत नींबू पूरे तुर्की का मर्सिन शहर से ही आता है। 29 फीसद मुसम्मी का भी होता है उत्पादन

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली : तुर्की के मर्सिन शहर में नींबू और संतरे से यह विशाल और आकर्षक आकृतियां तैयार की गई हैं। यहां पर अंतरराष्ट्रीय मर्सिन साइट्रस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मर्सिन की सबसे प्रमुख फसल साइट्रस फ्रूट हैं। यहां पर पूरे तुर्की का 54 प्रतिशत नींबू, 29 प्रतिशत मुसम्मी, 14 प्रतिशत संतरा और तीन प्रतिशत चकोतरा होता है। वर्ष 2010 से इस अंतरराष्ट्रीय साइट्रस फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मर्सिन में साइट्रस फ्रूट और शहर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है।

कई देश लेते हैं हिस्सा

इस अंतरराष्ट्रीय साइट्रस फ्रूट फेस्टिवल में दुनियाभर के कई देश हिस्सा लेते हैं। इसमें अल्बानिया, अल्जीरिया, अजेरबाइजान, बेलारूस, बोस्निया, बुल्गारिया आदि शामिल हैं। इस दौरान नींबू, संतरे आदि से बनाई विभिन्न आकृतियों की परेड का आयोजन किया जाता है। इसमें दुनियाभर के स्मारक और जीव-जंतु बनाए जाते हैं।

तैयारी

नोएडा के सेक्टर-145 में बन रहा है इंस्टीट्यूट, 18 महीने का लक्ष्य, कई हजार टन वजनी मालवाहक ट्रेनों व उनके एलिवेटेड ट्रैक पर होगा शोध, ऑस्ट्रेलिया से आएंगी अत्याधुनिक मशीनें

15 नवंबर से बनना शुरू होगा हैवी हॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट

अर्पित त्रिपाठी, नोएडा

देश में माल ढुलाई में तेजी लाने व रेलवे मार्ग पर यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी समयबद्धता सुधारने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर पर कई हजार टन लेकर मालवाहक ट्रेन दौड़ेंगी। इस कॉरिडोर को और सुविधाजनक बनाने के साथ ही रेलवे की तकनीक को और विकसित करने के लिए देश का पहला हैवी हॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एचएचआरआइ) 15 नवंबर से नोएडा के सेक्टर-145 में बनना शुरू हो जाएगा। इसके सिविल का कार्य नोएडा की कंपनी हिमकोन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड करेगी। सिविल कार्य पूरा करने का लक्ष्य 18 महीने का रखा गया है। इसके बाद यहां ऑस्ट्रेलिया से अत्याधुनिक मशीनें, उपकरण आदि लाए जाएंगे। इसी जगह पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआइएल) का कमांड कंट्रोल रूम भी बनेगा। 2021 तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

सेक्टर-145 में 22.5 हेक्टेयर जमीन पर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। इसके अलावा यहां शोध किया जाएगा। शोध का विषय हैवी हॉल (भारी भरकम चीजों को एलिवेटेड ट्रैक पर चलाना) होगा। इस विषय पर रेलवे के इंजीनियर रिसर्च करेंगे, जिसके बाद उस तकनीक का प्रयोग भारतीय रेलवे में किया जाएगा। डीएफसीसीआइएल के मुताबिक भविष्य में हमें ऐसे रेलवे ट्रैक चाहिए, जो जमीन पर न बनाकर हवा में यानी एलिवेटेड तर्ज पर बनाए जाएं। इन ट्रैकों पर 1.5 किलोमीटर की मालगाड़ी चलेंगी, जिनका लोड के साथ वजन करीब 13.5 हजार टन के आसपास होगा। इनकी क्षमता को और बढ़ाने, ट्रैक पर ट्रैफिक कम करने, माल को जल्द से जल्द गंतव्य तक पहुंचाने आदि पर यहां शोध होगा। यहां अधिकारियों व शोधार्थियों के लिए आवास भी बनेगा। इन ट्रैकों पर ऐसी मालवाहक ट्रेन दौड़ेंगी, जिनमें एक के ऊपर एक ट्रक खड़े होकर गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। कंटेनर रूपी इन डिब्बों की उंचाई भी काफी होगी।

15 नवंबर से देश का पहला हैवी हॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनना शुरू हो जाएगा। नोएडा की एक कंपनी को इसकी सिविल का कार्य सौंपा गया है जिसे 18 महीने में कार्य पूरा करना है। इसके बाद यहां अत्याधुनिक मशीनें व उपकरण लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। 2021 में फ्रेट कॉरिडोर के साथ ये भी शुरू हो जाएगा।

-वाइपी शर्मा, उप मुख्य परियोजना प्रबंधक, नोएडा इकाई, डीएफसीसीआइएल

आस्ट्रेलिया से आएंगे सभी उपकरण, विदेशी विशेषज्ञ करेंगे शोध की शुरुआत

डीएफसीसीआइएल के मुताबिक सिविल कार्य पूरा होने के बाद सभी उपकरण व मशीनें आस्ट्रेलिया से आएंगी। इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। शुरुआत में विदेशी विशेषज्ञ यहां शोध करेंगे। दरअसल विदेशं में मालवाहक ट्रेनों के लिए अलग से ट्रैक हैं, जिन पर शोध होते रहते हैं। कई देशों के विशेषज्ञ यहां आकर भारतीय रेलवे के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के साथ ही शोध भी करेंगे। शोध में भौगोलिक स्थित को ध्यान में रखकर ट्रैक को अपग्रेड करेंगे। साथ ही मालवाहक ट्रेनों की क्षमता, गुणवत्ता, स्पीड आदि पर भी कार्य किया जाएगा।

मदरसे में पढ़ाई जा रही गीता और कुरान

तेज प्रकाश सैनी, मुरादाबाद

भगतपुर टांडा के गांव चांदपुर गढ़ी के कादरी नगर में मदरसा अलजामिया मक्किया खजाइनुल इरफान में बच्चे कुरान के साथ ही गीता व संस्कृत पढ़ रहे हैं। गीता में कृष्ण को अर्जुन द्वारा दिए गए उपदेश मदरसे के बच्चों को विशेष रूप से बताए जाते हैं। संस्कृत की किताब भी बच्चे पढ़ रहे हैं। यही नहीं रोजाना सुबह योग की कक्षा भी यहां लगती है।

संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है। वेदों की इस भाषा की तालीम मुस्लिम बच्चे भी ले रहे हैं। मजहबी जुबान कही जाने वाली संस्कृत हिंदू-मुस्लिम मजहब को मजबूत करने के लिए इस मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। वेद ग्रंथ क्या हैं और इसके इतिहास को मदरसे में बताया जा रहा है। बच्चों को संस्कृत के श्लोक कंठस्थ हैं।

मुस्लिम शिक्षक फहीम व मुहम्मद इरफान पढ़ा रहे हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र कालेज के प्रोफेसर डॉ. अहमद रजा बच्चों को ऑनलाइन संस्कृत पढ़ा रहे हैं। समय-समय पर मदरसे में आकर संस्कृत के साथ गीता का सार पढ़ाते हैं। छात्र मुहम्मद नदीम, फैजान व रेहान संस्कृत में होशियार हैं। वर्ष 2011 में शुरू हुए इस मदरसे में वेदों के ज्ञान को उर्दू व फारसी में पढ़ाने के लिए किताब भी लिखवाई जा रही है।

मुल्क को समझना है तो मुस्लिम बच्चों को संस्कृत आनी चाहिए : जहीर

मदरसे के अध्यक्ष सूफी जहीर आलम कादरी ने बताया कि हिंदू व मुस्लिम कल्चर में ज्यादा अंतर नहीं है, यह अंतर इंसान की सोच ने बढ़ाया है। यह बहुत बड़ी कमी रही है कि संस्कृत को मदरसों से दूर रखा। संस्कृत वेदों की भाषा है, अपने मुल्क को समझना है तो मुस्लिम बच्चों को संस्कृत आनी चाहिए। इसी में गीता के उपदेश हैं।

श्रीकृष्ण के अलावा पढ़ाया जा रहा राम का जीवन चरित्र : प्रबंधक इरशाद कादरी कहते हैं कि संस्कृत में गीता का सार आसानी से समझ में आए इसके लिए छोटे-छोटे माडल तैयार किए गए हैं, जिसमें गीता का ज्ञान भी है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए थे वह भी मुस्लिम बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। राम का जीवन चरित्र भी पढ़ाया जा रहा है।

गीता में श्रीकृष्ण उपदेश बच्चों को विशेष रूप से बताए जा रहे

संस्कृत पढ़ रहे मदरसे के बच्चों को श्लोक कंठस्थ

मुरादाबाद के मदरसा अलजामिया मक्किया खजाइनुल इरफान में बच्चों को संस्कृत पढ़ाते शिक्षक। जागरण

सैकड़ों महिलाओं की प्रेरणा बनी यह किसान बिटिया

धार, मप्र : खेत में काम करती रंजना बास्केल। नई दुनिया

प्रेमविजय पाटिल, धार

- दो साल के परिश्रम और सूझबूझ से पिता की चार बीघा जमीन को बना दिया मुनाफे का सौदा
- सात गांवों की सैकड़ों महिलाओं को खेती में सक्रिय भागीदारी के लिए किया तैयार

मप्र के धार जिले की 24 वर्षीय रंजना वास्केल ने न केवल पिता की 4 बीघा जमीन को मुनाफे का सौदा बना दिया, बल्कि 7 गांवों की सैकड़ों महिलाओं को खेती में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार कर दिया है।

रंजना ने परंपरागत कृषि की जगह उद्यानिकी को आजमाया। उनका यह प्रयोग सफल रहा। दो साल के भीतर ही आज वह महज चार बीघा जमीन के बूते भी अपनी और अपने परिवार की आजीविका चलाने योग्य हो गई हैं। रंजना की यह सफलता क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गई है। आसपास के सात गांवों की 200 अन्य महिलाएं और युवतियां रंजना के नक्शेकदम पर चल पड़ी हैं। रंजना की तरह ही छोटी जोत वाले गरीब परिवारों से जुड़ीं ये महिलाएं अब दूसरों के खेतों में मजदूरी करने की जगह अपने छोटे से खेत में सब्जियां पैदा कर आत्मनिर्भर होने लगी हैं।

नारी सशक्तीकरण

रंजना गरीब आदिवासी परिवार की बेटी है। मनावर तहसील के ग्राम उदयीपुर में पिता की मात्र 4 बीघा जमीन होने की वजह से मजदूरी करने की नौबत आ गई। पढ़ने की चाह थी, लेकिन आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। 100 रुपये रोजनदारी पर लोगों के खेतों में काम करना पड़ा। लेकिन इस दौरान रंजना को एक बात समझ में आई कि अपने खेत में ही इतना श्रम कर लिया जाए तो आर्थिक शोषण से बचा जा सकता है।

आत्मनिर्भर होने के लिए रंजना ने 2017 में पिता के साथ खेती का काम शुरू किया। छोटा भाई दसवीं में पढ़ रहा है। ऐसे में उसे पढ़ाई के लिए पूरा अवसर दिया और खुद चार बीघा खेती को मुनाफे का सौदा बनाने में जुट गई। आदिवासी युवती ने धीरे-धीरे खेत की सारी जिम्मेदारी संभाली और एक परिपक्व किसान के तौर पर अपने आप को तैयार कर लिया। हालांकि गरीबी के चलते ट्रैक्टर और अन्य साधनों की कमी महसूस करती हैं, लेकिन कहती हैं कि साधन से नहीं बल्कि इच्छाशक्ति से खेती करने की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि सोयाबीन, कपास, मक्का, गेंदा के फूल और मौसमी सब्जी की खेती करके रंजना अब मजदूरी को बाय-बाय कर चुकी है। रंजना की ख्याति चारों ओर फैली तो वे अपने ग्राम उदीयापुर, खंडलाई, शिरा खान बोरलाई, मोहाली, शाला कैमरा और जाकर में गरीब आदिवासी परिवारों की महिलाओं को भी इस विधा की जानकारी देने लगीं। यही नहीं, स्वयं सहायता समूह भी शुरू किया, जिसके माध्यम से अब तक 200 महिलाओं को मुनाफे की खेती करना सिखा चुकी हैं। रंजना कहती हैं, आमतौर पर यह धारणा होती है कि दो-चार बीघा जमीन वाले परिवारों को मजदूरी कर पेट पालना पड़ता है। लेकिन यदि छोटे से खेत में भी सूझबूझ के साथ खेती की जाए तो मजदूरी की नौबत नहीं आएगी। मैंने यही किया। अब दूसरों को भी सिखा रही हूं।

कृषि विज्ञान केंद्र जैसे सहयोगी विभागों तक भी छोटी जोत वाले किसान पहुंचें, तो उन्हें काफी जानकारी मिल सकती है। सभी युक्तियों के साथ काम किया जाए तो, निश्चित रूप से सफलता हाथ लगती है। मेरी प्रेरणा से अब इस इलाके की सैकड़ों महिलाएं मजदूरी करने की बजाय अपनी जमीन पर खेती में जुटी हुई हैं। जितना मजदूरी में कमा लेती थीं, उससे कहीं अधिक कमा रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, धार के प्रभारी डॉ. केएस किराड़ ने बताया कि रंजना क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। छोटी जोत वाले अनेक परिवारों ने उसकी सफलता से सीखा है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

मच्छरों की नापसंदगी बनेगी उनके खात्मे का हथियार

विक्सन सिक्वेरिया, कानपुर

- मच्छरों को नापसंद पौधों से रोक सकेंगे डेंगू-मलेरिया
- आइआइटी में तैयार सॉफ्टवेयर से मिलान और जल्द नतीजा आसान

मच्छर-मक्खियों की नापसंदगी ही उनके खात्मे का हथियार बनेगा। आइआइटी के बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायोइंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नितिन गुप्ता ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो बताएगा कि मच्छर और मक्खी को किन पौधों की गंध पसंद नहीं है। उन्हीं पौधों से इनका खात्मा किया जा सकेगा और लोगों को डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी।

डॉ.गुप्ता ने बताया कि प्रकृति में मौजूद पेड़-पौधों से निकलने वाली गंध को सूंघने के लिए मच्छर व मक्खियों की क्षमता अलग-अलग होती है। उनके अंदर 70 से 80 ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनसे यह कुछ पौधों को अधिक व कुछ को कम सूंघना पसंद करते हैं। इसके अलावा ऐसे पौधे भी हैं जिनसे ये दूर रहते हैं बल्कि उनकी गंध से दूर भाग जाते हैं।

मनुष्य के प्रति भी मच्छर व मक्खी खास गंध की वजह से आकर्षित होते हैं। मच्छर व मक्खियों के व्यवहार को लेकर कई शोध हो रहे हैं। इन शोध को करने में लंबा समय लगने के साथ बहुत खर्च आता है। डॉ. गुप्ता ने इसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार किया है। इससे फूल, पौधे, पेड़ व पत्तियों के गुण व उनकी गंध के साथ मच्छर एवं मक्खियों के प्रोटीन से मिलान आसान रहा। इससे वह परिणाम निकलकर जल्द सामने मिले जो लंबी शोध के बाद प्राप्त किए गए थे।

उन्होंने बताया कि कुछ मच्छर नीम के पेड़ से दूर भाग रहे थे जबकि कुछ पत्तियों पर आराम से बैठे थे। इसी तरह कुछ अन्य पेड़-पौधों के कल्चर लेकर मच्छर के प्रोटीन से मिलान किया गया तो बेहतर नतीजे सामने आए। उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर पर परीक्षण से अध्ययन करके असरदार दवाइयां बनाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही मच्छर और मक्खियों का प्रसार आसानी से रुकेगा।

देशभर की मिट्टी में पोषक तत्वों की भारी कमी, घट रही है उत्पादकता

रिपोर्ट ▶ प्रोजेक्ट की ताजा रिपोर्ट में सामने आया सच, बिगड़ रही मिट्टी की सेहत

पंजाब व हरियाणा को छोड़ देश के बाकी हिस्से में नाइट्रोजन की कमी

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

फर्टिलाइजर के असंतुलित प्रयोग से देश के ज्यादातर हिस्सों की मिट्टी में पोषक तत्वों की भारी कमी हो गई है। इसके चलते एक ओर जहां फसलों की उत्पादकता घट रही है वहीं कृषि उपज की पौष्टिकता पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कराये गये मृदा परीक्षण की रिपोर्ट में यह सच सामने आया है। देश के लगभग सभी हिस्सों की मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों कमी से कृषि उपज की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट से खेती में कई तरह की सहूलियत होने की संभावना है। इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीएआर) के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने बताया कि देश में औसतन 133 से 134 किलोग्राम यूरिया सालाना प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जा रही है। जबकि कुछ प्रदेशों और कुछ जिलों में यूरिया का प्रयोग 300 से 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सालाना हो रहा है। 'जागरण' से बातचीत में डॉक्टर महापात्र ने बताया सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट से कई तरह की जानकारी मिली है। मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जबर्दस्त कमी पाई गई है जिनमें जिंक, बोरॉन व गंधक प्रमुख है।

डॉक्टर महापात्र ने बताया, 'देश के 95 फीसद जमीन में नाइट्रोजन की कमी है। 90 फीसद जमीन में फॉस्फोरस और 55 फीसद जमीन में पोटाश की कमी है।' सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स समेत अन्य सभी पोषक तत्वों का होना जरूरी है।

देश में सालाना 133 से 134 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जा रहा है। प्रतीकात्मक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2015 में परंपरागत और जैविक खेती पर जोर देने की बात कही थी। मिट्टी में कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए जैविक खाद की तत्काल जरूरत है। जमीन की पूर्ण उर्वरता को बनाए रखना जरूरी है। महापात्र ने कहा, 'आइसीएआर का अपना अनुसंधान है, जिसमें जैविक खाद के साथ फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुत अधिक लाभप्रद होगा।' इन दोनों के बीच संतुलन बनाने से फसलों की उत्पादकता में 50 फीसद तक की वृद्धि हो सकती है।

देश में फर्टिलाइजर के संतुलन के बारे में महापात्र ने बताया 'देश की मिट्टी में फिलहाल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की 4-2-1 के अनुपात में प्रयोग की जरूरत है। जबकि देश में इस समय 7-3-1 के अनुपात में इन खादों का प्रयोग हो रहा है। इसका असर उपज की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसे लेकर किसानों में जागरुक करने की सख्त जरूरत है।

पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जरूरत से ज्यादा खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। देश के 14.5 करोड़ किसानों में से 10 करोड़ किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच कर उन्हें सॉयल हेल्थ कार्ड सौंप दिये गये हैं। स्वायल हेल्थ कार्ड पर दर्ज सूचनाओं के अनुरूप फर्टिलाइजर का प्रयोग करने की जरूरत है।

इस बारे में फर्टिलाइजर सचिव छबिलेंद्र राउल ने बताया कि वर्ष 2018-19 में खेती में कुल 320 लाख टन यूरिया खाद की खपत हुई। जबकि गैर-यूरिया खादों का प्रयोग 200 लाख टन रहा। सॉयल हेल्थ कार्ड परियोजना और नीम कोटेड यूरिया आने से यूरिया की खपत में कमी आई है।' राउल ने बताया कि आने वाले दिनों में जल्द फर्टिलाइजर का वितरण किसानों के सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। इससे फर्टिलाइजर का प्रयोग वैज्ञानिकों के सलाह के अनुसार होगा।

403 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर बनाया रिकॉर्ड

मनोज सिंह, रांची

- झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में हुई सुनवाई
- इससे पहले भी 350 याचिकाओं पर कर चुके हैं सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने एक दिन में 403 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले भी वो इस तरह का रिकॉर्ड कायम चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक दिन में करीब 350 से ज्यादा जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। इस बार उन्होंने अपने बनाए रिकॉर्ड को ही तोड़ा है। दरअसल, दीपावली के अवकाश से पहले हाई कोर्ट की अधिकतर बेंचों में जमानत याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा आरोपितों को राहत प्रदान की जा सके। क्योंकि दीपावली को लेकर हाई कोर्ट में एक सप्ताह का अवकाश है।

झारखंड हाई कोर्ट। फाइल

पहले भी बना चुके हैं रिकॉर्ड

इन दिनों जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में सिर्फ जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले भी उन्होंने करीब 350 याचिका पर सुनवाई की थी। बताया जाता है कि इस दौरान कोर्ट मास्टर सुनवाई के दौरान खड़े रहे, क्योंकि अदालत इन मामलों में इतनी तेजी से आदेश पारित कर रहा था कि उन्हें बैठने तक का मौका नहीं मिला। इस बार भी पहली पारी में ही उन्होंने 403 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रिकॉर्ड कायम किया है। अदालत अधिवक्ताओं से भरी थी, क्योंकि न जाने कब किस अधिवक्ता का मामला सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष आ जाए। खचाखच भरी अदालत में जस्टिस आर मुखोपाध्याय फाइल देखते हुए लगातार आदेश लिखवाते रहे और पहली पाली में 403 जमानत याचिकाओं पर आदेश पारित कर दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी पाली में अदालत में दिए आदेश पर हस्ताक्षर किये। क्योंकि जज के आदेश के बाद ही उसको निचली अदालतों को फैक्स भेजा जाता है और वहां पर हाई कोर्ट की शर्तों को पूरा करने के बाद आरोपित को जेल से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है।

...और रातों रात ही विसर्जित कर दिए गए छह लाख दीये

जागरण संवाददाता, अयोध्या : पिछले साल दीपोत्सव के बाद राम की पैड़ी पर बिखरे पड़े दीयों को लेकर हुई किरकिरी से सबक लेते हुए नगर निगम ने इस बार विशेष सावधानी बरती और रातों रात उन्हें विशेष रूप से बनाए गए डंपिंग स्थल पर विसर्जित कर दिया गया। सुबह दीपावली के दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पहुंचे तो वहां की सफाई देखकर प्रभावित हुए बिना न रह सके। स्वच्छता के इस अभियान में निगम के चार सौ कर्मी लगाए गए थे।

दीपोत्सव ने एक ओर जहां अयोध्या के पर्यटन विकास में नया अध्याय जोड़ा, तो दूसरी ओर नगर निगम ने भी स्वच्छता की अलख जगाई। दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण राम की पैड़ी ही रही। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित की अगुवाई में स्वयंसेवकों ने चार लाख नौ हजार नौ सौ 65 दीयों को जलाया था। सबसे बड़ी चुनौती इन दीयों को रात भर में ही हटाने की भी थी। नगर निगम के करीब चार सौ कर्मियों ने न केवल दीयों को हटाया, बल्कि रामकी पैड़ी की सफाई भी की। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर आयुक्त डॉ. नीरज शुक्ल ने स्वयं मौजूद रह कर निगम कर्मियों का हौसला बढ़ाया। इन दीयों को नगर निगम के डंपिंग स्थल पर विसर्जित किया गया।

गौरतलब है कि गत वर्ष दीपोत्सव के बाद दीये राम की पैड़ी पर ही पड़े रह गए थे। इस वजह से नगर निगम की खासी आलोचना हुई थी। इसीलिए नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए पहले से ही सफाई की रूपरेखा बनाई थी।

545 किलोमीटर पैदल चलकर जानी गंगा की सेहत

जागरण संवाददाता, कानपुर

- हरिद्वार से प्रयागराज तक 32 दिन में पूरी की पदयात्रा
- आइआइटी कानपुर के पूर्व छात्र ने की पड़ताल, केंद्र को सौपेंगे रिपोर्ट

नदियों के पानी की गुणवत्ता व जल स्तर मापने की तकनीक विकसित करने वाले आइआइटी कानपुर के पूर्व छात्र श्रीहर्षा ने हरिद्वार से प्रयागराज तक 32 दिन में 545 किमी पदयात्रा कर गंगा और उसके आसपास खेतों की पड़ताल की। उनकी रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्ष में गंगा जल साफ तो हुआ है लेकिन कानपुर, फर्रुखाबाद व फतेहपुर में सर्वाधिक प्रदूषण मिला। जाजमऊ में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां काला पानी गंगा में मिल रहा है। श्रीहर्षा यह रिपोर्ट जलशक्ति विभाग, नमामि गंगे व केंद्रीय जल आयोग को देंगे।

आइआइटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक व वाटर रिसोर्स एनर्जी से एमटेक करने वाले श्रीहर्षा ने 25 सितंबर से 26 अक्टूबर तक गंगा किनारे पदयात्रा कर प्रदूषण, जल स्तर व जलीय जंतुओं की स्थिति देखी। इस मिशन में गंगोत्री स्थित आश्रम के स्वामी पुष्करानंद भी शामिल रहे। श्रीहर्षा ने बताया कि गंगा व अन्य छोटी नदियों की स्थिति सुधरी है। ग्रामीण अब नदियों में कूड़ा नहीं फेंक रहे हैं। हालांकि शहरों में नदी किनारे व पुल पर प्लास्टिक के साथ पूजन सामग्री फेंकने पर रोक नहीं लग पा रही है। इसके अलावा नाले भी गंगा में गिर रहे हैं।

गंगा में गहराई कम : श्रीहर्षा ने पदयात्रा के दौरान तीन सौ से अधिक लोगों से गंगा व खेती किसानी के संबंध में बातचीत की। 80 से 90 साल के वह बुजुर्ग भी थे, जिनके समय में गंगा का पानी स्वच्छ हुआ करता था। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले गंगा में मछली, केंचुए व अन्य जलीय जीवों की भरमार थी। मगर, अब नजर नहीं आते। गंगा की गहराई बहुत कम हो चुकी है जिससे गर्मी के दिनों में कई स्थानों पर पानी सूख जाता है।

बस, दाल-रोटी चल जाए : कृत्सनम टेक्नोलॉजीज स्टार्टअप के संस्थापक श्रीहर्षा ने बताया कि गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों से बातचीत में यह बात भी सामने आई कि उन्हें अधिक मुनाफे की उम्मीद नहीं है। वह इतना ही सोचते हैं कि फसल की लागत निकल आए और घर की दाल-रोटी चल जाए।

केसर से महका कश्मीर

वाकई, कश्मीर की आबोहवा बदल रही है। कश्मीर में केसर की फसल तैयार हो चुकी है। श्रीनगर से करीब 13 किलोमीटर पहले जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांपोर में सड़क के दोनों ओर खेतों में किसानों को केसर उतारते देखा जा सकता है। अक्टूबर व नवंबर में केसर का सीजन होता है। इस बार अच्छी फसल से किसान काफी खुश है। दुनिया में सबसे महंगे मसालों में शुमार केसर की कीमत 200 से 250 रुपये प्रति एक ग्राम है। पांपोर के 226 गांव में केसर की खेती होती है और कश्मीर में करीब डेढ़ लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। किसानों को अपना केसर बेचने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश पर पांपोर में इस बार एक मंडी भी स्थापित की गई है। कामरान रशीद बट

जिला व सैन्य अस्पतालों में भी होगी मेडिकल की पढ़ाई

हिमांशु मिश्र, बरेली

देशभर में स्पेशलाइज्ड चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने बड़ा फैसला लिया है। अब देशभर के जिला चिकित्सालयों और रक्षा मंत्रालय से जुड़े 17 सैन्य अस्पतालों को टीचिंग हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। 2003 से पहले भी यह नियम लागू था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था।

एमसीआइ की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस (बीओजी) की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। एमसीआइ के एक सदस्य के मुताबिक, इसका काफी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। शिक्षकों की कमी के चलते परास्नातक की सीटें काफी कम हुआ करती थीं। चूंकि, अब मिलिट्री, एयरफोर्स अस्पतालों में भी पीजी के छात्रों की पढ़ाई संभव होगी तो परास्नातक की सीटें भी काफी बढ़ जाएंगी। इन अस्पतालों के सीनियर चिकित्सकों को भी अध्यापन कार्य का लाभ मिल पाएगा। वह टीचिंग गतिविधियों में शामिल होकर अपने अनुभव नए चिकित्सकों से साझा कर सकेंगे। हालांकि, कितने छात्र इन अस्पतालों में पढ़ाई कर पाएंगे अभी इस पर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है।

जिला अस्पतालों में ट्रेनिंग से होगा चिकित्सीय सुधार: मेडिकल कॉलेजों से एमडी, एमएस व अन्य परास्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को जिला अस्पताल में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा।

इससे उनकी विशेषज्ञता में निखार आएगा और आम लोगों को इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर भी उपलब्ध हो पाएंगे। अभी तक छात्र मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में ही ट्रेनिंग करते थे। इससे जिला अस्पतालों में लोगों को यह सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं। इस प्रस्ताव को एमसीआइ ने पास कर दिया है। हालांकि लागू करने के लिए खाका तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है।

बदले जाएंगे यहां के अस्पताल: टीचिंग हॉस्पिटल में रक्षा मंत्रालय के मिलट्री अस्पताल बरेली, मेरठ, पुणे, जालंधर, किरके, सिकंदराबाद, पठानकोट, आगरा, जबलपुर, रांची, रुड़की और श्रीनगर, एयरफोर्स हॉस्पिटल, कानपुर, कमांड हॉस्पिटल, पुणे, कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल, पुणे, बेस हॉस्पिटल, उधमपुर, एयरफोर्स हॉस्पिटल, जोरहट।

गधा मेला

उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार-झारखंड से पहुंचे व्यापारी, रितिक रोशन और रणवीर सिंह नाम वाले गधे आठ-आठ लाख में बिके

11 लाख में 'शाहरुख', 10 लाख में बिका 'सलमान'

जागरण संवाददाता, चित्रकूट

बॉलीवुड के शाह रुख खान का नाम मंदाकिनी के तट पर नरक चौदस के दिन शुरू होने वाले तीन दिवसीय ऐतिहासिक गधा मेले में भी सब पर भारी रहा। यहां सिने स्टार के नाम वाले गधों की बोली लाखों रुपये में लगी। सबसे महंगा शाहरुख खान नाम का गधा 11 लाख रुपये में बिका। सलमान खान नाम वाले गधे की कीमत 10 लाख रुपये लगी तो रितिक रोशन और रणवीर सिंह के नाम के गधे आठ-आठ लाख रुपये में बिके। स्टार नाम वाले हष्ट पुष्ट गधे जहां 25 हजार से शुरू होकर लाखों रुपये में बिके तो सामान्य गधे 20 हजार रुपये तक। मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक के व्यापारी आए। चित्रकूट का ऐतिहासिक गधा मेला रामघाट मंदाकिनी तट पर नयागांव के कटरा गूदर में लगता है। यहां गधे बॉलीवुड के हीरो हिरोइनों के नाम पर बिकते हैं।

औरंगजेब ने की थी मेले की शुरुआत : मेले की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब ने की थी। व्यापारी रमेश चंद्र और दिनेश कुमार ने बताया कि मशीनरी के अधिक इस्तेमाल और वैश्विक मंदी के कारण पशु व्यापार में गिरावट आई है। इसीलिए, मेले में अब कारोबारी कम हुए हैं। अच्छे गधों की मांग रहती है। इससे बिक्री में परेशानी नहीं होती।

चित्रकूट में दीपावली अमावस्या पर गधा मेले में खरीदारी करने आए विभिन्न क्षेत्रों के लोग। जागरण

पांच करोड़ से अधिक का कारोबार : गधा मेले में पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। कारोबारियों ने बताया कि अब अच्छी किस्म की नस्ल पर फोकस किया गया है। इससे गधों से काम लेना आसान होगा। गधा मेला बुधवार को भी लगा रहेगा।

दीपावली अमावस्या पर पांच दिवसीय दीपदान मेला में 40 लाख श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में डुबकी लगाकर दीप जलाए। कामतानाथ के दर्शन कर कामदगिरि की परिक्रमा की। धनतेरस से शुरू हुआ यह मेला भैय्या दूज को संपन्न हो गया। मेले में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु आए। भीड़ के आगे मेला क्षेत्र कम पड़ गया।

सुनी नहीं गई गुहार, श्रमदान से पुल किया तैयार

ज्ञानेंद्र सिंह, प्रयागराज

गांव की गर्भवती बहू को तड़पते और पत्थर खदान में घायल मजदूर के दर्द ने पुरालक्षन के चिरौंजीलाल कोल को झकझोर दिया था। क्षेत्र में बेलन नदी पर पुल न होने से इलाज के अभाव में कई जान पहले भी जा चुकी थी। अपने ब्लॉक मुख्यालय मांडा पहुंचने के लिए लगभग 32 किमी की दूरी तय करनी पड़ती थी। पुल के लिए कोई सुनने वाला न था। न अफसर और न ही जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देते थे। उनके निर्देश पर सर्वे आदि का काम होता था, मगर निर्माण नहीं। निराशा के इस दौर में श्रमदान ने जिले में कुछ ऐसा कर दिखाया जो मिसाल बन गया।

उद्यमशीलता की यह कहानी है यमुनापार के कोरांव तहसील में मांडा ब्लाक की। इस विकासखंड में बहने वाली बेलन नदी के दोनों तरफ 17 गांवों के लोग पुल न होने से परेशान थे। पुल न होने से लोगों को 26 किमी दूरी तय कर तहसील मुख्यालय और 72 किमी दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। दुश्वारी के इस दौर में पुरालक्षन गांव के चिरौंजी आगे आए, सैकड़ों लोगों को जोड़ा। फिर शुरू कर दिया पुल निर्माण। बेरी गांव के आनंद प्रकाश शुक्ला उर्फ बबलू शुक्ला तथा पुरालक्षन गांव के सदानंद दुबे से सबसे ज्यादा मदद मिली। दोनों ने चिरौंजी के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से आह्वान किया। फिर क्या था, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लगभग 16 सौ लोगों ने श्रमदान किया। तीन सौ से ज्यादा लोगों ने आर्थिक और निर्माण सामग्री के रूप में मदद की। किसी ने 10 हजार तो किसी ने 20 हजार रुपये दिए। कई लोगों ने सीमेंट की 20 से सौ बोरी तो कई लोगों ने सरिया, बालू और गिट्टी की मदद की। इस पुल के निर्माण में श्रमदान समेत लगभग 32 लाख रुपये का खर्च आया है। पुल लगभग तैयार है। केवल सड़क बाकी है, जो जल्दी बन जाएगी।

प्रयागराज के कोरांव के पुरालक्षन गांव में बेलन नदी पर श्रमदान से बना पुल। जागरण

फूले नहीं समा रहे ग्रामीण : ग्रामीणों की सहभागिता से बने पुल को देख लोग फूले नहीं समा रहे हैं। पुल निर्माण में सहयोग करने वाले घोरहई के बब्बू सिंह ने बताया कि पूरे इलाके के लोगों को काफी दिक्कत होती थी। अब पुल तैयार है और लोग अपनी लगन और मेहनत पर इतरा रहे हैं।

इन गांवों के लोगों को मिलेगा लाभ : पांडेयपुर, सिरावल, घोरहई, झरवनियां, बेरी, मडफ़ा, घूघा, सलैया, पियरी, कूदर, हाटा, पूरालक्षन, नेवढिया बयालिस, मझिगवां, पसेरा, गजाधरपुर। इन गांवों को लोगों को अब कई किमी घूमकर ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। पुल से अब मुख्यालयों की दूरी कम हो जाएगी।

सोने-चांदी के भाव में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : मंगलवार को सोने-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। दिन के कारोबार में पीली धातु 548 रुपये की गिरावट के साथ 38,857 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिकी। इसके साथ ही चांदी की कीमत में भी 1,190 रुपये की गिरावट देखी गई। यह 47,090 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव में बिकी। इससे पहले शुक्रवार के सत्र में सोना 39,405 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 48,280 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बंद हुए थे।

भारत के पास सक्षम नेतृत्व, टेक्नोलॉजी और युवा वर्ग हैं, जो अर्थव्यवस्था को गति देने में पूरी तरह सक्षम हैं।

— मुकेश अंबानी, चेयरमैन, आरआइएल

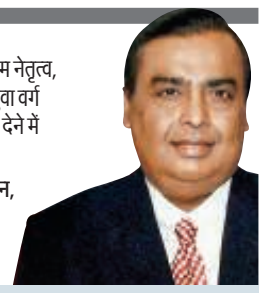

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
39,831.84	11,786.85	₹ 38,857	₹ 47,090	₹ 70.84	$ 60.92
▲ 581.64	▲ 159.70	▼ ₹ 548	▼ ₹ 1,190	▼ ₹ 0.06	

राहत ▶ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षतामें गठित समिति करेगी टेलीकॉम उद्योग की मांगों पर विचार

सचिवों की समिति देगी टेलीकॉम संकट का हल

एजीआर, स्पेक्ट्रम मूल्य में कमी, भुगतान में मोहलत समेत सभी पहलू होंगे शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्पेक्ट्रम लाइसेंस फीस और यूसेज चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट के आघातकारी के फैसले से हलकान टेलीकॉम उद्योग की चिंताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया है। यह समिति उद्योग की मांगों के साथ उसके लिए वित्तीय पैकेज की संभावनाओं पर विचार करेगी।

वित्त, विधि तथा संचार सचिवों की सदस्यता वाली समिति टेलीकॉम कंपनियों की वित्तीय स्थिति के सभी पहलुओं के साथ उन पर पड़ रहे अतिरिक्त दबाव का आकलन करेगी। टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से स्पेक्ट्रम की कीमत के भुगतान में समय की मोहलत देने के अलावा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में राजस्व का पांच फीसद योगदान करने की शर्त में ढील देने और इसे कम करने की भी मांग की है। समिति इन मांगों के औचित्य पर भी गौर करेगी।

इस समिति के साथ-साथ दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से भी टेलीकॉम कंपनियों की उस मांग पर विचार किए जाने की संभावना है जिसके तहत कंपनियां वॉयस और डाटा सेवाओं के लिए ग्राहकों से न्यूनतम शुल्क लेने की अनुमति चाहती हैं। यह मांग भारती एयरटेल और वोडाफोन जैसी उन पुरानी टेलीकॉम कंपनियों की ओर से रखी गई है जिनका रिलायंस जियो के बाजार में उतरने से पहले बाजार में दबदबा था। इनका कहना है कि ऐसा होने से संपूर्ण सेक्टर को सुनिश्चित मुनाफे के साथ लंबे समय तक के लिए वित्तीय मजबूती हासिल करने में मदद मिलेगी।

समिति टेलीकॉम कंपनियों की उस मांग पर भी मंथन करेगी जिसमें स्पेक्ट्रम नीलामी के 2020-21 और 2021-22 के लिए निर्धारित भुगतान शेड्यूल को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया गया है।

गौरतलब है कि पिछले बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम लाइसेंस फीस और यूजर चार्ज पर 16 साल तक चले मुकदमे के बाद दूरसंचार विभाग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनियों को उसे ब्याज और जुर्माने समेत कुल 1.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान का आदेश दिया था। कोर्ट ने दूरसंचार विभाग के एन्युअल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) में नॉन-कोर सेवाओं से प्राप्त राजस्व को भी शामिल करने के दूरसंचार विभाग के तर्क को सही ठहराया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही टेलीकॉम उद्योग में सन्नाटा पसरा हुआ है और कंपनियां सरकार से राहत की उम्मीद कर रही हैं। फैसले का सबसे बुरा असर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर पड़ा है जिन पर 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक की मार पड़ी है। वैसे तो फैसले का संबंध रिलायंस कम्यूनिकेशंस और एयरसेल समेत 13 अन्य टेलीकॉम कंपनियों से भी है। मगर इनमें से ज्यादातर या तो बंद हो चुकी हैं, या बंद होने की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। सबसे नई टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो तथा घाटाग्रस्त सरकारी कंपनियां- बीएसएनएल और एमटीएनएल इस मामले की पक्षकार नहीं थीं। लिहाजा उन पर इसका कोई प्रतिकूल असर पड़ने वाला नहीं है।

प्रतीकात्मक

ये हैं प्रमुख मांगें

- स्पेक्ट्रम शुल्क में कमी, नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम की कीमत के भुगतान में मोहलत तथा मोबाइल फोन कॉल दरों में बढ़ोतरी की जाए
- वॉयस और डाटा सेवाओं के लिए ग्राहकों से न्यूनतम शुल्क लेने की अनुमति दी जाए
- स्पेक्ट्रम नीलामी के 2020-21 और 2021-22 के लिए निर्धारित भुगतान शेड्यूल को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए

एयरटेल ने तिमाही नतीजे 14 नवंबर तक टाले

नई दिल्ली, प्रेट्र : टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने दूसरी तिमाही के नतीजे 14 नवंबर तक के लिए टाल दिए हैं। कंपनी का कहना है कि वह अपनी 42 हजार करोड़ रुपये की देनदारी पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। एयरटेल इसके लिए सरकार से छूट मिलने की उम्मीद में है। कंपनी की इस घोषणा के बाद इसके शेयरों में तीन परसेंट से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। गौरतलब है कि मंगलवार को एयरटेल को जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित करने थे। लेकिन कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि वह इन नतीजों को 14 नवंबर तक के लिए टाल रही है। एयरटेल ने अपने नोटिस में कहा है कि वह दूरसंचार विभाग से अपनी देयता को लेकर स्पष्टता की मांग की है। कंपनी ने सरकार से इसमें छूट के लिए भी आग्रह किया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में सीएसआर पर खर्च बढ़ाएं कंपनियां : सीतारमण

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय कारोबार जगत से आग्रह किया है कि वह अपना सीएसआर आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेशों में खर्च करें। वित्त मंत्री ने कंपनियों से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास कार्यों में खर्च करने का आग्रह किया। उन्होंने पिछले वर्ष कॉरपोरेट जगत द्वारा इस मद में किए गए खर्च की सराहना की। पिछले वर्ष कंपनियों ने कुल 13 हजार करोड़ रुपये कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधान के तहत खर्च किए थे।

सीतारमण ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में सीएसआर के तहत पर्याप्त धन खर्च होता है। इसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों में भी खर्च किया जाना चााहिए, जिससे इन राज्यों के विकास में मदद मिल सके।

पहली बार हो रहे नेशनल सीएसआर अवार्ड कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि बहुत कमाई कर लेना ही सम्मान पाने का आधार नहीं है। उस कमाई का एक हिस्सा समाज को वापस लौटाना असल में सम्मान पाने का आधार है। समाज से कमाई गई संपत्ति का हिस्सा समाज को वापस लौटा देना ही सीएसआर है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत कुछ बड़ी कंपनियों को अपने तीन साल के औसत मुनाफे का कम से कम दो परसेंट सीएसआर के तहत खर्च करना होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कंपनियों ने सीएसआर पर खर्च को गंभीरता से लेना शुरू किया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों ने सीएसआर के मद में 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया है। सरकार ने सीएसआर मद के खर्च को अनिवार्य किया हुआ था, जिसमें विफल रहने पर कंपनियों पर कानून के उल्लंघन का मामला चल सकता था। लेकिन इसी वर्ष अगस्त में कंपनियों के लिए उठाए गए सुधारवादी कदमों के तहत सरकार ने सीएसआर पर खर्च को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। हालांकि सरकार ने कंपनियों से बार-बार आग्रह किया है कि वे इस मद के खर्च को गंभीरता से लें, ताकि सामाजिक विकास के कार्यों को गति दी जा सके।

▶ वित्त मंत्री ने कारोबारी जगत से गरीबों पर भी सीएसआर खर्च बढ़ाने का किया आग्रह

प्रतीकात्मक

मेकमायट्रिप-गो और ओयो के खिलाफ जांच का आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म मेकमायट्रिप-गोआइबिबो (एमएमटी-गो) और एप आधारित होटल सर्विस कंपनी ओयो के खिलाफ कथित अनुचित कारोबारी व्यवहार की जांच का आदेश दिया है। इस बारे में 'होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया' (एफएचआरएआइ) ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत मिलने के बाद प्रतिस्पर्धा नियामक ने इन कंपनियों के कारोबार के विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद पाया कि प्रथम दृष्टि में प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन का मामला बनता है। सीसीआइ दो संबद्ध बाजारों के आधार पर इनके खिलाफ आरोपों का आकलन किया। मेकमायट्रिप-गोआइबिबो (एमएमटी-गो) देश में होटल की बुकिंग के लिए ऑनलाइन सेवाएं देती है। वहीं ओयो देश में बजट होटलों के लिए फ्रेंचाइजिंग सेवा बाजार है। मेकमायट्रिप ने गोआइबिबो का अधिग्रहण कर लिया है।

सीसीआइ ने कहा कि प्रथम दृष्टि में एमएमटी-गो संबद्ध बाजार में दबदबा रखती हैं। हालांकि ओयो बजट होटलों के लिए फ्रेंचाइजिंग सेवा की बड़ी कंपनी है, लेकिन वह अपने संबद्ध बाजार में दबदबे की स्थिति में नहीं है।

कानून के उल्लंघन का मामला : सीसीआई ने आदेश में कहा है कि एमएमटी-गो और ओयो के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 3(4) के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला बनता है। यह धारा प्रतिस्पर्धा रोधी करारों को रोकने से संबंधित है। वहीं एमएमटी-गो के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या धारा-चार के तहत जांच का मामला बनता है। यह धारा बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है। सीसीआइ के मुताबिक ओयो और एमएमटी के बीच कॉमर्शियल करार से ओयो को तरजीह मिलती है और इससे ट्रीबो, फैब होटल या कोई अन्य होटल चेन बाहर हो जाती हैं।

प्रतीकात्मक

▶ एफएचआरएआइ की शिकायत के बाद सीसीआइ ने की कार्रवाई

▶ नियामक ने इन्हें प्रथम दृष्ट्या पाया स्पर्धा नियमों के उल्लंघन का दोषी

ऑर्गेनिक उत्पादों की वैश्विक बाजार में बढ़ी मांग, खूब बढ़ रहा निर्यात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वैश्विक बाजार में भारत के आर्गेनिक कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसका नतीजा है कि इन उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। साल 2018-19 में ऐसे उत्पादों का निर्यात 49 परसेंट बढ़ा है। ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को हुआ।

एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) के आंकड़ों के मुताबिक बीते वित्त वर्ष देश से 75.7 करोड़ डॉलर से अधिक के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। जबकि इसके पिछले वर्ष 51.5 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था। वैश्विक बाजारों में जिन उत्पादों की सर्वाधिक मांग रही उनमें अलसी, तिल एवं सोयाबीन, अरहर, चना, चावल, चाय व औषधीय पौधे शामिल हैं। एपीडा के चेयरमैन पवन के. बड़ठाकुर ने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के अतिरिक्त कनाडा, ताइवान व दक्षिण कोरिया से भी इन उत्पादों का मांग बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त जर्मनी भी इन उत्पादों का बड़ा आयातक है।

एपीडा के चेयरमैन ने कहा कि भारत में वर्ष 2018-19 में 26.7 लाख टन प्रमाणित ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों का उत्पादन किया गया। इनमें तिलहन, गन्ना, मोटे अनाज, कपास, दलहन, औषधीय पौधे, चाय, फल, मसाले, मेवे, सब्जियां और कॉफी जैसे उत्पाद शामिल हैं। बड़ठाकुर ने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पाद केवल खाद्य उत्पादों तक ही सीमित नहीं है बल्कि कपास के रेशे और फंक्शनल फूड प्रोडक्ट भी इनमें शामिल हैं।

एपीडा के अनुसार ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है। जिंसों में सबसे ज्यादा उत्पादन तिलहन का होता है। बड़ठाकुर ने बताया कि 2018-19 में 6.14 लाख टन ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ।

ऑर्गेनिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए एपीडा बायोफैच इंडिया 2019 का आयोजन कर रहा है। तीन दिन तक चलने वाला यह मेला 7-9 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होगा। बड़ठाकुर ने कहा कि इस प्रदर्शनी में विदेश के निर्यातकों, प्रोसेसिंग कंपनियों, रिटेल चेन उद्योग, प्रमाणन संस्थाओं एवं उत्पादकों समेत 6,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

2018-19 में निर्यात में हुई 49 परसेंट की वृद्धि

प्रतीकात्मक

एसएफआइओ को डीएचएफएल की जांच सौंपने की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े डीएचएफएल मामले की जांच गंभीर अपराध जांच कार्यालय (एसएफआइओ) को सौंपने की तैयारी में है। हाल में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) की रिपोर्ट में डीएचएफल द्वारा फंड डायवर्जन की बात कही गई थी। इस वर्ष की शुरुआत में आरओसी के मुंबई ऑफिस ने डीएचएफल के प्रमोटर्स पर लगे वित्तीय अनियमितताओं और फंड डायवर्जन से संबंधित आरोपों की जांच शुरू की थी। अब सरकार इस मामले को एसएफआइओ को सौंपने की तैयारी कर रही है।

आरओसी ने कुछ दिन पहले ही अपनी जांच रिपोर्ट कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट में फंड डायवर्जन की ओर संकेत किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसएफआइओ जल्द ही इस मामले की जांच शुरू कर देगा। डीएचएफएल पर आरोप है कि उसने बैंक से लिए गए लोन में हेराफेरी की। इसके लिए मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। कंपनी ने कुल 97 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिसमें से 31 हजार करोड़ रुपये मुखौटा कंपनियों की सहायता से इधर-उधर किए गए। आरओसी ने अपनी जांच में मुखौटा कंपनियों के पते को भी गलत पाया है। आरओसी की जांच के अलावा केपीएमजी द्वारा की गई फॉरेंसिक ऑडिट में भी प्रमोटर्स द्वारा बड़े पैमाने पर फंड डायवर्जन की बात सामने आई थी। फिलहाल डीएचएफएल के कर्जदाता इसके लिए रिजॉल्यूशन प्लान लेकर आए हैं।

प्रतीकात्मक

▶ आरओसी की रिपोर्ट के आधार पर जांच की तैयारी

▶ मुखौटा कंपनियों की सहायता से फंड डायवर्जन का आरोप

भारतीय इकोनॉमी की सुस्ती अस्थायी : अंबानी

रियाद, प्रेट्र : रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी की सुस्ती अस्थायी है। सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम इसे वापस ट्रैक पर लाने में मददगार साबित होंगे। सऊदी अरब के वार्षिक निवेश फोरम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का परिणाम अगली कुछ तिमाहियों में नजर आने लगेगा। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में हिस्सेदारी के लिए सऊदी अरब की कंपनी अरैमको और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच इन दिनों बातचीत चल रही है। अंबानी का कहना था कि भारत और सऊदी अरब दोनों देशों के पास इस वक्त ऐसा नेतृत्व है जिसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। दोनों देशों के पास टेक्नोलॉजी और युवा वर्ग भी है, जिनके बूते आर्थिक विकास को गति दिया जा सकता है।

गौरतलब है कि पिछली पांच तिमाहियों के दौरान भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। इस वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान ग्रोथ रेट घटकर पांच परसेंट रह गई थी, जो 2013 के बाद सबसे कमजोर विकास दर थी। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने इकोनॉमी को गति देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

रेल कारखानों के लिए बनेंगी दो होल्डिंग कंपनियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने सरकार को रेल कारखानों के लिए दो अलग-अलग कंपनियों की स्थापना के लिए विवश कर दिया है। दोनो विभागों को खुश करने के लिए अब सरकार उत्पादन कारखानों के लिए एक के बजाय दो होल्डिंग कंपनियां बनाने पर विचार कर रही है। इनमें एक कंपनी इंजन कारखानों को, जबकि दूसरी कोच तथा व्हील फैक्ट्रियों के कामकाज को संभालेगी।

रेलवे बोर्ड का कहना है कि लोको और कोच फैक्ट्रियों को एक ही होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत रखने से व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी। बोर्ड ने पहली कंपनी का नाम इंडियन रेलवे मोटिव पावर कंपनी (आइआरएमपीसी) तथा दूसरी को इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी (आइआरआरएससी) रखने का सुझाव दिया है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार की इस योजना का रेलवे यूनियनों द्वारा सख्त विरोध किया जा रहा है।

इस समय रेलवे के पूर्ण स्वामित्व वाली आठ उत्पादन इकाइयां या कारखाने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू), उत्तर प्रदेश स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप (डीएलडब्ल्यू) तथा पंजाब स्थित डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स (डीएमडब्ल्यू) में इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण होता है। जबकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) तमिलनाडु, रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) पंजाब, मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) उप्र. तथा रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ), कर्नाटक और रेल व्हील प्लांट (आरडब्ल्यूपी), बिहार समेत पांच कारखाने यात्री डिब्बों और उनके पहियों का निर्माण करते हैं।

इन सभी इकाइयों में कुल मिलाकर लगभग 45 हजार कर्मचारी काम करते हैं। और इनका सालाना कुल वेतन बिल लगभग 3,100 करोड़ रुपये तथा टर्नओवर 19,500 करोड़ रुपये है। इसमें तीन लोको यूनिटों का संयुक्त वेतन बिल 1,360 करोड़ रुपये तथा टर्नओवर 8000 करोड़ रुपये है। जबकि चार कोच फैक्ट्रियों व दो पहिया कारखानों का संयुक्त वेतन बिल 1,765 करोड़ रुपये तथा टर्नओवर 11,500 करोड़ रुपये है।

इन इकाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने तथा लागत घटाने के लिए सरकार ने बिबेक देबराय समिति के सुझाव पर इनका निगमीकरण करने तथा इनके प्रबंधन के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनाने का निश्चय किया था। परंतु मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभागों की आपसी खींचतान इसके आड़े आ गई है। नतीजतन, सरकार को अपनी योजना में फेरबदल के लिए मजबूर होना पड़ा है। रेल मंत्रालय की ओर से तैयार अंतर-मंत्रालयी नोट से इसका पता चलता है। इसमें एक कंसल्टेंसी फर्म की सिफारिश के आधार पर रेलवे की ओर से एक होल्डिंग कंपनी के बजाय दो होल्डिंग कंपनियां बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

▶ मैकेनिकल लॉबी के दबाव में कोच व पहिया कारखानों के लिए इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी बनाने का प्रस्ताव

▶ इलेक्ट्रिकल लॉबी को संतुष्ट करने के लिए लोको फैक्ट्रियां इंडियन रेलवे मोटिव पावर कंपनी के अधीन आएंगी

प्रतीकात्मक

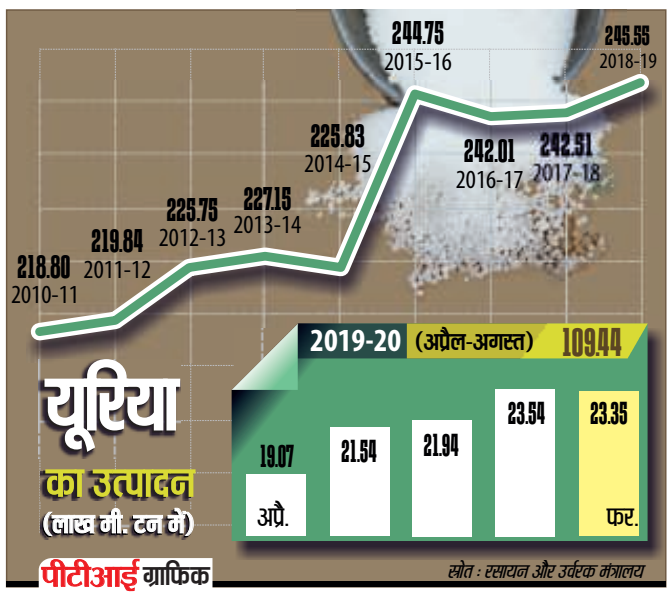

मजबूती

ऑटो सेक्टर के शेयरों में दर्ज किया गया तेज उछाल, ब्लूचिप कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों का दिखा असर

चार महीनों के उच्च स्तर पर शेयर बाजार

मुंबई, एजेंसियां : दिवाली की छुट्टी के बाद मंगलवार को कारोबारी सप्ताह का शानदार आगाज हुआ। इस दौरान प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में उछाल दर्ज किया गया। शेयर बाजारों के नए वर्ष के पहले दिन बीएसई का 30 शेयरों वाला संसेक्स 581.64 अंक यानी 1.48 परसेंट उछाल के साथ 39,831.84 पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में यह 39,917.01 तक पहुंच गया था। वहीं एनएसई के निफ्टी में 159.70 अंक की तेजी दर्ज की गई और वह 11,786.85 के स्तर पर बंद हुआ।

दिन के कारोबार में ऑटो शेयरों में 4.3, मेटल 3.9, आइटी 1.5 और फार्मा शेयरों में एक परसेंट तक की तेजी देखी गई। इस दौरान टाटा मोटर्स के शेयरों में सबसे ज्यादा 16.5 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। इसके अलावा मारुति सुजुकी 4.4 परसेंट और आयशर मोटर्स के शेयरों में 3.7 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी 2.30 परसेंट उछाल के साथ बंद हुए। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार भारती इन्फ्राटेल के शेयरों में नौ, वोडाफोन आइडिया में 8.1 और भारती एयरटेल के शेयरों में 3.3 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। जानकारों के मुताबिक ब्लूचिप कंपनियों के मजबूत तिमाही आंकड़ों और यूएस-चीन ट्रेड समझौते को लेकर आ रही सकारात्मक खबरों से बाजार में उत्साह का माहौल रहा।

शेयरों में उछाल के चलते एक दिन में ही निवेशकों की संपत्ति में 2.73 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। इस दौरान बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,73,355.21 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ 1,52,04,693.34 करोड़ पर जा पहुंचा। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हैड विनोद नायर के मुताबिक बड़ी कंपनियों द्वारा दूसरी तिमाही के दौरान अच्छी कमाई, ट्रेड-डील की खबरों के बीच ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर से छंटते संकट के बादल आदि कारणों से निवेशकों का मनोबल मजबूत हुआ है, जिससे निवेश को लेकर उत्साह देखा गया है।

मंगलवार को एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग और सियोल के शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं टोक्यो के बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

ग्लोबल इकोनॉमी से ट्रेड वार के छंटते बादलों के बीच शेयर बाजारों में मजबूती आ रही है। प्रतीकात्मक

टाटा मोटर्स के शेयरों में तेज उछाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे आने के बाद मंगलवार को टाटा मोटर्स के शेयरों में 17 परसेंट तक का उछाल दर्ज किया गया। इस दौरान कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 7,103 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। बीएसई में कंपनी के शेयर 16.63 परसेंट उछाल के साथ 172.55 रुपये की कीमत पर बंद हुए। वहीं निफ्टी में इसके शेयरों में 16.55 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। बीएसई और एनएसई दोनों जगह कंपनी के शेयरों ने सबसे ज्यादा तेजी का प्रदर्शन किया। एलकेपी सिक्युरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अश्विन पाटिल के मुताबिक टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजे उम्मीदों से बेहतर रहे हैं। चीन में टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी के इन नतीजों का असर इसके शेयरों पर देखा गया।

आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरों में तेजी

नई दिल्ली, प्रेट्र : निजी क्षेत्र के बैंक आइसीआइसीआइ के तिमाही नतीजों का असर इसके शेयरों पर दिखाई पड़ा। मंगलवार को बैंक के शेयरों में दो परसेंट तक की तेजी दर्ज की गई। दिन के कारोबार में बीएसई में बैंक के शेयर 1.74 परसेंट तेजी के साथ 477.55 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बंद हुए। वहीं एनएसई में इसके शेयर 1.37 परसेंट के उछाल के साथ 476 रुपये पर बंद हुए। बैंक ने पिछले सप्ताह शनिवार को अपने तिमाही नतीजे पेश किए थे। हालांकि जुलाई-सितंबर की तिमाही के दौरान कंपनी के शुद्ध मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके एनपीए में कमी के चलते असेट गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

एलटीसीजी, एसटीटी टैक्स से छूट देने की तैयारी कर रही सरकार

नई दिल्ली, एजेंसियां : केंद्र सरकार शेयर बाजार में निवेश बढ़ाने के लिए टैक्स के मोर्चे पर बड़े बदलाव की तैयारी में है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) शेयर बाजार में निवेश पर लगने वाले टैक्स में बदलाव पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी संभावना है कि निवेशकों को लांग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स, सिक्युरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) से राहत मिल जाएगी। सरकार इक्विटी निवेश पर सिंगल टैक्स प्रणाली की तैयारी कर रही है, ताकि निवेशकों के लिए यह बाजार सरल हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इसका प्लान तैयार कर लिया गया है। यह खबर आने के बाद संसेक्स और निफ्टी में करीब 1.5 प्रतिशत जोरदार तेजी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मामलों के विभाग और राजस्व विभाग ने इस सिलसिले में पीएमओ के साथ बैठकें की हैं। 2018 के आम बजट में इक्विटी निवेश पर 10 फीसदी एलटीसीजी का प्रावधान किया गया था। निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लांग और शॉर्ट टर्म गेन्स पर सरचार्ज में बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया था। उसके बाद पिछले दो महीनों से एफडीआइ निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

6 लोगों की मौत हो गई है फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में मंगलवार को आए तेज भूकंप से। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई। इस त्रासदी से सबसे ज्यादा मिंडानाओ द्वीप प्रभावित रहा।

डीएनए के नमूनों से हुई बगदादी की पहचान

आतंकी का अंत ▶ करीबी ने मुहैया कराए थे आइएस सरगना के अंडरवियर और रक्त के नमूने

सीरिया में अमेरिकी बलों के विशेष अभियान में मारा गया खूंखार आतंकवादी

वाशिंगटन, आइएएनएस : सीरिया में मार गिराए गए दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के सरगना अबू बकर अल-बगदादी की पहचान की पुष्टि उसके अंडरवियर और रक्त से लिए गए डीएनए नमूनों से की गई। बगदादी के एक करीबी ने ही उसके दो अंडरवियर और रक्त का नमूना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को मुहैया कराया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दुनिया के नंबर वन आतंकी बगदादी के मारे जाने का एलान किया था। उन्होंने बताया था कि शनिवार को सीरिया के इदलिब में अमेरिकी बलों के विशेष अभियान में बगदादी मारा गया। डेली मेल अखबार में सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसएफडी) के जनरल मजलूम अब्दी के हवाले से कहा गया है, 'बगदादी के करीबी लोगों में हमारा एक आदमी भी था। उसकी आइएस सरगना तक सीधी पहुंच थी। उसी ने इस साल बगदादी के अंडरवियर और रक्त का नमूना अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मुहैया कराया था। धमाके के बाद बगदादी के शव के चिथड़े उड़ गए थे। अमेरिकी सैनिकों ने इन नमूनों से मिले डीएनए से ही बगदादी की पहचान की।'

15 मिनट में हुई थी पहचान : ट्रंप के अनुसार, बगदादी की पहचान की पुष्टि महज 15 मिनट के अंदर हो गई थी। डेली मेल के अनुसार, बगदादी के सिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसकी पहचान के लिए एक बायोमीट्रिक फेसियल-रिकगनाइजेशन स्कैनर का भी इस्तेमाल किया गया था।

ढाई करोड़ डॉलर था इनाम : आइएस सरगना बगदादी के सिर पर ढाई करोड़ डॉलर (करीब 175 करोड़ रुपये) का इनाम था। पूरी दुनिया को इस कुख्यात आतंकी की तलाश थी।

ओसामा की भी इसी तरह हुई थी पहचान : अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन मई, 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी अभियान में मारा गया था। उसकी पहचान की पुष्टि के लिए उसके अवशेष अफगानिस्तान में स्थित अमेरिकी लैब भेजे गए थे, जहां डीएनए टेस्ट के जरिये उसकी पहचान हुई थी।

आइएस के खूंखार आतंकी अबू बकर अल-बगदादी की फाइल फोटो। रायटर

समुद्र में दफनाया गया अबू बकर का शव

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि बगदादी के शव को भी उसी तरह समुद्र में किसी अज्ञात स्थान पर दफना दिया गया, जिस तरह 2011 में अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के शव को समुद्र में दफन किया गया था। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ प्रमुख जनरल मार्क मिले ने बताया कि आइएस सरगना बगदादी के अवशेषों को अमेरिका के सशस्त्र संघर्ष कानून के तहत उचित तरीके से दफना दिया गया है।

बगदादी का उत्तराधिकारी भी ढेर

वाशिंगटन, प्रेट्र : आतंकी संगठन इस्लामिक इस्टेट (आइएस) के सरगना अबू बकर अल बगदादी को ढेर करने के बाद अब उसके पहले नंबर के उत्तराधिकारी को भी ढेर कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। माना जा रहा था कि बगदादी के बाद आतंकी संगठन की कमान अब्दुल्लाह कार्दश को सौंप दी गई थी। हालांकि ट्रंप ने मारे गए आतंकी का नाम नहीं बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदादी कई बीमारियों से ग्रसित था। इसलिए हाल के दिनों में उसके जीते-जी कार्दश ही आतंकी संगठन की देखरेख करता था।

बगदादी की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह उसके उत्तराधिकारियों के बारे में भी जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एलान किया था कि खूंखार आतंकी बगदादी अमेरिकी सेना की कार्रवाई में मारा गया। ट्रंप ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, 'हम उसके उत्तराधिकारियों के बारे में जानते हैं और उन पर हमारी नजर है।'

ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, 'अभी-अभी पुष्टि हो गई है कि बगदादी का नंबर वन रिप्लेसमेंट भी अमेरिकी सेना के हाथों मारा गया। वह आइएस का सरगना बनने वाला था, अब उसकी मौत हो चुकी है।'

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की घोषणा
- आइएस की कमान अब्दुल्लाह कार्दश को सौंपी गई थी

कायला मुलर के नाम पर था आइएस सरगना के खात्मे का अभियान

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका ने आइएस सरगना अबू बकर अल-बगदादी को मार गिराने के अपने अभियान को कायला मुलर का नाम दिया था, जिनकी आइएस ने अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। 26 साल की अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता कायला को वर्ष 2013 में आइएस आतंकियों ने सीरिया के एक अस्पताल से अगवा कर लिया था।

सीरिया में वह गृहयुद्ध से प्रभावित लोगों की मदद कर रही थीं। कई महिला बंदियों की जान बचाने वाली कायला की 2015 में हत्या कर दी गई थी। उनका शव हालांकि कभी बरामद नहीं हुआ। कायला के माता-पिता कार्ल मुलर और मार्शा मुलर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, 'अगर ट्रंप की तरह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने निर्णय लिया होता तो मेरी बेटी आज जीवित होती।' उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर अभियान चलाने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। ट्रंप ने बगदादी के मारे जाने की घोषणा करते समय कहा था, कायला लोगों की मदद करने वाली खूबसूरत युवा महिला थीं।

सीरियाई तेल कुंओं की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने तेज किए प्रयास

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने सीरिया में तेल कुंओं को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के साथ ही सीरियाई शासन और रूसी सहयोगियों से बचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने आइएस सरगना अबू बकर अल-बगदादी के मारे जाने के बाद इस मसले पर ध्यान केंद्रित किया है। यह कदम हालांकि ऐसे हालात में उठाए जा रहे हैं, जब सीरिया के कई क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि तेल कुंओं की सुरक्षा से सीरियाई कुर्दों के लिए आमदनी भी सुनिश्चित होगी। सीरिया में बचे हुए आइएस आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में कुर्द अमेरिका की मदद कर रहे हैं। एस्पर और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ प्रमुख जनरल मार्क मिले ने पेंटागन में प्रेस वार्ता में बगदादी को मार गिराने के अमेरिकी अभियान पर खुशी जाहिर की। एस्पर ने कहा, 'अमेरिका पूर्वोत्तर सीरिया के तेल कुंओं पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा।' इस बीच सीरिया में तुर्की के हमले पर ट्रंप ने सोमवार को फिर दोहराया, 'हम इस मामले में पुलिस की भूमिका निभाना नहीं चाहते।' तुर्की ने अक्टूबर के शुरू में कहा था कि वह सीरिया से लगती सीमा को सुरक्षित क्षेत्र बनाना चाहता है।

अमेरिकी खुफिया सैन्य अभियानों के अभिन्न अंग हैं ये कुत्ते

इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में अमेरिकी सेना में शामिल कुत्तों की बड़ी भूमिका रही। इस अभियान में घायल हुए कुत्ते की राष्ट्रपति ट्रंप ने तस्वीर सार्वजनिक की है। ये कुत्ता बेल्जियन मालीनोइस प्रजाति का है। संवेदनशील अभियानों में इस नस्ल के कुत्तों को अमेरिकी सेना साथ ले जाती है। अलकायदा प्रमुख को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराने वाली नेवी सील की टीम का हिस्सा इसी प्रजाति का एक कुत्ता था।

पहचान उजागर न करने की वजहें

बगदादी का पीछा करने और मरने पर विवश करने वाले कुत्ते की राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ तस्वीर सार्वजनिक की है। उसका नाम या कोड नाम नहीं सार्वजनिक किया गया है। हालांकि न्यूजवीक ने सूत्रों के हवाले से उनका नाम कोनन बताया है। अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अगर कुत्ते का नाम जाहिर हो जाता तो यूनिट का नाम सार्वजनिक होने की आशंका होती। इससे पूरी टीम पर खतरा बढ़ जाता।

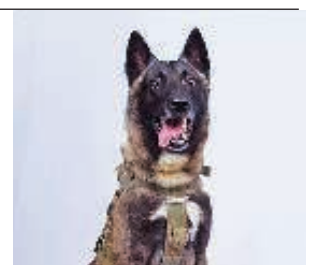

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर स्पेशल फोर्स के इस कुत्ते की तस्वीर शेयर की है। एएफपी

अमेरिकी सेना में कुत्तों की भूमिका

यूनाइटेड स्टेट्स वार डॉग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रोन एइलो के अनुसार अमेरिकी सेना में कुत्ते वियतनाम युद्ध से ही प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। सैनिकों की सुरक्षा में इन कुत्तों की बड़ी भूमिका होती है। आइईडी को सूंघकर पहचान करने की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें इसके लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है कि कहीं दुश्मन किसी पेड़ पर तो नहीं मौजूद है या फिर झाड़ियों के पीछे तो नहीं छिपा है। ऐसी स्थिति में कुत्ते और उनको संभालने वाले टीम की अगुआई करते हैं। इस तरह पूरी टीम को संभावित खतरे से बचाते हैं।

वजन	
नर	25-30 किग्रा
मादा	22-25 किग्रा
ऊंचाई	
नर	61-66 सेमी
मादा	56-61 सेमी
जीवनकाल	10-15 साल

खास है ये प्रजाति

मालीनोइस औसत से बड़े आकार वाले कुत्तों की खास प्रजाति है। गंध को सूंघने में इस नस्ल को दक्षता हासिल होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन की जमीनी सुरक्षा भी इनके ही जिम्मे है। यह प्रजाति मूल रूप से बेल्जियम में पाई जाती है।

छह से आठ साल कार्यकाल

अमेरिकी सेना में कुत्तों की सेवा का कार्यकाल छह से आठ साल का होता है। इसके बाद उनके गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सेवा मुक्त होने के बाद अमेरिकी सरकार उनके मद में कोई खर्च वहन नहीं करती है। इसीलिए तमाम ऐसे संगठन खड़े हो गए हैं जो सैन्य कुत्तों को मदद देने के लिए काम करते हैं। चाहे उनके चिकित्सकीय या देखभाल का खर्च हो, सबकी चिंता ये संगठन करते हैं।

न्यूज गैलरी

सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 11 तालिबान आतंकी ढेर

नांगरहार : अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में सुरक्षाबलों की कार्रवाई में तालिबान के 11 आतंकी मारे गए। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी (एनडीएस) ने बताया कि सुरक्षाबलों ने यह कार्रवाई बिलाल खेर स्थित तालिबान के गुप्त अड्डे पर की। आतंकियों ने इस ठिकाने पर बड़ी संख्या में हथियार, बम और गोला-बारूद जमा कर रखा था, जिसे नष्ट कर दिया गया। (एएनआइ)

ऑस्ट्रेलिया में इजरायली छात्रा के हत्यारे को 36 साल की जेल

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने आई इजरायली छात्रा आया मसार्वे (21) के हत्यारे कोडे हर्मन को अदालत ने 36 साल जेल की सजा सुनाई है। विक्टोरिया प्रांत की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोडे की सजा का एलान किया। इस साल जनवरी में रात में अपने हॉस्टल लौट रही मसार्वे की कोडे ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। (एपी)

अमेरिकी कॉलेज पार्टी में गोलीबारी करने वाला गिरफ्तार

ग्रीनविले : अमेरिका के टेक्सास प्रांत में बीते शनिवार की रात एक कॉलेज पार्टी में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रीनविले से गिरफ्तार ब्रैंडन रे गोंजालेज (23) को हंट काउंटी जेल में रखा गया है। इस गोलीबारी में दो छात्रों की मौत हो गई थी और 12 घायल हो गए थे। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब छात्र हैलोवीन पार्टी मना रहे थे। (एपी)

भारतवंशियों को लूटने वाली महिला सरगना को जेल

न्यूयॉर्क : अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के घरों में लूटपाट करने वाले गैंग की महिला सरगना को अदालत ने 37 साल जेल की सजा सुनाई है। मिशिगन की जिला अदालत ने सोमवार को 44 वर्षीय चाका कास्त्रो को सजा सुनाई। चाका और उसकी गैंग ने 2011 से 2014 के बीच जॉर्जिया, न्यूयॉर्क, ओहायो, मिशिगन और टेक्सास में लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दिया था। (प्रेट्र)

अस्पताल में भर्ती नवाज शरीफ की हालत बेहद नाजुक

- प्लेटलेट्स काउंट हो रहा कम, वजन भी सात किलो घटा

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (69) के डॉक्टर ने मंगलवार को बताया कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। उनका प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री का वजन भी 107 किलोग्राम से घटकर 100 किलो हो गया है।

जियो न्यूज के अनुसार, शरीफ के निजी डॉक्टर डॉ अदनान खान ने कई ट्वीट के जरिये उनकी सेहत की ताजा जानकारी दी। खान ने लिखा, 'पूर्व प्रधानमंत्री की हालत बेहद नाजुक है। कम प्लेटलेट्स काउंट और दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी किडनी भी ठीक से काम नहीं कर रही।' शरीफ मेडिकल सिटी के मुख्य कार्यकारी ने बताया कि डॉक्टरों को भी उपचार में परेशानी हो रही है। इससे पहले शरीफ को शनिवार को उपचार के दौरान ही सीने में तेज दर्द होने लगा था। रविवार को जारी शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि उनका प्लेटलेट्स काउंट एक दिन में ही 45 हजार से घटकर 25 हजार रह गया था। शरीफ का प्लेटलेट्स काउंट कम होकर 2,000 तक पहुंचने के बाद गत 21 अक्टूबर को आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

भ्रष्टाचार मामले में सजा आठ सप्ताह के लिए निलंबित

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को सुनाई गई सात साल की सजा आठ सप्ताह के लिए निलंबित कर दी है। शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला किया। कोर्ट ने उन्हें 20-20 लाख रुपये के दो जमानती बांड जमा कराने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि मंगलवार को खत्म हो रही थी। हाई कोर्ट के जजों की दो सदस्यीय पीठ ने खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर शरीफ को जमानत देते हुए कहा कि अगर इसमें विस्तार की जरूरत हुई तो पंजाब सरकार से संपर्क किया जा सकता है।

प्रदर्शनकारियों पर इराकी सुरक्षा बलों ने चलाई गोली, 18 की मौत

बगदाद, एपी : इराक के पवित्र शहर करबला में मंगलवार को मास्क और काले कपड़े पहने सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई। आठ सौ से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकार ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा, सरकार के खिलाफ दोबारा शुरू हुए प्रदर्शन के पांचवें दिन करबला में बड़ी हिंसा हो गई। यह हमला इमाम हुसैन के मकबरे से करीब दो किलोमीटर दूर उस जगह हुआ जहां प्रदर्शनकारी टेंट लगाकर बैठे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मास्क लगाए और काले कपड़े पहने लोग आए और गोलीबारी करने लगे। इस दौरान टेंट में आग भी लग गई। इराक में प्रदर्शन के दूसरे दौर में अब तक 72 लोग मारे जा चुके हैं। पहले दौर में भी 149 लोग मारे गए थे। करबला के पुलिस प्रमुख ने हालांकि प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की बात से इन्कार किया है। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 122 लोगों के घायल होने की बात कही है, जिनमें 66 सुरक्षाकर्मी हैं।

तेल संपन्न इराक में लोग भ्रष्टाचार, खराब आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और खस्ताहाल जनसुविधाओं आदि को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार में बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी ने मंत्रिमंडल में बदलाव और सुधार पैकेज की घोषणा भी की है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। सोमवार को छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए संघर्ष के बाद सरकार ने राजधानी बगदाद में रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू की भी घोषणा की है।

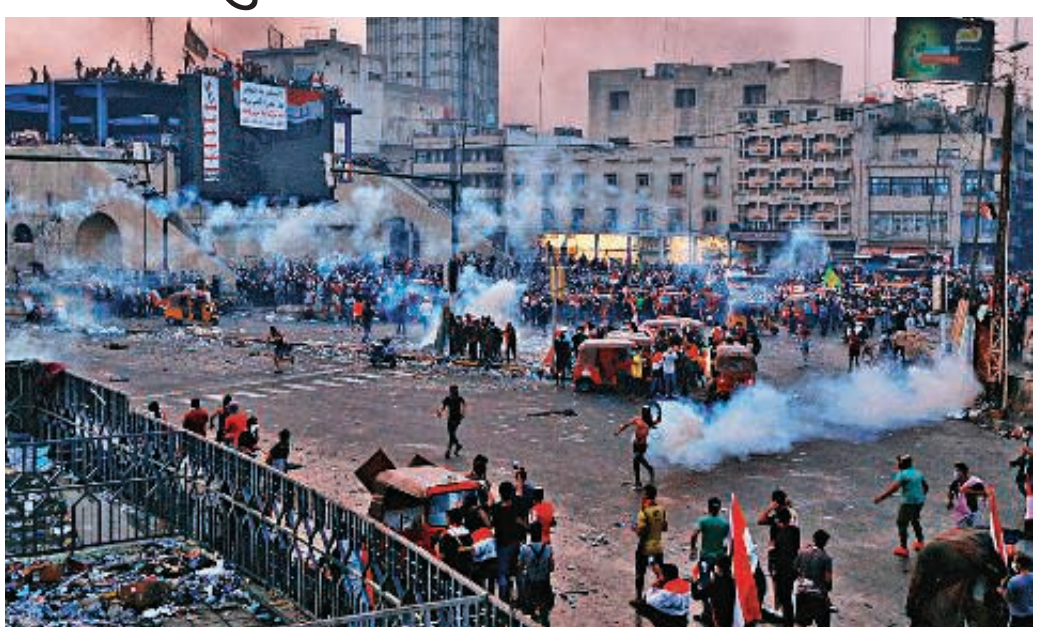

इराक की राजधानी बगदाद के तहरीर स्क्वायर पर सरकार विरोध प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। एपी

पाकिस्तानी हिंदू छात्रा के शव पर पुरुष का डीएनए मिला

लरकाना, आइएएनएस : मेडिकल की हिंदू छात्रा नम्रता चांदनी की रहस्यमय मौत मामले में एक सनसनीखेज रहस्य सामने आया है। फोरेंसिक टीम को छात्रा के शव और उसके कपड़ों से पुरुष का डीएनए मिला है। रोजनामा पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि जामशोरो के डीएनए केंद्र ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की अंतिम वर्ष की छात्रा की डीएनए रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है।

लरकाना के एसएसपी मसूद बंगस ने कहा कि संबंधित थाने को नम्रता की डीएनए रिपोर्ट मिल गई है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 16 सितंबर को छात्रावास के कमरे में नम्रता मृत पाई गई थी। उसके बाद लरकाना पुलिस ने 17 सितंबर को डीएनए सैंपल फोरेंसिक प्रयोगशाला को सौंप दिया था। शुरू में विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसकी मौत को आत्महत्या माना, लेकिन उसके भाई विशाल ने इसे हत्या कहा था।

जाधव पर आइसीजे के फैसले ने कम किया भारत-पाक के बीच तनाव

- आइसीजे प्रमुख ने कहा, बहुत संवेदनशील था यह मामला

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने कहा कि वह 'खुश' हैं कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में आए फैसले से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ। यूसुफ ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जाधव का मामला बहुत ही संवेदनशील था क्योंकि यह किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा था जिसे पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस मामले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ा दिया था।

आइसीजे ने इस साल जुलाई में फैसला दिया था कि पाकिस्तान जाधव की मौत की सजा पर पुनर्विचार करे। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी को 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। यूसुफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जाधव को दोषी ठहराए जाने और सजा की 'प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार' करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, 'हमारे पास एशियाई देशों के कई मामले हैं। मिसाल के तौर पर अदालत ने जुलाई में भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक विवाद को लेकर एक निर्णय सुनाया जो कि एक बेहद नाजुक एवं संवेदनशील मुद्दा था। इसे लेकर दोनों देशों में काफी तनाव पैदा हो गया था। हम इस बात को लेकर खुश हैं कि अदालत के फैसले ने उसके बाद से तनाव को घटाने ओर कम करने में योगदान दिया।'

आम चुनाव कराने की चौथी कोशिश करेंगे बोरिस

- तीन कोशिशों में नाकाम हो चुके हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन
- विपक्षी लेबर पार्टी कर सकती है दिसंबर में चुनाव का समर्थन

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन संसद में एक और विधेयक पेश कर 12 दिसंबर तक आम चुनाव कराने की चौथी बार कोशिश करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि यूरोपीय यूनियन द्वारा ब्रेक्जिट समयसीमा को 31 जनवरी तक बढ़ाए जाने के बाद, जॉनसन की इसी तरह की (जल्द चुनाव कराने की) एक कोशिश सांसदों ने एक दिन पहले ही खारिज कर दी थी। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन को 31 अक्टूबर तक बाहर निकालने के लिए जॉनसन के 'करो या मरो' संकल्प के नाकाम होने के बाद अब उन्हें हाऊस ऑफ कॉमन्स (ब्रिटिश संसद के निचले सदन) से मध्यावधि चुनाव का विधेयक पारित करा लेने की उम्मीद है।

तीन कोशिशें नाकाम रहने के बाद इस बार जॉनसन को कहीं अधिक संभावना नजर आ रही है क्योंकि उन्हें सांसदों के सिर्फ सामान्य बहुमत की जरूरत है। विपक्षी लेबर पार्टी ने कहा है कि वह दिसंबर में चुनाव कराने का समर्थन करेगी।

सोमवार को मतदान में सफलता नहीं मिलने पर निचले सदन से जॉनसन ने कहा था, 'हम इस स्थिति को जारी नहीं रहने देंगे और किसी न किसी रास्ते हम चुनाव की ओर बढ़ेंगे।' उन्होंने कहा, 'सरकार 12 दिसंबर को चुनाव कराने के लिए एक विधेयक पेश करने का नोटिस देगी ताकि हम आखिरकार ब्रेक्जिट को पूरा कर सके।'

विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बयन ने अपने शैडो कैबिनेट से कहा, 'मैंने लगातार कहा है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हमने अब ईयू से सुना है कि अनुच्छेद 50 को 31 जनवरी तक विस्तार दिया गया है। इसलिए नो-डील को केंद्र से बाहर रखने की हमारी शर्त पूरी हो चुकी है।'

ब्रेक्जिट सिक्के को गला देगा ब्रिटेन

ब्रिटेन का रॉयल मिंट ने 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से विदाई के बाद जारी होने वाले स्मारक सिक्कों को गलाने की योजना बनाई है। इसका कारण यह है कि ईयू से देश के बाहर निकलने की समयसीमा और तीन महीने बढ़ा दी गई है। ब्रिटिश ट्रेजरी के प्रवक्ता ने कहा कि यूरोपीय यूनियन से विदाई के बाद ये सिक्के प्रचलन में आएंगे।

सियासी विज्ञापन नीति

सोशल नेटवर्किंग कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के सीईओ को पत्र लिखकर जताया विरोध

जुकरबर्ग से सहमत नहीं फेसबुक के कर्मचारी

न्यूयॉर्क टाइम्स से

सैन फ्रांसिस्को : फेसबुक कर्मी सियासी विज्ञापन संबंधी नीति को लेकर सीईओ मार्क जुकरबर्ग से सहमत नहीं हैं। फेसबुक के सैकड़ों कर्मचारियों ने दुनिया की इस दिग्गज सोशल नेटवर्किंग कंपनी के सीईओ जुकरबर्ग और अन्य शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर सियासी नेताओं को अपने पोस्ट में मनचाहे दावे करने की छूट देने के नए फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने फेसबुक के शीर्ष नेतृत्व से अपने रुख पर पुनर्विचार का आग्रह किया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार को मिले पत्र में कर्मचारियों ने कहा है, 'सियासी विज्ञापनों पर फेसबुक का नया रुख इस कंपनी के दृष्टिकोण के लिए खतरा है। हम इस नीति का सख्ती के साथ विरोध करते हैं।' यह पत्र पिछले दो हफ्ते से कंपनी के एक साफ्टवेयर प्रोग्राम पर दिखाई दे रहा है। यह प्रोग्राम फेसबुक के सिलिकॉन वैली स्थित दफ्तर में आंतरिक संचार के लिए इस्तेमाल होता है। इस पर फेसबुक के ढाई सौ से ज्यादा कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं। यह संख्या हालांकि फेसबुक के 35 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के लिहाज से काफी कम है। लेकिन यह दर्शाता है कि अपने सियासी विज्ञापनों को लेकर इस कंपनी को आतंरिक रूप से किस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

'सियासी भाषण पर रोक नहीं लगाने के लिए प्रतिबद्ध'

फेसबुक की प्रवक्ता बर्टी थॉमसन ने कहा, 'कंपनी की संस्कृति खुलेपन पर आधारित है। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने कर्मचारियों के विचारों की सराहना करते हैं। हम सियासी भाषणों पर रोक नहीं लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सियासी विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने के लिए अतिरिक्त कदमों की तलाश करना जारी रखेंगे।'

इस घोषणा का हो रहा विरोध : फेसबुक ने पिछले माह यह घोषणा की थी कि नेताओं और उनके अभियान से जुड़े पोस्ट तकरीबन नियंत्रण मुक्त रहेंगे। जबकि इससे पहले फेसबुक ने पहले भुगतान वाले सियासी विज्ञापनों पर रोक लगा रखी थी।

फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की फाइल फोटो।

ट्रंप के विज्ञापन को हटाने से किया इन्कार : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए पिछले माह फेसबुक पर एक विज्ञापन चलवाया था। इसमें विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवारी पाने की होड़ में सबसे आगे माने जा रहे पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन के बारे में झूठा दावा किया गया था। बिडेन ने इस विज्ञापन को हटाने की मांग की थी, लेकिन फेसबुक ने मना कर दिया था।

श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में तमिलों पर डोरे डाल रहे गोतबाया

कोलंबो, आइएएनएस : श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोतबाया राजपक्षे तमिल मतदाताओं पर डोरे डालने में जुटे हैं। श्रीलंका के उत्तरी प्रांत की राजधानी जाफना में सोमवार को एक रैली में राजपक्षे ने तमिल समुदाय के लोगों से सहयोग की अपील करते हुए देश के विकास की बात कही। श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी) पार्टी के उम्मीदवार गोतबाया ने कहा कि वह तमिल बहुल क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए वचनबद्ध हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवारी तय होने के बाद गोतबाया की जाफना में यह पहली रैली थी। श्रीलंका में 16 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है।

गोतबाया ने रैली के दौरान अपनी पार्टी के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए कहा कि जीत हासिल होने पर वह अन्य दलों का सहयोग लेकर देश में नए संविधान का निर्माण करेंगे। श्रीलंका में 2009 में तमिल आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व गोतबाया ने ही किया था। वह उस समय राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की अगुआई वाली सरकार में रक्षा मंत्री थे।

लोकेशन डाटा के दुरुपयोग को लेकर गूगल पर मुकदमा

- ऑस्ट्रेलियाई नियामक का आरोप स्मार्टफोन यूजर्स को किया गुमराह

सिडनी, रायटर : दिग्गज तकनीकी कंपनी गूगल लोकेशन डाटा के दुरुपयोग के आरोप में फंस गई है। इस मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के एक नियामक ने गूगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गूगल पर आरोप है कि वह स्मार्टफोन यूजर्स को उनके निजी लोकेशन डाटा को जुटाने और उसके उपयोग के बारे में गुमराह कर रही है।

ऑस्ट्रेलियाई कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन (एसीसीसी) ने कहा है कि गूगल की स्थानीय यूनिट ने यूजर्स को करीब दो साल से अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। एसीसीसी ने संघीय अदालत में मंगलवार को दायर मुकदमे में कहा, 'गूगल के कृत्य से यूजर्स यह समझ रहे थे कि उनके लोकेशन के बारे में निजी डाटा एकत्र नहीं किया जा रहा। लेकिन हकीकत में उनका निजी डाटा गूगल द्वारा हासिल किया जा रहा था।' इस पर गूगल की एक महिला प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में कंपनी अपना बचाव करेगी। एसीसीसी के आरोपों की समीक्षा की जा रही है। इसके लिए नियामक से संपर्क किया जाएगा।

प्रतीकात्मक

फ्रांसीसी नियामक ने लगाया था 393 करोड़ जुर्माना : फ्रांस के एक नियामक ने गत जनवरी में निजता के उल्लंघन मामले में गूगल पर 5.55 करोड़ डॉलर (करीब 393 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था। आयरलैंड का डाटा प्रोटेक्शन कमीशन भी निजता कानून के उल्लंघन मामले में गूगल की जांच कर रहा है।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं।
— शाहबाज नदीम, भारतीय स्पिनर

तमिलनाडु की टी-20 टीम के कप्तान होंगे कार्तिक

चेन्नई, प्रेट्र: विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को आठ से 17 नवंबर तक होने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में तमिलनाडु टीम का कप्तान चुना गया है। हरफनमौला विजय शंकर उपकप्तान होंगे। टीम में आर अश्विन, मुरली विजय और वॉशिंगटन सुंदर भी हैं जो भारत-बांग्लादेश टी-20 सीरीज के बाद टीम से जुड़ेंगे। तमिलनाडु की टीम हाल ही में विजय हजारे के फाइनल में कर्नाटक से हारी है।

ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट का गवाह बनेगा कोलकाता

बीसीसीआइ अध्यक्ष गांगुली के प्रस्ताव को बीसीबी ने किया स्वीकार | पहली बार डे-नाइट टेस्ट खेलेंगी भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें

कोलकाता, प्रेट्र: भारत और बांग्लादेश के बीच 22 से 26 नवंबर तक यहां खेला जाने वाला सीरीज का दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच डे-नाइट होगा। बीसीसीआइ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मंगलवार को इस टेस्ट को लेकर लग रही अटकलों को विराम देते हुए यह जानकारी दी। इस तरह अब यह तय हो गया है कि कोलकाता का ईडन गार्डेंस स्टेडियम भारत के पहले डे-नाइट टेस्ट का गवाह बनेगा। गांगुली ने इस टेस्ट को गुलाबी गेंद से खेलने का प्रस्ताव बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के सामने रखा था। बांग्लादेश के खिलाड़ी हालांकि पहले इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बोर्ड के साथ कई दौर की बैठकों के बाद वे डे-नाइट टेस्ट खेलने को तैयार हो गए। गांगुली ने कहा कि यह अच्छी पहल है। टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने की जरूरत है। मैं और मेरी टीम ने इसके लिए काफी मेहनत की है। हम विराट कोहली का भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि वह इसके लिए तैयार हुए।

ओलंपियन का होगा सम्मान: इस टेस्ट मैच के दौरान अभिनव बिंद्रा, एमसी मेरी कॉम और पीवी सिंधू जैसे दिग्गज ओलंपिक पदक विजेताओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित करने की योजना हैं। इन सभी को टेस्ट मैच के लिए निमंत्रण दिया जाएगा।

हर वर्ष हो डे-नाइट टेस्ट: गांगुली चाहते है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में वार्षिक 'गुलाबी टेस्ट' (डे-नाइट) टेस्ट मैच का आयोजन होता है उसी तरह ईडन गार्डेंस में भी सालाना तौर पर डे-नाइट टेस्ट मैच का आयोजन हो। भारतीय क्रिकेटर लंबे समय से डे-नाइट टेस्ट मैच खेलने से बचते रहे हैं, लेकिन गांगुली ने शुक्रवार को कहा था कि कप्तान कोहली डे-नाइट टेस्ट खेलने के विचार से सहमत हैं और निकट भविष्य में इसका आयोजन हो सकता है।

बांग्लादेश के कोच को थी चिंता: बांग्लादेश के दक्षिण अफ्रीकी कोच रसेल डोमिंगो को चिंता थी कि कैसे मैच होगा, लेकिन टीम ने यह बदलाव स्वीकार किया और कुछ नया करने के लिए हामी भरी। मैच दोपहर को दो बजे शुरू होगा और मैच के बीच में चायकाल और डिनर ब्रेक होगा। डोमिंगो ने कहा कि हमें लगता है कि यह बड़ा मौका है। मुझे नहीं लगता कि भारत ने अब से पहले गुलाबी गेंद से टेस्ट खेला है। यह दुनिया की सबसे बड़ी टीम के खिलाफ ईडन गार्डेंस में एक बड़ा दिन होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं। हमारे सामने चुनौतियां हैं क्योंकि हमारे पास तैयारी का ज्यादा समय नहीं है, लेकिन भारत के लिए भी ऐसी ही स्थिति है। ऐसे में चुनौतियां दोनों टीमों के लिए बराबर रहने वाली हैं। गुलाबी गेंद से मुकाबला है, इसीलिए दोनों टीम ही किसी से कम नहीं होंगी। यह बदलाव अच्छा है।

यह गांगुली ही थे जिन्होंने भारत में पहली बार गुलाबी गेंद से डे-नाइट मैच कराया था। यह बंगाल क्रिकेट संघ का मोहन बागान और भवानीपुर के बीच खेला गया सुपर लीग का फाइनल मुकाबला था, जो जून 2016 में फ्लड लाइट में खेला गया था। मुहम्मद शमी और रिद्धिमान साहा उस मुकाबले में खेले थे। दोनों ही खिलाड़ियों के इस डे-नाइट टेस्ट में खेलने की संभावना है।

जब गुलाबी गेंद से खेली गई दलीप ट्रॉफी: 2016 में ही पहली बार बीसीसीआइ ने दलीप ट्रॉफी को गुलाबी गेंद से कराया था। यह तीन सत्रों तक गुलाबी गेंद से खेला गया, लेकिन बोर्ड ने प्रसारण कवरेज की वजह से इस वर्ष इसे डे-नाइट नहीं कराया। मयंक अग्रवाल, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, इशांत शर्मा मौजूदा टेस्ट टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें दलीप ट्रॉफी में गुलाबी गेंद से खेलने का अनुभव है। इस दौरान खास तौर से स्पिनरों ने ओस फैक्टर पर चिंता जाहिर की थी, जिसकी वजह से उनके पास करने को कुछ नहीं बचा था। गांगुली ने हालांकि विश्वास दिलाया कि परिस्थितियों की वजह से किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। गांगुली ने कहा कि हम इस समस्या को सुलझा लेंगे और यहां कोई ओस की दिक्कत नहीं होगी। हम डे-नाइट वनडे में भी ओस स्प्रै का इस्तेमाल करते हैं।

शेख हसीना रहेंगी मौजूद: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कोलकाता टेस्ट के पहले दिन मौजूद रहेंगी। साथ ही भारत के भी कई दिग्गज इस मुकाबले के लिए यहां मौजूद रहेंगे। गांगुली ने कहा कि यह मेरा काम है। मैं इसीलिए यहां पर हूं, क्योंकि मैंने यह खेल लंबे समय तक खेला है, तो मुझे लगता है कि यह टेस्ट क्रिकेट के लिए एक सार्थक कदम है और उम्मीद है कि इससे मैदान पर दर्शक भी आएंगे।

सिर्फ 11 डे-नाइट टेस्ट का इतिहास: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक सिर्फ 11 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले गए हैं। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट खेला गया था। पिछली बार डे-नाइट टेस्ट इस वर्ष जनवरी में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच ब्रिसबेन में खेला गया था। भारतीय टीम को पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डे-नाइट टेस्ट के लिए मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय टीम ने तब इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था।

कोलकाता का ईडन गार्डेंस स्टेडियम, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच डे-नाइट टेस्ट खेला जाएगा • फाइल फोटो, प्रेट्र

कोई कसर नहीं छोड़ेगा सीएबी : डालमिया

कोलकाता, प्रेट्र: बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के सचिव अभिषेक डालमिया ने मंगलवार को कहा कि भारत के पहले डे-नाइट टेस्ट मैच को सफल बनाने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

डालमिया ने कहा कि एक शब्द में कहूं तो हम खुश हैं। सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी यह एक बड़ी खुशखबरी है। ईडन में बहुत सारे इतिहास बने हैं। यह इसकी उपलब्धियों में एक और होगी। उन्होंने कहा कि सीएबी यह सुनिश्चित करेगा कि इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं रह जाए। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान इसे और भव्य बनाएगा। डालमिया ने कहा कि हम बुधवार से ही तैयारी शुरू कर देंगे, ताकि इसे कार्निवल का रूप दे सके। हम बीसीसीआइ अध्यक्ष संग बैठकर सभी तैयारियों को अमलीजामा पहनाएंगे। साथ ही हम भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी संपर्क बनाए रखेंगे। वहीं, बीसीसीआइ के सचिव जय शाह ने कहा कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा दिन है। सौरव, मैंने और हमारी टीम ने इस आइडिया पर काम किया। यह हमारा पहला कदम है। यह समय इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अच्छा है, क्योंकि बांग्लादेश के बाद हमें ज्यादा टेस्ट नहीं खेलने है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह दोनों देशों के बोर्ड के बीच सहज संबंधों का प्रतीक है।

बांग्लादेश के कप्तान शाकिब पर दो वर्ष का प्रतिबंध

ढाका, प्रेट्र: सटोरिये के पेशकश की जानकारी नहीं देने पर बांग्लादेश के टेस्ट और टी-20 कप्तान शाकिब अल हसन पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने दो वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है जिससे वह तीन नवंबर से शुरू हो रहे भारत दौरे पर नहीं आ सकेंगे। शाकिब पर एक साल का पूर्ण प्रतिबंध और एक साल की अवधि का निलंबन लगाया गया है। एक साल की अवधि का निलंबन तब लागू होगा जब अगर शाकिब आइसीसी की भ्रष्टाचार रोधी संहिता को मानने से इन्कार कर देते हैं। शाकिब से तीन बार सटोरिये ने संपर्क साधा था, जिसमें से एक बार उनसे भारतीय सटोरिये ने आइपीएल के दौरान संपर्क किया था।

नहीं खेल पाएंगे टी-20 विश्व कप: एक वर्ष का प्रतिबंध लगने के बाद शाकिब अगले वर्ष होने वाले आइपीएल और ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक होने वाले टी-20 विश्व कप में भी नहीं खेल सकेंगे।

मैं काफी दुखी हूं: शाकिब ने कहा कि जिस खेल से मुझे प्यार है, उससे निलंबित किए जाने से मैं काफी दुखी हूं, लेकिन मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूं। आइसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में खिलाड़ियों पर काफी निर्भर है। मैंने सटोरिये की पेशकश की जानकारी नहीं देकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

ये बनेंगे अब बांग्लादेश के कप्तान: शाकिब की गैरमौजूदगी में मुश्फिकर रहीम टेस्ट में और महमूदुल्लाह रियाद या मुसद्दक हुसैन टी-20 में बांग्लादेश की टीम की कप्तानी कर सकते हैं। भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलने के बाद बांग्लादेश को दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है।

32 वर्षीय शाकिब को आइसीसी के निर्देशानुसार ही बांग्लादेश की टीम के अभ्यास कैंप से दूर रखा गया था। आइसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई ने शाकिब से इस वर्ष जनवरी और अगस्त में बात की थी और उन्होंने इकाई को यह जानकारी नहीं दी थी कि उनसे सटोरियो ने संपर्क साधा था, जबकि इकाई पहले से ही दीपक अग्रवाल नाम के सटोरिये के शाकिब से संपर्क करने की बात को जानती थी। आइसीसी ने कहा कि अग्रवाल ने शाकिब से टीम की रणनीति और संयोजन की जानकारी तीन अलग-अलग मौकों पर मांगी थी। इसमें से एक बार 26 अप्रैल 2018 को सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के मैच से पहले अग्रवाल ने संपर्क किया था। इसमें से कुछ मैसेज शाकिब ने डिलीट कर दिए थे। इसको लेकर शाकिब ने स्वीकार किया कि अग्रवाल के यह मैसेज अंदर की जानकारी देने के लिए थे। वहीं, अग्रवाल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 2017 और जनवरी 2018 में श्रीलंका और जिंबाब्वे के साथ खेली गई त्रिकोणीय सीरीज के दौरान शाकिब से संपर्क किया था।

आइसीसी ने कहा कि अग्रवाल शाकिब से मिलना चाहता था, लेकिन क्रिकेटर ने मिलने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि शाकिब को लगता था कि अग्रवाल पैंतरेबाज है। साथ ही मैसेज की बातचीत से उन्हें लग रहा था कि अग्रवाल सटोरिया है। हालांकि, शाकिब पांच वर्ष के प्रतिबंध से बच गए, लेकिन उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने आइसीसी की सभी जांच और आरोपों को स्वीकार लिया है।

हाल ही में की थी खिलाड़ियों की अगुआई: शाकिब ने हाल ही में खिलाड़ियों की हड़ताल की अगुआई की थी, लेकिन बीसीबी द्वारा उनकी मांगों को मान लिए जाने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई।

झटका
- सटोरिये की पेशकश की जानकारी छुपाने पर आइसीसी ने लिया कदम
- भारतीय दौरे पर नहीं आ सकेंगे दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर

आज भारत दौरे पर आ सकती है बांग्लादेश की टीम

नई दिल्ली, एएनआइ: बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचने की संभावना है। टीम शाम को पांच बजे पहुंच सकती है। बांग्लादेश की टीम आइटीसी मौर्य, जबकि टीम इंडिया ताज मान सिंह होटल में रुकेगी।

शाकिब अल हसन • फाइल फोटो, प्रेट्र

नीदरलैंड्स ने 2020 टी-20 विश्व कप के लिए किया क्वालीफाई

दुबई, प्रेट्र: नीदरलैंड्स ने मंगलवार को आइसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप के क्वालीफाइंग प्लेऑफ में यूएई को आठ विकेट से हराकर अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस टूर्नामेंट का टिकट हासिल कर लिया।

नीदरलैंड्स की ओर से ब्रेंडन गलोवेर ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 12 रन पर चार विकेट हासिल किए, जिसकी वजह से यूएई की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 80 रन ही बना पाई। इसके बाद नीदरलैंड्स ने महज 15.1 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। उसके लिए बेन कूपर ने 41 गेंद में 53 रन बनाए।

नीदरलैंड्स टी-20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। इससे पहले पपुआ न्यू गिनी और आयरलैंड ने क्वालीफाई किया है। हालांकि यूएई के पास अभी भी टी-20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने का मौका होगा, लेकिन इसके लिए उसे करो या मरो के मुकाबले में स्कॉटलैंड को हराना होगा। यूएई के कप्तान अहमद रजा के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उलटा पड़ गया और टीम ने नौ रन तक पांच विकेट गंवा दिए।

जिम पहुंच बोले बुमराह, जल्द आ रहा हूं

नई दिल्ली, आइएएनएस: वेस्टइंडीज दौरे के बाद चोटिल हुए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर वापसी के लिए अब तैयार हैं। बुमराह ने मंगलवार को जिम सत्र भी किया और यहां एक तस्वीर क्लिक कर अपने प्रशंसकों के साथ साझा भी की। इस तस्वीर पर बुमराह ने दो शब्द लिखकर साफ संकेत दे दिए हैं कि वह अब अपनी कमर दर्द से उबर चुके हैं और जल्द ही मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। बुमराह ने जिम में वेट लिफ्टिंग मशीन के सामने खड़े होकर यह तस्वीर क्लिक की और लिखा जल्द आ रहा हूं। बुमराह फिट हो चुके हैं और अपनी रोजाना की एक्सरसाइज के लिए जिम में हैं। इससे पहले उनकी फिटनेस को लेकर सोमवार को खबर आई थी कि यह तेज गेंदबाज अपनी पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट से तेजी से उबर रहा है और अब उन्होंने हल्की रनिंग और वार्मअप एक्सरसाइज भी शुरू कर दी हैं। हालांकि, उनकी फिटनेस पर अंतिम निर्णय बेंगलुरु के एनसीए में ही होगा, जहां फिजियो नितिन पटेल की देखरेख में बुमराह की चोट और फिटनेस की जांच की जाएगी। इससे पहले बुमराह इस चोट के इलाज के लिए लंदन गए थे। यहां उनकी सर्जरी की भी चर्चा थी, लेकिन वहां डॉक्टरों ने पाया कि बुमराह पीठ को सर्जरी की जरूरत नहीं है।

भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह • ट्विटर

छत पर क्रिकेट खेल निराले अंदाज में आउट हुए धवन: टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन इन दिनों दिवाली की छुट्टियों पर अपने घर पर हैं। छुट्टियों के मौके पर जब यहां गब्बर को अपने रिश्तेदारों के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो उन्होंने इसे हाथों-हाथ लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में शिखर अपने घर की छत पर ही क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं। 21 सेकेंड के इस वीडियो में वह बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए शिखर ने इसे जो कैप्शन दिया है वह भी मजेदार है। शिखर ने लिखा कि फैमिली वाली क्रिकेट का मजा ही कुछ और है। दरअसल यहां शिखर के आउट होने के अंदाज से आप भी फैमिली वाली क्रिकेट का मतलब समझ सकते हैं। शिखर यहां गमलों को विकेट मानकर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें करीबी पांच फील्डरों ने बल्लेबाजी क्षेत्र और पिच के आसपास ही घेर लिया है। धवन यहां शॉट नहीं खेल सकते और वन टिप वन हैंड भी यहां आउट है। धवन इसी अंदाज में आउट होते हैं।

टी-20 में ऑस्ट्रेलिया सही दिशा में अग्रसर : मैक्सवेल

ब्रिस्बेन, एएफपी: ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल का मानना है कि टी-20 क्रिकेट में टीम पिछले एक-दो साल से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मैक्सवेल ने कहा कि मेरा मानना है कि पिछले डेढ़-दो साल से हमने अच्छी उन्नति की है और अपने परिणाम में काफी सुधार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह हमारे खेलने के तरीके में भी झलकता है जब हमने टी-20 क्रिकेट देखना शुरू किया था।

ओसाका डब्ल्यूटीए फाइनल्स से हटीं

शेनजेन (चीन), रायटर: दो बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका कंधे की चोट के कारण मंगलवार को सत्र के आखिरी टूर्नामेंट डब्ल्यूटीए फाइनल्स से हट गईं। इस बात की जानकारी टूर्नामेंट के आयोजकों ने मंगलवार को दी।

यह लगातार दूसरा वर्ष है कि जब चोटिल होने के कारण ओसाका को इस इस टूर्नामेंट से हटना पड़ा। पिछले साल मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उन्हें इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। दुनिया के तीसरे नंबर की खिलाड़ी ओसाका को रेड ग्रुप में मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी से भिड़ना था, लेकिन अब उनके हटने से नीदरलैंड्स की किकी बर्टेंस को मौका मिल गया। चोट के कारण डब्ल्यूटीए फाइनल्स से हटने पर निराशा जाहिर करते हुए ओसाका ने कहा, 'मैं फाइनल्स से हटकर निराश हूं। शेनजेन में होने वाला यह शानदार और डब्ल्यूटीए का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है।

टेनिस डायरी

- कंधे की चोट के कारण साल के अंतिम टूर्नामेंट से हटीं नाओमी
- पिछले साल भी हुई थीं चोट का शिकार

पेरिस मास्टर्स में सोंगा आगे बढ़े

पेरिस, एएफपी: फ्रांस के अनुभवी टेनिस स्टार विल्फ्रेड सोंगा पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 2008 में पेरिस मास्टर्स जीतने वाले फ्रांस के अंतिम खिलाड़ी रहे सोंगा ने रूस के आंद्रे रूबलेव को एक सेट से पिछड़ने के बाद 4-6, 7-5, 6-4 से हराया। 34 वर्षीय सोंगा ने इस मुकाबले के निर्णायक सेट में चार बार मैच प्वाइंट बचाए। उनके अलावा जेरेमी चार्डी और पेनोइट पियरे ने भी अगले दौर में जगह बनाकर अपने घरेलू प्रशंसकों को जश्न मनाने के मौके दिए। चार्डी ने अमेरिका के सैम क्वेरी को 5-7, 6-3, 7-5 से हराया, जबकि पियरे ने बोस्निया के डेमिर जुमहूर को 7-5, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं, बोर्ना कोरिक को फर्नांडो वर्डास्को ने 3-6, 6-4, 6-3 से हराया।

शिव व छह अन्य भारतीय मुक्केबाज सेमीफाइनल में

टोक्यो, प्रेट्र: भारत के स्टार मुक्केबाज और चार बार के एशियन चैंपियन शिव थापा (63 किग्रा) ने मंगलवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करके ओलंपिक टेस्ट इवेंट में अपना पदक पक्का किया, जबकि छह अन्य भारतीयों ने रिंग में उतरे बिना ही सेमीफाइनल में जगह बनाई।

थापा ने स्थानीय मुक्केबाज युकी हिराकावा को 5-0 से हराया। असम के इस मुक्केबाज ने इस महीने के शुरू में अपना तीसरा राष्ट्रीय खिताब जीता था। सेमीफाइनल में बुधवार को उनका सामना जापान के ही देसुके नारिमात्सु से होगा। नारिमात्सु को पहले दौर में बाई मिली थी।

वहीं, निखत जरीन (51 किग्रा) सहित छह भारतीयों का रिंग में उतरे बिना ही पदक पक्का हो गया। इन सभी को बाई मिली। जरीन के अलावा सुमित सांगवान (91 किग्रा), आशीष (69 किग्रा), वनालिम्पुइया (75 किग्रा), सिमरनजीत कौर (60 किग्रा) और पूजा रानी (75 किग्रा) ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस महीने के शुरू में राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले सांगवान का सामना कजाखिस्तान के एबेक ओरलबे से होगा, जबकि जरीन जापान की साना कवानो से भिड़ेगी। जरीन हाल में एमसी मेरी कॉम से ट्रायल मुकाबला करवाने को लेकर चर्चा में रही थीं।

मुकाबला
- थापा ने ओलंपिक टेस्ट इवेंट में पदक किया पक्का
- छह भारतीय रिंग में उतरे बिना ही अंतिम चार में पहुंचे

विश्व चैंपियनशिप से बाहर जोशना

काइरो, प्रेट्र: भारत की शीर्ष स्क्वॉश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा प्री क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त नूर इल शेरबिनी से सीधे गेम में हारने के कारण सीआइबी पीएसए विश्व महिला स्क्वॉश चैंपियनशिप से बाहर हो गईं। विश्व में 12वें नंबर की खिलाड़ी जोशना को 5-11, 3-11, 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। तीन बार की विश्व चैंपियन इल शेरबिनी शुरू से हावी हो गईं और उन्होंने पहले दो गेम में आसान जीत दर्ज की। चिनप्पा ने तीसरे गेम में उन्हें थोड़ी चुनौती दी, लेकिन वह मिस्र की खिलाड़ी को सीधे गेम में जीत दर्ज करने से नहीं रोक पाईं। जोशना की यह मिस्र की इस खिलाड़ी के हाथों लगातार दूसरी हार है। वह 2017 में चाइना स्क्वॉश ओपन में भी उन्हें हार मिली थी।

कांस्य के लिए भिड़ेंगे वीर देव

बुडापेस्ट, प्रेट्र: वीर देव गुलिया (79 किग्रा) यूडब्ल्यूडब्ल्यू अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हारने के कारण अब कांस्य पदक के मुकाबले में भिड़ेंगे।

गुलिया ने शुरू से शानदार फॉर्म दिखाई। उन्होंने हंगरी के बोतोंड लुकास को 3-1 से हराने के बाद चीन के लिगान चाइ को 7-2 से पराजित करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। गुलिया ने सोमवार रात अंतिम आठ में भी प्रभावशाली प्रदर्शन करके मंगोलिया के बातजुल दामजिन को 12-1 से शिकस्त दी थी। सेमीफाइनल में हालांकि इस 22 वर्षीय पहलवान का सफर अजरबेजान के अबुबाकर अबाकारोव ने थाम दिया, जिन्होंने 8-1 से जीत दर्ज की। गुलिया अब कांस्य पदक के लिए प्लेऑफ मैच खेलेंगे।

इस बीच 70 किग्रा में नवीन क्वालीफाइंग मुकाबले में रूस के 16वीं वरीयता प्राप्त चेरमेन वालीव से 0-11 से हार गए। रूसी खिलाड़ी के फाइनल में पहुंचने के कारण नवीन को रेपचेज में खेलने का मौका मिल गया, जहां उनका मुकाबला मंगोलिया के तेमुलेन एनखतुया से होगा।

गुलिया के अलावा भारत के अन्य पहलवानों में श्रवण (65 किग्रा) और आकाश अंतिल (97 किग्रा) ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। श्रवण ने कजाखिस्तान के शीर्ष वरीयता प्राप्त रिफात सैबोतालोव को 8-6 से हराया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में वह फ्रांस के इलमान मुखातरोव से 6-10 से हार गए। फ्रांसीसी पहलवान फाइनल में नहीं पहुंच पाया।

अंडर-23 विश्व कुश्ती
- गुलिया को सेमीफाइनल में करना पड़ा हार का सामना
- चैंपियनशिप में नवीन भी रेपचेज दौर में पहुंचने में सफल रहे

तैयारी | बीसीसीआइ ने कंपनी को दिया 10 दिन में 60 गेंद तैयार कराने का ऑर्डर, गेंद को खास चमक देने पर रहेगा कंपनी का जोर

डे-नाइट टेस्ट में एसजी गेंद से होगी खिलाड़ियों की असली परीक्षा

निखिल शर्मा • नई दिल्ली

कोलकाता का ईडन गार्डेंस स्टेडियम ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने अभी तक डे-नाइट टेस्ट नहीं खेला है। ऐसे में इस डे-नाइट टेस्ट में एसजी कंपनी की गेंद दोनों टीमों के खिलाड़ियों की असल परीक्षा लेगी। बीसीसीआइ ने कंपनी को 10 दिनों के भीतर ही 60 गेंद उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया है।

पहली बार डे-नाइट में होगा एसजी का इस्तेमाल: ऐसा पहली बार होगा जब डे-नाइट टेस्ट में एसजी गेंद का इस्तेमाल होगा। अब तक हुए सभी 11 डे-नाइट टेस्ट कूकाबुरा व ड्यूक से खेले गए हैं।

दलीप ट्रॉफी में हुआ था कूकाबुरा का इस्तेमाल

बीसीसीआइ ने 2016 में पहली बाद दलीप ट्रॉफी में गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह गेंद एसजी कंपनी की नहीं थी। यह कूकाबुरा गेंद थी, जिसके बाद गेंद की चमक को लेकर युवराज सिंह व सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने शिकायत की थी। साथ ही स्पिनरों को इस गेंद से समस्या हुई थी।

10 दिन में 60 गेंद का ऑर्डर: एसजी कंपनी के निदेशक पारस आनंद ने दैनिक जागरण को बताया कि मंगलवार शाम को बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोलकाता में डे-नाइट टेस्ट मैच आयोजित होने की जानकारी दी। उसके कुछ देर बाद ही बीसीसीआइ की ओर से हमारे पास 10 दिनों के भीतर 60 गेंद तैयार कराने का ऑर्डर आ गया था।

खास चमक हल करेगी समस्या: पारस ने आगे बताया कि गुलाबी गेंद में अब तक यह समस्या आती रही है कि यह 20 से 25 ओवर बाद ही चमक खो देती थी और फ्लड लाइट में खिलाड़ियों को गेंद को देखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन हमारी कंपनी इस समस्या पर ही काम करेगी। हम ऐसी गेंद तैयार करेंगे जो 80 ओवर तक भी अपनी चमक नहीं खोएगी। हम बीसीसीआइ को इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे।

खिलाड़ियों को किया है संतुष्ट: पिछले वर्ष विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों ने एसजी गेंद की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद से कंपनी ने अपनी गेंद में सुधार किया है। पारस ने कहा कि पिछले वर्ष खिलाड़ियों को कुछ समस्या हुई थी। कंपनी ने इस पर काम किया। आप इस सत्र में अगर देखें तो अब 50 ओवर बाद तेज गेंदबाज विकेट निकाल रहे हैं। चौथे और पांचवें दिन मुहम्मद शमी और उमेश यादव जैसे तेज गेंदबाज स्पिन के मुफीद हो चुकी पिच पर विकेट निकाल रहे थे। बीसीसीआइ सूत्रों की मानें तो गांगुली ने एक टीम बनाई है, जो कंपनी के साथ तालमेल बनाए रखेगी।

एसजी गेंद ही प्राथमिकता: गांगुली ने भी एसजी गेंद के इस्तेमाल को लेकर कहा कि डे-नाइट टेस्ट में इसी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पहला टेस्ट एसजी से ही होगा। एक सीरीज में दो गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हमने एसजी को चुना। हमने एसजी कंपनी को 10 दिन के भीतर ऑर्डर पूरा करने को कहा है। इस ऑर्डर से दोनों टीम अभ्यास करेंगी। इसी के साथ कोलकाता टेस्ट के लिए भी इन्हीं गेंद का इस्तेमाल किए जाने की योजना है।

बत्ती गुल होने को लेकर बदनाम रहा है ईडन

विशाल श्रेष्ठ • कोलकाता

कभी मैच के दौरान फ्लड टावर की बत्तियां बुझने को लेकर बदनाम रहा ईडन गार्डेंस स्टेडियम भारत में पहले डे-नाइट टेस्ट मैच की मेजबानी कर नया इतिहास रचने जा रहा है। बेशक ईडन के नाम बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज होने जा रही है, लेकिन इसके साथ ही बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के सामने बहुत बड़ी चुनौती भी आ गई है, हालांकि कैब इसके सफल आयोजन को लेकर आश्वस्त है।

कैब के एक अधिकारी ने बताया कि ईडन में मैच के दौरान फ्लड टावर की बत्तियां बुझना बीते जमाने की बात हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। फ्लड टावर की बत्तियों की पूरी व्यवस्था नई है, इसलिए डे-नाइट टेस्ट के पांच दिनों में इसे लेकर कोई समस्या नहीं होगी। वहीं, कैब सूत्रों ने बताया कि फ्लड टावर की बत्तियों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर खेल उसकी दूधिया रोशनी में ही होगा। प्रत्येक फ्लड टावर की बत्तियों व जेनरेटर का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाएगा। मालूम हो कि ईडन में मैच नहीं होने पर भी उसके चारों फ्लड टावर की बत्तियों को समय-समय पर जलाकर उनकी जांच की जाती है।

बत्तियां गुल होने का लंबा इतिहास: ईडन में मैच के दौरान बत्तियां गुल होने का लंबा इतिहास रहा है, फिर चाहे वह अंतरराष्ट्रीय मैच हो या फिर आइपीएल मैच। इसे लेकर कैब की काफी किरकिरी भी हुई है। 2008 में आइपीएल के दौरान डेक्कन चार्जर्स व कोलकाता नाइटराइडर्स के मैच के दौरान अचानक एक फ्लड टावर की बत्तियां गुल हो गई थीं, जिसके कारण 25 मिनट तक मैच बाधित रहा था। इसी मैदान पर 24 दिसंबर, 2009 को भारत-श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच में भी 15 मिनट तक हाई कोर्ट छोर वाले फ्लड टावर की बत्तियां गुल रही थीं, जिसके कारण मैच 23 मिनट तक रुका रहा था। 27 मार्च, 2016 को आइसीसी टी-20 विश्व कप में बांग्लादेश-न्यूजीलैंड के बीच सुपर-10 के मैच में भी बत्तियां 10 मिनट तक गुल रही थीं। ईडन में बत्तियां गुल होने को लेकर अक्सर साजिश के आरोप भी लगते रहे हैं।

ईडन में मैच के दौरान कई बार बुझी हैं बत्तियां, कैब आश्वस्त, डे-नाइट टेस्ट के दौरान नहीं होगी ऐसी कोई घटना

परिवार के साथ समय बिताने के बाद ट्रेनिंग पर लौटे रहाणे

मुंबई, आइएएनएस : भारतीय टेस्ट उपकप्तान अजिंक्य रहाणे परिवार के साथ समय बिताने के बाद ट्रेनिंग पर लौट आए हैं। 31 वर्षीय रहाणे ने कुछ समय के लिए खेल से ब्रेक लिया था क्योंकि वह दूसरी बार पिता बने थे। उनकी पत्नी राधिका ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने सात अक्टूबर को अपने परिवार के साथ एक फोटो भी पोस्ट की थी, जिसके बाद पूर्व क्रिकेटरों ने उन्हें बधाई दी थी।

समय के मुताबिक शरीर को ढालना डे-नाइट टेस्ट में परेशानी होगी।
– निलेश कुलकर्णी, पूर्व स्पिनर

फुटबॉल डायरी ▶ 2-0 से हराकर जीता महिला कोपा लिबर्टाडोरेस कप का खिताब, टूर्नामेंट में किए 16 गोल

फेरोविरिया को हरा कोरिनथियंस बना चैंपियन

कोरिनथियंस ने दूसरे हाफ में दागे दोनों गोल

क्विटो (इक्वाडोर), रायटर : ब्राजील के महिला फुटबॉल क्लब कोरिनथियंस ने सोमवार को महिला कोपा लिबर्टाडोरेस का खिताब जीत लिया। कोरिनथियंस ने दूसरे हाफ में दो गोल करते हुए फेरोविरिया को 2-0 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया।

साओ पाउलो के क्लब कोरिनथियंस ने पहले हाफ में बेहतर खेल दिखाया, जहां उसका एक गोल ऑफ साइड करार दिया गया। हालांकि, खेल के 73वें मिनट में गियोवाना क्रिवेलरी ने जवाबी हमले के दौरान गोल करके कोरिनथियंस को बढ़त दिलाई। इसके बाद निर्धारित समय से एक मिनट पहले जूलियट ने गोल करके कोरिनथियंस की जीत पर मुहर लगा दी।

इक्वाडोर में 17 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में कोरिनथियंस की टीम अजेय रही और इस दौरान उसने 16 गोल किए। पिछले 11 साल में यह आठवां मौका है जब किसी ब्राजीली टीम ने इस टूर्नामेंट में खिताबी जीत हासिल की है। दक्षिण अमेरिका के 10 देशों की 16 टीमों ने महिला कोपा लिबर्टाडोरेस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिसे दक्षिण अमेरिका में यूएफा चैंपियंस लीग के स्तर का टूर्नामेंट माना जाता है। इससे पहले कोलंबिया के क्लब अमेरिका ने पराग्वे के क्लब केरो पोरटेनो को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।

खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ जश्न मनाती कोरिनथियंस की टीम की खिलाड़ी। एएफपी

ब्राजील और उरुग्वे से भिड़ेगा अर्जेंटीना

ब्यूनस आयर्स, आइएएनएस : दो बार का विश्व चैंपियन अर्जेंटीना अपने दक्षिण अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी ब्राजील और उरुग्वे से दो दोस्ताना मुकाबलों में भिड़ेगा। अर्जेंटीना की टीम सऊदी अरब में 15 नवंबर को ब्राजील के खिलाफ उतरेगी और उसके चार दिन बार वह उरुग्वे से इजराइल में खेलेगी। इन मुकाबलों के लिए अर्जेंटीना के कोच लियोन स्कॉलनी अपने स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी को टीम में बुला सकते हैं, जो तीन महीने का निलंबन काट चुके हैं।

बाला देवी ने बदलाव की सराहना की

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय महिला फुटबॉल टीम की सीनियर खिलाड़ी बाला देवी ने हाल के समय में राष्ट्रीय स्तर व्यवस्था में आए बदलाव की तारीफ की और कहा कि इससे कई तरीकों से खिलाड़ियों की मदद हुई है। वियतनाम के खिलाफ तीन और छह नवंबर को खेले जाने वाले भारत के दोस्ताना मुकाबलों की तैयारियों के लिए वह टीम के साथ शिविर में भाग ले रही हैं। बाला देवी ने कहा, 'मैंने 2005 में पदार्पण किया और पिछले एक दशक से अधिक समय से राष्ट्रीय टीम में खेल रही हूं। लेकिन, हाल के समय में कई बदलाव आए हैं और ये सभी बदलाव अच्छे हैं। हमें आहार व्यवस्था, प्रशिक्षण सत्रों में बदलाव के साथ वीडियो विश्लेषण की मदद भी मिल रही है, जो काफी अहम है। उचित आहार योजना, कार्बोहाइड्रेट संतुलन, प्रोटीन के सेवन, ऐसे पहलू हैं जिनका आजकल ध्यान रखा जा रहा है। यह खिलाड़ियों को तेजी से फिटनेस हासिल करने में मदद करता है। पहले की तुलना में हम अब जिम में ज्यादा समय बिता रहे हैं।

टी-20 विश्व कप की तैयारी अब हो गई शुरू : बेयरस्टो

वेलिंगटन, एएफपी : इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी-20 सीरीज के जरिये उनकी टीम आगामी टी-20 विश्व कप की तैयारी शुरू करेगी। टी-20 विश्व कप अगले साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा।

बेयरस्टो ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह टी-20 विश्व के लिए हमारी तैयारियों की शुरुआत है। 50 ओवर के विश्व कप का साइकल चार साल पहले शुरू हुआ था और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने उस विश्व कप में खेला उसी तरह का प्रदर्शन आगामी टी-20 विश्व कप में भी करने में कामयाब रहेंगे। बेयरस्टो ने कहा कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने का यह एक बेहतरीन समय है। कुछ बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक टीम के लिए बहुत क्रिकेट खेली है और वे सभी एक साथ हैं। उन्हें उतार-चढ़ाव से जूझने का अनुभव भी है। बेयरस्टो ने हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अभ्यास मैच में 45 गेंदों पर 78 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इंग्लैंड को इस साल हुए विश्व कप का खिताब दिलाने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी।

सीएसए अश्वेत खिलाड़ियों को मैदान में कम उतारने पर जांच करेगा

जोहानिसबर्ग, प्रेट्र : दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट (सीएसए) ने घरेलू सीरीज में बोर्ड के बदलाव के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहने पर केप कोबरा के टीम चयन की जांच करेगा, जिसने वॉरियर्स के खिलाफ आवश्यक तीन के बजाय सिर्फ दो अफ्रीकी मूल के अश्वेत खिलाड़ियों को मैदान में उतारा था। सीएसए ने परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता के तहत घरेलू मैचों के लिए हर टीम के अंतिम-11 खिलाड़ियों में छह अश्वेत खिलाड़ी को जगह देने की अपेक्षा रखता है जिसमें तीन अफ्रीकी मूल के अश्वेत खिलाड़ी हों। कोबरा की टीम ने केपटाउन में सोमवार को शुरू हुए चार दिवसीय प्रथम श्रेणी मैच में सिर्फ दो अफ्रीकी मूल के अश्वेत खिलाड़ियों को शामिल किया।

अखोना एमनियाका को पहले टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें अंतिम-11 में जगह नहीं मिली। कोबरा ने हालांकि बाद में टीम संयोजन को लेकर सीएसए को अपने रुख से अवगत कराया। सीएसए के संचार के प्रमुख थेमी माउंटेम्बी ने बताया कि सीएसए को प्रशासनिक शर्तों को पूरा नहीं करने के मामले में वेस्टर्न केप क्रिकेट (केप कोबरा) का आवेदन मिला है।

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ धौनी रिटायर, प्रशंसकों का ऐतराज

नई दिल्ली, आइएएनएस : ट्विटर पर अगर कोई हैशटैग ट्रेंड कर जाए तो इंटरनेट पर पूरे जमाने की नजरें वहां टिक जाती हैं, लेकिन यह हैशटैग अगर महेंद्र सिंह धौनी की रिटायरमेंट से जुड़ा हो तो उनके प्रशंसकों को इस हैशटैग का रुख बदलना भी बखूबी आता है।

मंगलवार की सुबह ट्विटर पर हैशटैग धौनी रिटायर्स खूब ट्रेंड कर रहा था। यह देखते ही धौनी के प्रशंसकों में मायूसी छा गई एक बार को उन्हें भी लगा शायद अपने हीरो धौनी को वह मैदान से बाहर ही रिटायर होते देखेंगे। लेकिन जल्दी ही प्रशंसकों को यह माजरा समझ में आ गया कि यह धौनी की मंशा नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर सेट किया गया फेक ट्रेंड है। इसके बाद धौनी के फैन्स इस ट्रेंड को रिवर्स करते हुए नेवर रिटायर धौनी ट्रेंड करा दिया।

महेंद्र सिंह धौनी। फाइल फोटो

धौनी के एक प्रशंसक ने लिखा कि धौनी जानते हैं उन्हें कब रिटायर करना है, कृपया आप ट्विटर से चले जाइए। इस यूजर ने कहा कि मुझे सुबूत चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि शुरुआत करने वाले बहुत हैं फिनिशर्स सिर्फ एक। एक अन्य यूजर ने यह खास तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभी हमें यह परिश्रम चाहिए। इस यूजर ने सवाल पूछा है कि कोई लड़की भी जब यह पूछे कि जादुई तीन शब्द कौन से हैं?

एटीके के फायरपावर से सावधान रहना चाहेगा चेन्नइयन

चेन्नई, आइएएनएस : दो बार का चैंपियन चेन्नइयन एफसी हीरो इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) के छठे सत्र में पहली जीत के लिए बेताब है। बुधवार को उसे जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में एटीके से भिड़ना है और चेन्नई की टीम इस मैच को जीतकर खाता खोलना चाहेगी। चेन्नई की टीम के खाते में सिर्फ दो अंक हैं। उसे अपने पहले मैच में एफसी गोवा के हाथों 0-3 से हार मिली थी जबकि रविवार को मुंबई सिटी एफसी से उसने गोलरहित ड्रॉ खेला था। ऐसे में जबकि एटीके अपने पिछले मैच में हैदराबाद एफसी के खिलाफ 5-0 की जीत के साथ चेन्नई पहुंचा है, मेजबान टीम के लिए पूरे अंक हासिल कर पाना आसान नहीं होगा।

चेन्नई की टीम ने गोवा के खिलाफ खराब प्रदर्शन किया था लेकिन मुंबई के खिलाफ उसके प्रदर्शन में थोड़ा सुधार दिखा था। यह अलग बात बात है कि यह टीम अब तक दो मैचों में एक भी गोल नहीं कर सकी है। कोच जॉन ग्रेगोरी हालांकि इससे निराश नहीं हैं और उनका ध्यान टीम द्वारा बनाए गए मौकों पर है। ग्रेगोरी ने कहा कि मुंबई के खिलाफ हमने सबकुछ किया लेकिन स्कोर नहीं कर सके। हमने कई मौके बनाए। हमने गोल पर 18 शॉट्स लिए। सभी टारगेट पर नहीं थे लेकिन कुछ में गोल करने का मौका था। मैं हैरान हूं कि हम कैसे स्कोर नहीं कर पाए। अमरिंदर ने कुछ शानदार बचाव किए और इस कारण मैं अपनी टीम में सुधार से प्रभावित हूं।

रफाएल क्रिवेलारो, अनिरुद्ध थापा, लालियाजुआला चांग्ते और द्रागोस फिर्टूलेस्कू पर चेन्नई के लिए मौके बनाने की जिम्मेदारी होगी जबकि एटीकी इन्हें शांत करने के लिए हर एक कोशिश करेगा। गोवा के खिलाफ चेन्नई के डिफेंस में छेद दिखा था लेकिन मुंबई के खिलाफ क्लीन शीट के बाद यह चिंता थोड़ी कम हुई है। लूसियान गोइयान के नेतृत्व में उसके डिफेंस पर एटीके के मजबूत आक्रमणकारियों को रोकने की

चेन्नइयन एफसी के कोच जॉन ग्रेगोरी। फाइल फोटो

जिम्मेदारी होगी।

हैदराबाद के खिलाफ डेविड विलियम्स और रॉय कृष्णा ने बेहतरीन खेल दिखाया था। स्पेनिश मिडफील्डर इदु गार्सिया भी बेहतरीन फार्म में दिखे थे। विंग्स में माइकल सूसाइराज और प्रबीर दास ने भी प्रभावित किया था। ग्रेगोरी को आभास है कि एंटोनियो हाबास की टीम में काफी फायरपावर है लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का यकीन है कि उनकी टीम इस फायरपावर को रोकने में सफल होगी।

ग्रेगोरी ने कहा कि एटीके को अपने दूसरे मैच में शानदार जीत मिली। उसने हर एक मौके पर गोल किया। विलियम्स और कृष्णा ने बेहतरीन खेल दिखाया। इन खिलाड़ियो को चुप रख पाना मुश्किल होगा लेकिन हम इन्हें रोकने में सफल होंगे, इसे लेकर मैं आश्वस्त हूं।

एटीके ने अपने दोनों मैचों में काफी जल्दी गोल किए थे और इसे लेकर ग्रेगोरी की टीम को सावधान रहना होगा। इसे लेकर ग्रेगोरी ने कहा कि हमने हर समय सावधान रहना होगा। एटीके की शुरुआत अच्छी होती है। यह उसने दोनों मैचों में साबित किया है। अब देखना होगा कि कौन मैच जीतता है।

विविध

सड़क हादसे में सफाईकर्मी सहित छह की मौत लेफ्टिनेंट का आइडी कार्ड मिलने से सनसनी

नईदुनिया, इंदौर

- एक मृतक सेना में सफाई कर्मी था, लेकिन उसके पास से लेफ्टिनेंट का आईडी कार्ड मिला
- पुलिस की सूचना पर सेना ने शुरू की जांच, जयप्रकाश के घर पर लगवाया ताला

मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार सुबह दो कारों की भिड़ंत में छह लोगों की मौत हो गई। इनमें महू में सेना में पदस्थ सफाईकर्मी जयप्रकाश झा, उसका चार माह का बेटा, माता-पिता और दो सहयोगी भी शामिल हैं। उसकी पत्नी और साली गंभीर घायल हुई हैं। जयप्रकाश के पास लेफ्टिनेंट का आइडी कार्ड मिला है। इससे पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जानकारी मिलते ही सेना भी सक्रिय हो गई है।

मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जब जयप्रकाश झा की क्षतिग्रस्त कार की तलाशी ली तो कार में रखे बैग में वायरलेस सेट, लेफ्टिनेंट का आइडी कार्ड, रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज और वर्दी मिली। सूचना पर सैन्य अधिकारी और सैन्य इंटेलिजेंस की टीम जांच करने पहुंच गई। कई घंटों बाद राजफाश हुआ कि जयप्रकाश सफाई कर्मी था और जो दस्तावेज मिले, वह फर्जी हैं। कर्नल स्तर के अधिकारियों ने तत्काल जयप्रकाश के घर पर ताला लगवा दिया और उसके लैपटॉप और मोबाइल की जांच शुरू कर दी।

झपकी लगने से हादसे की आशंका : पुलिस को आशंका है कि कार चला रहे जयप्रकाश को झपकी लग गई होगी और कार डिवाइडर पर चढ़ गई। रफ्तार तेज होने के कारण कार नियंत्रण से बाहर हो गई और 10 फीट चौड़े व ढाई फीट ऊंचे डिवाइडर को लांघते हुए कई बार पलटी। फिर करीब 75 फीट दूर जाकर दूसरी लेन में सामने से आ रही स्क्रैप व्यापारियों की कार से जा भिड़ी।

इंदौर में देवास बाइपास पर मंगलवार सुबह दो कारें आपस में भिड़ गईं। हादसे के बाद दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। नईदुनिया

इस कार में बैठे चार व्यापारी अरशद पुत्र ताज मोहम्मद निवासी गोंडा (उप्र), अनवर पुत्र रमजान निवासी सिद्धार्थनगर (उप्र), अर्जुन पुत्र शिवदीन यादव निवासी अहिरोला (उप्र)व धनीराम पुत्र गौतम दसई निवासी बलरामपुर (उप्र) घायल हो गए। केप्टिवा सवार जयप्रकाश झा (26) सहित उनके पिता नूनू झा (65), मां सुमित्रा (60), बेटा आरव (चार माह) सहित सहायक रोशन और गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। जयप्रकाश की पत्नी सुरुचि और साली रुचि घायल हैं।

छुट्टियां निरस्त होने से आधे रास्ते से लौट रहे थे

घायल सुरुचि के अनुसार उनका परिवार मूलत: बिहार के वैशाली जिले के महुआ के झंडाहा लोमा बिजरौली का रहने वाला है। सोमवार रात वह छठ पूजा के लिए घर जा रहे थे। लेकिन, अचानक जयप्रकाश ने कहा कि छुट्टियां निरस्त हो गई हैं इसलिए सभी बीच रास्ते से ही लौट आए। जिस वक्त हादसा हुआ, तब सभी सो रहे थे। मुझे तो अस्पताल में ही होश आया।

अमेरिका से आए पत्र से पता चला मप्र के शिशु गृह में हो रहा है शोषण

नईदुनिया, रीवा : मध्य प्रदेश के रीवा में संचालित आंचल शिशु गृह में बच्चों के शोषण का मामला उजागर हुआ है। यह राजफाश अमेरिकी नागरिकों द्वारा गोद लिए गए बच्चों ने किया है। अमेरिका से आए पत्र के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि रीवा में संचालित आंचल शिशु गृह से चार बच्चों को अमेरिका के रहने वाले क्लिंटन एवं आमडा ने गोद लिया था। लगभग चार माह पूर्व उन बच्चों को वह अमेरिका लेकर गए थे। वहां काउंसलिंग के दौरान बच्चों ने रीवा शिशु गृह में शोषण किए जाने की बात बताई। इसके बाद अमेरिका से भारत सरकार को पत्र भेजा गया। मामले की जांच कर कार्रवाई करने के लिए शासन का पत्र रीवा कलेक्टर को मिला है। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर शिशु गृह में रह रहे पांच बच्चों को मातृछाया शिशु गृह सतना भेज दिया गया है। साथ ही नए बच्चों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। आंचल शिशु गृह का संचालन निवोदिता कल्याण समिति करती है। शिशु गृह की जांच करने के लिए कलेक्टर ने पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

अमेरिका से एक पत्र शिशु गृह के खिलाफ मिला है। इसकी जांच करवाई जा रही है। शिशु गृह में रह रहे बच्चों को सतना भेज दिया गया है। नए बच्चों का प्रवेश बंद कर दिया गया है।

रायपुर के एसएसपी को शिकागो में मिला बेस्ट पुलिसिंग का अवार्ड

नईदुनिया, रायपुर

- भारत से इकलौते अधिकारी, जिन्हें अवार्ड के लिए नामित किया गया
- इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस (आइएसीपी) देती है अवार्ड

छत्तीसगढ़ के रायपुर में मिशन ई-रक्षा, हर हेड हेलमेट अभियान चलाकर 15 हजार से अधिक दोपहिया वाहन चालकों को नि:शुल्क हेलमेट बांटने पर एक बार फिर से एसएसपी आरिफ शेख को सोशल पुलिसिंग के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आइएसीपी अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस (आइएसीपी) के शिकागो (यूएसए) में हुए 126वें वार्षिक सम्मेलन में शेख को यह अवार्ड आइएसीपी अध्यक्ष पॉल सेल ने दिया।

शेख यह अवार्ड पाने वाले देश के इकलौते आइपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले बालोद एसपी रहते हुए कम्युनिटी पुलिसिंग, बस्तर में होमलैंड सिक्युरिटी के क्षेत्र बेहतर काम करने पर यह अवार्ड वह हासिल कर चुके हैं।

रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख को बेस्ट पुलिसिंग के लिए शिकागो में अवॉर्ड से सम्मानित करते आइएसीपी संस्था के अध्यक्ष पॉल सेल।

पुलिस अधिकारियों की अंतरराष्ट्रीय संस्था देती है अवार्ड

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस ऐसा संगठन है, जो दुनिया भर में पुलिसिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को अवार्ड प्रदान करता है। संस्था का मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया वर्जिनिया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। इस अवार्ड को पुलिसिंग का आस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। यह अवार्ड 40 वर्ष से कम उम्र के पुलिस अफसरों को दिया जाता है। संगठन ऐसे पुलिस अधिकारियों का चयन करता, जिनके कार्यों से पुलिसिंग में नया प्रयोग हुआ, अच्छे कार्यों से बदलाव आया हो। पिछले पांच वर्षों में पुलिस की छवि सुधारने के लिए एसएसपी आरिफ शेख द्वारा किए गए कार्यों के आकलन के आधार पर यह अवार्ड दिया गया। समारोह में विश्व के सात देशों के 40 पुलिस अफसरों को ये अवार्ड दिया गया।

कबीर की मजार पर पहली बार दीपावली पर जले दीये

राज नारायण मिश्र, संतकबीर नगर

पूरे विश्व को शांति और समरसता का संदेश देने वाले महान संत कबीर की मजार पर पहली बार दीपावली मनी। कबीर की मस्जिद भी दीयों से रोशन हुई। इससे पहले सिर्फ कबीर की समाधि पर ही लोग दीपक जलाते थे। वाराणसी के कबीर चौरा के संत विचारदास, लाल बाबा और मजार के मुतव्वली खादिम हुसैन अंसारी की संयुक्त अपील पर नगर के लोग आगे आए और समाधि के साथ ही मजार को भी रोशन कर दिया। इससे पहले दीपावली पर मजार अंधेरे में ही रहती थी। दीपोत्सव कार्यक्रम का नेतृत्व संत रामलखन दास उर्फ लाल बाबा ने किया।

विश्व को प्रेम-सद्भाव का संदेश : कबीरपंथी संत रामलखन दास के मुताबिक कबीर ने पूरे विश्व को प्रेम, सद्भावना का संदेश दिया है। इनकी वाणी व दिखाए गए रास्ते पर चलने से ही विश्व में शांति, प्यार की भावना विकसित होगी।

कबीर चौरा मगहर के महंत विचार दास के मुताबिक कबीर ने जो मार्ग दर्शन किया है, उस पर सभी को चलने की जरूरत है। इसी से शांति और आपसी भाईचार की भावना बढ़ेगी। दीपावली पर मजार को रोशन करना एक बेहतर पहल है।

शराब के लिए 300 रुपये नहीं दिए तो दबंगों ने पूरे परिवार को पीटा, एक की गई जान

नईदुनिया, भिंड

- मप्र के भिंड जिले का मामला, केस दर्ज
- एक महिला की हालत गंभीर होने पर किया ग्वालियर रेफर

मध्य प्रदेश में भिंड जिले के पुर गांव में शराब के लिए 300 रुपये नहीं देने पर दबंगों ने एक युवक को पीटा। वह उसे पीटते हुए उसके घर ले गए। वहां बचाने आए मां-बाप से भी मारपीट की। मारपीट में घायल युवक के पिता ने मंगलवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मां को ग्वालियर रेफर किया गया है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे पुर गांव निवासी उदयवीर जाटव पुत्र श्रीपाल जाटव घर पर थे। उनके पास गांव के ही सोनू नरवरिया पुत्र सिद्धार्थ नरवरिया का फोन आया। सोनू ने उदयवीर से अपने घर आने को कहा। वहां सोनू और उसके भाई रामू नरवरिया ने उदयवीर से शराब के लिए 300 रुपये मांगे। उदयवीर ने रुपये देने से इन्कार किया तो आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोपित उदयवीर को पीटते हुए उसके घर तक ले गए। यहां उदयवीर को बचाने के लिए बुजुर्ग पिता श्रीपाल जाटव (65) और मां लोंगश्री जाटव आईं। आरोपितों ने उन्हें भी पीटा। पिटाई से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयवीर का कहना है कि वह घायल माता-पिता को साथ लेकर देहात थाने गए। यहां करीब एक घंटे बाद रिपोर्ट लिखी गई। श्रीपाल और लोंगश्री को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां मंगलवार सुबह नौ बजे श्रीपाल की मौत हो गई। लोंगश्री के सिर में गहरी चोट बताकर डॉक्टर ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया।

पुर गांव में झगड़े में बुजुर्ग घायल हुए थे। आरोपितों पर केस दर्ज किया है। एससी-एसटी एक्ट भी लगाया गया है। एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है।
–शैलेंद्र कुशवाह, थाना प्रभारी, थाना देहात, भिंड

मौसम विशेष

दक्षिणी राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली में आंशिक बादल छाये रहेंगे। शीतल सुबह में धुंध रहेगी। दिन आरामदायक बना रहेगा। प्रदूषण में हल्की वृद्धि जारी रहेगी। रात का मौसम शीतल रहेगा। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में सुबह और छिटपुट बादलों के साथ दिन सहज रहेगा।

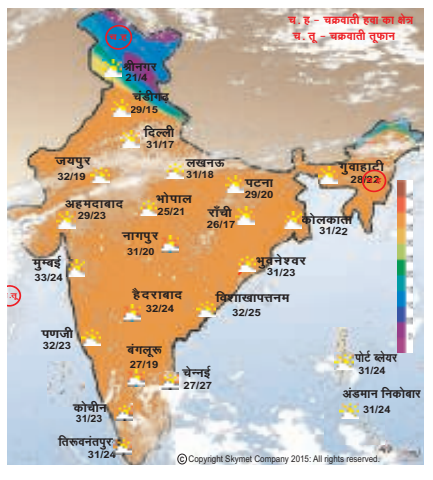

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/25/व	अहमदाबाद	34/25/आंबा
कोलकाता	31/23/आंबा	बड़ोदा	34/22/आंबा
चेन्नई	32/23/व	नागपुर	32/20/व
हैदराबाद	31/23/आंबा	इन्दौर	30/22/आंबा
बंगलूरू	26/19/आंबा	रांची	30/21/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/24/व	पटना	32/22/आंबा
गुवाहाटी	29/22/आंबा	जमशेदपुर	31/23/व
गंगटोक	12/-2/व	पुणे	30/21/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 30 अक्टूबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश बना भारत

1945 में आज ही भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य बना। ब्रिटिश उपनिवेश होने के बावजूद भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वतंत्र सीटें मिलीं। अक्टूबर 1944 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत मूल देश बना था।

कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गैट समझौता हुआ

1947 में आज ही कई देशों के बीच जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) समझौता हुआ। इसका मकसद शुल्क और कोटा को कम करते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। 23 देशों ने जेनेवा में हस्ताक्षर किए और एक जनवरी 1948 से यह अमल में आया।

भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे डॉ. होमी जहांगीर भाभा

आज अगर हम आधी दुनिया को अपने परमाणु हथियारों की जद में कर चुके हैं तो इसके पीछे डॉ. भाभा की कड़ी मेहनत रही है। 1909 में आज ही मुंबई में जन्म हुआ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी एस्टाब्लिशमेंट, ट्रांबे (अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर) के संस्थापक निदेशक रहे। भारत के परमाणु कार्यक्रम में इन दोनों का अहम योगदान है। 1942 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय ने एडम्स प्राइज से नवाजा। 1954 में पद्मभूषण मिला। नोबेल के लिए भी नामांकित हुए। 24 जनवरी 1966 को विमान दुर्घटना में मौत हो गई।

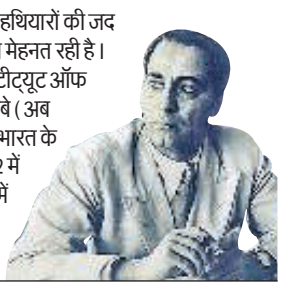

इधर-उधर की

कभी देखा है ऐसा कामचोर घोड़ा

बीजिंग, एजेंसी : घोड़ों के करतब से इतिहास भरा पड़ा है। इनकी बहादुरी और शौर्य गाथाएं इन्हें योद्धाओं का सबसे खास मित्र बताती रही हैं। लेकिन चीन के जिंगैंग में एक घोड़े की कामचोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यूट्यूब पर डाले गए इसके वीडियो को अब तक 25 लाख लोग देख चुके हैं। दरअसल यह घोड़ा किसी को सवारी करने ही नहीं देता है। जैसे ही कोई इस पर सवार होता है, तभी यह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। अपने शरीर और हाव-भाव को ऐसा कर देता है, मानो इसमें जान ही नहीं हो। जैसे सवार दूर जाता है, फिर से यह उठ खड़ा हो जाता है। इस वीडियो पर प्रतिक्रियाएं भी अनोखी आ रही हैं। कुछ लोग इसे बहुत समझदार और चतुर बता रहे हैं। तो कुछ लोग इसकी कामचोरी पर लताड़ लगा रहे हैं।

पर्वतारोही ने सात माह में फतह कीं 14 सबसे ऊंची चोटियां

नेपाल के निर्मल पुरजा ने तोड़ा पोलैंड के पर्वतारोही जेरेज कुकुक्जा का रिकॉर्ड

काठमांडू, एएफपी : नेपाल के पर्वतारोही निर्मल पुरजा ने मंगलवार को दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को सबसे कम समय में फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। निर्मल ने अपनी इस उपलब्धि को सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने 8,000 मीटर से ऊंची दुनिया की 14 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई के लक्ष्य को सिर्फ सात महीने में हासिल कर लिया।

निर्मल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, 'मिशन एचीव्ड'। इसमें उन्होंने चीन की अंतिम चोटी शीशपंगमा को फतह करने का भी उल्लेख किया है। उनसे पहले पोलैंड के पर्वतारोही जेरेज कुकुक्जा ने वर्ष 1987 में यह रिकॉर्ड कायम किया था। उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने में सात साल 11 महीने और 14 दिनों का समय लगा था। निर्मल ने हाल में एक साक्षात्कार में कहा था कि जब उन्होंने पहली बार अपनी योजना के बारे में लोगों को बताया तो वे उन पर हंसने लगे। लोगों ने कहा कि यह कैसे संभव होगा? निर्मल ने कहा, हमें अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए।

अप्रैल में शुरू किया था प्रोजेक्ट पॉसिबल

ब्रिटिश सेना में काम कर चुके निर्मल (36) अप्रैल में 'प्रोजेक्ट पॉसिबल' की शुरुआत की थी। इसके पहले चरण में उन्होंने अन्नपूर्णा, धौलागिरि, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ल्होत्से और मकालू पर्वत पर चढ़ाई की। दूसरे चरण में वह पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने 8,125 मीटर ऊंचे नंगा पर्वत की सफल चढ़ाई की। सितंबर में चो ओयू और मनासलु चोटी को तो उन्होंने एक सप्ताह में ही फतह कर लिया था।

निर्मल पुरजा। फाइल

एवरेस्ट पर जाम की स्थिति का फोटो हुआ था वायरल

इस वर्ष एवरेस्ट में पर्वतारोहियों के कारण जाम की स्थिति बन गई थी। फाइल

रायटर के अनुसार, निर्मल पुरजा ने मई में एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों की भीड़ की एक तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद नेपाल सरकार को एवरेस्ट पर भीड़ घटाने के लिए चढ़ाई के नियम बदलने पड़े थे।

अब आसानी से बनाई जा सकेगी सबसे ठोस सामग्री

स्पेक्ट्रम

- स्पेन के शोधकर्ताओं ने विकसित की नई तकनीक
- बोरॉन कार्बाइट बनाने में मिली सफलता, सस्ते दामों में बन सकेंगे यातायात साधनों के डिजाइन

मैड्रिड, प्रेट्र : प्रकृति की सबसे ठोस सामग्रियों में शुमार बोरॉन कार्बाइट नामक यौगिक को बनाने के लिए पहली बार वैज्ञानिकों ने एक विधि विकसित की है। दावा है कि इसकी मदद से अब किफायती दामों पर विमानों, कारों और अन्य यातायात के साधनों के डिजाइन बनाए जा सकेंगे।

साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि बोरॉन कार्बाइट सिरैमिक मैटेरियल (चिकनी मिट्टी की सामग्री) से संबंधित होता है। इस अध्ययन के शोधकर्ताओं में स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सिवेले के शोधार्थी भी शामिल थे। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह सामग्री बहुत कठोर है। यह उच्च तापमान पर भी स्थिर रहती है और रेडियोएक्टिव विकिरण को भी आसानी से झेल सकती है।

अध्ययन में बताया गया है कि बोरॉन कार्बाइट परिवार में बी 4 सी से बी 14 सी तक के यौगिक शामिल रहते हैं, जो बी (बोरॉन) और सी (कार्बन) के अनुपात पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक यौगिक के अलग-अलग भौतिक गुण भी होते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, 'इससे पहले हुए अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया था कि बी 6 सी सैद्धांतिक रूप से रेडियो तरंगों का विकिरण झेलने में सक्षम था। लेकिन इसका उत्पादन के करने के लिए अब तक कोई तरीका मौजूद नहीं था।'

प्रतीकात्मक

'लेजर जोन' का किया इस्तेमाल : नए अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने लेजर जोन तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें तेज लेजर विकिरण और फिर इसे जमाने की प्रक्रिया शामिल थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस तरह से प्राप्त बोरॉन कार्बाइट में 52 गिगापास्कल (जीपीए) की कठोरता आ जाती है और इसका यंग मॉड्यूलस 600 जीपीए होता है।

हीरे से भी कठोर है सामग्री : शोधकर्ताओं ने कहा, 'सबसे कठोर हीरे की तुलना में यह कहीं ज्यादा ठोस है क्योंकि सबसे कठोर हीरा लगभग 45 जीपीए का होता है। हालांकि, इसका यंग मॉड्यूलस 1050 जीपीए होता है।' उन्होंने कहा कि ऐसे में यह माना जा सकता है कि हीरे के बाद यह 'बी 6 सी' प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है।

बीमारी फैलने से रोकेंगे सेटेलाइट-ड्रोन

अध्ययन ▶ सिस्टोसोमाइसिस के कारणों का पता लगाकर शोधकर्ताओं ने किया दावा

कहा, इसके जरिये दुर्लभ बीमारियों से लोगों को दिलाई जा सकती है निजात

वाशिंगटन, प्रेट्र : भूमध्यरेखा के आसपास रहने वाले लोगों में फैलने वाली बीमारियों के कारणों का पता लगाने में ड्रोन और सेटेलाइट से लिए गए चित्र कारगर साबित हो सकते हैं। यह जानकारी अमेरिकी की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के एक नए अध्ययन में दी गई है। दरअसल, शोधकर्ताओं ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सिस्टोसोमाइसिस का पता करने के लिए ड्रोन और सेटेलाइट की मदद ली और पता लगाया है कि यह बीमारी कैसे लोगों में फैल रही है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इसके जरिये हम बीमारियों को बढ़ने से रोक सकेंगे।

सिस्टोसोमाइसिस एक परजीवी जनित रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह मलेरिया के बाद सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। अफ्रीकी देशों में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। इस बीमारी का परजीवी खास तौर से सदाबहार और वर्षा वनों के आस-पास रहने वाले समुदायों को निशाना बनाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सुबह से दोपहर तक तेज धूप और शाम होते-होते तेज बारिश होती है। ऐसी जलवायु में सिस्टोसोमाइसिस का परजीवी अन्य जीवों की मदद से आसानी से पनप जाता है। घने जंगलों के कारण इससे प्रभावित इलाकों की पहचान करना भी कठिन होता है।

नए अध्ययन में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि यदि ड्रोन, सेटेलाइट और गूगल अर्थ के जरिये ऐसे क्षेत्र चिह्नित किए जाएं तो यह अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि भूमध्यरेखा के आसपास सिस्टोसोमाइसिस कैसे फैल रहा है? इसके लिए शोधकर्ताओं ने उन क्षेत्रों के नमूने लेने के लिए फील्ड सैंपलिंग और हवाई चित्रों का उपयोग किया, जहां सिस्टोसोमाइसिस का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। शोधकर्ताओं ने कहा, 'इस दौरान उन्हें वातावरण में कई सुराग मिले, जो ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।'

20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं पीड़ित : पीएनएसी नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि विश्व में 20 करोड़ से ज्यादा लोग सिस्टोसोमाइसिस से पीड़ित हैं। इसका इलाज किया जा सकता है पर दुनिया के कुछ हिस्सों से इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता।

ऐसे फैलता है परजीवी : सिस्टोसोमाइसिस का परजीवी ताजे पानी में घोंघे के भीतर विकसित होते हैं और इनके जरिये नदियों, झीलों और तालाबों में फैल जाते हैं। यदि कोई इस पानी के संपर्क में आता है तो ये परजीवी उसकी त्वचा को भेद कर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।'

बीमारी के लक्षण : जिस व्यक्ति के शरीर में सिस्टोसोमाइसिस का परजीवी प्रवेश कर जाता है, उसका मूत्र (यूरिन) मार्ग और आंतें संक्रमित हो जाती हैं। इसके अलावा उसे पेट दर्द, डायरिया, खूनी पेचिस शुरू हो जाते हैं। यह लिवर और किडनी को खराब कर देता है। कई बार तो यह बांझपन का भी कारण बन जाता है। इससे प्रभावित बच्चों की शारीरिक वृद्धि तक रुक जाती है।

30 साइटों पर किया काम : यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के शोधकर्ता चेल्सी वुड ने कहा, 'इस अध्ययन के लिए उन्होंने अफ्रीका के उत्तर-पूर्वी सेनेगल की उन 30 साइटों पर काम शुरू किया, जहां के ग्रामीण स्थानीय नदी-तालाबों के पानी से सीधा संपर्क में रहते थे। शोधकर्ताओं ने लोगों के इस व्यवहार पर चिंता जताते हुए ऐसे मौकों पर सोच-विचार कर काम करने की सलाह दी है क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए सजा मिल जाए, जिसे उसने किया ही न हो। शोधकर्ताओं ने कहा, 'स्वचालित कारें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) पर आधारित होती हैं, जो मशीन लर्निंग के जरिये अपना काम करती हैं।'

प्रतीकात्मक

इलाकों की मैपिंग हो सकती है फायदेमंद

अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने दो साल तक इस क्षेत्र में सेटेलाइट और ड्रोन के जरिये घोंघे के वितरण की मैपिंग की। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जिस स्थान पर उन्हें घोंघे मिले थे तीन माह बाद उन इलाकों से घोंघे गायब हो गए थे, जिसका मतलब है कि घोंघे हमेशा गतिशील रहते हैं। वुड ने कहा, 'यदि हम ऐसे इलाकों की मैपिंग कर लेते हैं तो काफी हद तक हम सिस्टोसोमाइसिस को फैलने से रोक सकते हैं।'

शोध अनुसंधान

डिप्रेशन में प्रभावी हो सकती है पैरासिटामोल

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि डिप्रेशन (अवसाद) की गंभीर अवस्था को नियंत्रित करने में एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट मसलन पैरासिटामोल, स्टैटिन और एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावी हो सकती हैं। चीन के टोंग्जी अस्पताल के शोधकर्ताओं के अनुसार, दुनियाभर के करीब एक तिहाई अवसादग्रस्त लोगों पर मौजूदा दवाओं का सही असर नहीं हो पाता। पीड़ितों पर काउंसिलिंग थेरेपी और दवाओं का दुष्प्रभाव होना आम बात है। इन शोधकर्ताओं ने गत जनवरी में प्रकाशित हुए अध्ययनों का विश्लेषण किया और मेजर डिप्रेशन के इलाज में एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं को प्रभावी और सुरक्षित पाया। इन दवाओं को डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में 52 फीसद ज्यादा प्रभावी पाया गया। -प्रेट्र

घर के पास हो फास्ट फूड की दुकान तो बच्चे होते हैं प्रभावित

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक हालिया अध्ययन में कहा है कि स्कूल या घर के पास जंक फूड आउटलेट बच्चों के खाने की आदत पर असर डाल सकता है। इस तरह बच्चों के मोटापे की चपेट में आने का खतरा बढ़ सकता है। एनवाईयू स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकताओं की टीम ने फास्ट फूड आउटलेट के पास रहने वाले पांच से 18 साल की उम्र वाले बच्चों में से 20 फीसद को मोटापे से पीड़ित पाया। 38 फीसद ज्यादा वजनी पाए गए। -एएनआइ

भूल सुधार

दैनिक जागरण के 29 अक्टूबर के अंक में आजकल पेज के मत्थे पर अंतरराष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी के गठन की तारीख 29 अक्टूबर, 1963 लिखी गई है, इसकी जगह 29 अक्टूबर, 1863 होना चाहिए था। दरअसल इसी तारीख को इस अंतरराष्ट्रीय पहल के संदर्भ में पांच मूल प्रस्ताव अंगीकार किए गए थे जिन्हें इस संस्था की बुनियाद कहा जाता है। साल के प्रकाशन में हुई त्रुटि के लिए खेद है।

दिवाली पर नारंगी रंग की रोशनी से जगमगाई बिल्डिंग

दिवाली के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क के मिडटाउन मैनहट्टन स्थित एम्पायर एस्टेट बिल्डिंग पर नारंगी रंग की रोशनी की गई। यह खास आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोशिएशन (एफआइए) और एम्पायर एस्टेट ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से किया था। यह दुनिया में बढ़ती भारत की साख का भी प्रतीक है। न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में भारतवंशी हैं, जो दिवाली का उत्सव पूरे धूमधाम के साथ सेलीब्रेट करते हैं। प्रेट्र

....जब अवाक रह गईं मेलानिया

मानव कंकाल की पोशाक पहने स्कूली बच्चे को देखकर अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप गहरे अचरज में पड़ गईं। बच्चे को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मौका था, वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में हैलोवीन फेस्टिवल का। इस उत्सव में स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने बच्चों के साथ उत्सव का आनंद उठाया और उन्हें उपहार भी भेंट किए। रायटर

स्क्रीन शॉट

निगेटिव किरदार निभाने के लिए तैयार हैं आयुष्मान

लगातार छह हिट फिल्में देने के बाद आयुष्मान खुराना अपनी अगली फिल्म 'बाला' के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं। आयुष्मान की फिल्में अक्सर वर्जित माने जाने वाले सामाजिक मुद्दों पर मजाकिया तरीके से वार करती हैं। गंजेपन पर आधारित इस फिल्म में आयुष्मान एक बार फिर कॉमिक किरदार में नजर आएंगे। फिल्म के प्रमोशन के लिए 'द कपिल शर्मा शो' के सेट पर पहुंचे आयुष्मान ने बताया कि ज्यादातर कॉमेडी फिल्में करने के कारण लोग उनसे किसी गंभीर या निगेटिव किरदार की आशा नहीं करते। अगर उन्हें कोई निगेटिव किरदार निभाने का मौका मिलता है तो उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने किरदारों में लगातार प्रयोग करना पसंद करते हैं। आयुष्मान ने शो के सेट पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में फैली अफवाहों पर भी खुलासा किया। अफवाह थी कि 'बाला' की शूटिंग के दौरान उसी गेटअप में घर आने पर उनकी पत्नी उन्हें नहीं पहचान सकीं। इस पर आयुष्मान ने कहा कि काश! ऐसा हो पाता। फिल्म का शेड्यूल इतना व्यस्त था कि उन्हें घर जाने का समय ही नहीं मिला।

मेरी बहन के पास है दुनिया का सबसे अच्छा भाई : कार्तिक आर्यन

मंगलवार को भाईदूज का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। भाई-बहन के रिश्ते के बीच की मजबूती और प्यार को दर्शाते इस त्योहार की धूम बॉलीवुड में भी खूब रही। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन कृतिका तिवारी के साथ दो तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए कार्तिक ने लिखा, 'मेरी बहन के पास दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। यह हमेशा मैं नहीं, वह कहती है। भाईदूज मुबारक।'

दो साल में एक फिल्म करने की कोशिश करते हैं वीर दास

कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास ने साल 2007 में फिल्म 'नमस्ते लंदन' में एक कैमियो रोल से हिंदी सिनेमा में अभिनय में डेब्यू किया था। वह हाल ही में अपने प्रोडक्शन में बनी कॉमेडी वेबसीरीज 'जेस्टिनेशन अननोन' में लोगों को हंसाते नजर आए। वीर को बॉलीवुड में बतौर अभिनेता साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'डेल्ही बेली' से पहचान मिली। इस फिल्म को लेकर वीर ने कहा, 'एक तरह से उस फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का करियर वहीं से शुरू हुआ था। आज मैं अपनी पसंद की फिल्में कर रहा हूं। यह सब मुझे 'डेल्ही बेली' की वजह से ही मिला है। एक्टिंग के अलावा और भी कई चीजों में व्यस्त रहने के कारण मैं ज्यादा फिल्मों में काम नहीं कर पाता हूं। मेरी कोशिश हर दो साल में एक फिल्म करने की होती है। फिल्म यूनिट का हिस्सा बनना मुझे पसंद है।' डिजिटल माध्यम के आने से इन दिनों कॉमेडी के नए प्रारूप सामने आ रहे हैं। वीर मानते हैं कि जितनी ज्यादा कॉमेडी होगी कलाकारों को उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। इससे कलाकारों की कमाई भी बढ़ेगी और अच्छी स्क्रिप्ट भी लिखी जाएंगी। वीर दास को कॉमेडी किरदारों के लिए टाइपकास्ट किए जाने से कोई समस्या नहीं है। उनका कहना है कि वह कॉमेडियन हैं तो उनसे कॉमेडी कराई जा रही है। अगर आगे उन्हें और तरह का रोल करने के मौके नहीं भी मिले, तो भी वह खुश रहेंगे। 'जेस्टिनेशन अननोन' के बाद वीर दास जल्द ही कॉमेडी फिल्म 'हंसमुख' में नजर आएंगे।

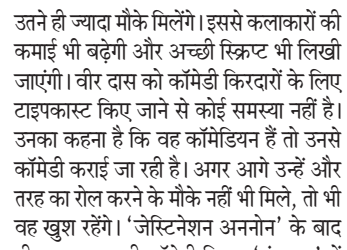

मृणाल कर सकती हैं शाहिद के साथ काम

फिल्म की शूटिंग शुरू होने तक फिल्मों की स्टारकास्ट को लेकर बदलाव होते रहते हैं। इंडस्ट्री में एक कलाकार का दूसरे कलाकार को रिप्लेस करना कोई नई बात नहीं है। खबरें आ रही हैं कि तेलुगु फिल्म 'जर्सी' की हिंदी रीमेक में मृणाल ठाकुर ने कन्नड़ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को रिप्लेस किया है। अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बॉलीवुड के गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक, फिल्म 'जर्सी' के मेकर्स रश्मिका की जगह मृणाल ठाकुर को ले सकते हैं। मृणाल ने 'बाटला हाउस' और 'सुपर 30' जैसी फिल्में की हैं। खबरें हैं कि मृणाल ने फरहान अख्तर के साथ फिल्म 'तूफान' की शूटिंग भी खत्म कर ली है। 'तूफान' स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होगी। 'जर्सी' फिल्म भी स्पोर्ट्स ड्रामा होगी, जो एक असफल क्रिकेटर के जीवन पर आधारित होगी। रश्मिका को रिप्लेस करने की कई वजहें सामने आ रही हैं, जिसमें एक यह है कि 'जर्सी' के मेकर्स अगले महीने फिल्म की शूटिंग शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन वह डेट्स रश्मिका ने अपनी दूसरी साउथ फिल्म के लिए दे रखी है। यह दूसरी बार होगा जब 'कबीर सिंह' फिल्म के बाद शाहिद कपूर तेलुगु फिल्म के हिंदी रीमेक में काम करेंगे। शाहिद 'जर्सी' फिल्म में जो किरदार निभाने वाले हैं, उसे मूल फिल्म में अभिनेता नानी यानी नवीन बाबू गंता ने निभाया था। तेलुगु फिल्म 'जर्सी' इसी वर्ष रिलीज हुई थी और अब इसकी हिंदी रीमेक भी बन रही है। हिंदी रीमेक का निर्देशन मूल फिल्म के निर्देशक गौतम तिन्नानुरी ही करेंगे।

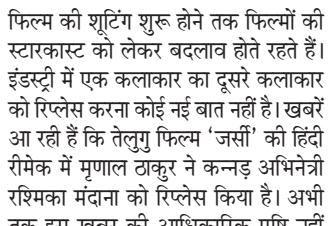

चला पता

डीएनए सैंपलों की जांच कर वैज्ञानिकों ने किया दावा, कहा- जांबेजी नदी के दक्षिण क्षेत्र में दो लाख साल पहले रहते थे होमो सैपियंस

उत्तरी बोत्सवाना में रहते थे होमो सैपियंस

पेरिस, एएफपी : आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहां हुई थी इसे लेकर अभी तक कई दावे किए जा चुके हैं। लेकिन सटीक स्थल का पता अभी तक नहीं दिया गया है। वैज्ञानिकों ने सोमवार को दावा किया कि उत्तरी बोत्सवाना में दो लाख वर्ष पहले आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई थी। यह मनुष्य के पूर्वजों की भूमि के बारे में सबसे अहम दावा है।

लंबे समय से माना जा रहा है कि आधुनिक मानव - होमो सैपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। वैज्ञानिक अभी तक यह बताने में असमर्थ हैं कि हमारी प्रजाति का जन्म स्थान कहां है। वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय टीम ने 200 खोएसान लोगों के डीएनए सैंपल लिए। यह जातीय समूह एल0 के रूप में ज्ञात डीएनए की शाखा के बहुत बड़े हिस्सा के लिए जाना जाता है। यह जातीय समूह आज के समय में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में रहता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने डीएनए सैंपल का भौगोलिक वितरण, पुरातात्विक और जलवायु परिवर्तन आंकड़े के साथ मिलान किया। सामने आए परिणाम के आधार पर वैज्ञानिकों ने बोत्सवाना में जांबेजी नदी के दक्षिण क्षेत्र में दो लाख साल पहले की अवधि का पता लगाया।

जिस इलाके प्रारंभिक मानव रहते थे उस क्षेत्र में कई वर्षों तक वेटलैंड बने रहे और बाद में पूरा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो गया। प्रतीकात्मक

ऐसे किया अध्ययन : इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने एक आनुवांशिक मैप बनाया। इसमें दिखाया गया था कि प्रागैतिहासिक मानव लगभग 70,000 वर्षों तक इस क्षेत्र में रहते थे और 1,30,000 साल पहले उन्होंने चरम मौसमी आपदाओं के चलते मजबूरन दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और गार्सन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के वेनेसा हेस ने कहा, 'हम जानते हैं कि आधुनिक मनुष्यों की उत्पत्ति लगभग दो लाख साल पहले अफ्रीका में हुई थी। लेकिन हमें यह नहीं पता कि उनके वास्तविक आवास किस स्थान पर हैं।'

झीलों के किनारे रहते थे आधुनिक मानव

शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन में उसे क्षेत्र का पता लगाने का दावा किया है। उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र को मैकगादिकगाडी-ओकवांगो कहा जाता था, जहां बड़े पैमाने पर झीलें थीं। यह क्षेत्र आधुनिक विक्टोरिया झील का लगभग दोगुना था और यहां आज बहुत बड़ा रेगिस्तान है।

ऐसे हुआ आबादी का विभाजन

नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, लगभग दो लाख साल पहले भूगर्भिक प्लेटों के खिसकने से यह झील टूट गई थी, जिसके बाद यहां एक बहुत बड़ा वेटलैंड बन गया था। शोधकर्ताओं ने कहा इस क्षेत्र में न केवल मानव रहते थे बल्कि शेर और जिराफ जैसे कई अन्य जीवों के लिए भी यह सबसे उपयुक्त जगह थी। इसके 70 हजार वर्षों बाद पहली बार आनुवांशिक विभाजन शुरू हुआ और आधुनिक मनुष्यों का एक समूह उत्तर-पूर्व की ओर चला गया। इसके 20 हजार साल बाद एक समूह ने दक्षिण की ओर प्रवास कर गया।